❝ अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचें और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखें।
-नेल्सन मंडेला

सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन लोगों की निगाहें अब इसके राजनीतिक असर पर रहेंगी।

राहत और रिहाई

शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए एक अभूतपूर्व फैसले में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत भले मिल गई हो, पर यह उन पर लगे कथित आरोपों से रिहाई नहीं, बल्कि तात्कालिक राहत ही है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय में असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम राहत दी है, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी दो जून को उन्हें हर हाल में समर्पण करना होगा। यही नहीं, इस दौरान मुख्य मामले में सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी, जिसके निर्माण और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र आने पर उपराज्यपाल ने जहां सीबीआई जांच की सिफारिश की, वहीं ईडी ने अगस्त, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी द्वारा एक के बाद एक नौ समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए। अंततः 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इन्कार करने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अदालत ने पहले 28 मार्च, फिर एक अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर और फिर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। इस बीच केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई, फिर उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से फौरी जमानत मिलने के बावजूद इस मामले से जुड़ी पेचीदगियों से सवाल पैदा होते हैं। केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अंतरिम जमानत के दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते।

दूसरी बात, यह फैसला क्या दूसरे मामलों के लिए नजीर बनेगा और जेल में बंद अन्य राजनेता क्या इसी आधार पर जमानत नहीं मांगेंगे? चुनाव के बीच केजरीवाल की अंतरिम रिहाई के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। शीर्ष अदालत द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार, केजरीवाल विचाराधीन मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते और न ही मामले से जुड़े गवाहों से बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को भी इससे दिल्ली और बाहर एक चेहरा मिलेगा, हालांकि निर्वाचन आयोग की भी उन पर नजर रहेगी। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाकी चार चरणों में इसका क्या असर होता है।

तलाक का चलन बढ़ रहा है

बढ़ते तलाक की समस्या का समाधान पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों में तलाशा जा सकता है। हमने परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया है। एक साथ भोजन करने और दिल से दिल की बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं है, जहां परेशानियों व खुशियों का आदान-प्रदान होता है।

दंत चिकित्सक की कुर्सी बातचीत करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, आपका मुंह खुला हुआ होता है और आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। सौभाग्य से मेरे पास एक बातूनी दंत चिकित्सक है। यह युवा महिला विवाह बाजार में तब से है, जबसे मैं उसे जानती हूं। वह लगभग 35 वर्ष की है और विवाह बाजार पर उसकी बातचीत आमतौर पर प्रफुल्लित करने वाली होती है। लेकिन पिछली कुछ मुलाकातों (हां, मैं अक्सर दंत चिकित्सक के पास जाती हूं) में वह तलाकशुदा लोगों की बढ़ती संख्या के बारे में बताती रही है।

अद्वैता काला
पत्रकार, फिल्म कथा लेखक एवं चर्चित उपन्यासकार

डेढ़ दशक पहले एक योग्य और शिक्षित युवा महिला, जिसने कभी शादी नहीं की हो, कभी तलाकशुदा लोगों की ओर देखती तक नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे, पर बहुत कम थे। तलाकशुदा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए फिर से जीवनसाथी तलाशना मुश्किल था, महिलाओं के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। मगर अब विवाह बाजार बदल चुका है, सभी इच्छुक विवाह बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अब तलाक को कलंक समझे जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है।

शहरी इलाकों में तलाक अब सामान्य बात हो गई है, हालांकि लोग अब भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह अच्छी बात है या बुरी। उदारीकरण के बाद के युग में भारतीय समाज में नाटकीय बदलाव आए हैं, क्योंकि पारिवारिक इकाई में रिश्ते और लैंगिक भूमिकाएं भी विकसित हुई हैं। जिस भारतीय समाज में कभी तलाक के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, वहां आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशकों में तलाक के मामलों में 350 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षित रूप से बड़े शहरों में तलाक के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 से 2017 के बीच तलाक के मामलों में मुंबई में 40 फीसदी की और दिल्ली में 1990 से 2012 के बीच 36 फीसदी की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि देश में अब भी तलाक के मामले एक फीसदी के निचले स्तर पर हैं। हालांकि धीरे-धीरे इनमें वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय विवाह की स्थिरता की अवधारणा खतरे में है। वर्ष 2019 में दिल्ली में 60 फीसदी से अधिक तलाक की पहल महिलाओं ने की। इसके कई कारण हैं-उच्च साक्षरता दर, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने महिलाओं को अपने जीवन और निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित किया है।

शोध के मुताबिक, दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक विवाहों की तुलना में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों में वैवाहिक विफलता की दर उच्च है। लेकिन इसकी सफलता एवं विफलता का अनुमान केवल आंकड़ों से नहीं लगा सकते। ऐसे कई कारक हैं, जो तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं और महिला सशक्तीकरण के कदमों को तलाक दर के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह इस देश की महिलाओं एवं बेटियों से अन्याय के साथ-साथ एक गलत धारणा होगी।

आइए, देखते हैं कि वे कौन से कारण हैं, जो तलाक दर को प्रभावित करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 53 फीसदी तलाक की पहल 24 से 35 वर्ष के लोगों द्वारा होती है। जाहिर है कि पीढ़ीगत नजरिये में बदलाव हो रहा है। जैसे-जैसे दुनिया ऑनलाइन एक-दूसरे से जुड़ रही है, मानवीय रिश्ते और अधिक नाजुक हो गए हैं। 'समझौता' एक बुरा शब्द बन गया है, जबकि एक समय यह वैवाहिक जोड़ों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गुण था। अब समझौते को विफलता माना जाता है। इसके अलावा, हनीमून स्थलों के साथ इंस्टाग्राम के लिए तैयार और फिल्टर की गई छवियां, गंतव्य शादियां, दुल्हन के पहनावे एक तरह की वैवाहिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, जिससे वैवाहिक रिश्ते संबंधों के जुड़ाव की तुलना में उत्सव ज्यादा बन जाते हैं। ये सब चीजें युवा जोड़ों के समक्ष एक नई वास्तविकता प्रस्तुत करते हैं, जो स्थायी रिश्ते के लिए अस्थिर नींव प्रदान करता है।

पारिवारिक संरचना भी नाटकीय रूप से बदली है और नौकरी की जरूरतों के कारण घर से दूर जाने की मजबूरी ने परिवार में बुजुर्गों की भागीदारी लगभग समाप्त कर दी है। अब युवा अपने दम पर रिश्ते तय करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15 भारतीय जोड़ों में से एक बांझपन से जूझ रहा है। हालांकि प्रजनन संबंधी उपचार में नाटकीय प्रगति हुई है, मगर यह बहुत महंगा विकल्प है। ज्यादातर जोड़े वित्तीय स्थिरता सहित कई कारणों से माता-पिता बनने में देरी कर रहे हैं। बच्चे जोड़ों के लिए दांपत्य संभालने और रिश्तों में स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा होते हैं। पारिवारिक मूल्य और जुड़ाव अब भी भारतीय समाज को दूसरों से अलग करते हैं और तलाक के आंकड़े कम रखते हैं।

हालांकि तलाक का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इसका समाधान पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों और उनसे मिलने वाली स्थिरता और सहयोग में तलाशा जा सकता है। हमने परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया है। एक साथ भोजन करने और दिल से दिल की बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं है, जहां परस्पर सहयोग और परेशानियों व खुशियों का आदान-प्रदान होता है। रोजगार के लिए युवाओं का घर-परिवार से दूर जाना एक अन्य पहलू है, जिससे निपटने की जरूरत है। पिछले दशकों में छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है और कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है। अब लोग अपने घर के नजदीक रोजगार के अवसर पा सकते हैं, जिससे उन्हें काम और पारिवारिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।

हमें अपनी विचार प्रक्रिया को नया स्वरूप देना होगा और पश्चिमी जीवन-शैली के अंधानुकरण से दूर जाना होगा। हमें व्यक्तिगत सशक्तीकरण और पारिवारिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाना होगा। एक समय पश्चिम ने व्यक्तिगत उत्कृष्टता का जश्न मनाया था और दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत किया था, पर अब वह अपनी विफलता दर्शा रहा है, जिसमें किशोर उम्र में गर्भधारण, एकल अभिभावक वाले घर, स्कूलों में हिंसा, नशीले पदार्थों की लत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सब कई कारणों से होता है, जिसमें परिवार का टूटना भी शामिल है। एक समाज के रूप में आगे बढ़ने के लिए रुककर एक कदम पीछे हटने का वक्त आ गया है।

जीवन धारा

बिनोवा भावे

फल की उम्मीद मत करो। *गीता* यह भी बताती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता के साथ करना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए।

फल की इच्छा का त्याग भी जीवन की कला है

जो कर्म करते हैं, उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे। यह हमारा अधिकार है। और इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखने को न मिले तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी ही भावना या वृत्ति बताती है। वह कहती है-'कर्म तो अवश्य करो, पर फल पर अपना अधिकार मत मानो'। जो कर्म करता है, उसे फल का अधिकार अवश्य है। परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है-लूंगा तो फल के सहित ही। जबकि तमोगुण कहता है-छोडूंगा तो कर्म के सहित ही। यों दोनों एक-दूसरे के भाई ही हैं। इसलिए तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सतगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो, पर फल को छोड़ दो। यानी फल को छोड़कर कर्म करो। फल की उम्मीद मत करो।

गीता यह भी बताती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता के साथ करना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न-चिंतन में उसका थोड़ा-बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी। परंतु फलेच्छा-रहित पुरुष की तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। जैसे नदी को छुट्टी नहीं, हवा को विश्राम नहीं और सूर्य सदैव जलते ही रहना जानता है, उसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा-कर्म को ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट नहीं होगा तो किसका होगा! इसके अलावा सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म-दृष्टि में जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ की दृष्टि से देखता है-'मेरा ही कर्म और मुझे ही फल'। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका थोड़ा भी ध्यान हटा, तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं दिखता। ज्यादा हुआ तो व्यावहारिक दोष दिखेगा। परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। इसलिए वह इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी-सी भी कमी न रह जाए। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। कैसे भी देखिए, फल-त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है। इसलिए फल-त्याग को योग या जीवन की कला ही कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें, तो भी खुद कर्म में जो आनंद है, वह उसके फल में नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है, वह आनंद का एक स्रोत ही है। जैसे- चित्रकार से कहो कि तुम चित्र मत बनाओ और ऐसा करने के लिए तुम जो मांगोगे, देंगे। लेकिन उसका मन चित्र बनाए बिना कहां मानने वाला है! वह तो चित्रकारी किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही कर्म उसका आनंद है। इसी तरह बच्चा खेल के मजे के लिए खेलता है और इसमें उसे व्यायाम का फल अपने आप मिल जाता है।

जैसी भावना, वैसा फल

सूत्र

सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़े-से कर्म से अनंतगुना फल प्राप्त कर लेता है। यह फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है। हालांकि सांसारिक मनुष्य की तपस्या कम कठिन नहीं होती, लेकिन बस फर्क इतना है कि वह तपस्या क्षुद्र फलों की खातिर ही होती है

दूसरा पहलू

दो शोधार्थियों ने दावा किया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सजगता कार्यक्रम से बच्चों और किशोरों में अवसाद बढ़ रहा है।

स्वस्थ बच्चों को बीमार न बनाएं

हाल के वर्षों में बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। विकसित देशों के किशोर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपने अवसाद और उसके इलाज के बारे में बताते रहते हैं। छोटी उम्र के बच्चों में उदासी और खुद को नुकसान पहुंचाने की बढ़ती प्रवृत्ति से परेशान स्कूल भी पाठ्यक्रम में इनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ शोधार्थी यह चेतावनी दे रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देकर हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस संबंध में सजगता के कार्यक्रम निश्चित तौर पर कुछ बच्चों का भला करते हैं, लेकिन इससे समाज में यह सोच बनती है कि ज्यादातर बच्चे व किशोर अवसादग्रस्त हैं, जिसका इलाज जरूरी है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।

एलेन बैरी

मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देकर हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। इससे यह सोच बनती है कि ज्यादातर बच्चे व किशोर अवसादग्रस्त हैं, जबकि ऐसा नहीं है।

शोधार्थियों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में अवसाद से बचने के कार्यक्रमों का हवाला दिया, जिनमें शामिल होने वाले बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उन बच्चों की तुलना में बेहतर नहीं पाया गया, जिन्होंने इन कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था।

मेंटल हेल्थ अमेरिका का ताजा आंकड़ा बताता है कि 60 फीसदी से अधिक अवसादग्रस्त अमेरिकियों को इलाज नहीं नहीं मिलता। मानसिक स्वास्थ्य एक समस्या है, जिसके निदान से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अमेरिका में हुआ एक नया शोध बताता है कि जो बच्चे और किशोर स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, उन्हें अवसादग्रस्त और मानसिक समस्या से ग्रस्त बता दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो शोधार्थियों ने तो दावा किया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सजगता कार्यक्रम से बच्चों और किशोरों में अवसाद बढ़ रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में यह संदेश जा रहा है कि किशोर मानसिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं, जिनका निदान कोई पेशेवर ही कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों की राय यह है कि स्कूलों को छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने से बचना चाहिए।

अजीब विडंबना है कि एक तरफ तो मानसिक रूप से मजबूत स्कूली बच्चों को भी अवसाद मिटाने के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करनी पड़ती है, दूसरी ओर, मेंटल हेल्थ अमेरिका का ताजा आंकड़ा बताता है कि 60 फीसदी से अधिक अवसादग्रस्त अमेरिकियों को इलाज नहीं नहीं मिलता। हालांकि ऐसे शोध के अपने खतरे भी हैं। कई स्कूलों ने ऐसे शोधों को खारिज किया है।

आंकड़े

सौर ऊर्जा उत्पादक

वर्ष 2023 में हमारा देश जापान एवं जर्मनी को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है।

चीन	584.15
अमेरिका	238.12
भारत	113.41
जापान	110.14
जर्मनी	61.56

आंकड़े किलोमीटर में, वर्ष 2023-24 के नवंबर तक के | स्रोत : Ember

परमहंस ने अपने भांजे से कहा-मुझे आज तक ईश्वर के अतिरिक्त कोई मिला नहीं। हरेक प्राणी में ईश्वर को खोजोगे, तो तुम्हें सब में ईश्वर ही मिलेंगे।

ईश्वर सब में हैं

अंतर्यात्रा
संकलित

स्वामी परमहंस साधना और ध्यान करने के लिए रात में पंचवटी के जंगल में जाया करते थे। पंचवटी के जंगल को बहुत भयानक माना जाता था। इसलिए रात तो छोड़िए, दिन में भी वहां कोई जाना नहीं चाहता था।

रामकृष्ण परमहंस के भांजे हृदयराम रोज उन्हें जंगल में जाते देखते, तो चिंतित हो उठते थे। हृदयराम उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह दिन भर उनके साथ रहते और उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, मामा, आप हर रात इतने खतरनाक जंगल में जाकर साधना क्यों करते हैं? स्वामी जी ने कहा, नहीं हृदयराम, वह जंगल खतरनाक नहीं है। वहां मुझे ईश्वर की निकटता का आभास होता है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, जो खतरनाक हो। वह स्थान निर्जन होने के कारण शांत है। और ईश्वर का चिंतन शांति में ही हो पाता है।

हृदयराम ने अपने मन का भय व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन वहां जंगली जीव भी तो हैं, जिनसे आपको खतरा हो सकता है।

स्वामी जी ने प्यार से कहा, सभी में तो ईश्वर हैं। मुझे तो आज तक ईश्वर के अतिरिक्त कोई मिला नहीं। असल में हरेक प्राणी में ईश्वर को खोजोगे, तो तुम्हें सबमें ईश्वर ही मिलेंगे। हृदयराम निरुत्तर हो गया।

आज का इतिहास

भारत ने किया सफल पोकरण परमाणु परीक्षण का ऐलान

11 मई साल का 131वां दिन है और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने एक अरब का आंकड़ा छू लिया, जब नयी दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का एक अरबवां नागरिक घोषित किया गया। यह दिन देश के इतिहास में एक और खास घटना के साथ दर्ज है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोकरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि हानि बीमा पालिसी की शुरुआत की गई। 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि। 1940 में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग सिर्वस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। 1951 में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया।

कृषि व खाद्य के लिए समग्र नीति बने

किसानी के पारंपरिक ज्ञान के बेहतर उपयोग के साथ ही किसानों के खर्च और कर्ज में कमी बेहद जरूरी है।

भारत डोगरा

कृषि

राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कृषि व खाद्य नीति की बहुत चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ऐसी समग्र नीति नहीं बन पाई है, जिसमें सभी जरूरतों का संतुलित समावेश हो सके। ऐसी समग्र नीति में आठ उद्देश्यों का संतुलित निर्वाह होना चाहिए, जो परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

पहला उद्देश्य तो यह है कि किसानों को, विशेषकर छोटे व मध्यम किसानों को संतोषजनक, टिकाऊ व रचनात्मक आजीविका उपलब्ध हो। संतोषजनक का मतलब उन्हें उपज की उचित कीमत मिले, जिससे जीवन-निर्वाह के अनुकूल आय प्राप्त हो। टिकाऊ का अर्थ आजीविका व इसका आधार भावी पीढ़ी के लिए भी टिका रहे। पानी-मिट्टी जैसी खेती की बुनियादी जरूरतें अच्छी स्थिति में बनी रहें। रचनात्मक का अर्थ खेती-किसानी के

ज्ञान का किसान बेहतर उपयोग कर सकें, जिसमें परंपरागत ज्ञान व महिला किसानों की समझ की बड़ी भूमिका है। खर्च और कर्ज में कमी जरूरी है।

दूसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य पदार्थ उचित कीमत पर मिलें, जो उन्हें स्वस्थ व नीरोग रखें। तीसरा उद्देश्य यह है कि कृषि व गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। भू-जल स्तर ठीक बना रहे, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहे, जल-स्रोत उपलब्ध हों, किसान के मित्र, जो कीट-पतंगे, मधुमक्खियां, पक्षी आदि हैं, उनकी भी रक्षा हो तथा परागण की क्रिया ठीक से हो। सभी गांवों में भरपूर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष रहें। परंपरागत बीजों की रक्षा भी बहुत जरूरी है।

चौथा उद्देश्य यह है कि जलवायु बदलाव के मौजूदा दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम रखा जाए और इस कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी स्थितियों व आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो। बुरे मौसम व आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से बेहतर तैयारी करनी होगी। यदि ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने का कार्य ठीक से हो, तो इसके लिए विश्व स्तर पर स्थापित कोष से धनराशि प्राप्त की जा सकती है और किसानों को दी जा सकती है।

पांचवां उद्देश्य है कि भूमिहीन खेत मजदूरों को बेहतर मजदूरी और जहां संभव हो, कुछ भूमि देकर उनकी सहायता की जाए। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की भलाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। विशेषकर डेयरी व पशुपालन, किचन गार्डन आदि के माध्यम से भी इनकी मदद हो सकती है।

छठा उद्देश्य है कि खेती के उत्पादों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि केवल खेती से गांव व गांव के लोगों की समृद्धि का मजबूत आधार नहीं बनता है। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

सातवां उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न भागों की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार कृषि विकास की अलग-अलग जरूरतों के अनुकूल नियोजन होने चाहिए। यानी विकेंद्रित स्थानीय जरूरतों के अनुकूल कृषि नीति पर अधिक जोर देना चाहिए।

आठवां और अंतिम उद्देश्य यह है कि खेती व ग्रामीण विकास के लिए सरकारों को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। एक बार किसानों के कर्ज को माफ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि सस्ती तकनीक अपना कर वे आगे कर्ज से बच सकें।

बेशक इन सब उद्देश्यों का एक साथ एक समग्र संतुलित नीति में समावेश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस राह पर चलते हुए हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों में कोई आपसी टकराव नहीं है। इन सभी उद्देश्यों को हम एक साथ एक समय में समावेशी नीति से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक इन नीतियों के साथ कुछ समाज-सुधार के कार्य नहीं जुड़ेंगे, तब तक बेहतर से बेहतर आर्थिक नीतियां भी सफल नहीं होंगी।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 85 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

दैनिक जलते दीप

जोधपुर, शनिवार 11 मई 2024

अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला बेहद चिंताजनक

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अस्पताल जैसी जिस जगह पर लोग अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने, जान बचाने की भूख में जाते हैं, वहां अन्य कर्मचारियों से लेकर खुद कुछ चिकित्सक तक उनकी सेहत को कई बार दांव पर लगा देते हैं। सीबीआइ ने छानबीन के बाद दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे जिस भ्रष्ट तंत्र का खुलासा किया है, वह बेहद चिंताजनक है। गौरतलब है कि इस अस्पताल के दो चिकित्सकों सहित ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक ओर रिश्वत के बदले वहां कुछ खास कंपनियों के उत्पाद के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं मरीजों पर भर्ती होने के लिए पैसे भी लिए जाते थे। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खबरों के मुताबिक, किसी गर्भवती के परिजन जब तक रिश्वत की रकम नहीं चुकाते थे, तब तक उन्हें वार्ड में जगह नहीं दी जाती थी। मरीजों और उनके परिजनों को धमकाने के भी आरोप हैं। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी में सबसे अहम माने जाने वाले अस्पतालों में से एक में इस तरह का भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा था और उस पर किसी की नजर नहीं जा रही थी या फिर जानबूझ कर उसकी अनदेखी की जा रही थी। माना जाता है कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर चाकचौबंद होगी और यहां इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बन सकती। मगर इस जाने-माने अस्पताल में कुछ चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने रिश्वत के बदले कुछ खास कंपनियों के उत्पादों और उपकरणों के कारोबार को जिस तरह बढ़ावा दिया, वह हैरान करने वाला है। सवाल है कि इस भ्रष्टाचार को खुद अस्पताल के तंत्र के भीतर या फिर सरकार के संबंधित महकमों की नजर और फिर कार्रवाई के दायरे में आने में इतना वक्त कैसे लग गया? चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और उनके उपयोग पर नजर रखने के लिए क्या वहां कोई व्यवस्था नहीं है? अगर है, तो कुछ खास कंपनियों के सामानों पर लगातार मेहरबान होने पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? अगर मरीजों से गलत तरीके से पैसे वसूले जाते थे या फिर कुछ खास ब्रांड के उत्पाद ही लेने पर मजबूर किया जाता था, तो यह इतनी देर से पकड़ में क्यों आया? जाहिर है, भ्रष्टाचार का यह दुश्चक्र अस्पताल के कुछ डाक्टर और अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल रहा होगा। यह छिपा तथ्य नहीं है कि कई बार मरीजों को कुछ डाक्टर गैरजरूरी दवाइयां लेने की सलाह भी देते हैं। दवा या चिकित्सा उपकरणों के कारोबार को बढ़ावा देने के एवज में दवा कंपनियों की ओर से डाक्टरों को दुनिया के अलग-अलग देशों के दौरे पर ले जाने या महंगा तोहफा देने के प्रस्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जिसमें किसी खास दवा कंपनी से धन या सुविधाओं के बदले डाक्टर मरीजों को वैसी दवाएं लेने या जांच कराने की सलाह दे देते हैं, जो निहायत ही गैरजरूरी होती हैं। इसकी क्या गारंटी है कि मरीजों को इस तरह की जिन दवाओं का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, वे उनकी सेहत के लिहाज से खतरनाक या अनुपयोगी नहीं होंगी या उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा? मगर यह अफसोसनाक हकीकत है कि पैसा बनाने के खेल में शामिल चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को मरीजों के जीवन की कोई फिक्र नहीं होती।

मुद्दों की भटकन

हम कहते नहीं थकते कि देश का विकास कुलांचे भर रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था हैं। अभी पांचवें स्थान पर हैं व जल्दी ही तीसरे स्थान पर होंगे। ये ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी भारतीय युवाओं की है। हम चांद पर पहुंचे। हमने मंगल के दरवाजे पर दस्तक दी। हमारी ओलंपिक में उपलब्धियां रहीं। पैरा ओलंपिक में हमारे मेडलों का सैकड़ा पहली बार आया। अकसर ये हमारे मीडिया की सुर्खियां हुआ करती थीं। लेकिन सवाल है कि आम चुनाव के तीसरे चरण तक आते-आते देश का राजनीतिक विमर्श इतना नकारात्मक क्यों हो गया? आखिर क्यों हम देश की जनता को सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव में मतदान करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकते? अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों में नकारात्मकता व आक्रामकता क्यों है? क्यों राजनीतिक दलों के नेता आमने-सामने बैठकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों व भविष्य के एजेंडे को लेकर जनता से रूबरू नहीं होते? अमेरिका व अन्य विकसित देशों में शीर्ष राजनेताओं द्वारा लंबी बहसों से जनता को समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। आखिर अमृतकाल के दौर में पहुंचकर भी देश में मतदाता इतना जागरूक क्यों नहीं हो पाया है कि उसे क्षेत्रवाद, धर्म-संप्रदाय, जातिवाद और अन्य संकीर्णताएं न लुभा सकें? क्यों चुनाव आयोग की मुहिम में बरामद रिकॉर्ड मूल्य की वस्तुओं में आधा मूल्य नशीले पदार्थों का होता है? क्यों छोटे-छोटे प्रलोभनों के जरिये मतदाता बहकते हैं? कहीं न कहीं हमारे नेताओं ने देश के जनमानस को पूरी तरह लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने के बजाय संकीर्णता के शार्टकट से अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। निस्संदेह, देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिये समाज में जागरूकता आई है। लोग सार्वजनिक विमर्श में अखबार व अन्य मीडिया की भाषा बोलते नजर आते हैं। तो फिर वे मतदान करते समय क्यों बहक जाते हैं? आखिर क्यों कहा जाता है कि फलां जगह पचास प्रतिशत या साठ प्रतिशत मतदान हुआ है? आखिर पचास प्रतिशत या चालीस प्रतिशत वोट न देने वाले लोग कौन हैं? यहां एक तथ्य यह भी है कि यदि आम चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग धर्म, सांप्रदायिकता, क्षेत्र, जाति व अन्य संकीर्णताओं का सहारा ले रहे हैं तो कहीं न कहीं एक वजह यह भी है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी लोग इन मुद्दों की तरफ आकर्षित होते हैं? कई जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनावों में नाराजगी दिखाई देती है तो जनता फिर दूसरे राजनैतिक दल को सत्ता सौंप देती है। यह उसके पास विकल्प न होने की स्थिति होती है, लेकिन फिर दूसरा दल भी उन्हीं संकीर्णताओं को अपना एजेंडा बनाकर चुनाव मैदान में आ जाता है। सवाल यह है कि किसी दल ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं क्यों नहीं उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जाता है? क्या दल विशेष को अपनी बखान की गई उपलब्धियों की जमीनी हकीकत का अहसास होता है? भारत एक विविधता की संस्कृतियों का देश है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता और जरूरतें हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक रुझान और दक्षिण भारत के राजनीतिक रुझान में हमेशा अंतर देखा गया है। जिसका लाभ एक क्षेत्र में पिछड़ने वाला राजनीतिक दल दूसरे क्षेत्र में उठाता है। हाल के दशकों में ऐसे कद्दावर नेता कम ही हुए हैं जिनकी राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता रही हो। लेकिन देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिये जरूरी है कि सत्ता की रीतियां-नीतियां पूरे देश के मनोभावों के अनुकूल हों। राजनेताओं की कार्यशैली और घोषणाएं संकीर्णताओं से मुक्त हों। यदि देश में नकारात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जिसका असर हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता पर भी पड़ेगा। यदि राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मकता का प्रवाह नहीं होता तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े लोकतंत्र का बड़प्पन हमारे राजनेताओं में भी नजर आना चाहिए और मतदाताओं में भी। यदि हम संकीर्णताओं के पक्ष में मतदान कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हम कमजोर व अयोग्य लोगों को ऊंची कुर्सी पर बैठाकर लोकतंत्र का अवमूल्यन कर रहे होते हैं।

प्रसंगतः उपदेश और व्यवहार

एक जिज्ञासु युवक किसी प्रसिद्ध महात्मा के पास गया और उनसे कुछ उपदेश सुनाने की प्रार्थना करने लगा। महात्मा ने उस युवक को गौर से देखा फिर बोले, 'मेरा पहला उपदेश तो यही है कि आज के बाद किसी से उपदेश मत मांगना।' यह सुनकर युवक हैरानी से बोला, 'क्यों महाराज, उपदेश सुनना तो अच्छी बात है।' उसकी बात पर महात्मा बोले, 'इसका जवाब अभी मिल जाएगा।' कुछ देर सोचने के बाद महात्मा ने उससे पूछा, 'बताओ, सच बोलना अच्छा है या बुरा?' युवक बोला, 'सच बोलना तो अच्छा है महाराज।' महात्मा ने फिर प्रश्न किया, 'चोरी करना ठीक है या गलत?' युवक बोला, 'गलत है महाराज।' महात्मा का अगला सवाल था, 'कटु वचन व मीठे वचनों में कौन सा वचन बोलना अधिक सार्थक है?' युवक बोला, 'महाराज, मीठे वचन बोलना ही अधिक सार्थक है।' इसके बाद महात्मा ने कहा, 'एक अंतिम बात और बताओ पुत्र कि समय का सदुपयोग करना चाहिए अथवा नहीं।' युवक ने जवाब दिया, 'समय का सदुपयोग तो अवश्य करना चाहिए क्योंकि गया समय कभी वापस नहीं आता।' महात्मा बोले, 'तुम सब कुछ जानते ही हो तो अब और क्या उपदेश सुनना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि कुछ बड़ी-बड़ी गूढ़ बातें ही उपदेश हैं? ऐसी बातें सुनने से क्या फायदा जो सुनने में तो अच्छी लगें पर समझ में ही न आएं और जिनसे हमारे जीवन में कोई अंतर न आए। उपदेश की सार्थकता तभी है जब वह हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को बदले। जीवन में छोटी-छोटी बातें ही ज्यादा काम आती हैं। तुम्हें जीवन के मूलभूत गुणों का ज्ञान है, लेकिन मात्र ज्ञान से काम नहीं चलता। उन गुणों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए।' युवक महात्मा का जवाब सुनकर दंग रह गया। उसने महात्मा से कहा कि आगे से वह इस बात का ध्यान रखेगा और जिन सार्थक बातों को वह जानता है, उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारेगा।

राष्ट्रीय अस्मिता को सींचने का प्रथम उद्घोष

– प्रेम सिंह

ब्रिटिश शासकों, इतिहासकारों, अध्येताओं, लेखकों, लोकगीतकारों ने 10 मई, 1857 को मेरठ से शुरू हुए सिपाही विद्रोह को कई नामों से उल्लेखित किया है। नामों की यह विविधता विद्रोह के प्रति लोगों के अलग-अलग नजरियों को दर्शाती है। नजारियों की जंग में विद्रोह को अपमानजनक संबोधन 'गदर' से लेकर 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' तक बताया गया है। हालांकि, अंग्रेजों द्वारा अपमानजनक सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त किया गया गदर शब्द आगे चल कर भारतीयों के लिए सम्मानजनक अर्थ ग्रहण कर लेता है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अमेरिका में 1913 में गठित संगठन का नाम गदर रखा गया। अपने मुखपत्र का नाम भी उन्होंने 'गदर' रखा। सन् 1857 के विद्रोह पर करीब 75 साल बाद लिखे गए पहले हिंदी उपन्यास का शीर्षक भी 'गदर' है। अमृतलाल नागर ने विद्रोह संबंधी ब्योरे एकत्रित किए तो उस पुस्तक का नाम 'गदर के फूल' रखा। नोमन्क्लेचर के अलावा इस विद्रोह के चरित्र को लेकर भी कई धारणाएं मिलती हैं। उसे 'सामंती' से लेकर 'जनवादी' तक कहा जाता है। विद्रोह में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में भी कई दावे मिलते हैं। ब्रिटिश रेकॉर्ड्स में विद्रोह में मारे जाने वाले अंग्रेजों -बच्चों और महिलाओं समेतङ्क का आंकड़ा 6000 के करीब है। विद्रोह के दमन के दौरान और दमन के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई बदले की कार्रवाई में मारे जाने वाले भारतीय पक्ष के लोगों की संख्या 8 लाख से 30 लाख तक बताई जाती है। इसमें विद्रोह से जुड़े अकाल और महामारी में मारे जाने वाले भारतीयों की संख्या को भी शामिल किया जाता है। विद्रोह के इतिहासकारों, उससे जुड़ी विभिन्न घटनाओं और पात्रों पर आधारित संस्मरण एवं कथात्मक विवरण लिखने वाले लेखकों के लेखन में सभ्य-असभ्य और क्रूर-क्रांतिकारी का परस्पर विरोधी विमर्श भी मिलता है। वर्ष 1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या विद्रोह मूलतः राष्ट्रीयता के विचार से परिचालित था- यह सवाल भी खासा विवादास्पद रहा है। कहने का आशय यह है कि 1857 के विद्रोह के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए तर्कों-प्रतितर्कों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने मौजूद है। विद्रोह की 167वीं वर्षगांठ पर लिखी गई इस टिप्पणी में क्रांतिकारियों के 'झंडा सलामी गीत' के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या विद्रोह के मूल में पराधीनता की पीड़ा से पैदा हुआ राष्ट्रीयता का विचार था। दरअसल, राष्ट्रीयता का विचार एक सीधा और सरल विचार कभी नहीं रहा है। युग-विशेष, युगीन परिस्थितियां, सामाजिक ताना-बाना आदि कारक राष्ट्रीयता के विचार को एक जटिल, और कई बार अंतर्विरोधपूर्ण विचार बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के विचार को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

'झंडा सलामी गीत' अथवा कौमी तराना 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख पात्र अज़ीमुल्ला खान यूसुफजई ने लिखा था, और दिल्ली के 'पयाम-ए-आजादी' नामक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। फरवरी, 1857 में शुरू किए गए इस उर्दू-हिंदी पत्र के प्रकाशक अज़ीमुल्ला खान और मुख्य संपादक बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पोते मिर्जा बेदार बख्त थे। (यह स्वाभाविक है कि पत्र को नाना साहिब का सरंक्षण प्राप्त था। क्योंकि उनके दीवान अज़ीमुल्ला खान फरवरी, 1857 में एक फ्रेंच प्रिंटिंग प्रेस लेकर भारत आए थे, जिस पर यह पत्र छापा जाता था)। सितंबर, 1857 से यह पत्र मराठी में झांसी से भी प्रकाशित हुआ। बादशाह ज़फ़र का प्रसिद्ध 'पेंफलेट' 'पयाम-ए-आजादी' में ही प्रकाशित हुआ था। पूरे उत्तर भारत में तेजी से इस पत्र का प्रसार फैल गया था। 29 मई, 1857 को पत्र ने विद्रोह को अपना समर्थन घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 'देशद्रोह' के आरोप में पत्र के प्रकाशन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। बेदार बख्त को फांसी दे दी गई। अज़ीमुल्ला खान के बारे में माना जाता है कि वे कानपुर की पराजय के बाद नाना साहिब के साथ नेपाल की सीमा की ओर निकल गए थे, जहां 28 वर्ष की आयु में बीमारी से उनकी मौत हो गई।

कानपुर निवासी अज़ीमुल्ला खान न सिपाही थे न सामंत। वे अत्यंत साधारण सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। उनके मिस्त्री पिता का निधन हो चुका था। वर्ष 1837-38 के अकाल में अपनी माता के साथ वे संयोग से जीवित बच पाए थे। बाद में माता का भी निधन हो गया। उन्होंने अनाथालय में रह कर और एक अंग्रेज के घर में काम करते हुए शिक्षा प्राप्त की। वे पहले कई अंग्रेजों के सचिव बने, और फिर नाना साहिब के दीवान का पद सम्हाला। नाना साहिब ने बहुभाषाविद (उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाएं आती थीं) और कुशाग्र-बुद्धि अज़ीमुल्ला खान को प्रधानमंत्री के पद पर प्रोन्नत किया।

ऐसा माना जाता है कि आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी अज़ीमुल्ला खान अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान नाना साहिब की पेंशन तो बहाल नहीं करा पाए, लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य से भारत को मुक्त कराने का विचार और दृढ़ इरादा लेकर भारत लौटे। ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है, यह मिथक उन्होंने अपनी आंखों से टूटता हुआ देखा। उन्होंने देखा कि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं को रूस की सेना ने पराजित कर दिया है। अज़ीमुल्ला खान नवजागरण की चेतना के दायरे के बाहर की गई देश की स्वाधीनता की चिंता और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं।

हम ओज के 'झंडा सलामी गीत' की व्याख्या करें तो पाते हैं कि इसमें ब्रिटिश आधिपत्य को भारत की राष्ट्रीय पराधीनता के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तानी इस मुल्क के स्वाभाविक मालिक हैं। यह सही है कि 1857 के विद्रोह का भौगोलिक विस्तार मुख्यत~ उत्तर, पूर्व और मध्य भारत तक था। लेकिन क्रांतिकारियों का दावा हिमालय से समुद्र-पर्यंत हिंदुस्तान का था। यह एक जरखेज धरती है, जिसकी संपदा को अंग्रेज लूट रहे हैं। 'ऐसा मंतर मारा' की ध्वनि है कि अंग्रेजियत का जादू महत्वपूर्ण माने जाने वाले भारतीयों के सिर चढ़ कर बोल रहा था। इस ध्वनि की गूंज गांधी के 'हिंद स्वराज्य' में मिलती है, जहां वे कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमने खुद उनकी गुलामी कबूल की है। यह सही है कि ज्यादातर राजे-रजवाड़ों और भारतीय ब्रिटिश आर्मी की बटालियनों ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया; अथवा तटस्थ रहे। नव-शिक्षित भद्रलोक द्वारा प्रवर्तित नवजागरण की चेतना का संबंध भी 1857 के विद्रोह के साथ नहीं जुड़ता। झंडा सलामी गीत में उस समय के प्रामाणिक भारतीय की कसौटी प्रस्तुत की गई है कि वही सच्चा भारतीय है जो शहीदों की ललकार पर गुलामी की जंजीरें तोड़ने का उद्यम करता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 1857 के विद्रोह के बाद चले आजादी के संघर्ष के फलस्वरूप जो भारत की आजादी संभव हुई, उसके खिलाफ राजे-रजवाड़े, धार्मिक संगठन और कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खिलाफ थे। ऐसे अप्रामाणिक भारतीयों के चलते देश का बंटवारा भी हुआ।

यह सही है कि विद्रोह में कई बार धार्मिक, जातिवादी, जातीय (एथनिक), क्षेत्रीय आदि फॉल्टलाइंस उभरती हैं। एक उपमहाद्वीप के आकार के देश में, जिसका अत्यंत प्राचीन समाज विविधताओं और साथ ही विषमताओं से भरा हो, विद्रोह के दौरान फॉल्टलाइंस का उभरना स्वाभाविक था। गौरतलब है कि झंडा सलामी गीत में धार्मिक अस्मिता के सवाल पर देश की आजादी का आह्वान नहीं किया गया है। अलबत्ता, सभी धर्मावलंबियों के बीच एकता और प्यार का उल्लेख किया गया है। शायद अज़ीमुल्ला खान धार्मिक अस्मिता की पुकार को राष्ट्रीय अस्मिता की पुकार में बदलना चाहते थे।

(लेखक दिल्ली वि.वि. के पूर्व शिक्षक और भा.उ.अ.सं., शिमला के पूर्व फेलो हैं।)

राजनैतिक उदासीनता रै कारण राजस्थानी नै नीं मिळ सकी संवैधानिक मान्यताः डॉ. राजपुरोहित

मायड़ भासा सूं जुड़ियोडौ है प्रदेस री युवा पीढी रौ भविस, साहित्य अकादेमी सिरै राजस्थानी पुरस्कार 2023 अर मारवाड़ रतन अवार्ड 2024 सूं पुरस्कृत ख्यातनाम कवि-आलोचक डॉ.गजेसिंह राजपुरोहित सूं खास बंतळ

राजस्थानी भासा -साहित्य रा ख्यातनाम कवि-आलोचक डॉ.गजेसिंह राजपुरोहित अेक कांनी राजस्थानी भासा नै संवैधानिक मान्ता दिरावण सारु साचा मन अर समरपित भाव सूं महताऊ खेचळ कर रैया है तो सागै ई अै आपरी सतत साहित्य साधना अर अनूठी आलोचनात्मक दीठ रै कारण राजस्थानी साहित्य जगत मांय आपरी ऊजळी अर लूंठी ओळखाण राखै। लारला दिना इणारी राजस्थानी प्रबंध काव्यकृति 'पळकती प्रीत' नै साहित्य अकादेमी रौ सिरै राजस्थानी पुरस्कार अर हाल ई में मारवाड़ रतन अवार्ड - पद्मश्री डॉ.सीताराम लाळस पुरस्कार सूं पुरस्कृत डॉ. राजपुरोहित सूं हुयी अेक महताऊ साहित्यिक बंतळ रा कीं अंस-

आपरी राजस्थानी काव्यकृति 'पळकती प्रीत' कांई है- पळकती प्रीत राजस्थान रै मध्यकालीन राजस्थानी प्रेमाख्यांन नै आधुनिक दीठ रै परवांणै मानवीय संवेदना सूं परिपूरण प्रबंध काव्य रै रूप में अेक नवौ सिरजण है । इण मांय मूमल - महेन्दर, ढोला-मारू, जेठवा-ऊजळी, बाघो-भारमली, नरबद-सुपियारदे, सैणी-बीझाणंद, आभल- खींवजी, नागजी-नागवती, जलाल- बूबना, सोरठ - बींझौ, केहर-कंवळ जैड़ा जगचावा इग्यारह प्रेमाख्यानां रौ आधुनिक दीठ सूं कविता रूप में सिरजण हुयौ है ।

साहित्य अकादेमी रै इण सिरै अवार्ड रै अंतरगत कांई मिळै- साहित्य अकादेमी अवार्ड हरेक रचनाकार रै जीवण रौ अेक सुपनौ हुवै। साहित्य जगत मांय औ सै सूं सिरै अवार्ड है इण सारू हरेक रचनाकार इणनै आपरौ सौभाग्य मानै । इण पुरस्कार रै अंतरगत ताम्र फलक, शॉल, श्रीफळ, सैनांणी अर अेक लाख रिपिया ससम्मान मिळै।

आप आ पोथी अर औ पुरस्कार किण नै समरपित करियौ अर क्यूं- असल में राजस्थानी भासा - साहित्य मांय म्हनै ख्यातनाम कवि-आलोचक प्रोफेसर (डॉ.) अर्जुनदेव चारण रौ घणौ महताऊ सानिध्य मिल्यौ । वां सूं सदैव कीं न कीं सीखण नै मिल्यौ। जे आ केय दूं कै वे म्हारै सिरजण रा आदर्स है तो कोई अजोगती बात कोनी। कोराना काळ रै दरम्यान लिख्योड़ी आ पोथी म्है वां नै इज समरपित कीनी है सो औ पुरस्कार श्रद्धेय डॉ.अर्जुनदेव चारण नै समरपित करता म्हनै घणौ अंजस है।

राजस्थानी भासा-साहित्य नै लेय' र आज रौ युवा कांई सोच रेयौ है- राजस्थानी भासा-साहित्य नै लेय' र आज रौ युवा घणौ सकारात्मक है। वो आपरी मायड़ भासा अर साहित्य सूं हदभांत जुड़ियोड़ौ है । लगौलग महताऊ सिरजण कर रैयौ है । इणरी संवैधानिक मान्यता नै लेय र घणौ सजग अर सावचेत है । औ इज कारण है कै प्रदेस मांय आज रौ युवा राजस्थानी भासा री संवैधानिक मान्यता रै आंदोलन में आपरी सबळी भूमिका निभाय रैयौ है । मायड़ भासा सूं वांरौ भविस जुड़ियोड़ौ है सो आज प्रदेस रा युवा नै इण बात रौ पूरौ पतियारौ है कै आवणवाळा समैं मांय राजस्थानी भासा नै निस्चै ई संवैधानिक मान्यता मिळैला।

आधुनिक राजस्थानी मांय महिला लेखिकावां किण भांत सिरजण कर रैयी है- राजस्थानी समाज में महिलावां माथै सदैव दौवड़ी जिम्मेवारी रैयी पण महताऊ बात आ है कै राजस्थानी साहित्य में वे सदैव सारथक सिरजण करती रैयी। आज गुमेज री बात तो आ है कै आधुनिक साहित्य री सगळी विधावां मांय राजस्थानी महिलावां भारतीय भासावां रै जोड़ाजोड़ सिरजण कर रैयी है।

आधुनिक काल में दूजी भासावां री जोड़ में आप राजस्थानी री विधावां नै किण रूप में मानौ- राजस्थानी रौ साहित्य आदिकाल सूं सिमरध रैयो हैं। भारतीय भासावां रै परिपेख में देखां तो दूजी भासावां सूं ई पैला राजस्थानी में गद्य रौ विगसाव हुयौ हैं। मध्यकालीन राजस्थानी में पट्टा -परवाना, रुका, बहियां, दवावैत वचनिका आद गद्य शैलियां में बोहळायत में रचनावां मिली। आधुनिक काल रै परिपेख में देखां तो कविता, कहाणी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, आलोचना आद विधावां में मोकळौ सिरजण होय रैयौ हैं, जकौ विश्व री किणी भासा सूं कमती नीं हैं। समै रै परवांण विसय ई आज रै अनुरूप अर आधुनिकताबोध सूं सराबोर हैं। आज राजस्थानी साहित्य भारतीय साहित्य रै जोड़ाजोड़ ऊभौ है ।

आपरी दीठ में एक कवि सामान्य लोगां सूं अलग व्है- भारतीय वाड्मय में कवि ने प्रजापति यानि बिरमा रै बराबर मानीज्यौ हैं। कवि समाज में नव-सिरजण रौ काम करिया करै। वौ संवेदनशील व्हिया करै। औ इज कारण हैं कै वौ पशु-पंखी, मांणस जात आद री पीड़ा नै अपणी समझ' र जीवै अर भोगै, सबदां रौ खोळियौ देय'र लोक रै सांमी राखै। सामान्य लोग दूजां रै सुख-दुख अर पीड़ नै अपणी नीं बणा सकै, पण कवि बणाया करै। औ इज कारण हैं कै वौ सामान्य लोगां सूं सोचण-समझण अर लिखण री दीठ सूं अलग व्हिया करै।

अबार आप जेएनवीयू रै राजस्थानी विभाग रा विभागाध्यक्ष हौ। विश्वविद्यालय आपनै इण बरस कुलपति अवार्ड 2023 समरपित कीनौ। राजस्थानी भाषा-साहित्य रै सारूं कांई योजनावां हैं आपरी- राजस्थानी विभाग रै विभागाध्यक्ष रूप में दूजी वळा म्हनै सेवा करण रौ अवसर मिल्यौ हैं। अठै केई शोधार्थी आपणी भासा अर संस्कृति रै महताऊ विसयां माथै शोधरत हैं, जिणारै शोध सूं राजस्थानी साहित्य में वधापौ होवैला, साथै ई शोध री दीठ सूं नूंवा प्रतिमान थापित होवैला। राजस्थानी विभाग लगोलग सांस्कृतिक अर साहित्यिक गतिविधियां रै माध्यम सूं युवा रचनाकार नै प्रोत्साहित करण रौ काम ई कर रैयो हैं। म्हारै सारू आ गुमेज री बात है कै म्हारी सेवावां रै लेखै म्हारै विश्वविद्यालय परिवार रा मुखिया प्रोफेसर (डॉ.) के.एल. श्रीवास्तव इण बरस गणतंत्र दिवस रै सुभ अवसर माथै कुलपति अवार्ड दीनौ । निस्चै ई इण भांत रै सम्मान सूं हरेक शिक्षक नै सकारात्मक काम करण री प्रेरणा मिळै।

कांई राजस्थान में प्राथमिक सिक्सा अपांरी मायड़ भासा में संभव है- हां, बिलकुल संभव है । नवी सिक्सा नीति रै त्हैत अबै आ आस घणी प्रबळ हुयी है । देस अर दुनिया रा तमाम भासाविद आ मानै कै टाबरा नै प्राथमिक सिक्सा वांरी मायड़ भासा में इज मिलणी चाहीजै। पण राजस्थान में उल्टी गंगा चालती दीसै क्यूंकै अठै उच्च सिक्सा रै अंतरगत बारवीं सूं लैय'र एम.अे. अर पीएच-डी. तांई अपांरी मायड़ भासा राजस्थानी मांय भणाई हुवै पण दुरभाग सूं अठै री प्राथमिक सिक्सा मांय टाबरां नै आपरी मायड़ भासा में भणाई रौ हक अजै तांई नीं मिळियौ । अबै प्रदेस में नवी सिक्सा नीति रै त्हैत प्रबळ आस जगी है कै अठै रा टाबरा नै ओ हक बेगौ ई मिळैला।... निस्चैई ई मिलणौ ई चाहीजै ।

आप आपरी साहित्यिक जातरा नै किण रूप में देखौ- म्हैं आज जद साहित्य अकादमी अवार्ड मिलण री बखत म्हारी साहित्यिक जातरा नै निरखूं-परखूं तो लखावै कै आ ईश्वर री इज किरपा हैं, जकौ म्हनै इण दिसा में प्रवृत्त करियौ। घर में न कोई साहित्यकार हौ अर न कोई परिवेस हौ। ठेठ गांवाऊ परिवेस सूं निकल'र इत्ती तक पूगणौ म्हारै सारूं अंजस री बात हैं। बाळपणै में लिखण-पढ़ण री रुचि ही अर इण रूचि रै पांण इज अेक-अेक पांवडौ आगै बधतौ रैयो हूं। इयां म्हारी पैली पोथी राजस्थानी काव्य संग्रै 'जस रा आखर' सन 2006 में प्रकासित हुयी । इणरै पछै आज लग म्हारै मौलिक सिरजण री सात अर संपादन री दस पोथियां प्रकासित होय चूकी है । औ पुरस्कार इण साहित्य साधना रौ इज सारथक परिणाम हैं।

आपनै लारला दिना प्रदेस रौ प्रतिष्ठित अवार्ड मारवाड़ रतन अवार्ड 2024 मिळियौ, साहित्यिक जगत में इण बात री सगळा नै घणी खुसी है आप वां सूं कांई कैवणी चावौ- सही बात तो आ है कै इण पुरस्कार सारु म्हैं नीं तो आवेदन करियौ अर नीं कोई डिजायर भिजवाई । औ पुरस्कार समिति अर समिति संरक्षक रौ सामूहिक निरणै है जिणरी राजस्थानी साहित्य जगत अर राजस्थान रा मोटयार खूब सरावण कीनी। असल में राजस्थानी भासा, साहित्य अर संस्कृति रै विकास अर सार-संभाळ सारू महरानगढ म्यूजियम ट्रस्ट अर वांरा संरक्षक महाराजा श्री गजसिंह जी मारवाड़-जोधपुर लारला कैई बरसा सूं अणूती ई महताऊ अर उल्लेखजोग काम है । इणी 'ज कड़ी मायड़ भासा-साहित्य में उल्लेखजोग सेवा सारु ट्रस्ट कांनी सूं औ अवार्ड दियौ जावै। अबार आखै राजस्थान री युवा सगती अपांरी मायड़ भासा अर संस्कृति नै बचावण रा समरपित भाव सूं महताऊ जतन कर रैयी है । वां युवा मांय सूं जद किणी अेक रौ इण सारु चयन हुयौ तो आखै प्रदेस रा मोटयारां अर पढेसरां नै खुसी होवणी वाजिब है । अठै आ बात कैय दूं कै आज प्रदेस रौ युवा आपरी मायड़ भासा राजस्थानी में आपरौ भविस देख रेयौ है तो कोई अजोगती बात कोनी ।

देस री आजादी रै छियोत्तर बरसां पछै ई राजस्थानी भासा नै संवैधानिक मान्यता क्यूं नीं मिळी, आवण वाळा समै में इण भासा नै संवैधानिक मान्यता मिळैला कै नीं- आ बात सही है कै राजस्थानी भासा री संवैधानिक मान्यता रौ आंदोलन देस री आजादी सूं पैला ई चाल रैयौ है । राजस्थानी अेक सिमरध अर सुतंतर भासा है जिणनै अमेरिका अर नेपाल जैड़ा देस मान्यता दीनी। इणरौ जुगां जूनौ इतिहास अर विसाल साहित्य भंडार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, महाविद्यालयां अर विश्वविद्यालयां में भणाई जावै । साहित्य अकादेमी कांनी सूं राजस्थानी लेखकां नै हर बरस भारतीय भासावां रै जोड़ाजोड़ पुरस्कार मिळै। यूजीसी पढेसरां नै पी-अे एच.डी. सारू स्कॉलरशिप देवै। चुणाव मांय राजनेता इणी'ज भासा मांय आम जन सूं वोट मांगै पण औ दुरभाग है कै प्रदेस रै राजनेतावां री उदासीनता रै कारण आजादी रै छियोत्तर बरसां पछै ई अपांरी मायड़ भासा संवैधानिक मान्यता नै तरस रैयी है। अठै जे म्हैं आ बात केय दूं कै प्रदेस रै राजनेतावां री उदासीनता रै कारण अपांरी मायड़ भाषा राजस्थानी नै संवैधानिक मान्यता नीं मिळ सकी तो कोई अजोगती बात कोनीं। अबै औ मसलौ देस रा मानीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मंसा माथै निरभर है। वे जद चावैला उणीज दिन राजस्थानी भासा नै संवैधानिक मान्यता मिळ जावैला। कह्यौ जावै कै आसा अमर धन हुवै सो म्हनै भरोसौ है कै आवण वाळा समै मांय अपांरी मायड़ भासा नै प्रदेस री सरकार पैली राजभासा अर केन्द्र सरकार संवैधानिक मान्यता प्रदान कर अवस ई संविधान री 8वीं अनुसूची में सामिल करेला । निस्चै ई हरेक राजस्थानी सारू सोनै रौ सूरज उण दिन ई उगैला जिण दिन राजस्थानी भासा नै संवैधानिक मान्यता मिळैला।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रेम त्याग व ममता की मूरत होती है मां

रमेश सर्राफ धमोरा

-रमेश सर्राफ धमोरा

दुनिया में मां की तुलना भगवान से की जाती है। भारत में गंगा नदी को पवित्र मान कर मां का दर्जा दिया जाता है जो इस बात का संकेत है कि मां अपने आप में एक उपाधि है। कई धार्मिक ग्रंथो में जननी की महिमा का बखान मिलता है। प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 12 मई को मातृ दिवस मनाया जाएगा।

मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रम्हांड समा जाए। जब हम मां बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो शब्द के उच्चारण के साथ ही पूरा मुंह भर जाता है। मां ममता की मूरत होती है। पूरी दुनिया के सभी धर्मों ने मां के रिश्ते को सबसे पवित्र माना गया है। अपने बच्चों के प्रति मां का प्यार, दुलार, समर्पण और त्याग अनमोल होता है। मां को सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया में मई माह के दूसरे रविवार को मातृत्व दिवस (मदर डे) के रूप में मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस माताओं एवं मातृत्व का सम्मान करने वाला दिन होता है। एक मां ही होती है जो सभी की जगह ले सकती है। लेकिन उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। मां अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा और उनकी देखभाल करती है। इसलिए मां को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। मां वह शख्स होती है जो नो माह तक अपने बच्चे को कोख में रखकर जन्म देती है। उसके बाद उसका लालन-पालन करती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक मां का अपने बच्चों के प्रति स्नेह कभी कम नहीं होता है। वह खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों के सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहती है। मां अपनी संतान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस रखती है।

मां होने का अर्थ है उत्तरदायित्व और निस्वार्थता से पूरी तरह से अभिभूत होना। मातृत्व का मतलब है रातों की नींद हराम करना। मां भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। उसके जितना त्याग और प्यार कोई नहीं कर सकता है। मां विश्व की जननी है उसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मां ही हमारी जन्मदाता होती है और वही हमारी सबसे पहली गुरु होती है। इसीलिए हम धरती को भी धरती माता कहते हैं। जो अपने उपर हम सब का वजन उठाती है।

मां को संस्कृत में मातरः कहते है। मां ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने अंश द्वारा अपनी शक्ति का संचार और विस्तार करता हैं। पुराणों के अनुसार मां का अर्थ लक्ष्मी है। जिस प्रकार मां लक्ष्मी सृष्ठि का पालन करती है उसी प्रकार मां भी शिशु का पालन करती है। इस प्रकार मां को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। एक मत यह है कि इस सृष्टि का आरंभ मनु और शतरूपा नामक स्त्री-पुरुष के समागम से हुआ। मनु के नाम पर ही उनकी संतान को मनुज या मानव कहा गया। मनु की संतान को जिसने जन्म दिया उसे मां कहा गया। और इस प्रकार मां शब्द की उत्पत्ति हुई।

हमारे देश में गाय को भी गौमाता कह कर पुकारते हैं जो हमें अपने अपना दूध पिला कर बड़ा करती है। मां हमारे जीवन की सबसे प्रमुख हस्ती होती है जो बिना कुछ पाने की उम्मीद किए सिर्फ देती ही रहती है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है जो हम अपने पूरे जीवन में किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मां बच्चे की पहली गुरु होती है।

भारतीय संस्कृति तथा कुछ ग्रंथों के अनुसार मां शब्द की उत्पत्ति गोवंश से हुई। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसके सर्वप्रथम रंभानें में जो स्वर निकालता है वह मां होता है। यानी कि बछड़ा अपनी जन्मदात्री को मां के नाम से पुकारता है। इस प्रकार जन्म देने वाली को मां कहकर पुकारा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम बछड़े ने ही अपनी मां गाय को रंभाकर मां पुकारा और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई।

देखा जाए तो मातृ दिवस का इतिहास सदियों पुराना एवं प्राचीन है। यूनान में परमेश्वर की मां को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता था। 16वीं सदी में इंग्लैंड का ईसाई समुदाय ईशु की मां मदर मेरी को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाये जाने की शुरूवात हुई। ह्यमदर्स डेह्न मनाने का मूल कारण समस्त माताओं को सम्मान देना और एक शिशु के उत्थान में उसकी महान भूमिका को सलाम करना है।

मातृत्व दिवस को आधिकारिक बनाने का निर्णय पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति वूडरो विलसन ने आठ मई 1914 को लिया था। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने और मां के सम्मान में एक दिन के अवकाश की सार्वजनिक घोषणा की थी। वे समझ रहे थे कि सम्मान, श्रद्धा के साथ माताओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। जिससे मातृत्व शक्ति के प्रभाव से युद्धों की विभीषिका रुके। तत्पश्चात हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। वर्तमान में ये भारत के साथ यूके, चीन, यूएस, मेक्सिको, डेनमार्क, इटली, फिनलैण्ड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, बेल्जियम सहित कई देशों में मनाया जाता है। हर साल माताओं के प्रति अपने आदर और सम्मान को व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

मां शब्द की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में कई मत हैं। विभिन्न शैलियों ने मां शब्द की व्याख्या की है। ये एक अक्षर वाला मां संबोधन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर शब्द माना जाता है। मां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है। इसका वर्णन शब्दों मे करना नामुमकिन है। मां वो है जो न सिर्फ हमे जन्म देती है बल्कि हमे जीना भी सिखाती है। मां शब्द का अर्थ है निस्वार्थ प्यार और बलिदान। मां भगवान का जीता जागता स्वरूप है। मां खुले दिल से अपने बच्चो का भरपूर ख्याल रखती है। मां वो होती है जो खुद भूखी सो जाए पर अपने बच्चो को भूखा रहने नहीं देती। उसे खुद कितनी भी तकलीफ हो वो जताती नहीं और ऐसे मे भी सिर्फ अपने बच्चो की ही सलामती की दुआ करती है। मां की ममता समुद्र से भी गहरी है।

दुनिया में हर शब्द का अर्थ समझा और समझाया जा सकता है। लेकिन मां शब्द का अर्थ समझना और समझाना दोनों ही लगभग नामुमकिन है। मां शब्द का अर्थ समझाना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि मां के प्यार को मां के बलिदान को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मां के दिल में जितना प्यार अपने बच्चों के लिए होता है। अगर मां के सभी बच्चे कोशिश भी करें तो उसका कुछ अंश भी अदा नहीं कर सकते।

– रमेश सर्राफ धमोरा

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी

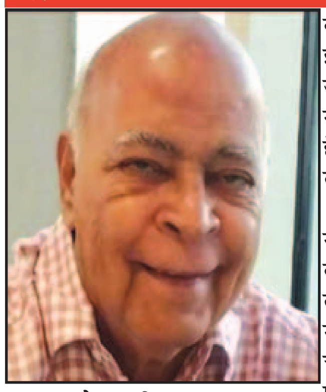
-अशोक भाटिया

भारत में पानी की बबार्दी पर लोग आम तौर पर परेशान नहीं होते हैं। शहर हो या गांव, हर जगह लोग पानी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन भारत में पानी की कमी कितनी भयावह हो सकती है इसका अंदाजा आप यूनेस्को की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा।

यूनेस्को की रिपोर्ट की मानें तो साल 2016 में धरती पर 9.33 करोड़ आबादी पानी के संकट से जूझ रही थी। उसके बाद कई देशों में जल-संकट काफी तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा ये भी किया गया है कि एशिया में लगभग 80 प्रतिशत आबादी जल संकट से जूझ रही है। यह संकट पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है।

महाराष्ट्र में पारा 40 के पार पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप के कारण मुंबई को जलापूर्ति करने वाले जलाशय तेजी से सूख रहे हैं। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सातों झीलों का पानी जुलाई में खत्म हो जाएगा। झीलों में पानी का मौजूदा स्तर मुंबईकरों को चिंतित कर रहा है। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों में फिलहाल 16 फीसदी पानी बचा है और पिछले साल की तुलना में यह भंडार काफी कम है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन इसी तरह गर्मी जैसे हालात बने रहेंगे, जिसके चलते मुंबई में 15 से 20 फीसदी पानी की कटौती का संकट पैदा हो गया है। हालांकि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (इटउ) ने लोगों को सांत्वना देते हुए कहा है कि शहर में जल आपूर्ति कर रहे सात जलाशयों का भंडार जुलाई के अंत तक रहेगा और निवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भी भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6 हजार घन मीटर थी जो साल 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा देश की बढ़ती आबादी भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

ऐसे में वर्तमान में जल को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में लोगों को पीने का पानी तक ढंग से मुहैया करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जल को संरक्षित करने के किसी भी प्लान को बनाने के लिए सरकार के पास देश के सभी नदियों और जलाशयों का डेटा होना चाहिए। जो कि सबसे बड़ी चुनौती है।

दरअसल वाटर रिसोर्सेज इनफॉरमेशन सिस्टम के पास जलाशय और नदियों का आंकड़ा तो मौजूद है लेकिन अलग-अलग शहरों के छोटी नहरों का कोई डाटा मौजूद नहीं है जिन्हें ग्रामीण भारत की जीवन रेखा माना जाता है और यही नहरें बाढ़ रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती हैं। इसके अलावा भारत में पानी के आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसियां राज्य स्तर पर हैं और ये राज्य इन डाटा को तैयार करने के विकेंद्रीकृत और लोकल मैकेनिज्म का उपयोग करती हैं। ऐसे में जल निकायों का प्रबंधन करने के लिए, हमें औपचारिक डेटा के साथ एकीकृत करने के लिए समुदायों के प्रासंगिक और पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी की कमी से जूझ रहा है। इस समस्या को समझते हुए विश्व में पानी की बबार्दी रोकने, महत्व समझने, संरक्षण करने और सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं और तरीके निकाले जाने जरुरी हैं।

भारत में ज्यादातर जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं, नहर, नदियां सूखती और प्रदूषित होती जा रही हैं। ये जल संकट की ओर इशारा है, इसलिए इस स्थिति में जल्द से जल्द परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। शहरों में नहर होने के कई फायदे होते हैं ये नहर बारिश के पानी को संरक्षित करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। सामान्य तौर पर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में बहुत सारी नहरें और छोटे- छोटे जलाशय बनाए जाते हैं। सूखाग्रस्त राज्यों में नहरों और छोटे छोटे जलाशयों का का मुख्य रूप से सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नहर का इस्तेमाल घरेलू उपयोग और मछली पालन के लिए भी किया जाता है।

जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल निकायों की जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, जो देश में तालाबों, टैंकों, झीलों और जलाशयों का एक व्यापक डेटा बेस है। जनगणना के अनुसार भारत में तालाबों, टैंकों और झीलों जैसे 24.24 लाख जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं जबकि सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संख्या गणना के मुताबिक भारत में कुल 24.24 लाख जल संरचनाएं हैं, जिनमें से 97.1 प्रतिशत यानी 23.55 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9 प्रतिशत यानी 69,485 शहरी क्षेत्रों में हैं। इसी जनगणना के मुताबिक टैंकों की सबसे ज्यादा संख्या आंध्र प्रदेश में है, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संख्या झीलों की है।

केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जलाशयों की गणना की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2023 के अप्रैल महीने में ट्वीट के माध्यम से ये लिखा था कि आगे चलकर राज्य में पानी का संकट सामने नहीं आए, इसके लिए राज्य की महायुति की सरकार कटिबद्ध है।

इस रिपोर्ट के अनुसार देश में ज्यादा जल निकाय बहुत छोटे हैं। भारत के अधिकांश जल निकाय एक हेक्टेयर से कम बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उनका पता लगाना और उन पर नजर रखना एक चुनौती बने रहने की संभावना है। उपग्रहों का उपयोग करके इन जल निकायों को मानचित्रित करने का तरीका भी काम नहीं कर सकता है, यही कारण है कि भू-आधारित ट्रैकिंग यानी जल शक्ति जनगणना की शुरूआत की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार कई जल निकायों का पानी इतना पुराना और इतना गंदा है कि उसे इस्तेमाल नहीं करने में वर्गीकृत किया गया है।

बता दें कि पिछले कुछ सालों में इजरायल ने बारिश के जल संचय के साथ पानी का बेहतर इस्तेमाल कर जल संकट की मुसीबत से छुटकारा पा लिया। भारत में वर्तमान में एक साल में जितनी बारिश होती है, अगर उसका संचय सही तरीके से किया जाए और नई तकनीक से उसे पीने के लायक बनाकर इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत हद तक समस्या कम हो सकती है। जरूरत है कि पानी को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों, तभी पानी हमारा जीवन रक्षक बन सकेगा।

चिंताजनक स्थिति यह भी है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या को साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के बहुत-से देशों में पेयजल का संकट है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। दुनिया के 2 से 3 अरब लोग साल में कम से कम एक महीने पानी की कमी से जूझते हैं।

वर्तमान स्थिति में भारत भूजल का अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालांकि निकाले गए भूजल का सिर्फ 8 प्रतिशत पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी का 80 फीसदी भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। शेष 12 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में जल संकट की वजह यहां जरूरत से ज्यादा भूजल का दोहन है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानें तो देश में हर साल सिंचाई के लिए 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, इस कारण है कि कुछ राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है।

वैज्ञानिकों की माने तो धरती का तापमान जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही ऋतु-चक्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और पानी की किल्लत से परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल पिछले बीस सालों में धरती के बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों का असर और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के ऋतु-चक्र मेंअल-नीनो का असर देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब है कि देश में बरसात कम हो रही है और गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूसरे देशों की तुलना में पानी की बबार्दी कहीं ज्यादा होती है।

जल संकट की एक बड़ी वजह कारखानों के जहरीले पानी को पाइप के मदद से जमीन के अंदर पहुंचाना भी है। दरअसल भारत में तीन लाख से ज्यादा छोटे-बड़े बूचड़खाने हैं। इन कारखानों में हर दिन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। इसी तरह दूसरे देशों में भी बूचड़खानों के कारण करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। जल संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत सरकार की योजना के बारे में बताया जाता है कि इस समाया भारत में जल संरक्षण की चार योजनाए चल रही है 1। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 -2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3, जल शक्ति अभियान- कैच द रेन अभियान 4, अटल भूजल योजना ।

पानी की किल्लत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया होने वाली है। जल संकट आने वाले समय में झगड़े-फसाद की वजह भी बन सकता है। जानकारों की मानें तो अगला विश्व युद्ध पानी के एकाधिकार को लेकर हो सकता है। बात भले ही हास्यापद लगे परन्तु बताया जाता है कि ग्रामीण महाराष्ट्र में कई लोगों ने दूसरी शादी इसलिए करते हैं ताकि एक पत्नी पानी लाए और पहली पत्नी घरेलू कार्य निपटा सके। इस टर्म को 'वाटर वाइफ' कहते हैं। अगर दूसरे राज्यों में भी ऐसे हालात हुए तो संभव है कि महाराष्ट्र का यह प्रयोग दूसरे राज्य के लोग भी करने लग जाए, जो आगे चलकर कई सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

-अशोक भाटिया

प्रेम का आदि उद्गम स्थल है मातृत्व

-ललित गर्ग

-ललित गर्ग-

मातृ दिवस-समाज में माताओं के प्रभाव व सम्मान का वैश्विक उत्सव है जो माताओं और मातृतुल्य विभूतियों का सम्मान करता है, माताओं के द्वारा अपनी संतान, परिवार और समाज के लिए उनके बलिदान, अमूल्य योगदान और समर्पण को याद करने, सम्मान देने एवं पूजने का पवित्र दिन है। मातृत्व दिवस सम्पूर्ण मातृ-शक्ति को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे मदर्स डे, मातृ दिवस या माताओं का दिन चाहे जिस नाम से पुकारें यह दिन सबके मन में विशेष स्थान लिये हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस अन्ना जार्विस द्वारा स्थापित किया गया था, जो उनकी अपनी मां के मानवीय कार्यों के प्रति समर्पण से प्रेरित था, 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में नामित किया, जिसे बाद में अन्य देशों ने अपनाया। मां के उपकार इतने बड़े है कि इंसान अगर पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दे तो मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। संतान के लालन-पालन के लिए हर दुख का सामना बिना किसी शिकायत के करने वाली मां के साथ बिताये दिन सभी के मन में आजीवन सुखद व मधुर स्मृति के रूप में सुरक्षित रहते हैं।

विश्व के विभिन्न भागों में मातृत्व दिवस अलग-अलग दिन एवं अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। जापान में, माताओं को उपहार में दिया गया कार्नेशन प्यार और कृतज्ञता का प्रतीक है, जबकि इथियोपिया के परिवार बड़े उत्सव की दावतों के लिए इकट्ठा होते हैं। नेपाल में माता तीर्थ औंसी नामक एक विशेष धार्मिक त्योहार मनाया जाता है। मदर्ड डे का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहास में मदर्स डे मनाने का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति में मां के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रही हैं, लेकिन आज आधुनिक दौर में जिस तरह से मदर्स डे मनाया जा रहा है, उसका इतिहास भारत में बहुत पुराना नहीं है। इसके बावजूद तीन-चार दशक से भी कम समय में भारत में मदर्स डे काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मां शब्द में संपूर्ण सृष्टि का बोध होता है। मां शब्द में वह आत्मीयता एवं मिठास छिपी हुई होती है, जो अन्य किसी शब्दों में नहीं होती। मां नाम है संवेदना, भावना और अहसास का। मां के आगे सभी रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। मातृत्व की छाया में मां न केवल अपने बच्चों को सहेजती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसका सहारा बन जाती है। समाज में मां के ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मातृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है- सभी प्रकार के प्रेम का आदि उद्गम स्थल मातृत्व है और प्रेम के सभी रूप इसी मातृत्व में समाहित हो जाते हैं। प्रेम एक मधुर, गहन, अपूर्व अनुभूति है, पर शिशु के प्रति मां का प्रेम एक स्वर्गीय अनुभूति है।

हर संतान अपनी मां से ही संस्कार पाता है। लेकिन मेरी दृष्टि में संस्कार के साथ-साथ शक्ति भी मां ही देती है। इसलिए हमारे देश में मां को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में मां को सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। श्रीमद् भगवद् पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता की सेवा से मिला आशीष सात जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने मां की महिमा को उजागर करते हुए कहा है कि जब मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो एकमात्र ऐसा दिन था मेरे जीवन का जब मैं रो रहा था और मेरी मां के चेहरे पर एक सन्तोषजनक मुस्कान थी। एक माँ हमारी भावनाओं के साथ कितनी खूबी से जुड़ी होती है, ये समझाने के लिए उपरोक्त पंक्तियां अपने आप में सम्पूर्ण हैं।

अब्राहम लिंकन का मां के बारे में मार्मिक कथन है कि जो भी मैं हूँ, या होने की उम्मीद है, मैं उसके लिए अपने प्यारी माँ का कर्जदार हूँ। किसी औलाद के लिए माँ शब्द का मतलब सिर्फ पुकारने या फिर संबोधित करने से ही नहीं होता बल्कि उसके लिए माँ शब्द में ही सारी दुनिया बसती है, दूसरी ओर संतान की खुशी और उसका सुख ही माँ के लिए उसका संसार होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ठोकर लगने पर या मुसीबत की घड़ी में माँ ही क्यों याद आती है क्योंकि वो माँ ही होती है जो हमें तब से जानती है जब हम अजन्में होते हैं। बचपन में हमारा रातों का जागना, जिस वजह से कई रातों तक माँ सो भी नहीं पाती थी। वह गिले में सोती और हमें सूखे में सुलाती। जितना माँ ने हमारे लिए किया है उतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जाहिर है माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक दिन नहीं बल्कि एक सदी, कई सदियां भी कम है। माँ अपने आप में पूर्ण संस्कारवान, मनुष्यत्व व सरलता के गुणों का सागर है। माँ जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि पालन-पोषण करने वाली जीवन-निर्मात्री भी है। मां तो ममता की सागर होती है। लेकिन माँ की इस ममता को नहीं समझने वाले कुछ आधुनिक बच्चे यह भूल बैठते हैं कि इनके पालन-पोषण के दौरान इस माँ ने कितनी कठिनाइयां झेली होगी।

मां के अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है या यूं कहें कि मां ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की यह चरमता केवल माताओं में ही नहीं, वरन सभी मादा जीवों में देखने को मिलती है। अपने बच्चों के लिए भोजन न मिलने पर हवासिल (पेलिकन) नाम की जल-पक्षिनी अपना पेट चीर कर अपने बच्चों को अपना रक्त-मांस खिला-पिला देती है। किन्तु त्याग की यह चरमता ही मां अर्थात नारी जाति की शत्रु बन गयी। समाज पुरुष प्रधान होता गया और नारी का अवमूल्यन होता गया। धीरे-धीरे वह पुरुष की उपभोग्या, उसके चरणों की दासी बनकर रह गयी। शिक्षा-आत्मसम्मान वंचिता दासी की संतति महान कैसे हो सकती है? उसमें तो दास सुलभ चारित्रिक प्रवृत्तियां आएंगी ही। अतः नारी के अवमूल्यन के साथ-साथ पुरुष जाति का नैतिक अधःपतन होता गया।

मां प्राण है, मां शक्ति है, मां ऊर्जा है, मां प्रेम, करुणा और ममता का पर्याय है। मां धरती पर जीवन के विकास का आधार है। मां ने ही अपने हाथों से इस दुनिया का ताना-बाना बुना है। सभ्यता के विकास क्रम में आदिमकाल से लेकर आधुनिककाल तक इंसानों के आकार-प्रकार में, रहन-सहन में, सोच-विचार, मस्तिष्क में लगातार बदलाव हुए। लेकिन मातृत्व के भाव में बदलाव नहीं आया। मां को धरती पर विधाता की प्रतिनिधि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच तो यह है कि मां विधाता से कहीं कम नहीं है। मां एक भाव है मातृत्व का, प्रेम और वात्सल्य का, त्याग का और यही भाव उसे विधाता बनाता है।

मां विधाता की रची इस दुनिया को फिर से अपने ढंग से रचने वाली विधाता है। मां सपने बुनती है और यह दुनिया उसी के सपनों को जीती है और भोगती है। मां जीना सिखाती है। पहली किलकारी से लेकर आखिरी सांस तक मां अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती। मां पास रहे या न रहे मां का प्यार दुलार, मां के दिये संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। मां ही अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण करती हैं। इसीलिए मां को प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि मातृत्व के भाव पर नारी मन पर किसी दूसरे भाव का असर न आए। जैसाकि आज कन्याभ्रूणों की हत्या का जो सिलसिला बढ़ रहा है, वह नारी-शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप हैं तथा उसके लिए मातृत्व ही जिम्मेदार है। कन्याभ्रूणों की हत्या एक ओर मनुष्य को नृशंस करार दे रही है, तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी मानविकी पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मातृ-दिवस को मनाते हुए मातृ-महिमा पर छा रहे ऐसे अनेक धुंधलों को मिटाना जरूरी है, तभी इस दिवस की सार्थकता है।

-ललित गर्ग

भविष्य का अहिंसक महाशक्ति भारत होगा। भारतीय विदेश नीति में वैश्विक परिवार की परिकल्पना

भारत की सकारात्मक विदेश नीति और निरपेक्ष छवि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण तथा आदर्श की तरह सामने आई है, इसी रफ्तार से यदि भारत अपनी आंतरिक क्षमता, आर्थिक नीति तथा विदेशी संबंधों को गति देती है तो इसमें कतई संदेह नहीं कि भारत आने वाले समय में आर्थिक सामरिक और वैश्विक शांति का नेतृत्व करेगा जिसके फलस्वरूप उसे शांति महाशक्ति के रूप में पूरा विश्व स्वीकार करेगा।

- संजीव ठाकुर

पिछले कुछ वर्षों की कोविड-19 महामारी के कारण पूरा विश्व अशांत एवं तनावग्रस्त रहा है। इसके तुरंत बाद तालिबान-अफगानिस्तान युद्ध में विश्व युद्ध की आशंका मंडराने लगी थी, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन वार से पूरा विश्व चिंता तथा तनाव के मध्य जीने लगा था। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन लगभग तबाही के कगार पर बैठा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुनः पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने एवं पूर्व में परमाणु बमों का इस्तेमाल करने की घोषणा ने आग में घी का काम कर दिया है। परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की विभीषिका के बादल मंडराने लगे हैं। विश्व के अनेक राष्ट्र जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और अन्य यूरोपीय देश भारत और रूस के कई वर्षों के निरंतर घनिष्ठ संबंधों के आधार पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री से यह आशा लगाए बैठे हैं कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थता कर युद्ध में विराम लाने का प्रयास करेंगे। विगत दिनों समरकंद में अंतरराष्ट्रीय बैठक में मोदी ने एक-एक कर के वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर पुतिन तथा जेलेंस्की से युद्ध विराम की अपील भी की है। ऐसे में भारत की गुटनिरपेक्षता एवं वैश्विक शांति तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसा भारतीय दर्शन अत्यंत समीचीन एवं प्रासंगिक हो गया है। वर्तमान वैश्विक त्रासदी एवं वैश्विक अशांति के दौर में एक दूसरे की सहायता करना एवं एक दूसरे के मंतव्य, संवेदना को समझने की बड़ी आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का रुकना अब शांति बहाली के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश ने लगभग 40 देशों को कोविड-19 के महामारी के दौरान कई तरह से मदद भी की है। हालांकि भारत में महामारी के दौरान यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों ने भी अपना परिवार मानकर खुले दिल से संक्रमण से लड़ने के लिए आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान की थी।

भारत की विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक शांति की नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य की गई है। इसमें दो मत नहीं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की वन टू वन बैठक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप की नीति एवं भावना की दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने बड़ी सराहना की,और उस पर विश्व को अमल करने की बात भी कही। भारत की विश्व के कई देशों को की गई सहायता भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। भारत के प्रधानमंत्री ने सदैव अपनी अभिव्यक्ति में भी यह स्पष्ट रूप से जताया है कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है एवं इसकी शांति तथा सुरक्षा की चिंता करते हुए अपनी विदेश नीति बनाता है।

वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही प्राचीन समय से अब तक भारत में हर जाति, हर धर्म के लोगों को शरण दी थी। उन्हें अपनाया गया फिर चाहे वह मुगल हो या अंग्रेज ही क्यों ना हो। भारत ने सभी को एक परिवार मानकर व्यवहार किया है। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोलवीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोप मैं औद्योगीकरण का युग प्रारंभ हुआ और अलग-अलग देशों ने अपने-अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए और तब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्षति पहुंची। तब राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद एक राष्ट्र तक ही सीमित होकर रह गया है। आज पूरा विश्व अलग-अलग समूहों में बट चुका है, और अपने लाभ तथा उद्देश्यों के प्रति सजग तथा अलर्ट है। इन सभी देशों का उद्देश्य विकास और शांति का ही है। अतः सभी देशों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बलवती करना चाहिए। अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विकासवान देश इस भावना से कार्य करने पर प्रगति पर हैं, पर कुछ देश जो वैश्विक अशांति के लिए खतरा बन चुके हैं। सब दूसरे देशों सेअलग-थलग पड़ गए हैं। यह बात सर्वविदित है कि विश्व के देशों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकजुट होकर विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि विकास का मार्ग एकजुटता से होकर ही प्रशस्त होता है। अभी इस दिशा में बहुत काम करना शेष भी है। और जिस दिन विश्व के देश आपस की कटुता वैमनस्यता और मतभेद को बुलाकर एक धरातल पर आ जाएंगे उस दिन वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना संपूर्ण आकार ले लेगी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अभी अमेरिका के दौरे पर संयुक्त राष्ट्र संघ स्क्वाड और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान वसुधैव कुटुंबकम एवं वैश्विक शांति की दुनिया से पुरजोर अपील भी की है। और वैश्विक शांति के लिए कुछ देशों को इस बात से बाज आने का संकेत भी दिया है। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका सफल यात्रा के बाद पूरे विश्व में भारत का कद तो ऊंचा हुआ ही है, इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी बलवती हुई है। इसी भावना के साथ भारत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। यदि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का छठवां सदस्य बनता है, तो यह भारतीय गणतंत्र की बड़ी सफलता होगी। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भारत ने अपनी वैश्विक विदेश नीति के तहत एक प्रमुख नीति बनाकर विश्व में शांति तथा विकास की बात हमेशा दोहराई है। आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि भारत देश की बात विश्व के देश बड़ी शांति और पूरे ध्यान से सुनते हैं। कई देशों ने आपसी भाईचारे पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। यह भारतीय कूटनीति की बड़ी सफलता भी है। वसुदेव कुटुंबकम जियो और जीने दो तथा वैश्विक शांति के मार्ग पर भारत चलकर वैश्विक गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह भारत का अमोघ अस्त्र साबित होगा जिससे विश्व में शांति सौहार्द और विकास स्थापित होने की संभावना बलवती होगी।

- संजीव ठाकुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

गरीबी उन्मूलन की ओर भारत

भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधिकतम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओर धकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से 'गरीबी हटाओ' के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सत्ता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयास शायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। आज जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैंकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रैल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है

– बाल मुकुन्द ओझा

राहुल गांधी को लोग गंभीरता से क्यों नहीं लेते है, यह प्रश्न सियासी क्षेत्रों में तेजी से चर्चित हो रहा है। राहुल गांधी को बहुत गुस्सा आता है जब लोग उन्हें तरह तरह की उपमाओं से नवाजते है। राहुल कई बार यात्राएं निकालकर लोगों के बीच गए। हर तबके के लोगों से मिले। उनका प्यार भी उन्हें मिला, मगर राजनीति में जो सफलताएं उन्हें मिलनी चाहिए उससे मरहूम रहे। राहुल की दादी इंदिरा गाँधी की आवाज में जादू था। राहुल यह जादू अपने भाषणों में जाहिर नहीं कर पाए। लोगों ने तमाम तरह की उपमाओं से उन्हें विभूषित किया। किसी ने पप्पू कहा तो किसी ने शहजादा। आलू से सोना बनाने की किवदंती भी उनसे जोड़ दी गई। राहुल की बहिन प्रियंका ने इस पर भाजपा को कई बार घेरा और कहा मेरा भाई हजारों किलोमीटर पैदल चला है। इस बीच उनके विवादित भाषण भी काफी चर्चा में रहे विशेषकर प्रधान मंत्री मोदी पर उनकी टिप्पणियां लोगों को हजम नहीं हुई। राहुल ने अपने विवादित बयानों से कई बार मोदी को पटकने की चेष्टा की मगर हर बार उनका दांव खाली गया। चौकीदार चोर से लेकर आरक्षण खत्म करने के उनके बयान हवा हवाई साबित हुए। अमेठी में हार से भी उनका जनाधार घटा। भाजपा का कहना है जब उनकी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों ले। सोनिया, प्रियंका और कांग्रेस के नेता इस गहरी सोच में डूबे हैं कि आखिर राहुल में क्या कमी रह गई की जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के युवराज राहुल गाँधी खूब पसीना बहाने के बावजूद सियासत में वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयासरत है। गाँधी – नेहरू परिवार में दो ही ऐसे नेता हुए जिन्होंने हार का स्वाद चखा। एक हार इंदिरा गाँधी के साथ जुडी है। 1977 में इंदिरा गाँधी रायबरेली से समाजवादी नेता राज नारायण से हार गई थी। इस सियासी परिवार के नाम दूसरी हार राहुल गाँधी के नाम है जिन्हें 2019 में समृति ईरानी ने हराकर धमाका कर दिया था, हालाँकि राहुल वायनाड से जीत कर संसद पहुँच गए थे। राहुल पिछले दो दशकों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर लगातार एक सफल राजनेता की भूमिका में सक्रियता से जुड़े है मगर लाख प्रयासों के बाद भी वे अपनी पार्टी को हार के गर्त में जाने से नहीं रोक पाए है। वे जनता से जुड़े मुद्दे और नारे लगातार उछाल कर मुख्य धारा में बने रहने का प्रयास कर रहे है मगर सफलता अब तक नहीं मिली है। वे हर चुनाव में एक नया जुमला उछालते है मगर ये जनता के गले नहीं उतर पा रहे है। चौकीदार चोर, पनोती और जेब कतरा से लेकर अम्बानी अडानी के मुद्दे फेल हो चुके है। या यों कहे जनता ने नकार दिए। वे मोदी पर निजी हमले करने से बाज नहीं आते मगर जनता की अदालत में हर बार ठुकरा दिए जाते है। राहुल की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा भी जनता में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पायी।

ाहुल गांधी की एक दशक की सियासी यात्रा पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। इससे पूर्व जब दुनिया भर के दिग्गज नेता दिल्ली में आयोजित जी –20 में शामिल होकर जहाँ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में खुलकर सराहना कर रहे थे तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर देश और मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। यह वह वक्त था जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। ऐसे समय में भी राहुल गांधी भारत को कोसने से बाज नहीं आये। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रित संस्थाओं पर पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश पर यूरोपीय संघ के हलकों में भी चिंता है। राहुल ये दावा करते रहे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गाँधी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कहा देश के संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले हो रहे हैं। सरकार दहशत में है और पीएम मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। राहुल गाँधी अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी के बहाने देश के लोकतंत्र पर हमला बोलते तनिक भी नहीं हिचकिचाते। चीन की तरफदारी कर राहुल देश को ही कटघरे में खड़ा करते रहे है। मगर वे यह भूल गए देश की जनता ने नेहरू, इंदिरा और राजीव की भांति मोदी को भी प्रचंड बहुमत के साथ देश का ताज पहनाया है। वे यह भी कहते है भारत एक राष्ट्र नहीं है। जब से कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर हुई है तब से उनकी हालत बिन पानी मछली सी हो रही है। धीरे धीरे कांग्रेस लगातार अपना वजूद खोती जा रही है मगर सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गौरतलब है राहुल ने देश की सवैंधानिक संस्थाओं यथा चुनाव आयोग, न्यायालय और प्रेस पर भी समय समय पर हमला बोला है। मोदी और भाजपा की आलोचना खूब कीजिये जनाब, मगर देश को बक्श दीजिये। कांग्रेस में यह क्या हो रहा है, अपनी पार्टी को संगठित करने के बजाय देश को तोड़ने वाली बातें कर क्या हासिल करेंगे यह समझ से बाहर है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

प्रेम का आदि उद्गम स्थल है मातृत्व

मां के अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है या यूं कहें कि मां ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की यह चरमता केवल माताओं में ही नहीं,वरन् सभी मादा जीवों में देखने को मिलती है। अपने बच्चों के लिए भोजन न मिलने पर हवासिल (पेलिकन) नाम की जल-पक्षिनी अपना पेट चीर कर अपने बच्चों को अपना रक्त-मांस खिला-पिला देती है। किन्तु त्याग की यह चरमता ही मां अर्थात् नारी जाति की शत्रु बन गयी।

– ललित गर्ग –

मातृ दिवस-समाज में माताओं के प्रभाव व सम्मान का वैश्विक उत्सव है जो माताओं और मातृतुल्य विभूतियों का सम्मान करता है, माताओं के द्वारा अपनी संतान, परिवार और समाज के लिए उनके बलिदान, अमूल्य योगदान और समर्पण को याद करने, सम्मान देने एवं पूजने का पवित्र दिन है। मातृत्व दिवस सम्पूर्ण मातृ-शक्ति को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे मदर्स डे, मातृ दिवस या माताओं का दिन चाहे जिस नाम से पुकारें यह दिन सबके मन में विशेष स्थान लिये हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस अन्ना जार्विस द्वारा स्थापित किया गया था, जो उनकी अपनी मां के मानवीय कार्यों के प्रति समर्पण से प्रेरित था, 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में नामित किया, जिसे बाद में अन्य देशों ने अपनाया। मां के उपकार इतने बड़े है कि इंसान अगर पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दे तो मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। संतान के लालन-पालन के लिए हर दुख का सामना बिना किसी शिकायत के करने वाली मां के साथ बिताये दिन सभी के मन में आजीवन सुखद व मधुर स्मृति के रूप में सुरक्षित रहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में मातृत्व दिवस अलग-अलग दिन एवं अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। जापान में, माताओं को उपहार में दिया गया कार्नेशन प्यार और कृतज्ञता का प्रतीक है, जबकि इथियोपिया के परिवार बड़े उत्सव की दावतों के लिए इकट्ठा होते हैं। नेपाल में माता तीर्थ औंसी नामक एक विशेष धार्मिक त्योहार मनाया जाता है। मदर्ड डे का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहास में मदर्स डे मनाने का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति में मां के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रही हैं, लेकिन आज आधुनिक दौर में जिस तरह से मदर्स डे मनाया जा रहा है, उसका इतिहास भारत में बहुत पुराना नहीं है। इसके बावजूद तीन-चार दशक से भी कम समय में भारत में मदर्स डे काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मां शब्द में संपूर्ण सृष्टि का बोध होता है। 'मां' शब्द में वह आत्मीयता एवं मिठास छिपी हुई होती है, जो अन्य किसी शब्दों में नहीं होती। मां नाम है संवेदना, भावना और अहसास का। मां के आगे सभी रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। मातृत्व की छाया में मां न केवल अपने बच्चों को सहेजती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसका सहारा बन जाती है। समाज में मां के ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मातृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है- सभी प्रकार के प्रेम का आदि उद्गम स्थल मातृत्व है और प्रेम के सभी रूप इसी मातृत्व में समाहित हो जाते हैं। प्रेम एक मधुर, गहन, अपूर्व अनुभूति है, पर शिशु के प्रति मां का प्रेम एक स्वर्गीय अनुभूति है। हर संतान अपनी मां से ही संस्कार पाता है। लेकिन मेरी दृष्टि में संस्कार के साथ-साथ शक्ति भी मां ही देती है। इसलिए हमारे देश में मां को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में मां को सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। श्रीमद् भगवद् पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता की सेवा से मिला आशीष सात जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने मां की महिमा को उजागर करते हुए कहा है कि जब मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो एकमात्र ऐसा दिन था मेरे जीवन का जब मैं रो रहा था और मेरी मां के चेहरे पर एक सन्तोषजनक मुस्कान थी।' एक माँ हमारी भावनाओं के साथ कितनी खूबी से जुड़ी होती है, ये समझाने के लिए उपरोक्त पंक्तियां अपने आप में सम्पूर्ण हैं। अब्राहम लिंकन का मां के बारे में मार्मिक कथन है कि जो भी मैं हूँ, या होने की उम्मीद है, मैं उसके लिए अपने प्यारी माँ का कर्जदार हूँ। किसी औलाद के लिए 'माँ' शब्द का मतलब सिर्फ पुकारने या फिर संबोधित करने से ही नहीं होता बल्कि उसके लिए माँ शब्द में ही सारी दुनिया बसती है, दूसरी ओर संतान की खुशी और उसका सुख ही माँ के लिए उसका संसार होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ठोकर लगने पर या मुसीबत की घड़ी में माँ ही क्यों याद आती है क्योंकि वो माँ ही होती है जो हमें तब से जानती है जब हम अजन्में होते हैं। बचपन में हमारा रातों का जागना, जिस वजह से कई रातों तक माँ सो भी नहीं पाती थी। वह गिले में सोती और हमें सूखे में सुलाती। जितना माँ ने हमारे लिए किया है उतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जाहिर है माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक दिन नहीं बल्कि एक सदी, कई सदियां भी कम है। माँ अपने आप में पूर्ण संस्कारवान, मनुष्यत्व व सरलता के गुणों का सागर है। माँ जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि पालन-पोषण करने वाली जीवन-निर्मात्री भी है। मां तो ममता की सागर होती है। लेकिन माँ की इस ममता को नहीं समझने वाले कुछ आधुनिक बच्चे यह भूल बैठते हैं कि इनके पालन-पोषण के दौरान इस माँ ने कितनी कठिनाइयां झेली होगी। मां के अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है या यूं कहें कि मां ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की यह चरमता केवल माताओं में ही नहीं, वरन् सभी मादा जीवों में देखने को मिलती है। अपने बच्चों के लिए भोजन न मिलने पर हवासिल (पेलिकन) नाम की जल-पक्षिनी अपना पेट चीर कर अपने बच्चों को अपना रक्त-मांस खिला-पिला देती है। किन्तु त्याग की यह चरमता ही मां अर्थात् नारी जाति की शत्रु बन गयी। समाज पुरुष प्रधान होता गया और नारी का अवमूल्यन होता गया। धीरे-धीरे वह पुरुष की उपभोग्या, उसके 'चरणों की दासी' बनकर रह गयी। शिक्षा-आत्मसम्मान वंचिता दासी की संतति महान कैसे हो सकती है? उसमें तो दास सुलभ चारित्रिक प्रवृत्तियां आएंगी ही। अतः नारी के अवमूल्यन के साथ-साथ पुरुष जाति का नैतिक अधःपतन होता गया। मां प्राण है, मां शक्ति है, मां ऊर्जा है, मां प्रेम, करुणा और ममता का पर्याय है। मां धरती पर जीवन के विकास का आधार है। मां ने ही अपने हाथों से इस दुनिया का ताना-बाना बुना है। सभ्यता के विकास क्रम में आदिमकाल से लेकर आधुनिककाल तक इंसानों के आकार-प्रकार में, रहन-सहन में, सोच-विचार, मस्तिष्क में लगातार बदलाव हुए। लेकिन मातृत्व के भाव में बदलाव नहीं आया। मां को धरती पर विधाता की प्रतिनिधि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच तो यह है कि मां विधाता से कहीं कम नहीं है। मां एक भाव है मातृत्व का, प्रेम और वात्सल्य का, त्याग का और यही भाव उसे विधाता बनाता है। मां विधाता की रची इस दुनिया को फिर से अपने ढंग से रचने वाली विधाता है। मां सपने बुनती है और यह दुनिया उसी के सपनों को जीती है और भोगती है। मां जीना सिखाती है। पहली किलकारी से लेकर आखिरी सांस तक मां अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती। मां पास रहे या न रहे मां का प्यार दुलार, मां के दिये संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। मां ही अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण करती हैं। इसीलिए मां को प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि मातृत्व के भाव पर नारी मन पर किसी दूसरे भाव का असर न आए। जैसाकि आज कन्याभ्रूणों की हत्या का जो सिलसिला बढ़ रहा है, वह नारी-शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप हैं तथा उसके लिए मातृत्व ही जिम्मेदार है। कन्याभ्रूणों की हत्या एक ओर मनुष्य को नृशंस करार दे रही है, तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी मानविकी पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मातृ-दिवस को मनाते हुए मातृ-महिमा पर छा रहे ऐसे अनेक धुंधलों को मिटाना जरूरी है, तभी इस दिवस की सार्थकता है।

(ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

पाकिस्तान में गधों की हत्या पर रोक

– सुभाष आनंद

हुसैनीवाला के पार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान में गधों की हत्या पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है लेकिन गौ हत्या पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। भारत में प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का मोटा मांस यूरोपीय देशों के साथ अरब देशों में निर्यात किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में गधों के मांस और उसकी खालों के निर्यात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है क्योंकि पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग काफी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रसद की सप्लाई के लिए यह एक मात्र साधन है। पाकिस्तान में गधे बहुत मूल्यवान माने जाते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान में गधों की संख्या 50 लाख से ऊपर है। यह पाकिस्तान का कौमी सरमाया एवं विदेशी मुद्रा की कमाई का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष गधों के मांस और खाल के निर्यात से पाकिस्तान को 150 अरब डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। पाकिस्तानी गधे चीन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। गधों का अचार भी चीन में सप्लाई किया जा रहा है। गधों का मांस अधिकतर हांगकांग और वियतनाम को निर्यात किया जा रहा है। गधों का मांस बड़ा शक्तिवर्धक होता है जबकि गधे की खाल सौंदर्य सामग्री बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। पाकिस्तान में दो वर्ष के भीतर गधों की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है जो गधा पहले 2000-3000 में आसानी से मिल जाता था अब 5000-6000 में मिलने लगा है। पाकिस्तान में गधों की कीमतें बढ़ने से गधों की चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी है, पाकिस्तान के कबीलों में अब गधों को दहेज में देने की प्रथा बढ़ती जा रही है। पंजाब पुलिस को बड़े पैमाने पर गधा चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अब लोगों ने गधों की चोरी के भय से चौकीदार रखने शुरु कर दिए हैं।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गधे के व्यापार में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में बीमारी से मरे गधों का मीट लोग खाते रहे हैं। पाकिस्तान में मांसाहार की बहुलता के कारण वहां भेड़ बकरियां और मुर्गे के अलावा मोटे मीट के रूप में गाय, बैल, भैस और ऊंट का मीट भी आम खाने को मिल रहा है। पाकिस्तान में इसी प्रवृत्ति की आड़ में वहां के दो नगरों मुल्तान और कसूर में 10 कसाई ऐसे मिले हैं जो बीमारी से मरे गधों का मांस बेचते पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध समाचार पत्र डॉन ने प्रकाशित समाचार के अनुसार एक किसान अतीक अहमद का गधा गंभीर बीमारी से भर गया था। उसने गधे का शव निकटवर्ती डम्प में फैंक दिया अगले दिन उसने देखा कि उसके मृतक गधे की खाल दो व्यक्ति उतार रहे हैं और शव के छोटे-छोटे टुकड़े करके बोरी में डालकर अपनी दुकान पर ले गए। सूत्रों से मिली जानकारी गधे का मीट 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रहे हैं। इसी प्रकार कसूर में दो भाईयों की दुकान पर पंजाब पुलिस द्वारा रेड करने के पश्चात पाया गया है कि वह मृतक गधों की खरीद करते हैं और उसके मांस को बाजार में बेच देते हैं। वहां डॉक्टर अनीक रहमान का कहना है कि बीमार गधों का मांस खाने के कारण कसूर की कई कॉलोनियों के लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई कसाईयों ने माना है कि हम पिछले दो महीनों से बीमारियों से मर रहे गधों के मीट का व्यापार कर रहे हैं। अब पंजाब पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरु कर दी है। पाकिस्तान में गधों को लेकर पंजाब की मरियम सरकार बहुत चिंतित है और पंजाब पुलिस को नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। (विनायक फीचर्स)

कविता

लव यू जिंदगी

बातों बातों में
जिंदगी से उलझ गया
बात बढ़ गई
बात का बतंगड़ हुआ
जंग हुई
पर न जीत हुई न हार हुई
जीते कोन-हारे कोन
यह बात तो ख़ास हुई
गर मै हारू
तो जीते जंग किससे ये जिंदगी
मै जीत लू
इती आसान नहीं ये जिंदगी
बस! अब तो
उलझन सी है ये जिंदगी
होंगी शिकायतें
हजारों तुझसे ऐ जिंदगी
आखिर !
मेरी ही तो है ये जिंदगी
आ गले लग
आई लव यू माई जिंदगी
बस ! सिर्फ़ तू है
मेरी जिंदगी लव यू जिंदगी

राकेश कुमार 'राकेश'
(भादरा, राजस्थान)

भारतीय संस्कृति तथा कुछ ग्रंथों के अनुसार मां शब्द की उत्पत्ति गोवंश से हुई। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसके सर्वप्रथम रंभानें में जो स्वर निकालता है वह मां होता है। यानी कि बछड़ा अपनी जन्मदात्री को मां के नाम से पुकारता है। इस प्रकार जन्म देने वाली को मां कहकर पुकारा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम बछड़े ने ही अपनी मां गाय को रंभाकर मां पुकारा और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई।

प्रेम त्याग व ममता की मूर्ति होती है मां

– रमेश सर्राफ धमोरा

दुनिया में मां की तुलना भगवान से की जाती है। भारत में गंगा नदी को पवित्र मान कर मां का दर्जा दिया जाता है जो इस बात का संकेत है कि मां अपने आप में एक उपाधि है। कई धार्मिक ग्रंथो में जननी की महिमा का बखान मिलता है। प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 12 मई को मातृ दिवस मनाया जाएगा। मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रम्हांड समा जाए। जब हम मां बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो शब्द के उच्चारण के साथ ही पूरा मुंह भर जाता है। मां ममता की मूरत होती है। पूरी दुनिया के सभी धर्मों ने मां के रिश्ते को सबसे पवित्र माना गया है। अपने बच्चों के प्रति मां का प्यार, दुलार, समर्पण और त्याग अनमोल होता है। मां को सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया में मई माह के दूसरे रविवार को मातृत्व दिवस (मदर डे) के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस माताओं एवं मातृत्व का सम्मान करने वाला दिन होता है। एक मां ही होती है जो सभी की जगह ले सकती है। लेकिन उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। मां अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा और उनकी देखभाल करती है। इसलिए मां को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। मां वह शख्स होती है जो नो माह तक अपने बच्चे को कोख में रखकर जन्म देती है। उसके बाद उसका लालन-पालन करती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक मां का अपने बच्चों के प्रति स्नेह कभी कम नहीं होता है। वह खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों के सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहती है। मां अपनी संतान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस रखती है। मां होने का अर्थ है उत्तरदायित्व और निस्वार्थता से पूरी तरह से अभिभूत होना। मातृत्व का मतलब है रातों की नींद हराम करना। मां भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। उसके जितना त्याग और प्यार कोई नहीं कर सकता है। मां विश्व की जननी है उसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मां ही हमारी जन्मदाता होती है और वही हमारी सबसे पहली गुरु होती है। इसीलिए हम धरती को भी धरती माता कहते हैं। जो अपने उपर हम सब का वजन उठाती है। मां को संस्कृत में मातरः कहते है। मां ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने अंश द्वारा अपनी शक्ति का संचार और विस्तार करता हैं। पुराणों के अनुसार मां का अर्थ लक्ष्मी है। जिस प्रकार मां लक्ष्मी सृष्टि का पालन करती है उसी प्रकार मां भी शिशु का पालन करती है। इस प्रकार मां को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। एक मत यह है कि इस सृष्टि का आरंभ मनु और शतरूपा नामक स्त्री-पुरुष के समागम से हुआ। मनु के नाम पर ही उनकी संतान को मनुज या मानव कहा गया। मनु की संतान को जिसने जन्म दिया उसे मां कहा गया। और इस प्रकार मां शब्द की उत्पत्ति हुई। हमारे देश में गाय को भी गौमाता कह कर पुकारते हैं जो हमें अपने अपना दूध पिला कर बड़ा करती है। मां हमारे जीवन की सबसे प्रमुख हस्ती होती है जो बिना कुछ पाने की उम्मीद किए सिर्फ देती ही रहती है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है जो हम अपने पूरे जीवन में किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मां बच्चे की पहली गुरु होती है।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि
गरीयसी।

वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में आचार्य वाल्मीकि कहते हैं कि माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है और उनके चरणों में ही वैकुंठ धाम है।

नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति
मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राण, नास्ति मातृसमा
प्रिया।।

यह श्लोक जीवन में माता के महत्व को बताता है। इस श्लोक में कहा गया है, माता के समान कोई छाया नहीं है और न ही उनके समान कोई सहारा है। न तो दुनिया में मां के समान कोई रक्षक नहीं और उनके समान कोई प्रिय वस्तु भी नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग के दौरान जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठर से सवाल पूछते हैं कि भूमि से भारी कौन है। तब युधिष्ठर कहते हैं कि माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं। अर्थात संसार में माता का स्थान सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। भारतीय संस्कृति तथा कुछ ग्रंथों के अनुसार मां शब्द की उत्पत्ति गोवंश से हुई। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसके सर्वप्रथम रंभानें में जो स्वर निकालता है वह मां होता है। यानी कि बछड़ा अपनी जन्मदात्री को मां के नाम से पुकारता है। इस प्रकार जन्म देने वाली को मां कहकर पुकारा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम बछड़े ने ही अपनी मां गाय को रंभाकर मां पुकारा और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई।

देखा जाए तो मातृ दिवस का इतिहास सदियों पुराना एवं प्राचीन है। यूनान में परमेश्वर की मां को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता था। 16वीं सदी में इंग्लैंड का ईसाई समुदाय ईशु की मां मदर मेरी को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाये जाने की शुरुवात हुई। 'मदर्स डे' मनाने का मूल कारण समस्त माताओं को सम्मान देना और एक शिशु के उत्थान में उसकी महान भूमिका को सलाम करना है। मातृत्व दिवस को आधिकारिक बनाने का निर्णय पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति वूडरो विलसन ने आठ मई 1914 को लिया था। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने और मां के सम्मान में एक दिन के अवकाश की सार्वजनिक घोषणा की थी। वे समझ रहे थे कि सम्मान, श्रद्धा के साथ माताओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। जिससे मातृत्व शक्ति के प्रभाव से युद्धों की विभीषिका रुके। तत्पश्चात हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। वर्तमान में ये भारत के साथ यूके, चीन, यूएस, मेक्सिको, डेनमार्क, इटली, फिनलैण्ड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, बेल्जियम सहित कई देशों में मनाया जाता है। हर साल माताओं के प्रति अपने आदर और सम्मान को व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मां शब्द की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में कई मत हैं। विभिन्न शैलियों ने मां शब्द की व्याख्या की है। ये एक अक्षर वाला मां संबोधन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर शब्द माना जाता है। मां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है। इसका वर्णन शब्दों मे करना नामुमकिन है। मां वो है जो न सिर्फ हमे जन्म देती है बल्कि हमे जीना भी सिखाती है। मां शब्द का अर्थ है निस्वार्थ प्यार और बलिदान। मां भगवान् का जीता जागता स्वरूप है। मां खुले दिल से अपने बच्चो का भरपूर ख्याल रखती है। मां वो होती है जो खुद भूखी सो जाए पर अपने बच्चो को भूखा रहने नहीं देती। उसे खुद कितनी भी तकलीफ हो वो जताती नहीं और ऐसे मे भी सिर्फ अपने बच्चो की ही सलामती की दुआ करती है। मां की ममता समुद्र से भी गहरी है। दुनिया में हर शब्द का अर्थ समझा और समझाया जा सकता है। लेकिन मां शब्द का अर्थ समझना और समझाना दोनों ही लगभग नामुमकिन है। मां शब्द का अर्थ समझाना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि मां के प्यार को मां के बलिदान को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मां के दिल में जितना प्यार अपने बच्चों के लिए होता है। अगर मां के सभी बच्चे कोशिश भी करें तो उसका कुछ अंश भी अदा नहीं कर सकते।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

बाबूलाल दाहिया ने देसी बीजों की खेती को बढ़ावा दिया है। उनका संरक्षण व संवर्धन किया है, बीजों की अदला-बदली के साथ संस्कृति व विरासत से जुड़े परंपरागत ज्ञान को बचाया है। जलवायु बदलाव व प्रतिकूल मौसम के इस दौर में देसी बीजों की विविधतापूर्ण, कम लागत वाली खेती के प्रति विश्वास जगाया है। इससे मिट्टी-पानी का भी संरक्षण होता है। यह रसायनमुक्त और कुदरती और आत्मनिर्भर खेती है। उनके अनोखे संग्रहालय में श्रम संस्कृति की झलक मिलती है। खेती की अलग-अलग पद्धतियों के बारे में जान सकते हैं।

किसानी का अनोखा म्यूजियम

नवाचार

■ बाबा मायाराम

पिछले कुछ सालों से किसानों का संकट बढ़ रहा है, जिसकी खबरें आती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देसी बीजों की खेती की ओर भी रूझान बढ़ रहा है, इसकी चर्चा कम होती है। आज मैं ऐसे ही एक किसान की कहानी बताने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल देसी खेती बल्कि लोक साहित्य व ग्रामीण संस्कृति को बचाने की पहल की है।

इस पहल के अगुआ बाबूलाल दाहिया हैं। वे मध्यप्रदेश के सतना जिले में उचहेरा विकासखंड के पिथौराबाद गांव में रहते हैं। उनकी इस पहल के कारण यह साधारण सा गांव चर्चा में आ गया है। साल 2019 में देसी बीजों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है।

लगभग 15 साल पहले मैं घूमते-घामते उनके गांव पहुंचा था और उनसे मुलाकात की थी। उस समय वे आंगन में धान की देसी किस्मों को अलग-अलग छांटने के काम जुटे थे। उनका खपरैल का घर था। गोबर से लिपा-पुता था। सुघड़ता से चीजें रखी थीं। दीवार पर रस्सी से टंगी धान की बालियों के गुच्छे लटक रहे थे। गीली बालियों की खुशबू आ रही थी। महिलाएं हाथ की चक्की में उड़द दाल बना रही थीं।

इसके बाद तो मैं उनसे कई बार मिला, कार्यक्रमों में साथ रहा, कुछ प्रांतों की लम्बी यात्राएं भी कीं। लम्बी कद काठी और चिर-परिचित मुस्कान, यही उनकी खास पहचान है। वे गांव में रहते हैं और उसकी संस्कृति में रचे-बसे हैं। उनकी गिनती बघेली के प्रमुख कवियों में होती है। उन्होंने मुझे खेती की कई कहावतें व मुहावरे भी सुनाए। इस पर उनकी किताब 'सयानन के थाती' भी है।

बाबूलाल दाहिया, सालों पहले लोकगीत, लोकोक्तियां, मुहावरें और लोक साहित्य का संकलन व सृजन करते थे। इन पर उनकी किताबें भी हैं। लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि अधिकांश लोक साहित्य व मुहावरे लोक अनाजों पर हैं और देसी अनाज लुप्त हो रहे हैं. तो उन्हें बचाने की मुहिम में जुट गए।

इसी प्रकार, आज आधुनिक व रासायनिक खेती के दौर में परंपरागत खेती के कई औजार चलन से बाहर हो रहे हैं, जिनसे किसान खेती करते थे, अनाज उगाते थे और वे ग्रामीण संस्कृति के प्रतीक थे। इन कृषि औजारों की किसान त्यौहारों पर पूजा भी करते हैं। इसलिए वह इन कृषि औजारों का संग्रह भी करने लगे, जिससे लोग उनकी परंपरागत संस्कृति को पहचानें, और इसे बचाने की पहल करें।

उन्होंने उनके घर के ही अतिरिक्त कमरों में यह संग्रहालय (म्यूजियम) बनाया है। इसमें लकड़ी, लोहे, मिट्टी, बांस, पत्थर, चमड़ा और धातु की कई प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। खेत-खलिहान, ग्रामीण जीवन में रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली सभी चीजें शामिल की गई हैं।

यहां लकड़ी के हल, बक्खर, बैलगाड़ी हैं, तो लोहे की खुरपी, चिमटा, करछुली भी हैं। पत्थर की सिल, चक्की, खल-बट्टा है तो मिट्टी की हांडी, चूल्हा, गुल्लक, मटकी भी शामिल है। इसी प्रकार, बांस की टोकनी, सूपा और पंखा इत्यादि है। इस संग्रहालय को देखने और ग्रामीण संस्कृति को समझने दूर-दूर से लोग आते हैं और इनमें ग्रामीण संस्कृति की एक झलक पाते हैं।

इसके पहले बाबूलाल दाहिया ने देसी बीज बैंक बनाया, उनकी खेती की, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया और इस प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार किया। उनकी कुल 8 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में ही देसी धान का प्रयोग करते हैं। बाकी 6 एकड़ में भी देसी किस्में लगाते हैं, वह भी बिना किसी रासायनिक खाद के। साथ ही उचहेरा ब्लॉक के कुछ गांवों में भी किसानों के साथ मिलकर धान और मोटे अनाज (कोदो, कुटकी, ज्वार) की खेती करते हैं।

देसी बीज बैंक में देसी धान की 200 किस्में हैं। गेहूं की 20 किस्में, चना की 5 किस्में हैं। इसके अलावा, सांवा, ज्वार, कोदो, कुटकी की किस्में हैं। कई प्रकार की सब्जियों के बीज भी हैं।

वे बताते हैं कि पहले हमारे क्षेत्र में पचासों तरह की धानें हुआ करती थी। इनमें बहुत विविधता है। जैसे गलरी पक्षी की आंख की तरह होता है गलरी धान। इसी तरह किसी धान का दाना सफेद होता है तो किसी का लाल। किसी का काला तो किसी का बैंगनी, किसी का मटमैला। कुछ का दाना पतला तो किसी का मोटा और कोई गोल तो किसी का दाना लंबा। कुछ धान की किस्मों के पौधे हरे होते हैं तो किसी के बैंगनी। इनमें न केवल विविधता है, बल्कि अलग-अलग रूप रंग का अपना विशिष्ट स्वाद व अपूर्व सौंदर्य है।

वे बताते हैं कि देसी धान ऋतु के प्रभाव से पक जाती हैं। जैसे कोई एक ही किस्म की धान अलग-अलग समय में बोई जाए तो वे एक ही समय पक कर तैयार हो जाती हैं। यानी एक ही किस्म को अगर हम 1 जुलाई को बोएं और उसी किस्म को 1 अगस्त को बोएं तो वे एक साथ या कुछ दिनों के अंतर से ही पककर तैयार हो जाएंगी।

देसी धान को बार-बार निंदाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार निंदाई हो जाए तो बहुत है। क्योंकि इसके पौधे को खरपतवार नहीं दबा पाती। क्योंकि इसका पौधा काफी ऊंचा होता है। कीट व्याधि को मकड़ी, मधुमक्खी, चींटी और मित्र कीट ही नियंत्रित कर लेते हैं। चिड़िया भी कीट नियंत्रण करने में सहायक हैं। केंचुएं निस्वार्थ भाव से निरंतर गुड़ाई कर जमीन को भुरभुरा बनाते हैं, खेत को बखरते हैं जिससे पौधे की बढ़वार में मदद मिलती है।

वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज बादलों के रंग, हवा के रूख, अवर्षा, खंड वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में माहिर थे। जैसे एक कहावत है कि 'पुरबा जो पुरबाई पावै, सूखी नदियां नाव चलाबैं।' यानी पूर्वा नक्षत्र में पुरवैया हवा चलने लगे तो वर्षा ज्यादा होती है। और ज्यादा बारिश से सूखी नदियों में इतना पानी हो जाता है कि उनमें नाव चलनी लगती है।

वे बताते हैं जैसे हमारे देसी बीज खत्म हो रहे हैं, वैसे ही उससे जुड़े व परंपरागत खेती से जुड़े कई शब्द भी खत्म हो रहे हैं। पूरी कृषि संस्कृति और जीवन पद्धति खत्म हो रही है। अब हमारा काम गेहूं, चावल और दाल जैसे शब्द से चल जाता है। लेकिन पहले बहुत सारे अनाज होते थे। उनके नाम थे जैसे समा, कोदो, कुटकी, मूंग, उड़द, ज्वार, तिल्ली आदि। फिर उन्हें बोने से लेकर काटने तक कई काम करने पड़ते थे।

बोवनी, बखरनी, निंदाई-गुड़ाई, दाबन, उड़ावनी और बीज भंडारण आदि। खेती की हर प्रक्रिया के अलग-अलग नाम थे। यह जरूर है कि ये शब्द किसी शब्दकोष में नहीं मिलेंगे, लेकिन लोक मानस में थे। बुजुर्ग अब भी इन शब्दों को आत्मीय ढंग से याद करते हैं। इसी प्रकार, खेती के परंपरागत औजार भी अब चलन से बाहर हो गए हैं, इसलिए संग्रहालय में इन्हें सुरक्षित रखा गया है।

वे कहते हैं कि हम यहां ज्यादा पानी वाली फसलें नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी की कमी है। विशेषकर, यह इलाका सूखा है। यहां की नदियों में पानी उत्तर भारत की तरह ही नहीं हैं, जहां साल भर पानी रहता है। वहां वर्षा हो या न हो, बर्फ पिघलने के कारण नदियों में पानी बना रहता है। यानी हमारे यहां की नदियां हिम पुत्री नहीं है, वन पुत्री हैं। पानी का स्रोत वन हैं। इन नदियों में पानी तभी होगा, जब वन होंगे पर वन जब होंगे तब हम पानी की किफायत बरतेंगे।

अगर हम तीन-तीन, चार-चार पानी वाली फसलें लगाएंगे तो धरती शुष्क होगी। पेड़-पौधे सूख जाएंगे। जब वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी। क्योंकि जैसे कोई हवाई जहाज बिना हवाई अड्डा के नहीं उतरता वैसी ही बिना वन के बादल भी नहीं उतरते। यानी बारिश नहीं होगी। इसलिए धान की खेती को लंबे समय तक करना है तो वनों को बचाना जरूरी है और यह तभी हो सकता है जब धान की कम पानी वाली किस्में लगाएं।

कुल मिलाकर, बाबूलाल दाहिया ने देसी बीजों की खेती को बढ़ावा दिया है। उनका संरक्षण व संवर्धन किया है, बीजों की अदला-बदली के साथ संस्कृति व विरासत से जुड़े परंपरागत ज्ञान को बचाया है। जलवायु बदलाव व प्रतिकूल मौसम के इस दौर में देसी बीजों की विविधतापूर्ण, कम लागत वाली खेती के प्रति विश्वास जगाया है। इससे मिट्टी-पानी का भी संरक्षण होता है। यह रसायनमुक्त और कुदरती और आत्मनिर्भर खेती है।

उनके अनोखे संग्रहालय में श्रम संस्कृति की झलक मिलती है। खेती की अलग-अलग पद्धतियों के बारे में जान सकते हैं। हमारे किसानों ने परंपरागत खेती के औजार अपने लंबे अनुभव, कौशल व हुनर से बनाए थे। इससे खेती का इतिहास भी पता चलता है। इसलिए हमें इस श्रम संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, और जिन्होंने इस संस्कृति को बनाया और आगे बढ़ाया, उन समुदायों के योगदान को भी याद रखा जाना चाहिए।

इसके साथ ही प्राकृतिक खेती पर जोर देना चाहिए। हरियाली के संरक्षण व पोषण के साथ ग्रामीण जीवन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आजीविका के साथ पर्यावरणरक्षक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम देसी बीज, परंपरागत खेती और ग्रामीण कृषि संस्कृति की ओर आगे बढ़ेंगे? लेकिन क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?

खेती की अलग-अलग पद्धतियों के बारे में जान सकते हैं। हमारे किसानों ने परंपरागत खेती के औजार अपने लंबे अनुभव, कौशल व हुनर से बनाए थे। इससे खेती का इतिहास भी पता चलता है। इसलिए हमें इस श्रम संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, और जिन्होंने इस संस्कृति को बनाया और आगे बढ़ाया, उन समुदायों के योगदान को भी याद रखा जाना चाहिए।

बीता सप्ताह

4 मई

- भारत ने ईरान, इजरायल की यात्रा से प्रतिबंध हटाया।
- म्यामार में लू की चपेट में आने 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई।
- इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के खेलने वाले स्पिनर जोश बेकर का निधन हो गया।

5 मई

- अश्लील विडियो के मामले में फंसे जेडीएस के पूर्व नेता प्रजवल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को हिरासत में लिया गया।
- भारत में लोकसभा का चुनाव देखने 23 देशों के पर्यवेक्षक भारत पहुंचे।
- संघर्ष विराम के लिए तुर्की ने इजरायल के साथ व्यापार रोका।
- हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ।

6 मई

- इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा से हटने की हमास की मांग नामंजूर कर दी।
- टेक्सास में बाढ़ग्रस्त इलाके से 6 सौ ज्यादा लोगों को बचाया गया।
- दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर खराब मौसम के कारण 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई।
- नया कोविड वैरिएंट 'फ्लर्ट' इम्यून सिस्टम से बचने में सक्षम विशेषज्ञों ने बताया।

7 मई

- देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले गए।
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेनानिवृत्त) संजय कुमार मिश्र ने शपथ ली।
- रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के संघीय चुनाव जीतने के बाद उनका पांचवा कार्यकाल शुरु हुआ।
- केरल हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में कहा कि बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

8 मई

- अंतागढ़ टेप कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंतुराम पवार की याचिका निराकृत कर दी।
- हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया।
- जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और उग्रवादी के बीच हुए मुठभेड़ में चार आतंकी मारे गए।
- फिल्म कलाकार शेखर सुमन ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली।

9 मई

- भारत में स्ट्रातेनेका की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुनियाभर से वायरस लेने की घोषणा की।
- अपनी नस्लवादी टिप्पणी के चलते विवादित हो जाने पर सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
- तुर्की के इस्तानुल हवाई अड्डे पर एक पाल वाहक विमान बिना पहिए खुले उतरा।
- इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बाबी को आदियाला जेल भेजने का आदेश दिया।

10 मई

- केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया को 10 मई को प्रात: काल 7.15 बजे आईटीबीपी की बैंड की धुन के साथ खोल दिए गए।
- तमिलनाडु के शिवकाशी के पास निजी फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने से आठ लोगों की मौत हो गई।
- 10वीं व 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी हुए जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी।
- पाकिस्तान में आतंकी हमले में सात लोगों की मौत हो गई।

संविधान से मजबूत है भारत की बुनियाद

2024 का लोकसभा चुनाव आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चुनाव है। यह प्रजातंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। पिछले 10 साल में हिन्दुत्ववादी दक्षिणपंथी सत्ता ने भारत की अस्मिता और उसकी सांस्कृतिक विरासत को बुरी तरीके से जख्मी किया है। आरएसएस और उसके हजारों हिन्दुत्ववादी संगठनों ने अपने भाषणों और कृत्यों से भारत की आत्मा को कुचल डाला है। आजादी के समय देश की जो परिस्थितियां थी, आज वही स्थितियां बना दी गई हैं। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदू महासभा के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि आजादी के साथ भारत को विभाजन झेलना पड़ा। विभाजन के दरमियान हुई सांप्रदायिक हिंसा और अमानवीयता ने भारत की स्वतंत्रता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। चर्चिल जैसे यूरोपीय नेता नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन गांधी के मार्गदर्शन, नेहरू के दूरदर्शी चिंतन और डॉ आंबेडकर के सामाजिक न्याय ने देश की नींव को मजबूत बनाकर खड़ा किया। तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए वैचारिक दरारों के बावजूद अगर भारत आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है तो उसकी बुनियाद भारत का संविधान है।

मोदी सरकार के 10 सालों में भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा हमला किया गया। डॉ. अंबेडकर भारतीय राष्ट्र और संविधान की चुनौतियों से अवगत थे। बाबा साहब संविधान निर्माण से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक लगातार लोकतंत्र और संविधान की चिंता करते रहे। उन्होंने संविधान सभा के अंतिम भाषण में उन चुनौतियों और आशंकाओं को सूत्रबद्ध किया। संविधान सभा में करीब 50 मिनट तक दिए गए इस भाषण की तमाम खूबियां हैं। दुर्योग से इस भाषण की चर्चा अगले 50 साल तक लगभग ना के बराबर हुई।

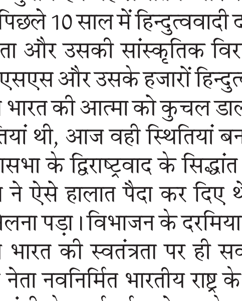

प्रो. रविकांत

90 साल के स्वाधीनता आंदोलन और लाखों कुर्बानियों के बाद प्राप्त आजादी को लेकर अंबेडकर बेहद चिंतित थे। भारत के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने कहा कि '26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा?' सदियों से सामन्तवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा?

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया डॉ अंबेडकर का यह भाषण 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण, बौद्धिक और चेतावनियों से लबरेज भाषण है। जिस तरह नेहरू का 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को दिया गया भाषण 'नियति से साक्षात्कार' की चर्चा भारत की गरीबी, बदहाली की चुनौतियों से निपटने और भारत के निर्माण के विषय में है, उसी तरह डॉ. अंबेडकर का भाषण वैचारिक और सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन जहां नेहरू के भाषण की चर्चा हमेशा की जाती रही, वहीं अंबेडकर के विचार और व्यक्तित्व की तरह उनके भाषण को भी भुला दिया गया। अगर उस भाषण को आने वाली कांग्रेसी सरकारों और उस समय के बुद्धिजीवियों ने ध्यान से पढ़ा और परखा होता तो शायद हिंदुत्ववाद के ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते।

संविधान निर्माण से लेकर उसके पारित होने और उसके बाद दशकों तक हिंदुत्ववादी संविधान के खिलाफ खड़े रहे। आरएसएस, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और भाजपा के नेता गाहे-बगाहे भारतीय संविधान को औपनिवेशिक दासता का प्रतीक और विदेशी बताते रहे। उनका आग्रह एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो भारतीयता के नाम पर मनुस्मृति पर आधारित हो। भारतीय संविधान की अप्रासंगिकता और असफलता को हिंदुत्ववादियों द्वारा बार-बार दोहराया गया। डॉ अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि, 'संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो बुरा साबित होगा, अगर उसके अनुसरण करने वाले लोग बुरे होंगे।'

90 साल के स्वाधीनता आंदोलन और लाखों कुर्बानियों के बाद प्राप्त आजादी को लेकर अंबेडकर बेहद चिंतित थे। भारत के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने कहा कि '26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा?' सदियों से सामन्तवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा? वर्चस्व और वंचित में विभाजित समाज एक साथ कैसे रहेगा? भारत की जनता कैसा आचरण करेगी? डॉ आंबेडकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को लेकर भी आशंकाग्रस्त थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी। संभवतया वह हमेशा के लिए खो जाए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है।' जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है। उसके लिए भारत का विचार ही हिंदुत्व है, समावेशी राष्ट्र नहीं। राष्ट्रवाद के नाम पर उसने हिंदुत्व को पोसा और अब खुले तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुनादी की जा रही है। भारतीय राष्ट्र के लिए आरएसएस के विचार बेहद खतरनाक थे। आज उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं।

भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया। भारत में प्रजातन्त्र का भविष्य कैसा है? इसकी क्या चुनौतियां हैं? प्रजातांत्रिक प्रणाली में डॉ अंबेडकर को तानाशाही का खतरा महसूस हो रहा था। उनकी आशंका थी कि कोई राजनीतिक दल अगर बड़ा बहुमत हासिल करता है तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा कि 'इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है।' इस लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर 'अबकी बार 400 पार' का नारा दिया जा रहा है। 400 सीटें जीतने का एजेंडा भी भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें संविधान बदलने के लिए दो तिहाई से अधिक बहुमत चाहिए। अम्बेडकर को इसकी आशंका थी। वे कहते हैं कि 'प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है।'

बाबा साहब की पहली चिंता स्वतंत्रता खो देने की थी। दरअसल, आजादी के बाद पूरे देश में नेहरू की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी। भारत के कोने-कोने में नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। अंबेडकर नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता के तानाशाह बनने की आशंका से घिरे हुए थे। जान स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा, 'अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए।' पिछले 10 साल में यही हुआ है। कारपोरेट मीडिया और थ्री डी इमेज के जरिए नरेंद्र मोदी की महानायक की छवि गढ़ी गई। मोदी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नख दंत विहीन बना दिया। मीडिया के जरिए विपक्ष को अप्रासंगिक बना दिया गया। मीडिया सरकार के कामों की समीक्षा करने और गलत नीतियों की आलोचना करने के बजाय मोदी का स्तुतिगान करने में मगन है। मीडिया ने नागरिकों के सवालों को उठाना बंद कर दिया है। उसने सरकार के काम को दायित्व नहीं बल्कि कृपा बना दिया है। हिन्दुत्ववादी तंत्र और मीडिया द्वारा लोगों को सरकार के प्रति कृतज्ञ होना सिखाया जा रहा है। जबकि अंबेडकर ने आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कोमेल को उद्धृत करके चेतावनी के तौर पर कहा था 'कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता।' वे आगे कहते हैं, 'यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिमाण के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता।' भारत एक अत्यंत आस्थावान देश है। भक्ति और आध्यात्मिकता की एक लंबी परंपरा है। राजनीति में यह भाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। अंबेडकर ने आगाह करते हुए कहा था कि 'धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंतत: तानाशाही का सीधा रास्ता है।' यह खतरा आज हम सबके सामने है। क्या भारत के लोग इस चुनाव में तानाशाही को पराजित करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं?

गरीबों के हित में बड़े बदलाव का संकेत है कांग्रेस का एजेंडा

जैसे-जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ रहा है उसके मद्देनजर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत कुछ पहले ही बदल चुका है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी एक दशक से भी ज्यादा वक्त में पहली बार मतदाताओं के सामने अपनी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट रूप से पेश करने में सफल हुई है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो पूरी तरह से वामपंथ के साथ चल रही है। सवाल यह नहीं है कि वह कितने डिग्री तक वामपंथ के साथ है परन्तु यह दिशा और स्थिति का सवाल ज्यादा है और बताता है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी किस स्थान पर खड़ी है। कभी उदारीकरण और निजीकरण की समर्थक पार्टी से इस वक्त जो उभर कर सामने आ रहा है वह अब सामाजिक न्याय, धन-आय सम्बन्धी असमानता या श्रमिकों के अधिकारों के एजेंडे के साथ एक अनिश्चय की स्थिति वाला रवैया नहीं है। यह एजेंडे का स्पष्ट रूप से रखा जाना है। यह वामपंथ की ओर एक तेज मोड़ है जो हाल के समय में कभी स्पष्ट नहीं था जितना इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान था। वर्तमान में मतदाताओं की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि पार्टी जनता की भावनाओं को समझ रही है और उसकी गतिविधियां राष्ट्र के मूड के अनुरूप है।

कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए इस प्रखर वैचारिक स्थिति के प्रति कटिबद्धता महत्वपूर्ण है जबकि कुछ लोग कहेंगे कि पार्टी परिस्थितियों से मजबूर हो गई है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि वामपंथ के प्रति इस झुकाव को नेतृत्व और काडर द्वारा पूरे दिल से गले लगाया गया है। कांग्रेस ने 4 जून को आने वाले परिणामों की घोषणा से बहुत पहले यह एक महत्वपूर्ण चुनाव किया है। उल्लेखनीय है कि नारेबाजी और उम्मीद-सेटिंग के कारण विजयी के रूप में देखे जाने के लिए भाजपा को अपने 303 के पिछले आंकड़े को पार करना होगा वहीं इंडिया गठबंधन को जीत का दावा करने के लिए भाजपा को 272 से नीचे खींचना होगा। इस बात की संभावना को छोड़ दें कि इस समय कांग्रेस और/या इंडिया गठबंधन इन चुनावों में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है या नहीं, लेकिन देश में एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले दिनों में भारत की नीति तय करेगी। यह एक ऐसी भूमिका है जिसे कांग्रेस ने त्याग दिया था और जिसके कारण वह अप्रासंगिक हो गई थी। इसी ने 'क्या', 'कैसे' और 'क्यों' की ठोस स्थिति में बंधी स्पष्ट राजनीतिक दिशा के अभाव में भाजपा के लिए जमीन छोड़ दी थी। इस निश्चित दिशा के बिना हमारे पास जो कुछ भी था वह भाजपा की सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार पर एक दंतहीन हमला था जिसमें दृढ़ विश्वास नहीं था और जो मतदाताओं की मंशा के अनुरूप कारगर नहीं है। बहरहाल अब कहानी बदल गई है।

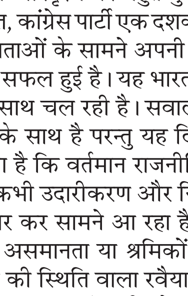

जगदीश रत्तनानी

किसी भी माध्यम का कुशल उपयोग इस बात की समझ के अभाव में खतरनाक है कि इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है और यह कहां ले जाएगा। आज की कांग्रेस के लिए यह सेवानिवृत्त नौकरशाहों से दूर रहने की चेतावनी होनी चाहिए। उसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए पैनी नजर रखनी होगी। चाहे वह सत्ता में हो या न हो, लेकिन कांग्रेस को एक टीम बनाने के लिए अधिक युवा नेतृत्व और प्रतिबद्ध लोगों की आवश्यकता होगी ताकि पार्टी जीवंत रह सके।

कांग्रेस में एक दशक से आ रही गिरावट और केंद्रीय सत्ता में रहने के दौरान भी इसकी धीरे-धीरे हो रही गिरावट, नव-उदारवादी एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए जानी जाने वाली पार्टी का अपरिहार्य परिणाम थी। हाल के दिनों में इसकी एकमात्र उपलब्धि 1991 के आर्थिक सुधार थे। ये सुधार भी परिस्थितियों के कारण मजबूरीवश किए गए थे। इन सुधारों ने एक ओर 'एनीमल स्प्रिट' (अर्थ व्यवस्था में, 'एनीमल स्प्रिट' शब्द बाजार मनोविज्ञान और स्वभावजन्य अर्थशास्त्र में उपयोग में आता है। 'एनीमल स्प्रिट' आत्मविश्वास, आशा, भय और निराशावाद की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्ति या व्यक्ति समूहों की वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा या बाधित कर सकती है) को उजागर करने का प्रयास किया लेकिन दूसरी ओर इसने श्रमिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने तथा व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की ओर भी कदम बढ़ाए। मजबूत शासन और कमजोर या गैर-मौजूद पुलिसिंग के अभाव या मिलीभगत के कारण यह भ्रष्टाचार सार्वजनिक क्षेत्र के आधिपत्य से निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। मोटे तौर पर इन घटनाक्रमों ने आश्चर्यजनक रूप से भाजपा समर्थक धनी वर्गों के उदय को बढ़ावा दिया जिन्होंने वर्ग, जाति और स्थिति के मामले में अन्य मिश्रित कुलीन वर्ग के साथ गठबंधन करते हुए भाजपा को सत्ता में लाने के लिए मदद की। इस काम के लिए उन्होंने कांग्रेस शासन में हुए बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का हवाला दिया। 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अन्ना हजारे की निंदनीय भूमिका पहले ही उजागर हो चुकी है जो भाजपा के वृहद भ्रष्टाचार घोटालों पर चुप रहे हैं।

इस फ्रेम में किसी भी कीमत पर जीडीपी वृद्धि भारतीय अभिजात वर्ग की बात करने वाला बिंदु आ गया जो आने वाले व्यवसायिक उछाल को भुनाना चाहता है। सत्तारुढ़ भाजपा ने विशेष प्राथमिकता देते हुए अपने चुनिंदा व्यापारिक घरानों को चरम सीमा पर पहुंचा दिया जबकि अन्य लोगों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए कहा गया। शेष भारत को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत असफल और अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली एवं खाद्य कूपन की योजना के कीचड़ में लोटने के लिए छोड़ दिया गया था। इस योजना के तहत आज 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मिलता है जो भारत के आधे से अधिक हैं।

आज कांग्रेस को और ताकत देने वाला एक ऐसा नेतृत्व है जो राष्ट्र के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और मजबूत दिख रहा है। राहुल गांधी नेतृत्व की भूमिका में खिल गए हैं और ड्राईविंग सीट पर जंच रहे हैं। वे सही संदेश और संकेत भेज रहे हैं। न्याय यात्रा की कहानियों और अनुभवों को मिलाकर राहुल एक रोमांचक राजनीतिक आख्यान बना रहे हैं जो साहसिक, जमीन से जुड़ा और ताज़ा है।

यह उल्लेखनीय है कि असंख्य बाधाओं के बावजूद राहुल गांधी इस अभियान को किसी भी कड़ुवाहट से दूर रखने में सफल रहे हैं जबकि भाजपा ने अपने संसाधनों को बड़े पैमाने पर राहुल और उनके परिवार को बदनाम करने के कड़ुवाहट भरे और घृणित अभियान पर केंद्रित कर रखा है। राहुल का उभरना यह भी साबित करता है कि राजनीतिक 'पंडितों' पर भरोसे की एक सीमा होती है। उनमें से कुछ उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं जिन पर सवाल उठ सकते हैं। इनमें से एक ने तो इस बेहद सफल न्याय यात्रा के समय और औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के इस पुनरुत्थान ने स्वयं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाए जा रहे भाजपा के अभियान को भी पटरी से उतार दिया है। भाजपा ने क्या किया है और अगले पांच वर्षों के लिए क्या करने का वादा करती है, यह बताने के बजाय भाजपा का अभियान इस बात पर केंद्रित है कि कांग्रेस क्या कर रही है या उसकी क्या कथित बुराइयां हैं। अगर पार्टी उस स्लाइड को वापस खींचने के प्रति सावधान नहीं है तो यह खुद के बजाय प्रतिद्वंद्वी के बारे में अधिक बात करने के जाल में फंस जाएगी।

अंत में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहे या न कहे लेकिन उसने मनमोहन सिंह और उन सभी सुधारों को खारिज कर दिया है जो उन्होंने पेश किए थे। नई कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। आखिरकार मनमोहन सिंह एक नौकरशाह थे जो भले ही अर्थव्यवस्था के उप-समूह में सफल रहे हों लेकिन राजनीति के सुपर सेट में बुरी तरह विफल रहे थे। आर्थिक सुधार एक माध्यम है जबकि राजनीति एक दर्शन है। किसी भी माध्यम का कुशल उपयोग इस बात की समझ के अभाव में खतरनाक है कि इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है और यह कहां ले जाएगा। आज की कांग्रेस के लिए यह सेवानिवृत्त नौकरशाहों से दूर रहने की चेतावनी होनी चाहिए। उसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए पैनी नजर रखनी होगी। चाहे वह सत्ता में हो या न हो, लेकिन कांग्रेस को एक टीम बनाने के लिए अधिक युवा नेतृत्व और प्रतिबद्ध लोगों की आवश्यकता होगी ताकि पार्टी जीवंत रह सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

एयर इंडिया एक्सप्रेस
कर्मियों की मनमानी

एयर इंडिया एक्सप्रेस में अनेक 'कैबिन क्रू' ने मनमानी करते हुए 'सिक लीव' ले ली जिससे उसकी उड़ानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हवाई यात्रा में उड़ान रद्द होने से अधिक परेशानी का कोई कारण नहीं होता है। इस प्रकार कहीं पहुंचने का अनुमान अनिश्चितता और असुविधा में बदल जाता है। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ यही हुआ जो एयर इंडिया का सस्ता विकल्प है। अनेक उड़ानें रद्द होने के कारण यह संकट में आ गई। भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन काफी समय से आर्थिक परेशानियों व आपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रही है। अनेक पुनर्गठन प्रयासों के बावजूद एयरलाइन अत्यधिक प्रतियोगी उद्योग में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। नवीनतम संकट उस समय पैदा हुआ जब एक्सप्रेस उड़ानों के 300 से अधिक वरिष्ठ क्रू सदस्यों ने स्वयं को अंतिम क्षण पर 'बीमार' बता दिया। इसके कारण मंगलवार रात से 90 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इससे हवाईअड्डों पर अव्यवस्था फैल गई तथा यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, एयर इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है जिससे गुरुवार को 74 एक्सप्रेस विमान रद्द होने की तुलना में 20 उड़ानें काम करने लगी हैं। इसके साथ ही 'सिक लीव' लेने वाले 30 क्रू सदस्यों को हटा दिया गया है। इस संकट का प्रमुख कारण लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायतें हैं जिनको एयर इंडिया एक्सप्रेस इम्प्लाइज़ यूनियन-एक्स्यू ने सामने रखा है। उसने कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार पर अपनी चिन्ता प्रकट की थी। इसमें आंतरिक तैनातियों में योग्य कर्मचारियों को पीछे छोड़ कर बाहरी

उम्मीदवारों को रखना शामिल है। एयरलाइन के स्वामी एक्स्यू को मान्यता नहीं देते हैं। नई दिल्ली के क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने भी प्रबंधन की श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए आलोचना की है जिससे निर्णय लेने में जिम्मेदारी का अभाव स्पष्ट होता है। एयर इंडिया में जारी वित्तीय संघर्ष तथा आपरेशनल चुनौतियों के कारण समस्या और गंभीर हुई है। हालांकि, अपनी मूल कंपनी के घाटे में होने के बावजूद एयर इंडिया एक्सप्रेस मुनाफे में है। 2021 में इसे टाटा समूह को बेच दिया गया था जिसने इसका विलय एयर एशिया इंडिया में कर दिया। इसका उद्देश्य 'गैर ट्रंक रूटों' तथा संबद्ध सेवाओं पर ध्यान देकर सस्ते उड़ान बाजार पर कब्जा करना था। यह टाटा की एकमात्र मुनाफे वाली एयरलाइन है। 2023 में एयरलाइन ने 116.84 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया था जबकि टाटा समूह की अन्य एयरलाइनें -एयरएशिया इंडिया, विस्तारा एवं एयर इंडिया को कुल मिला कर 15,530 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था। उड़ानें रद्द करने का व्यापक प्रभाव पड़ा है और यात्री अपनी पीड़ा सोशल मीडिया मंचों पर व्यक्त कर रहे हैं। हवाईअड्डों पर लंबी कतारें, संबंधित उड़ानें छूटने तथा सही सूचनाओं के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इन घटनाओं पर माफी मांगी है तथा सेवाओं में सुधार का वादा किया है, लेकिन यात्रियों का विश्वास टूट गया है। भारतीय विमानन क्षेत्र में असीम संभावनायें हैं, पर प्रबंधन संबंधी मुद्दे बहुत गंभीर हैं। सरकार को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि विमान यात्रियों पर ध्यान दिया जाए तथा एयरलाइनों को घाटा न हो। महामारी के साल उद्योग के लिए बहुत घातक रहे हैं और अब वह इनसे धीरे-धीरे उबर रहा है। पूरे क्षेत्र में संकट फैलने से पहले सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। उम्मीद है कि एयर इंडिया व उसकी सहायक एयरलाइनें जल्द ही वर्तमान अराजकता से मुक्ति पा कर तेजी से प्रगति करेंगी।

शहबाज़ शरीफ़ को खुला पत्र

हमने अनेक वर्षों तक आतंकी हिंसा सहन की। लेकिन जब हम इसे सहने में विफल हो गए तो हमने संसद के रास्ते से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। लेकिन हमने कभी हिंसा नहीं की।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

प्रिय वजीरे आजम शहबाज़ शरीफ़ साहब, मुझे अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। यह पड़ोसी देश 76 साल पहले तक हमारे देश का अंग था, पर दु:खद परिस्थितियों में यह हमसे अलग हो गया। मुझे विश्वास है कि बाकी भारतीयों की तरह आप भी उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिनके कारण यह विभाजन हुआ। इस विभाजन के प्रभाव आज भी जारी हैं जिनकी काली छाया न केवल पूरे उप-महाद्वीप पर पड़ रही है, बल्कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आपको संबोधित यह खुला पत्र एक विनम्र प्रयास है। मेरा उद्देश्य उन दशकों की परिस्थितियों पर गुस्सा प्रकट करना या किसी पर आरोप मढ़ना नहीं है। इसके बजाय मैं आधुनिक समय के विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करना चाहता हूं जो आज तक हमें प्रभावित कर रहे हैं। जब भी अयोध्या, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सामने आता है, मेरे दिमाग में लाहौर तथा आपके शानदार शहर के नौखला बाजार इलाके में स्थित गुरुद्वारा शहीद गंज की ओर ध्यान चला जाता है। गुरुद्वारा शहीद गंज के स्वामित्व पर विवाद था। जहां स्थानीय मुसलमानों का दावा था कि यह स्थान मूल रूप से मस्जिद था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में स्थानीय सिखों ने इसे एक गुरुद्वारे में बदल दिया था। 19वीं शताब्दी में सही अवसर आने पर कुछ मुस्लिम लीग सदस्यों के नेतृत्व में शहर के लोगों ने इस मामले को अदालत में उठाया था। लेकिन वे मुकदमा नहीं जीते क्योंकि अदालत ने उनको गुरुद्वारे को फिर से मस्जिद में बदलने की अनुमति नहीं दी।

उस समय कानूनी सलाहकारों का तर्क था कि आवश्यक होने पर इस फैसले के खिलाफ प्रिवी कौंसिल तक अपील की जा सकती है। लेकिन पंजाब के तत्कालीन प्रीमियर सर सिकंदर हयात खान ने सलाह दी कि इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए। उनके विचार से इससे पूरे उप-महाद्वीप में ऐसी परेशानियों का पिटारा खुल सकता था जो विभाजन के पहले से विद्यमान थीं। सिकंदर हयात खान ने इस पर आगे मुकदमेबाजी की भी सलाह नहीं दी। वे स्पष्ट रूप से इस मुकदमेबाजी के खिलाफ थे। उस समय अधिकांश कानूनविदों की राय थी कि 'एडवर्स पजेशन' के तर्क से उन बहुत से मंदिरों को वापस करना पड़ेगा जो मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। लेकिन उस समय शायद इस तथ्य को अनदेखा किया गया कि हिंदू मंदिर देवता का आवास होते हैं और ये केवल प्रार्थना स्थल नहीं होते हैं। गैर-हिंदू धर्म अपने पवित्र स्थलों को केवल प्रार्थना स्थल मानते हैं, जबकि हिंदू दर्शन के अनुसार देवी-देवताओं की प्रतिमायें आध्यात्मिकता की खोज में पहला चरण होते हैं।

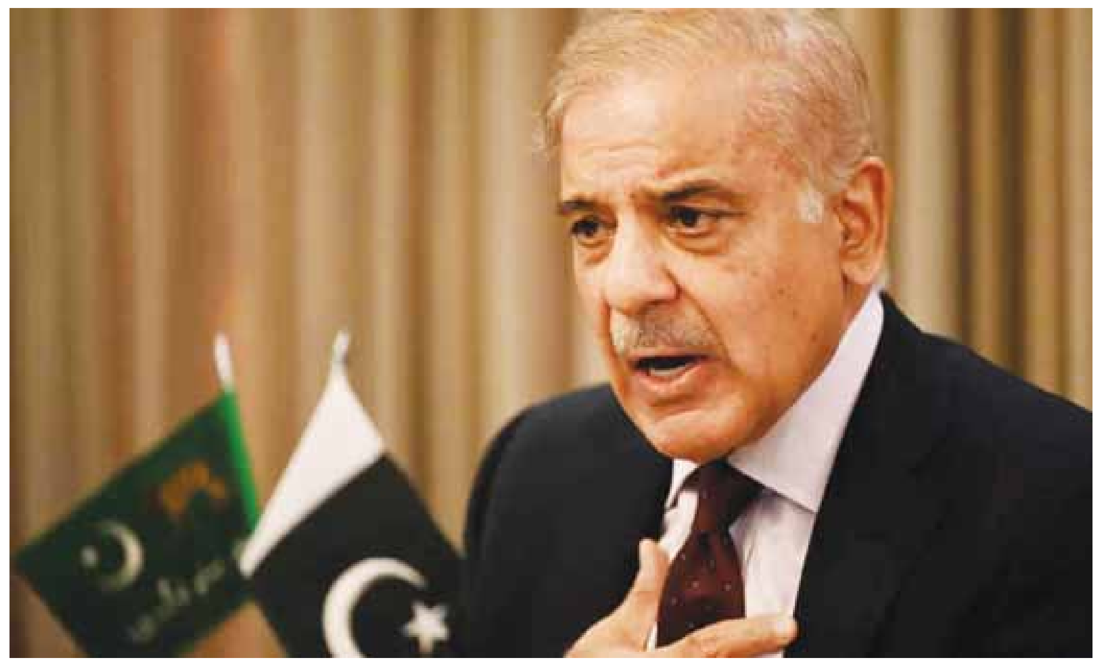

हिंदू विश्वास के अनुसार देवी-देवताओं या ईश्वर के अवतारों की मूर्तियों के दर्शन से आध्यात्मिक भावनायें सक्रिय होती हैं। इसके उलट सिख धर्म में कोई मूर्ति नहीं होती है और वहां हिंदू मंदिर की तरह आध्यात्मिकता के रास्ते पर बढ़ने के लिए इसका उपयोग भी नहीं होता है। यही विचार हजरत मूसा ने व्यक्त किया था जो यहूदीवाद के संस्थापक पैगंबर थे। यहूदी धर्म तीन 'सेमेटिक धर्मों' में से पहला धर्म है। इसे हज़रत मूसा द्वारा प्रतिपादित 'किताबी धर्म' भी कहा जाता है। इस्लाम भी इसी प्रकार का 'किताबी धर्म' है जिसका संचालन पवित्र कुरान के आधार पर होता है। हज़रत मूसा ने खासतौर से किसी प्रकार की मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया था। उनके द्वारा प्रतिपादित दस पवित्र आदेशों में से दूसरे में कहा गया है, 'तुम्हें अपने मालिक या ईश्वर की कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए।' आपका इस्लाम धर्म भी मूर्ति-पूजा के इसी घोर विश्वास तथा पवित्र आदेश का कठोरता से पालन करता है।

लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि आपके देश पाकिस्तान में आपने इस विश्वास का बहुत अधिक विस्तार किया है। इस विश्वास की परिणति दु:खद रूप से मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने के रूप में सामने आई है। आपके देश में 1947 में स्वतंत्रता के बाद से 75 से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया या उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। मैंने अपने विद्वान उर्दू शिक्षक से सुना था कि यह विश्वासी या 'मोमिन' के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि अविश्वासियों यानी 'काफिरों' द्वारा स्थापित मूर्तियों-'बुतों' को अपवित्र और नष्ट किया जाए। लेकिन हम दो पड़ोसी देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए आपकी जनता को इस प्रकार मूर्तियों को अपवित्र करने और मंदिरों को नष्ट करने के काम से बचना चाहिए था। मैं यह बात इस तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद कह रहा हूं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा या 'बुत परस्ती' के बजाय केवल विश्वास पर दृढ़ रहना या 'मजहब परस्ती' सिखाई जाती है। यह इस्लाम धर्म का संभवत: अभिन्न अंग है। लेकिन आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अन्य धर्म मानने वालों को भी अपने विश्वास का व्यवहार करने और पूजा करने का समान अधिकार प्राप्त है। हालांकि, अपने विश्वास का पालन करने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की भावनायें आहत न हों।

इस परिदृश्य में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखें तथा हमारे मंदिरों और मूर्तियों को पाकिस्तान में सुरक्षित बनाए रखने का निर्णय लें। आपकी पीढ़ी के राजनेताओं को इस बात से थोड़ा सहज अनुभव करना चाहिए कि भारतीय शांतिपूर्ण तथ काफी सीमा तक निष्क्रिय या उदासीन भी हैं। भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या मंदिरों और मूर्तियों के तोड़े जाने पर प्रतिक्रिया या कम से कम आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं करती है। दशकों पहले तक आम भारतीयों की यही मन:स्थित रही है, पर अब इसमें व्यापक बदलाव आ रहा है। आज भारत और भारतीय बदल रहे हैं। हमारी सभ्यतामूलक यात्रा में दिसंबर, 1992 में व्यापक और असली परिवर्तन आया है जिसका मैं सौभाग्य से एक विनम्र भागीदार रहा हूं। उस समय अपने नेताओं के मना करने के बावजूद उत्तेजित लोगों ने भगवान राम के जन्मस्थल पर बना मस्जिद का एक ढांचा ढहा दिया था।

भारत में हमने उन मंदिरों के पुन: निर्माण का अभियान चलाया है जो मध्ययुग में मूर्तिभंजकों का शिकार बने थे। इस संबंध में मैं जल्द ही अपने पूर्वी पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री बेगम शेख हसीना को भी पत्र लिखूंगा। उनके देश बांग्लादेश में भी हर साल दर्जनों मंदिर अपवित्र किये जाते हैं या उनको नष्ट कर दिया जाता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अच्छे पड़ोसियों को एक दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कृपया इस तथ्य को याद करें कि प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर उनके खंडहरों पर हजारों-हजार मस्जिदों का निर्माण भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और मध्ययुगीन इस्लामी शासकों के शासनकाल में हुआ है।

अब तक भारत में हमने सभी मामलों में कानूनी अदालतों के माध्यम से प्राचीन मंदिरों पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। भारत की जनता ने अपने मंदिरों पर अधिकार पाने के लिए एकपक्षीय कार्रवाई या हिंसक कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि आप पाकिस्तानी जनता तथा इस्लाम धर्मानुयाइयों को हिंसा करने से रोकें तथा अपने देश में हिंदू मंदिरों व मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कश्मीर में भी 130 से अधिक मंदिरों पर हमले किए गए और उनको अपवित्र किया गया। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि उस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण था। मैं जानता हूं कि हमारे द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने पर पाकिस्तान ने बहुत गुस्सा दिखाया था। लेकिन यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने अनेक वर्षों तक आतंकी हिंसा सहन की। लेकिन जब हम इसे सहने में विफल हो गए तो हमने संसद के रास्ते से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। लेकिन आपको निश्चित रूप से यह बात पसंद आएगी कि हमने कभी इस मुद्दे पर भी हिंसा नहीं की। खुशी की बात है कि भारतवर्ष के लगभग सभी मुस्लिम नागरिक कश्मीर में भी अधिकतम सीमा तक भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

दोराहे पर यूरोपीय संघ और चीन के रिश्ते

यह आवश्यक है कि वे बातचीत और परामर्श के माध्यम से आर्थिक और व्यापार घर्षणों को उचित रूप से संबोधित करें और एक-दूसरे की वैध चिंताओं को समायोजित करें।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भू राजनीतिक समायोजन, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से किया जा रहा है, यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों को शांत करने में व्यस्त हैं, जहां एक प्रमुख रैली एजेंडा चीन है। दो सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत और अमेरिका, दोनों के चीन के साथ अपने-अपने मुद्दे हैं, दुनिया भर में अब तक देखी गई कुछ सबसे प्रतिस्पर्धी चुनाव प्रक्रियाओं के बीच में हैं। इस बीच, यूरोपीय संघ, या कम से कम इसके कई सदस्य देश, अकेले ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगी, चीन के साथ उलझे हुए जाल को सावधानीपूर्वक पुन-व्यवस्थित कर रहे हैं।

यह कोई संयोग नहीं है कि चीनी प्रधान मंत्री शी जिनपिंग इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोप के तीन देशों के रणनीतिक दौरे पर थे। यह त्रि-राष्ट्र दौरा, जिसके दौरान चीनी प्रधान मंत्री ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी मुलाकात की, लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा है और यह वह समय भी है जब कई यूरोपीय देश अत्यधिक सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहे हैं। अपने बाज़ारों में, जिससे कई यूरोपीय ऑटो फैक्ट्रियां निरर्थक हो गईं।

यूरोपीय लोग इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में, पूरे क्षेत्र में ईंधन-सहायता प्राप्त मुद्रास्फीति को बढ़ाते हुए, चीन अपने सीमा रहित मित्रों रूस को स्थिर करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति के प्रेस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से उल्लिखित यूरोपीय लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जिसके लिए वे जाने जाते हैं, पहला विषय जिस पर हमने विचारों का आदान-प्रदान किया वह भूराजनीतिक स्थिति थी। हमने विशेष रूप से यूक्रेन और मध्य पूर्व में

संघर्ष पर चर्चा की। हम इस बात से सहमत हैं कि यूरोप और चीन का शांति और सुरक्षा में साझा हित है। हम चीन पर भरोसा करते हैं कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर अपने सभी प्रभाव का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति शी ने रूस के गैरजिम्मेदार परमाणु खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति शी रूस द्वारा जारी परमाणु खतरों की पृष्ठभूमि में ऐसा करना जारी रखेंगे। हमने रूस को कोई भी घातक उपकरण उपलब्ध नहीं कराने की चीन की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की है।% रूस को दोहरे उपयोग वाले सामानों की डिलीवरी को कम करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है जो युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं।

और यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए इस युद्ध से उत्पन्न खतरों की अस्तित्वगत प्रकृति को देखते हुए, यह यूरोपीय संघ-चीन संबंधों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ की ओर से चीन को संदेश था कि यूरोपीय धरती पर अन्यायपूर्ण युद्ध में रूस की मदद न करें, अन्यथा द्विपक्षीय संबंध संकट में पड़ जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं, त्रिपक्षीय बैठक के बाद चीनी टीम द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य के निचले तीन पैराग्राफ तक यूक्रेन और मध्य पूर्व का जिक्र नहीं था।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाषा में लिखा है, यूक्रेन संकट पर, राष्ट्रपति शी ने बताया कि चीन, फ्रांस और यूरोपीय संघ सभी शीघ्र युद्धविराम और यूरोप में शांति की वापसी चाहते हैं, और संकट के राजनीतिक समाधान का समर्थन करते हैं। चीन शांति के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए सख्ती से काम कर रहा है। चीन के उद्देश्यपूर्ण और उचित रुख और उसकी रचनात्मक भूमिका को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मान्यता दी गई है।

चीन संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में रहने के लिए तैयार है। इन वार्तालापों का अन्य महत्वपूर्ण तत्व व्यापार था, क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्ष ईंधन की बढ़ती लागत, अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल और, कोविड के बाद, आपूर्ति श्रृंखला बेमेल की बाधाओं को महसूस कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ ने अपनी बातचीत में चीनी सब्सिडी वाले उत्पादों, एक-दूसरे के बाजारों तक मुफ्त और निष्पक्ष पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर तीखे संकेत दिए। रक्षात्मक चीन ने कहा कि दोनों पक्षों के व्यापक साझा हित हैं और हरित एवं डिजिटल संक्रमण में सहयोग के लिए व्यापक गुंजाइश है।

यह आवश्यक है कि वे बातचीत और परामर्श के माध्यम से आर्थिक और व्यापार घर्षणों को उचित रूप से संबोधित करें और एक-दूसरे की वैध चिंताओं को समायोजित करें। चीन ने अपने कुछ सबसे बड़े बाजार साझेदारों को वापस लुभाने के लिए सही कदम उठाना शुरू कर दिया है, ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका, इंडो-पैसिफिक थिएटर में अन्य प्रमुख हितधारक, अपने चुनावों में व्यस्त हैं। भारत लगभग एक महीने में चुनाव से निपट लेगा, और एक चुस्त, चुस्त चीन नीति दृष्टिकोण की प्रतीक्षा है।

आप की बात

जनसंख्या संरचना

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जनसंख्या की अध्ययन रिपोर्ट जारी कर बताया गया है कि 65 वर्ष में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि 43 प्रतिशत है जबकि हिंदू समुदाय की जनसंख्या 8 प्रतिशत घट गई है। 2015 में मुसलमान कुल आबादी का करीब 14 प्रतिशत थे जबकि हिंदू समुदाय कुल आबादी का करीब 84 प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि 2011 में भारत में जनगणना हुई थी। इसके बाद 2021 में जनगणना कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। उम्मीद है कि नई सरकार जनगणना को प्राथमिकता देगी। विपक्षी नेताओं ने इस समय यह रिपोर्ट लाने पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वे 2015 के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, भाजपा के साक्षी महाराज, गिरिराज किशोर एवं अन्य ने इस पर चिन्ता जाहिर की है। उन्होंने मुसलमानो की बढ़ती जनसंख्या को भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करार दिया है। चुनावी माहौल में बेशक यह सियासत का मुद्दा हो, लेकिन राष्ट्र हित में एक व्यापक, विस्तृत एवं सर्व-स्वीकार्य जनसंख्या नीति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। सभी समुदायों में छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजे जाने चाहिए और इनको आर्थिक नीति का प्रमुख अंग बनाना चाहिए।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

चुनाव और अर्थव्यवस्था

भारत में हमेशा ही आम चुनाव के दूरगामी परिणाम होते रहे हैं जिससे न केवल राजनीतिक परिदृश्य बल्कि शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित होती रही है। दलाल स्ट्रीट से लेकर आम मजदूर तक हर कोई चुनाव के दौरान बड़ी बेचैनी अनुभव करता है। चुनाव अल्प अवधि में अस्थिरता लाते हैं पर उसके दीर्घकालिक प्रभाव मुख्य रूप से सत्तारूढ दल द्वारा लागू किए जाते हैं। सरकार की स्थिरता चाहे बहुमत के रूप में हो या गठबंधन के रूप में, निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में नीतिगत निरंतरता और आर्थिक सुधारों के कारण वर्तमान सरकार अच्छी स्थिति में है। भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा पिछले दस साल में दुनिया की सबसे बड़ी पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्वास है अगले पांच साल में वह विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में सफल होगा। लेकिन भारतीय मतदाताओं को खैरात बांट कर येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करने वाले दलों से सावधान रहना होगा। देश की आर्थिक प्रगति व भ्रष्टाचार-उन्मूलन से सारी जनता को लाभ होगा।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

रूस का बयान

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है कि अमेरिका भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह बयान ऐसे समय भारत-रूस दोस्ती का प्रतीक है, जब कनाडा, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में बैठे कुछ भारत-विरोधी तत्व भारत के लोकतंत्र की छवि खराब करने के प्रयास कर रहे हैं। रूस ने हमेशा भारत के साथ अपनी दिली-दोस्ती निभाई है और उसे सदाबहार बनाये रखा है। उसने दुनिया के किसी भी देश में व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मित्र भारत के लिए सदैव अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया है। आज भी उसने अमेरिका के खालिस्तानी मामले में दिए विवादित बयान के विरूद्ध भारत का पक्ष लिया है। रूस ने अपनी सूचनाओं के आधार पर भारत के मामले में अमेरिका को खरी-खरी सुना दी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान भारत में उन विपक्षी नेताओं के लिए सबक होना चाहिए जो भारतीय लोकतंत्र तथा भारत सरकार की विदेश नीति को पश्चिमी चश्मे से देखते हैं तथा अंध मोदी-विरोध के चलते सरकार की हर नीति पर शक करते हैं। रूसी बयान से भारतीय विदेश मंत्रालय की राजनयिक स्थिति निश्चित रूप से और मजबूत हुई है।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

विमान यात्रियों की पीड़ा

एयर इंडिया द्वारा दो-तीन दिनों से लगातार बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल करने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगे से महंगा किराया देकर यात्री अपने आवश्यक कार्य के लिए शीघ्र गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अधिक पैसा चुकाता है। इसके बावजूद फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलने पर वह मझधार में फंस जाता है। समय पर नहीं पहुंचने के कारण उसे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। टिकट के पैसे वापस कर देना कोई बड़ी बात नहीं हैं। हवाई कंपनियों को फ्लाइट निरस्त होने पर या 3 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखना चाहिए। पायलटों की हड़ताल से यात्रियों को बचाने के लिए समय रहते पायलटो की मांगों पर गंभीरता से विचार करके उनका समाधान होना चाहिए। आगे ऐसी स्थितियां नहीं बने, इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। फ्लाइट कैंसिल होने पर लोग एक्सप्रेस ट्रेनों की और रुख करते हैं मगर वहां भी जगह नहीं है। सरकार को देश की जनता की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चंदा लेने का आरोप

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस से देवेन्द्र पाल भुल्लर की रिहाई की एवज में 1.6 करोड़ डॉलर बतौर चंदा लेने का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना ने विश्व हिन्दू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया के साक्ष्य-आधारित आरोप के मद्देनजर एनआईए जांच की अनुशंसा की है। केजरीवाल पहले से ही आबकारी नीति मामले में जेल में हैं, जिसमें जमानत पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके एक दिन पहले जांच की सिफारिश की गई है। ताजा आरोप केजरीवाल के वर्तमान और भविष्य के लिए एक नये फंदे की तरह है। पंजाब के खालिस्तान आंदोलन के दौरान भुल्लर का रक्तरंजित इतिहास रहा है। वह खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा कुख्यात आतंकी है, जिसने दिल्ली की रायसीना रोड स्थित युवक कांग्रेस मुख्यालय के सामने 11 सितम्बर, 1993 को बम विस्फोट कर राजधानी को दहला दिया था। इसमें 11 लोग मौके पर ही मारे गए थे। जाहिर तौर पर यह मामला मौजूदा कानून के मुताबिक देशद्रोह की कोटि में आता है। ऐसे में चंदे का आरोप सिद्ध हो गया, जैसा कि उपराज्यपाल का मोंगिया के सुपुर्द किए साक्ष्यों के आधार पर दावा है, तो केजरीवाल राजनीतिक बियावान में जा सकते हैं। एक वीडियो में खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को यह कहते सुना-देखा गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार को 2014 से 2022 के दौरान खालिस्तान समर्थक समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली थी। फिर भी आप को इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। इसका मकसद आम चुनाव से केजरीवाल को दूर रखना है। उसे लगता है कि उपराज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें सांविधानिक एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। इस पद की व्यवस्था केंद्र-राज्य सरकारों के बीच समन्वयक एवं संकटमोचक दायित्व-पूर्ति के लिए की गई है। आप ने यह खुलासा नहीं किया है कि उसके आरोप का आधार क्या है? पर ऐसे गंभीर आरोप किसी भी पार्टी या सरकार की मुखिया के विरु द्ध लगे तो उसकी जांच की सिफारिश उपराज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है।

स्वरोजगार से बदलेगा जीवन

आरती कुमारी

बेरोजगारी अनेक समस्याओं की जड़ है। बेरोजगार युवा मानसिक तनाव की चपेट में आ जाते हैं। बहुत से युवा हताशा में नशे की लत के आदी बन जाते हैं। अकसर युवा भटक भी जाते हैं। कई बार वे आपराधिक दलदल में फंस जाते हैं। इसके कारण उनका जीवन तो नष्ट होता ही है, साथ ही परिवार की प्रतिष्ठा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। बेरोजगार युवकों द्वारा आत्महत्या करने के समाचार भी सुनने को मिलते रहते हैं।

बेरोजगारी के कारण

देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। इनमें निरंतर बढ़ती जनसंख्या प्रमुख है। इसके अतिरिक्त घटती कृषि भूमि, कुटीर उद्योंगों का निरंतर समाप्त होना, युवाओं का अपने पैतृक कार्यों से मोहभंग होना तथा राजकीय नौकरी पाने की इच्छा आदि भी बेरोजगारी में वृद्धि होने के कारण हैं। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व के परिदृश्य पर दृष्टि डालें, तो उस समय लोग स्वरोगार में ही लगे थे। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई, उससे तीव्र गति से रोजगार में गिरावट आई। शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य केवल राजकीय नौकरी प्राप्त करना हो गया। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई उस गति से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए। परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या दिन- प्रतिदिन बढ़ने लगी।

युवाओं को प्रशिक्षण

निःसंदेह जीवनयापन के लिए रोजगार अत्यंत आवश्यक है। रोजगार प्राप्त करने के लिए कुशल होना अति आवश्यक है। बेरोजगारी के साथ-साथ अकुशलता भी एक चुनौती बनी हुई है। जो युवा कुशल हैं, उन्हें कहीं न कहीं रोजगार मिल जाता है। किन्तु जो युवा अकुशल हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की इस समस्या को समझा। इसलिए उन्होंने युवाओं को कुशल करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रारंभ की। उन्होंने 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम पारिश्रमिक के समान या उससे अधिक मासिक पारिश्रमिक प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की क्रियान्वित की जा रही है। यह आजीविका प्रदान करने तथा निर्धनता कम करने का एक अभियान है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक भाग है। इससे ऐसे गरीब ग्रामीण युवा लाभान्वित हो रहे हैं, जो कुशल होना चाहते हैं। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है।

रोजगार के अवसर

भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र 'भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024' में कहा गया है कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तथा 14 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया गया है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इको सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वे स्टार्टअप का और अधिक विस्तार टियर-2 और टियर-3 शहरों में करेंगे। इसके अतिरिक्त देश को पर्यटन और सर्विसेज का वैश्विक केंद्र बनाएंगे, जिससे पूरे देश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

स्वरोजगार की महत्ता

स्वरोजगार का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे अनेक मामले देखने में आए हैं, जब उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। नौकरी में सीमित आय होती है, जबकि व्यवसाय के माध्यम से व्यक्ति अपार संपत्ति अर्जित कर सकता है। देश के अनेक लोग व्यवसाय के माध्यम से ही निर्धनता से निकलकर धनवान बने हैं। वास्तव में स्वरोजगार से जहां एक ओर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी ओर उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त होता है। इससे उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है। उनका रोजगार स्थायी होता है, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। इससे निर्धनता कम करने में भी सहायता मिलती है। वास्तव में निर्धनों को आर्थिक अवसरों की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए उनके कार्य क्षमताओं को विकसित करने के संबंध में भी अपार अवसर हैं। देश के जनसांख्यिकीय अधिशेष को एक लाभांश में विकसित करने के लिए सामाजिक एकजुटता के साथ ही मजबूत संस्थानों के एक नेटवर्क का होना अति आवश्यक है। भारतीय और वैश्विक नियोक्ता के लिए ग्रामीण निर्धनों को वांछनीय बनाने के लिए कौशल्य के वितरण के लिए गुणवत्ता और मानक सर्वोपरि हैं। इस योजना के अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं, जिनमें कौशल्य एवं नियोजन, अवसर पर समुदाय के भीतर जागरूकता पैदा करना, निर्धन ग्रामीण युवाओं की पहचान करना, परिक्षण व कार्य में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं को एकत्रित करना, युवाओं और उनके माता-पिता की काउंसिलिंग तथा योग्यता के आधार पर उनका चयन करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए ज्ञान, उद्योगों से जुड़े कौशल और मनोदृष्टि प्रदान करना, ऐसी नौकरियां प्रदान करना, जिनका सत्यापन स्वतंत्र जांच करने की विधियों से किया जा सके और जो न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक भुगतान करती हों आदि सम्मिलित है। यह नियुक्ति के बाद कार्यरत व्यक्ति को स्थिरता के लिए सहायक भी है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना युवाओं को प्रशिक्षण देगी, जिससे उनके करियर में प्रगति होगी। युवाओं का विकास होगा। बेरोजगारी के कारण होने वाले पलायन में कमी आएगी। यह राज्यों को कौशल्य परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए सक्षम बनाती है। इस योजना के कई विशेष घटक हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक रूप से वंचित समूह के अनिवार्य कवरेज द्वारा उम्मीदवारों का पूर्ण सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जाता है। धन का 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए और तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। उम्मीदवारों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन प्रतिरूप है। नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सरलीकरण एजेंसी के रूप में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राष्ट्रीय यूनिट ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्य करती है। यह योजना के राज्य मिशन कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान करती है और परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियां कौशल्य और नियोजन परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती है। यह योजना बाजार की मांग के समाधान के लिए नियोजन से जुड़ी कौशल्य परियोजनाओं के लिए 25,696 रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो परियोजना की अवधि और परियोजना के आवासीय या गैर आवासीय होने पर निर्भर करता है। योजना तीन महीने से लेकर 12 महीने तक के प्रशिक्षण अवधि की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान के घटक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 250 से अधिक व्यापार क्षेत्रों जैसे खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, मोटर वाहन, चमड़ा, विद्युत, पाइप लाइन, रत्न और आभूषण आदि को अनुदान प्रदान करता है। इसका एकमात्र अधिदेश है कि कौशल प्रशिक्षण मांग आधारित होना चाहिए और कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे में कुशल युवकों के लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। इस योजना का प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा उसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां प्रत्येक युवा अपने श्रम एवं कौशल क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। हम युवाओं को सीखते हुए कमाने के अवसर देने के लिए एनईपी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करेंगे। हम युवाओं को एनईपी और अन्य योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों की गारंटी देते हैं।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी !

अशोक भाटिया

भारत में पानी की बर्बादी पर लोग आम तौर पर परेशान नहीं होते हैं। शहर हो या गांव, हर जगह लोग पानी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन भारत में पानी की कमी कितनी भयावह हो सकती है इसका अंदाजा आप यूनेस्को की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। यूनेस्को की रिपोर्ट की मानें तो साल 2016 में धरती पर 9.33 करोड़ आबादी पानी के संकट से जूझ रही थी। उसके बाद कई देशों में जल-संकट काफी तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा ये भी किया गया है कि एशिया में लगभग 80 प्रतिशत आबादी जल संकट से जूझ रही है। यह संकट पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पारा 40 के पार पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप के कारण मुंबई को जलापूर्ति करने वाले जलाशय तेजी से सूख रहे हैं। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सातों झीलों का पानी जुलाई में खत्म हो जाएगा। झीलों में पानी का मौजूदा स्तर मुंबईकरों को चिंतित कर रहा है। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों में फिलहाल 16 फीसदी पानी बचा है और पिछले साल की तुलना में यह भंडार काफी कम है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन इसी तरह गर्मी जैसे हालात बने रहेंगे, जिसके चलते मुंबई में 15 से 20 फीसदी पानी की कटौती का संकट पैदा हो गया है। हालांकि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने लोगों को सांत्वना देते हुए कहा है कि शहर में जल आपूर्ति कर रहे सात जलाशयों का भंडार जुलाई के अंत तक रहेगा और निवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भी भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6 हजार घन मीटर थी जो साल 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा देश की बढ़ती आबादी भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में जल को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में लोगों को पीने का पानी तक ढंग से मुहैया करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जल को संरक्षित करने के किसी भी प्लान को बनाने के लिए सरकार के पास देश के सभी नदियों और जलाशयों का डेटा होना चाहिए। जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल वाटर रिसोर्सेज इनफॉरमेशन सिस्टम के पास जलाशय और नदियों का आंकड़ा तो मौजूद है लेकिन अलग-अलग शहरों के छोटी नहरों का कोई डाटा मौजूद नहीं है जिन्हें ग्रामीण भारत की जीवन रेखा माना जाता है और यही नहरें बाढ़ रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती हैं। इसके अलावा भारत में पानी के आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसियां राज्य स्तर पर हैं और ये राज्य इन डाटा को तैयार करने के विकेंद्रीकृत और लोकल मैकेनिज्म का उपयोग करती हैं।ऐसे में जल निकायों का प्रबंधन करने के लिए, हमें औपचारिक डेटा के साथ एकीकृत करने के लिए समुदायों के प्रासंगिक और पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी की कमी से जूझ रहा है। इस समस्या को समझते हुए विश्व में पानी की बर्बादी रोकने, महत्व समझने, संरक्षण करने और सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं और तरीके निकाले जाने जरुरी हैं। भारत में ज्यादातर जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं, नहर, नदियां सूखती और प्रदूषित होती जा रही हैं। ये जल संकट की ओर इशारा है, इसलिए इस स्थिति में जल्द से जल्द परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। शहरों में नहर होने के कई फायदे होते हैं ये नहर बारिश के पानी को संरक्षित करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है । सामान्य तौर पर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में बहुत सारी नहरें और छोटे- छोटे जलाशय बनाए जाते हैं। सूखाग्रस्त राज्यों में नहरों और छोटे छोटे जलाशयों का का मुख्य रूप से सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नहर का इस्तेमाल घरेलू उपयोग और मछली पालन के लिए भी किया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल निकायों की जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, जो देश में तालाबों, टैंकों, झीलों और जलाशयों का एक व्यापक डेटा बेस है। जनगणना के अनुसार भारत में तालाबों, टैंकों और झीलों जैसे 24.24 लाख जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं जबकि सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संख्या गणना के मुताबिक भारत में कुल 24.24 लाख जल संरचनाएं हैं, जिनमें से 97.1 प्रतिशत यानी 23.55 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9 प्रतिशत यानी 69,485 शहरी क्षेत्रों में हैं। इसी जनगणना के मुताबिक टैंकों की सबसे ज्यादा संख्या आंध्र प्रदेश में है, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संख्या झीलों की है। केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जलाशयों की गणना की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2023 के अप्रैल महीने में ट्वीट के माध्यम से ये लिखा था कि आगे चलकर राज्य में पानी का संकट सामने नहीं आए, इसके लिए राज्य की महायुति की सरकार कटिबद्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में ज्यादा जल निकाय बहुत छोटे हैं। भारत के अधिकांश जल निकाय एक हेक्टेयर से कम बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उनका पता लगाना और उन पर नजर रखना एक चुनौती बने रहने की संभावना है। उपग्रहों का उपयोग करके इन जल निकायों को मानचित्रित करने का तरीका भी काम नहीं कर सकता है, यही कारण है कि भू-आधारित ट्रैकिंग यानी जल शक्ति जनगणना की शुरुआत की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार कई जल निकायों का पानी इतना पुराना और इतना गंदा है कि उसे इस्तेमाल नहीं करने में वर्गीकृत किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में इजरायल ने बारिश के जल संचय के साथ पानी का बेहतर इस्तेमाल कर जल संकट की मुसीबत से छुटकारा पा लिया। भारत में वर्तमान में एक साल में जितनी बारिश होती है, अगर उसका संचय सही तरीके से किया जाए और नई तकनीक से उसे पीने के लायक बनाकर इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत हद तक समस्या कम हो सकती है। जरूरत है कि पानी को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों, तभी पानी हमारा 'जीवन रक्षक' बन सकेगा। चिंताजनक स्थिति यह भी है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या को साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के बहुत-से देशों में पेयजल का संकट है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। दुनिया के 2 से 3 अरब लोग साल में कम से कम एक महीने पानी की कमी से जूझते हैं। वर्तमान स्थिति में भारत भूजल का अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालांकि निकाले गए भूजल का सिर्फ 8 प्रतिशत पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी का 80 फीसदी भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। शेष 12 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में जल संकट की वजह यहां जरूरत से ज्यादा भूजल का दोहन है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानें तो देश में हर साल सिंचाई के लिए 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, इस कारण है कि कुछ राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती का तापमान जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही ऋतु-चक्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और पानी की किल्लत से परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल पिछले बीस सालों में धरती के बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों का असर और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के ऋतु-चक्र में 'अल-नीनो' का असर देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब है कि देश में बरसात कम हो रही है और गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूसरे देशों की तुलना में पानी की बर्बादी कहीं ज्यादा होती है। जल संकट की एक बड़ी वजह कारखानों के जहरीले पानी को पाइप के मदद से जमीन के अंदर पहुंचाना भी है। दरअसल भारत में तीन लाख से ज्यादा छोटे-बड़े बूचड़खाने हैं। इन कारखानों में हर दिन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। इसी तरह दूसरे देशों में भी बूचड़खानों के कारण करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। जल संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत सरकार की योजना के बारे में बताया जाता है कि इस समाया भारत में जल संरक्षण की चार योजनाए चल रही है 1। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 -2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3, जल शक्ति अभियान- 'कैच द रेन' अभियान 4, अटल भूजल योजना । पानी की किल्लत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया होने वाली है। जल संकट आने वाले समय में झगड़े-फसाद की वजह भी बन सकता है। जानकारों की मानें तो अगला विश्व युद्ध पानी के एकाधिकार को लेकर हो सकता है। बात भले ही हास्यापद लगे परन्तु बताया जाता है कि ग्रामीण महाराष्ट्र में कई लोगों ने दूसरी शादी इसलिए करते हैं ताकि एक पत्नी पानी लाए और पहली पत्नी घरेलू कार्य निपटा सके। इस टर्म को 'वाटर वाइफ' कहते हैं। अगर दूसरे राज्यों में भी ऐसे हालात हुए तो संभव है कि महाराष्ट्र का यह प्रयोग दूसरे राज्य के लोग भी करने लग जाए, जो आगे चलकर कई सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आज वर्क स्पेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें, और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज बिजनेस की प्रगति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे।

वृष राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन को दोहराने के लिए एकाग्रता बनाएं रखनी होगी। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, व्यापारिक योजनाओं को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें।

मिथुन राशिः आज आपका दिन घूमने-फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वाले आज आपको अच्छी राय देंगे। आज आप ऑफिस में किसी काम को आसानी से पूरा करेंगे, जिससे आपके जूनियर और सीनियर सभी तारीफ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथ ही आपकी रेस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। आज आपके व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे आपने माता पिता का ज्यादा ध्यान रखेंगें और बात भी मानेंगे।

सिंह राशिः आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। रुपए-पैसों के मामले में लापरवाही करने से आज आपको बचना चाहिए। टूर-ट्रेवल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में आप कुछ बदलाव करेंगे, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिल सकता है।

तुला राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखें। इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा। आज आप कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो और किसी की भावनाओं को भी ठेस न पहुचे।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। व्यापार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े-बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज आपको पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा।

धनु राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

मकर राशिः आज आपका दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा।

कुंभ राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा।

मीन राशिः आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आज आपके पारिवारिक रिश्तें में मधुरता बढ़ेगी।

भारत में रह खा कर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं नेताजी !

मनोज कुमार अग्रवाल

इन दिनों आम चुनाव का दौर चल रहा है चुनाव में सभी दलों द्वारा अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की जाती है । ऐसे भी बयान वीर नेता हैं जिनकी जहरीली बयान बाजी में देश के हितों के खिलाफ सुर निकलने लगे हैं तो ऐसे नेताओं को देश के नमक के साथ गद्दारी करने का खिताब दिया जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाला गुलाम कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा।' यह वाक्य दशकों से दोहराया जाता रहा है, अब भी दोहराया जा रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक चुनावी सभा में यही बयान दोहराया तो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को जैसे तन बदन में जलन लग गई। गुलाम कश्मीर संबंधी बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास परमाणु हथियार हैं।'यह बयान कोई पाकिस्तानी नेता ने नही भारत का नमक खाकर भारत में लम्बे अर्से तक सत्ता सुख और तमाम सुविधाओं का भोग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने दिया इस से अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है?

अब आपको देश की अस्मिता से जुड़े एक अन्य मामले में पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री के अत्यंत शर्मनाक बयान से रूबरू कराते हैं। आपको पता होगा अभी दो दिन पूर्व पुंछ में वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया और चार अन्य घायल हो गए। सेना पूरे क्षेत्र की तलाशी ले रही है और दो आतंकियों के स्कैच जारी कर उनकी जानकारी देने वालों के लिए 20 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को यह हमला 'चुनावी स्टंट' नजर आ रहा है। उन्होंने इस तरह का बयान दे कर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। आइए एक और सबसे जहरीली बयान बाजी से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं आप को याद होगा कि 2008 में मुंबई में ताज होटल पर घातक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें मुंबई की आतंकरोधी शाखा के प्रमुख हेमंत करकरे की जान भी चली गई थी। अब इस मामले को लेकर एक कांग्रेसी नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसमें एक शहीद की शहादत में भी राजनीति की एंट्री कर दी गई है। महाराष्ट्र के एक कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया है कि हेमंत करकरे आतंकी की गोली से नही शहीद हुए। इस नेता ने कहा है कि आतंकवादी अजमल कसाब ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने तत्कालीन आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे की हत्या की थी।यह तो घटिया राजनीति की चरम स्तर की गिरावट है। आखिर भारतीय राजनीति में पतन का यह दौर क्यों आ रहा है ऐसा कौन सा वोटर वर्ग है जो इस तरह के विवादास्पद बयान से खुश होता है जिस के वोट पाने के लिए नेताओं द्वारा इस तरह की बेहद शर्मनाक व देश के हित और स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने वाली बयान बाजी की जा रही है। दरअसल ये बयान ऐसे हैं, जिनमें पाकिस्तान का समर्थन करने की नीयत साफ नजर आती है। पहले फारूक अब्दुल्ला और बाद में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने जमकर कश्मीर की सत्ता की मलाई चट की है। उनके राज में कश्मीर में न केवल अलगाववाद चरम पर पहुंचा, बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का खुलेआम नरसंहार भी किया और रातोंरात मस्जिदों से माइक पर एलान कर घाटी के हिंदू पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया । इनके राज में कश्मीर में भारत की बजाय पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, देश की रक्षा करने वाले रक्षाबलों पर पथराव किया जाता था। लालचौक से लेकर स्टेडियम तक आतंकवाद के अड्डे बना दिये गये थे यह वही फारूक अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर 'चीन की मदद से उसे पुनः वापस लाने की बात कही थी। यह तथ्य देश में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वविदित है कि कश्मीर में आतंकी हमले पाकिस्तानी आतंकी करते हैं, ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी पाकिस्तानी आकाओं की हरकत पर परदा डाल कर उनकी तरफदारी करने वाला है, क्योंकि वह इसका इल्ज़ाम राजनीतिक लाभ के लिए अपने देश की सरकार पर ही थोप रहे हैं और अपने शहीद सैनिकों की शहादत पर सवाल खड़े कर रहे हैं।यह मानसिकता खतरनाक है। आपको याद होगा कि दिल्ली के जामिया नगर इलाक़े में 19 सितंबर, 2008 को एक मुठभेड़ के दौरान दो संदिग्ध आतंकवादी और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा की मौत हो गई थी. मारे गए संदिग्धों की पहचान आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद के रूप में हुई थी. बाद में दो संदिग्ध बाटला हाउस इलाके से गिरफ़्तार भी किए गए थे. उन दिनों दिल्ली पुलिस भी दिल्ली की कांग्रेस सरकार के अधीन थी लेकिन वोट की राजनीति के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। यही सिलसिला जारी है अब भी महाराष्ट्र के एक कांग्रेसी नेता जी कसाब की तरफदारी कर एक राष्ट्रवादी संगठन के सिर एक एटीएस अधिकारी का इल्ज़ाम मढने से नहीं चूक रहे हैं। पुलवामा हमले के समय भी शहादत पर इसी तरह की राजनीति की गई थी और अब फिर कांग्रेस नेता वैसी ही बात कर रहे हैं। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता वडेट्टीवार का है, जिसमें वे पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत को छिपाने के लिए आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। देश भूला नहीं है कि मुंबई के आतंकी हमले को किस तरह कांग्रेस नेताओं ने हिन्दू आतंकवाद का रूप देने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने तो भगवा आतंकवाद के नाम से किताब तक जारी कर दी थी।यह भारतीय राजनीति के ऐसे निर्लज्ज किरदार हैं जिन्होंने तमाम राष्ट्र की भावनाओं को आहत करते हुए पाकिस्तान परस्ती की मिसाल पेश की। ये दुश्मन की इस तरह बेशरमी से पैरवी करने वाले नेता भला देश का क्या भला करेंगे? केवल यही नहीं, देश को भीतर से तोड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं हम सत्ता में आए तो आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा ही हटा देंगे, जिसको जितना चाहिए, उसे उतना आरक्षण देंगे।' कौन नहीं जानता कि आरक्षण ने किस तरह देश को खोखला किया है, प्रतिभाओं का पलायन हुआ है, आरक्षण की आड़ में अनेक प्रतिभाओं से अवसर छीन लिए गए... फिर भी उसी आरक्षण को और बढ़ाने की बात देशहित में तो नहीं है। देश में अनेक तथाकथित सामाजिक संस्थाओं पर आरोप लगते रहते हैं कि वे विदेशी आकाओं से पैसे लेकर देश के विरुद्ध काम करती हैं। हाल ही में शिकंजे में आए न्यूजक्लिक के संस्थापक हों, आतंकी संगठन घोषित किए जा चुके पीएफआई के नेता हों, सीएए विरोधी दंगों के पैरोकार हों... सब पर ऐसे ही आरोप हैं। हद तो तब हो गई जब आम आदमी पार्टी भी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिक्ख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपये का लेने के आरोपों से घिर गई है। दिल्ली के राज्यपाल ने इसकी जांच एनआईए से कराने के आदेश दिए हैं।यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नयी मुसीबत साबित हो सकता है। लालच में कई लोग किस हद तक निम्न स्तर तक जा रहे हैं, यह देश की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत खतरनाक है, बल्कि अत्यंत निम्नस्तरीय राष्ट्रीय हित के विपरीत इस तरह की विध्वंसक व देश को तोड़ने वाली मानसिकता को समय रहते सख्ती से कुचला जाना चाहिए। सिर्फ एक खास समुदाय को प्रभावित करने के लिए उन्हें मुख्य धारा से अलग रखने के लिए कट्टरपंथी विचारों को बल देकर पाक परस्त सोच का संरक्षण और समर्थन करना देश द्रोह से कम नहीं है। देश की आम जनता को ऐसे राजनीतिक दलों व नेताओं का इस चुनाव में मतदान के जरिए पिंडदान कर देना चाहिए ताकि ऐसे घटिया मनोवृति वाले लोगों से राजनीति को कलुषित होने से बचाया जा सके।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

खुली जेल व्यवस्था

देशमें जहां एक ओर आबादी बढ़ी है तो दूसरी ओर आपराधिक घटनाओंमें वृद्धि हुई है लेकिन इसकी तुलनामें न तो जेलोंकी क्षमता बढ़ी है और न ही जेलोंकी स्थापनाएं हुई हैं। जेलोंमें क्षमतासे अधिक कैदियोंकी संख्या है। परिणामस्वरूप जेलोंकी व्यवस्था भी चरमरा गयी है। जेलोंमें सुधारके उपाय कम हुए हैं, परिणामस्वरूप जेलोंकी दशा अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इसी सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयने गुरुवारको खुली जेल व्यवस्थाको बढ़ावा देनेके बारेमें महत्वपूर्ण विचार किया है, जिसपर शासनको गम्भीरतासे चिन्तन करनेकी जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालयका कहना है कि खुली जेल व्यवस्थासे जेलोंमें कैदियोंकी बढ़ती समस्याका समाधान हो सकता है। साथ ही इससे कैदियोंके पुनर्वासके मुद्देका भी हल निकल सकता है। जेलों और कैदियोंसे सम्बन्धित एक याचिकापर गुरुवारको सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहताकी पीठका यह भी कहना है कि खुली जेल व्यवस्थाके तहत दोषियोंको दिनभर परिसरके बाहर कमाने और शामको जेलमें वापस लौटनेकी अनुमति दी जाती है। इस अवधारणाको दोषियोंको समाजसे जुड़ने और उनके मनोवैज्ञानिक दबावको कम करनेके लिए लाया गया था, क्योंकि उन्हें बाहर सामान्य जीवन जीनेमें कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। पीठ खुली जेल व्यवस्थाका विस्तार करना चाहती है, क्योंकि राजस्थानमें यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। सुनवाईके दौरान राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरणकी ओर पेश अधिवक्ताने बताया कि खुली जेल व्यवस्थाके बारेमें सभी राज्योंसे उनके विचार मांगे गये हैं। अबतक २४ राज्योंने अपने उत्तर प्रेषित किये हैं। इसीके साथ ही शीर्ष न्यायालयने देशमें यूनिफार्म ई-प्रिजन माड्यूलकी आवश्यकताके प्रति भी सहमति भी जताया है और कहा है कि इसके माध्यमसे समस्याओंको आसानीसे सुलझाया जा सकता है। वस्तुत: खुली जेल व्यवस्थाकी अवधारणा कोई नयी नहीं है। राजस्थानके पूर्व उत्तर प्रदेशमें भी डाक्टर सम्पूर्णानन्दके मुख्य मंत्रित्व कालमें खुली जेल व्यवस्था लागू की गयी थी लेकिन कालान्तरमें यह बंद कर दी गयी है। यदि राजस्थानमें यह प्रणाली ठीकसे काम कर रही है तो इसका विस्तार अन्य राज्योंमें भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही मौजूदा जेलोंकी व्यवस्था भी सुधारनी होगी। जेलोंकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि वहां कैदियोंको ठीकसे नहीं रखा जा सकता है। कैदियोंकी बढ़ती संख्याके सन्दर्भमें विचाराधीन कैदियोंके बारेमें भी प्रभावी कार्य योजना बनानी होगी। विचाराधीन कैदियोंकी संख्या कम नहीं है। इनसे सम्बन्धित मामलोंका त्वरित निस्तारण होना चाहिए। इससे कैदियोंकी संख्या कम हो जायगी, क्योंकि इनमें ऐसे भी कैदी हैं, जो निर्दोष हैं।

गलत खानपानसे बीमारियां

आजकलकी आधुनिक जीवनशैली, यांत्रिक संसाधनोंपर बढ़ती निर्भरता और गलत खानपानने देशमें गम्भीर बीमारियां और असामयिक मौतकी वृद्धिने चिन्ताजनक आंकड़े छू लिये हैं। इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशियनकी गुरुवारको जारी रिपोर्टमें चेतावनी दी गयी है कि भारतमें करीब ५० प्रतिशत बीमारियोंका कारण गलत खान-पान है। संस्थाकी गाइडलाइन है कि स्वस्थ जीवनशैली और पोषक तत्वोंसे भरपूर भोजनके सेवनसे ही गम्भीर बीमारियोंको रोका जा सकता है। नमक, तेल, चीनी और वसाका उपयोग कम करनेके साथ व्यायाम करनेकी सलाह दी है। प्रोटीन सप्लीमेण्ट और जंक फूडसे परहेज करें और खाना बनानेमें तेलका इस्तेमाल कमसे कम करें। यदि तेलका इस्तेमाल करना है तो सरसोके तेल इस्तेमालमें लायें। एक व्यक्तिको स्वस्थ रहनेके लिए दिनभरमें १२ सौ ग्राम खाना जरूरी है। भोजनमें सब्जियों और फलोंका दो भाग और बाकी एक भागमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शामिल हो। बच्चोंकी सेहतको लेकर संस्थाका शोध चौंकानेवाला है, जिसमें कुपोषण और मोटापाकी दोहरी स्थिति है। बाजारमें बिकनेवाले जंक फूड, फास्ट फूड खानेसे कम उम्रमें बच्चे ज्यादा वजन, मोटापा, डायबिटीजसे पीड़ित हैं। अधिक वजन और मोटापेकी समस्या हर उम्रके लोगोंमें गलत खान-पानकी वजहसे बढ़ रही है, जो अनेक जानलेवा बीमारियोंकी जननी है। यह सब कुछ जानते हुए भी हम खुद ही अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थोंको ही प्राथमिकता देते हैं। कुपोषण किसी व्यक्तिके पोषक तत्वोंके सेवनमें कमी, अधिकता या असन्तुलनके रूपमें परिभाषित करता है। भारत कुपोषणके इस दोहरे बोझका सामना कर रहा है। देशकी आबादीका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अति पोषणसे सम्बन्धित बीमारियोंसे ग्रस्त है तो दूसरी ओर अधिकांश आबादी अल्प पोषणसे ग्रस्त है। संयुक्त राष्ट्रकी रिपोर्टके अनुसार भारतमें अब भी २२ करोड़से ज्यादा लोग कुपोषित है। ऐसेमें पोषक तत्वोंसे भरपूर भोजनके प्रति मध्यम और उच्च वर्गको जहां जागरूक होना होगा, वहीं गरीबोंको सही पोषण मिले यह जिम्मेदारी सरकारकी है।

लोक संवाद

चुनावोंमें युवाओंकी भागीदारी

महोदय,-हालके वर्षोंमें कई शैक्षणिक और व्यावसायिक रूपसे योग्य लोगोंको राजनीतिमें प्रवेश करते देखा हैय उनमेंसे कुछ तो मंत्री भी बन गये हैं। लेकिन स्पष्ट रूपसे इस संबंधमें अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है। एक बड़ी निराशा एक निर्वाचन क्षेत्रमें लोगोंकी संख्याके साथ चुनाव-प्रचारकी उच्च लागत है। उम्मीद है कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्रोंके परिसीमनसे इस समस्याका कुछ समाधान सामने आयगा, जिसमें लगभग ५० प्रतिशतकी वृद्धि तय है। कोई भी सामान्य उम्मीदवार प्रति सीट लगभग दो मिलियन मतदाताओंको अपने पक्षमें करनेके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर सकता। केवल परिसीमन और बढ़ी हुई सीटोंसे चुनाव खर्चकी समस्याका समाधान नहीं होगा। अमीर उम्मीदवारोंके राजनीतिकी ओर आकर्षित होनेका एक और कारण यह पारम्परिक मान्यता है कि एक बार निर्वाचित होनेके बाद, उम्मीदवार चुनाव-प्रचारपर खर्च किया गया पैसा वापस पानेमें सक्षम होगा और उसके बाद बहुत पैसा कमायगा। एक बार जब भ्रष्टाचारके लिए दरवाजे बंद हो जायंगे तो अवसरवादियोंके लिए उम्मीदवार बननेका आकर्षण कम हो जायगा। यह बात पैसा कमानेके किसी भी नये रास्तेपर भी समान रूपसे लागू होती है। अनिवार्य मतदान न केवल प्रणालीको उन्नत करनेका, बल्कि चुनाव प्रचारकी लागतको कम करनेका भी एक तरीका है। इससे वोट बैंककी राजनीतिका चलन भी खत्म हो जायगा। उदाहरणके तौरपर एक समय था जब कुल मतदान ५० फीसदी या उससे भी कम होता था। इसलिए यदि उम्मीदवारके पास सुरक्षित वोट बैंक हो तो उसके लिए जीतना मुश्किल नहीं था। मतदानका प्रतिशत बढ़नेसे प्रतिबद्ध वोट बैंककी शक्ति और प्रभाव कम हो जाता है। मुफ्तखोरी लोकतंत्रमें चुनावकी प्रक्रियाको मतदाताओंको रिश्वत देनेके अलावा और कुछ नहीं देती। सवाल फिर वहीं है कि युवा अधिक संख्यामें चुनावोंमें भाग क्यों नहीं लेते। **-प्रफुल्ल गोराडिया, वाया ईमेल।**

मालदीवसे सतर्क रहनेका वक्त

सफलताके नशेमें चूर राष्ट्रपति मुइज्जूको यही लग रहा है कि उन्होंने इंडिया आउटका जो नारा दिया था, उसका असर संसदीय चुनावपर भी पड़ा है। लेकिन अमेरिकी फैक्टर सबकी आंखोंसे ओझल है। हिंद-प्रशांतमें क्षेत्रीय प्रभावको विस्तार देने और चीनको बेअसर करनेके लिए अमेरिकाने २०२३ में मालेमें दूतावास खोला था।

❐ **पुष्परंजन**

मोहम्मद मुइज्जूने चुनाव परिणामको 'सुपर मेजोरिटी' कहा है। दो लाख ८४ हजार ८८७ मालदीवियन वोटरोंमेंसे ८४.१४ फीसदीने संसदीय चुनावमें हिस्सा लिया था। मुइज्जूकी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने संसदकी ९३ सीटोंमेंसे ७१ पर फतह की है। पीएनसीके पास अपने गठबंधन दलोंके साथ कुल मिलाकर ७५ सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) पहलेकी ६५ सीटोंसे घटकर केवल १२ सीटोंपर रह गयी है। पीएनसीने ९० प्रत्याशी उतारे थे, जबकि एमडीपीने ८९ निर्वाचन क्षेत्रोंके लिए चुनाव लड़ा। १३० स्वतंत्र उम्मीदवारोंसे अलहदा जम्हूरी पार्टी (जेपी) के दस और डेमोक्रेट्सके ३९ कैंडिडेट्स थे। जीत-हारका फासला सुनकर हैरान होइयेगा। पचास-सौ वोटसे भारतके किसी गली-मोहल्ले और हाउसिंग सोसायटी चुनावमें लोग हारते-जीतते हैं। दुनिया मामून मालदीवकी विदेशमंत्री रह चुकी हैं। अहमद फारिस मामून उनके भाई हैं, जो कभी अर्थ मंत्रालय संभालते थे। पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूमकी दोनों संतानें इस बार चुनाव हार चुकी हैं। १९७८ से २००८ तीस सालतक अखंड राज किया था मामून अब्दुल गयूमने। उस कालखंडमें इनकी सन्तानोंके जलवे थे। जनमतकी ताकतने चमकते चांदको टूटा हुआ तारा बना डाला। यह बात सफलताके नशेमें चूर राष्ट्रपति मुइज्जूकी समझमें शायद देरसे आये। अभी सबको यही लग रहा है कि मुइज्जूने 'इंडिया आउट' का जो नारा दिया था, उसका असर संसदीय चुनावपर भी पड़ा है। बेशक पड़ा होगा। लेकिन अमेरिकी फैक्टर सबकी आंखोंसे ओझल है। इस परिणामसे अमेरिकाको भी झटका लगा है। अमेरिकी विदेश विभागने कहा कि हमने चुनाव परिणामोंपर बारीकीसे नजर रखी है। हमें यह सुनकर खुशी हुई कि पर्यवेक्षकोंने कोई बड़ा मुद्दा या अनियमितता नहीं बतायी है और नतीजे लोगोंकी इच्छाके अनुरूप हैं। हिंद-प्रशांतमें क्षेत्रीय प्रभावको विस्तार देने और चीनको बेअसर करनेके लिए अमेरिकाने २०२३ में मालेमें दूतावास खोला था। यूं तो अमेरिकाने मालदीवकी स्वतंत्रताके बाद १९६६ में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये थे। हिन्द महासागरमें अपनी रणनीतिक साझेदारीको विस्तार देनेके मकसदसे अमेरिकाने सितंबर, २०२० में मालदीवसे सुरक्षा सहयोगपर हस्ताक्षर किये थे तो क्या मालदीवमें अमेरिकी रणनीति विफल हो गयी। दिल्लीपर सवाल दरपेश करनेसे पहले इसपर भी विचार करनेकी आवश्यकता है। मालदीवने १९६५ में इसरायलके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। उस समय इसरायल, मालदीवको मान्यता देनेवाला तीसरा देश था और इसरायली राजदूत मालदीवके राष्ट्रपतिको अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करनेवाले पहले कूटनीतिक थे। २००९ में राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदके नेतृत्वमें मालदीवने इसरायलके साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृतिके क्षेत्रमें सहयोग समझौतेपर हस्ताक्षर किये। मालदीव इसरायली पर्यटकोंके बीच लोकप्रिय डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन गाजा युद्धके बाद सब कुछ बदल गया। वर्ष २०२३ में फिलीस्तीनके साथ एकजुटता दिखानेके लिए मालदीवमें इसरायल आउट जैसे प्रदर्शन आयोजित किये गये। मालदीवके सांसद सऊद हुसैनने इसरायली पासपोर्ट धारकोंको देशमें आनेपर प्रतिबंध लगानेके लिए संसदमें एक प्रस्ताव पेश किया था। साथमें इसरायली युद्धका समर्थन करनेवाली कम्पनियोंके बहिष्कारका आह्वान किया था। इन सबका फायदा मुइज्जूकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) को इस बारके संसदीय चुनावमें मिला है। भारतने जिस तरह नेतन्याहूके प्रति सहानुभूति दिखायी, उसने भी चुनाव प्रचारके समय पीपुल्स नेशनल कांग्रेसके लिए ईंधनका काम किया था। पीएनसीकी विजय और मुख्य विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की पराजयके पीछे पंचतंत्रकी तरह कहानीके पीछे कहानियोंके जाल बिछे हैं। इस समय सबसे गदगद चीन है। चीनी विदेश मंत्रालयके प्रवक्ता वांग वेनबिनने सोमवारको एक संवाददाता सम्मेलनमें कहा, 'हम सफल संसदीय चुनावोंके लिए मालदीवको बधाई देते हैं और मालदीवके लोगोंकी पसंदका पूरा सम्मान करते हैं। हमें साझा भविष्य तय करना है। मालदीवके साथ काम करनेको हम तैयार हैं।' अब जिस तरह मालदीवियन संसद 'मजलिस' में सुपर मेजोरिटी मुइज्जूकी पार्टीको हासिल हुई है, चीनके सोये अरमान जग चुके हैं। शिन्हुआ विश्वविद्यालयमें राष्ट्रीय रणनीति अनुसंधान विभागके निदेशक कियान फेंगने कहा, 'चुनावसे पहले, विपक्षी दलने संसदको नियंत्रित किया था, इसलिए मुइज्जूके राष्ट्रपति पदको काफी दबाव और चुनौतियोंका सामना करना पड़ा था। अब हासिल चुनावी जीत मुइज्जूको काफी मजबूत करती है, जो उनकी वर्तमान घरेलू और विदेशी नीतियोंके सुचारु कार्यान्वयनके लिए फायदेमंद है।' थिएनक्वांगछिंग चाइनिज अकादमी आफ सोशल साइंसमें सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उनके बयानपर गौर करें तो चीनी मंशा साफ हो जाती है। थिएनक्वांगछिंगने कहा, 'आकार और जनसंख्याके मामलेमें एक छोटे राष्ट्रके रूपमें मालदीवकी प्राथमिक चिन्ताएं स्वतंत्रता बनाये रखना और आर्थिक विकासको बढ़ावा देना है। मालदीवमें भारतकी सैन्य उपस्थिति देशकी स्वतंत्रता और सम्प्रभुताके लिए खतरा है। मुइज्जूका अभियान आर्थिक विकासपर काफी हदतक केन्द्रित है। यह चुनाव राष्ट्रपतिके विकास एजेंडेके लिए जनताके समर्थनको दर्शाता है।' मतलब साफ है कि चीनी बन्दूक प्रेसिडेंट मुइज्जूके कंधेपर है। वह संसदमें मालदीवके आर्थिक विकासके नामपर 'वन बेल्ट रोड इनीशिएटिव' की कई सारी लंबित योजनाएं पास करायंगे। संसदसे रक्षा समझौतोंकी पुष्टि करायंगे। इस इलाकेमें भारतके रणनीतिक असरको कैसे कम करना है, उसकी कवायद शुरू हो जायगी। इसे काउंटर करनेके लिए भारतको क्या करना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है। मालदीव भौगोलिक रूपसे एक ओर अदनकी खाड़ी और पश्चिमी हिन्द महासागरके होर्मुज जलडमरूमध्यके चोकप्वाइंटपर टिका है, दूसरी ओर पूर्वी हिंद महासागरके मलक्का जलडमरूमध्यके चोकप्वाइंटके बीच एक टोल गेटकी तरह अवस्थित है। ऐसे सामरिक महत्वके मुल्ककी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते। भारत और मालदीवके बीच ५४५ नॉटिकल माइल्सवाली समुद्री सीमाको एक द्विपक्षीय समझौतेके माध्यमसे सीमांकित किया गया था, जिसपर २८ दिसंबर, १९७६ को हस्ताक्षर किये गये थे और ८ जून, १९७८ को लागू हुआ था। हमारी प्राथमिकता सतर्कता गयी, दुर्घटना हुई वाली स्थितिसे बचनेकी होनी चाहिए। यूं तो भारतने अपनी सैन्य क्षमताको उन्नत करनेके लिए लक्षद्वीप द्वीप समूहमें एक नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु स्थापित किया है। यह बेस मालदीवका निकटतम नौसैनिक अड्डा होगा। लेकिन इसे काफी नहीं माना जा सकता।

मालदीव एक ओर अदनकी खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागरके होर्मुज जलडमरूमध्यके चोकप्वाइंटपर टिका है। दूसरी ओर पूर्वी हिंद महासागरके मलक्का जलडमरूमध्यके चोकप्वाइंटके बीच अवस्थित है। भारत और मालदीवके बीच ५४५ नॉटिकल माइल्सवाली समुद्री सीमाको एक द्विपक्षीय समझौतेके माध्यमसे सीमांकित किया गया था, जिसपर २८ दिसंबर, १९७६ को हस्ताक्षर किये गये थे और ८ जून, १९७८ को लागू हुआ था। भारतने लक्षदीप द्वीप समूहमें एक नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु स्थापित किया है। यह बेस मालदीवका निकटतम नौसैनिक अड्डा होगा।

भारतकी कुरबानियां भूला बंगलादेश

हिन्दुस्तानके फजलसे वजूदमें आया बंगलादेश भी भारत विरोधी देशोंकी फेहरिस्तमें शामिल हो गया है। हालमें मालदीवकी तर्जपर बंगलादेश नेशलिस्ट पार्टीके रहनुमाओंने 'इंडिया आउट' का नारा देकर भारतीय उत्पादोंके बहिष्कारकी आवाज बुलंद की है। भारतके रहमो-करमपर पलनेवाले मुल्क बंगलादेशमें भारत विरोधी आवाज चिन्ताजनक है।

❐ **प्रताप सिंह**

'ईस्ट पाकिस्तानकी हरियालीको लाल रंगसे रंग दिया जायगा'। ये अल्फाज सन् १९७१ में पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला लोगोंके सामूहिक कत्लेआमको अंजाम देनेवाले सैन्य आपरेशन 'सर्च लाइट' का 'कोडवर्ड' थे। इन अल्फाजका जिक्र सर्च लाइट मंसूबेके मास्टरमाईंड एवं पाकिस्तानी सेनाके मेजर 'राव फरमान अली' की डायरीमें मौजूद था। सन् १९७१ की जंगमें पाकिस्तानको तकसीम करके भारतीय सेनाने ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों सहित राव फरमान अलीको भी युद्धबंदी बनाकर हिरासतमें ले लिया था। जिस रफ्तारसे भारत आलमी सतहपर आर्थिक महाशक्ति तथा सैन्य कुव्वतके तौरपर उभर रहा है। कई मुल्क भारत विरोधी हिकारतका शिकार हो रहे हैं। हिंदुस्तानके फजलसे वजूदमें आया बंगलादेश भी भारत विरोधी देशोंकी फेहरिस्तमें शामिल हो गया है। हालमें मालदीवकी तर्जपर बंगलादेश नेशलिस्ट पार्टीके रहनुमाओंने इंडिया आउटका नारा देकर भारतीय उत्पादोंके बहिष्कारकी आवाज बुलंद की है। हालांकि बंगलादेशकी वजीरे आजम मोहतरमा शेख हसीनाने २६ मार्च २०२४ को अपने मुल्कके यौम ए तासीसके मौकेपर हिंदोस्तानकी मुखालफत करनेवाले लोगोंको तल्ख तेवर जरूर दिखाये थे परन्तु भारतके रहमो करमपर पलनेवाले मुल्क बंगलादेशमें भारत विरोधी आवाज चिन्ताजनक है। दिसंबर १९७१ से पहले बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानके रूपमें पाकिस्तानका हिस्सा था। पाकिस्तानके फौजी हुक्मरानोंके जुल्मोंसितमसे परेशान हो चुकी बंगला आवाम अपने लिए एक आजाद मुल्कके तौरपर जीना चाहती थी। परन्तु पाकिस्तानी तानाशाह याहिया खानके आदेशपर पूर्वी पाकिस्तानके सैन्य कमांडर टिक्का खानने बंगला आवामकी आजादीकी आवाजको खामोश करनेके लिए २५ मार्च १९७१ को आपरेशन सर्च लाइटके तहत बंगला लोगोंका नरसंहार करके बर्बरताकी सारी हदें पार कर दी थीं। पाकिस्तानी सेनाने आधी रातको ढाका विश्वविद्यालयपर हमला करके सैकड़ों छात्रों एवं प्रोफेसरोंका कत्ल कर दिया था। आपरेशन सर्च लाइटमें पाकिस्तानी सेना द्वारा कत्लोगारतकी हकीकतको ब्रिटेनके अखबार 'संडे टाइम्स' में पत्रकार 'एंथनी मैस्करनेहास' ने अपने आर्टिकलके जरिये जब आलमी सतहपर पेश किया तो हलाकतके उस खौफनाक मंजरसे आहत होकर अमेरिकाकी टाइम मैगजीनने टिक्का खानको 'बूचर ऑफ बंगलादेश' कहा था। सन् १९७१ की जंगकी वजह तथा पाकिस्तानका दो टुकड़ोंमें तब्दील होनेका कारण टिक्का खानका जहालतभरा आपरेशन सर्च लाइट ही बना था। परन्तु पाकिस्तानके हुक्मरानोंने बंगलादेशको रक्तरंजित करनेवाले कुख्यात टिक्का खानको मार्च १९७२ में पाकिस्तानी सेनाका चार सितारा जरनैल बनाया था। मानवताको शर्मशार करनेवाले आपरेशन सर्च लाइटकी बर्बरतासे बंगला लोगोंको बचानेके लिए भारतीय सेना सरहदोंकी बंदिशोंको तोड़कर पूर्वी पाकिस्तानमें दाखिल हुई। वीरभूमि हिमाचलके रणवांकुरोंसे सुसज्जित 'तीन डोगरा' बटालियनने सन् १९७१ की जंगमें बंगलादेशके महाजपर चौड़ाग्राम एवं काठियाचोर तथा चटगांव क्षेत्रोंकी लड़ाईमें पाकिस्तानी सेनाको धूल चटाकर घुटने टेकनेपर मजबूर कर दिया था।

डोगरा सैनिकोंके जोरदार हमले एवं संगीनोंसे पाकिस्तानी फौजकी हलाकतसे बेबस होकर पाकिस्तानी सेनाके ब्रिगेडियर 'एएमके मलिक' ने अपने ब्रिगेडके साथ तीन डोगरा बटालियनकी एक कम्पनीके सामने आत्मसर्मपण कर दिया था। युद्धमें पाकिस्तानी सेनाके मंसूबोंको ध्वस्त करके दास्तान ए शुजातका परिचय देनेवाले तीन डोगराके मेजर 'अनूप सिंह गहलोत' को 'महावीर चक्र' (मरणोपरांत) तथा हवलदार 'रमेश कुमार' एवं 'खुशाल चंद' दोनोंको 'वीर चक्र' (मरणोपरांत) से अलंकृत किया गया था। पूर्वी पाकिस्तानमें जिल्लतभरी शिकस्तसे बौखला कर जनरल 'नियाजी' के सलाहकार राव फरमान अलीके इशारेपर पाकिस्तानी सेनाने १४ दिसंबर, १९७१ को बंगला लेखकों, डाक्टरों, रजाकारों, शिक्षकों, वकीलों तथा बुद्धिजीवी वर्गके सैकड़ों लोगोंको मौतके घाट उतार दिया था। उस नरसंहारकी यादमें बंगलादेश १४ दिसंबरको 'बुद्धिजीवी दिवस' के तौरपर मनाता है। ढाकामें मौजूद 'शहीद बुद्धिजीवी स्मारक' पाकिस्तानी सेना द्वारा कत्लेआमकी दास्तांको बयान करता है। पूर्वी पाकिस्तानकी आवामने अपने मुल्ककी आजादीका एक मुद्दतसे जो पुरनूर ख्वाब देखा था, उसे भारतीय सेनाके ३८४५ जांबाजोंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर मुकम्मल किया था। युद्धमें बलिदान देनेवाले १९५ शूरवीरोंका संबंध हिमाचलसे था। भारतीय सेनाने पूर्वी पाकिस्तानको आजाद कराकर नये मुल्कको बंगला जुबानके नामपर बंगलादेश बनाकर बंगला लोगोंको ही सौंप दिया था। अत: बंगलादेशको भारतीय सैनिकोंकी कुर्बानियां याद रखनी होंगी। अंग्रेजों द्वारा बंगालके विभाजनसे आहत होकर अपने सूबेमें एकताका माहौल कायम रखनेके लिए रविंद्रनाथ टैगोरने सन् १९०६ में 'आमार सोनार बांग्ला' नामक गीतकी रचना की थी। बंगलादेशकी हुकूमतने आजादीके बाद सन् १९७२ में उस नगमेंको अपना कौमी तराना तसलीम कर लिया था। आज चीनके इशारेपर बंगलादेशके सियासतदान भारतका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब बंगलादेशने सन् १९७२ में 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में सदस्यताके लिए आवेदन किया था तो चीनने उस आवेदनपर 'वीटो' करके विरोध जता दिया था। पूर्वी पाकिस्तानमें सर्च लाइट मंसूबेके तहत ज्यों ही बंगला लोगोंका कत्लेआम शुरू हुआ। भारतीय सेनाने सिपुर्दे ढाकाकी तहकीकात शुरू कर दी थी। परन्तु पाकिस्तानकी तारीखको शर्मशार करनेवाला दिन १६ दिसंबर १९७१ मुकर्रर हुआ था। अलबत्ता भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तानमें दखलंदाजी न करती तो पाकिस्तानके सिपाहसालार टिक्का खान तथा राव फरमान अलीका बंगलादेशकी हरियालीको लाल करनेका मंसूबा 'सर्च लाईट' मुकम्मल हो जाता। यदि वर्तमानमें बंगलादेश महफूज है, वहां जम्हूरियत कायम है, बंगलादेशी लोग अपने मुल्कका यौम ए तासीस पूरे जश्नसे मनाते हैं तो इस आजादीके लिए बंगलादेशकी आवाम को भारतीय सेना का मरहून ए मिन्नत रहना होगा।

आत्मबोध

जीवनमें संतुलन

❐ **जग्गी वासुदेव**

हमें चीजोंको उसी तरह देखना चाहिए, जैसी वे वास्तवमें हैं। आपको धारणा बनानेकी आदत छोड़नेकी कोशिश नहीं करनी है, बस धारणा बनाइये ही नहीं। राय या धारणा एक कल्पना है। मैं किसी व्यक्तिकी ओर देखकर सोचूं, अरे, यह तो बहुत बुद्धिमान है या यह मूर्ख है, यह अच्छा है या यह बुरा है। ये सब कल्पनाएं है। क्यों न हम कल्पना किये बिना यूं ही देखें। लोगोंको कम उम्रमें ही यह गुण अपने अन्दर पैदा करना चाहिए। यदि आप धारणा नहीं बनाना चाहते तो आपको अपने मनमें एक खास संतुलन लाना होगा। सिर्फ वही मन साफ-साफ देख पाता है, बाकी सभीमें बस धारणा और विचार भरे हुए हैं। वे वास्तविकताको नहीं देख पाते। या तो आप चीजोंको उस तरह देखते हैं, जैसी वे वाकई हैं या आप अपने दिमागमें कल्पनाएं कर रहे हैं। आपका दिमाग कल्पना करनेके लिए नहीं है। आपके अन्दर बुद्धि धारणा बनानेके लिए नहीं है। आपको ऐसी बुद्धि मिली हुई है कि आप चीजोंको उनकी सतहसे परे देख सकते हैं। आप चीजोंको उनकी वास्तविकतामें देख सकते हैं, न कि जैसी वे ऊपरी तौरपर हैं। इनसानी बुद्धिका यही मतलब है। बुद्धि भेदनेवाली होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। आपकी राय काल्पनिक होती है। जिस पल आप किसी चीजको अच्छा और दूसरी चीजको बुरा समझते हैं, सब लोग किसी न किसी श्रेणीमें आ जाते हैं। आपको समझना होगा कि हर जीवन अपने आपमें अनूठा है। कोई किसी श्रेणीमें नहीं आता। यदि आप जान जायं कि अपने आसपासके हर जीवन रूपके अनूठेपनको कैसे पहचानना है तो आप देख पायंगे कि हर जीवन कितना असाधारण है। आपको थोड़ा-सा समय किसी भी जीवनपर ध्यान देते हुए बिताना चाहिए, इनसानोंको छोड़कर। वह कोई चींटी भी हो सकती है। मैंने चींटियोंको ध्यानसे देखनेमें काफी समय बिताया, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने चींटीको ज्यादा ध्यानसे देखा तो मुझे पता चला कि वह धरतीपर मशीनरीके सबसे शानदार नमूनोंमेंसे एक है। आप इस अस्तित्वमें एक बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, यदि आप यह जानते हैं तो आप धारणा नहीं बनायंगे। यदि आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं तो आपका धारणा बनाना स्वाभाविक है। यदि आप हर जीवनपर पर्याप्त रूपसे ध्यान देंगे तो आप इस अस्तित्वमें हर जीवनकी अहमियत जान जायंगे। धरतीपर अलग-अलग जीवन रूपोंकी अहमियतके क्रममें हम सबसे नीचे हैं, परन्तु हम खुदको बहुत ऊंचा समझते हैं। जब आप खुदको बहुत अहम समझने लगते हैं तो आप सिर्फ धारणा ही बनायंगे।

जलवायु संकटसे जीवन रक्षाका अधिकार

❐ **प्रोदिप्तो घोष**

सर्वोच्च न्यायालयने हालमें संविधानके अनुच्छेद १४ (समानताका अधिकार) और अनुच्छेद २१ (जीवन एवं आजादीकी सुरक्षा) के दायरेको विस्तार देते हुए स्वतंत्रताके अधिकार या जलवायु परिवर्तनके विपरीत प्रभावोंसे सुरक्षाकी आजादीको मान्यता दी है। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट हो कि आखिर अधिकारका अर्थ क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया वह दावा है (जैसे कि महिला, एलजीबीटीक्यूआई, इत्यादि) जिसकी अहमियत इसकी कीमतों और फायदोंसे कहीं ऊपर होती है। विभिन्न गैसोंके वैश्विक उत्सर्जन, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, इनकी वजहसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे प्रभावका विकासशील मुल्कोंके अपने उत्सर्जनसे संबंध कम ही है। इनकी सरकारें अपने तौरपर वैश्विक स्तरके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनको सीमित करनेमें कुछ अधिक नहीं कर सकतीं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मतिकी जरूरत है, इस दिशामें अपेक्षित चाल १९९२ से ही धीमी है, जब संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) नामक प्रस्ताव अपनाया गया था। यूएनएफसीसीसी मानता है कि जलवायु परिवर्तनके कारकोंको थामने, उत्सर्जन घटाने और प्रभावोंको कम करनेमें विकसित मुल्कोंके पास अधिक क्षमता है, इसे 'सामान्य किन्तु अन्तर लानेवाली जिम्मेवारी' नामक सिद्धांतके तौरपर जाना जाता है। पेरिस संधि २०१५ के ध्येयोंपर अमल फिलहाल शोचनीय रूपसे बहुत कम है, जिसके अंतर्गत वैश्विक औसत तापमानमें वृद्धि स्वीकार्य सीमा १.५ डिग्री सेल्सियसके भीतर बनाये रखना है। लेकिन यह न होनेपर, वास्तविक धरातलपर इसके प्रभाव स्वरूप मौसममें तीव्र बदलाव बढ़ते जा रहे हैं। इन परिस्थितियोंमें, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव भारतपर भी प्रभाव पड़ रहे हैं और अधिकांशत: इसके पीछे जिम्मेदार विकसित देशोंके कारनामे हैं, क्या एक आम नागरिक इस जलवायु परिवर्तनसे आजादीका हक पानेका दावा कर सकता है। तर्कके आधार कर कहें तो समस्याका मुख्य जिम्मेदार विकसित देशोंका समूह है।

अबतक, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन संधियां विकासशील राष्ट्रोंको सुधारक उपाय अपनानेके हेतु बहुत कम धन उपलब्ध करवा पायी हैं। इसलिए तो क्या सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेका अर्थ है कि लागत चाहे कितनी भी हो, भारतीय सरकारको पर्यावरणमें सुधारके उपाय करने ही होंगे। इस अधिकारकी अन्य अवधारणा है स्वतंत्रताका अधिकार बनाम भलाईका अधिकार। जीवनका अधिकार, अभिव्यक्तिकी आजादी इत्यादि स्वतंत्रताके अधिकारमें आते हैं। शिक्षाका अधिकार, जलवायु परिवर्तनसे निजातके अधिकार सहित साफ-सुथरा पर्यावरण पानेके हकको भलाई अधिकारोंमें गिना जाता है। स्वतंत्रता अधिकारमें केवल जरूरत है अन्य कोई इनका उल्लंघन न करने पाये जबकि भलाई अधिकार वह हैं जिसकी प्राप्ति करनेमें तदनुरूप कर्तव्योंपर उद्देश्यपूर्ण कारवाईकी जरूरत होती है। स्वतंत्रता अधिकारोंको लागू करनेमें अधिकांशत: बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगती। लेकिन कल्याण अधिकारोंको मूर्त रूप देनेमें सामान्यत: बहुत बड़े स्तरपर संसाधनोंकी आवश्यकता पड़ती है। किन्तु जब संसाधन पहलेसे कम पड़ते हों, जैसा कि विकासशील मुल्कोंमें होता है, तब चुनाव करते वक्त विभिन्न अन्य कल्याण अधिकारोंको तरजीह देनी पड़ती है।

अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तनके प्रभाव कम करनेमें बहुत ज्यादा धनकी जरूरत पड़ती है। विकसित देशोंकी ओरसे विशाल मात्रामें अंतरराष्ट्रीय मदद राशिकी अनुपस्थितिके मायने हैं कि भारत सरकारको अपने संसाधन जुटाकर इस समस्याका हल निकालना पड़ेगा। यदि सरकारको अन्य विभिन्न कल्याण अधिकार भी सुनिश्चित करने हैं तो सीमित संसाधनोंके चलते प्रत्येक मामलेमें प्राप्ति आंशिक ही होगी। लगातार बदलते अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन नियमोंके तहत पर्यावरण अधिकारकी सम्पूर्ण प्राप्तिको जरूरत है विकसित देशोंसे नवीन एवं अतिरिक्त संसाधन विकासशील मुल्कोंको दिये जाने की। लेकिन इस किस्मके संसाधन मिलनेकी संभावना बहुत क्षीण है। वर्ष २००५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त धनसे पर्यावरण संबंधित प्रभावोंपर एक अध्ययन हुआ था। इसके उद्देश्योंमें योजनाएं एवं निवारण कार्यक्रमका सुझाव देनेके अलावा जलवायु परिवर्तनके प्रभावसे बनी स्थितिमें राहत उपाय (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, वानिकी, चक्रवात शरणस्थली) की शिनाख्त करना और उनपर होनेवाले खर्चका अनुमान देना था। इसके निष्कर्ष चौंकानेवाले थे, भारतके सकल घरेलू उत्पादका लगभग १.८ प्रतिशत इस किस्मके कार्यक्रमोंके ऊपर खर्च हुआ था, यह व्यय भारतके रक्षा बजट जितना था। हो सकता है बादमें यह मात्रा और बढ़ गयी हो। अतएव क्या जलवायु परिवर्तनसे आजादीके अधिकारको मान्यता देनेकी व्यावहारिकतामें काफी उलझने हैं। साफ तौरपर बाहरी स्रोतोंका प्रभाव, यदि कोई है तो वह बहुत कम होगा। जलवायु परिवर्तनके प्रभावोंका जोखिम कम करनेमें होनेवाले खर्चके ऐतिहासिक स्तरके मद्देनजर लगता नहीं कि जलवायु परिवर्तन अधिकारको मूर्त रूप देनेके लिए सकल घरेलू उत्पादके अंशमें वृद्धि करनेकी गुंजाइश है। तथापि जैसा कि देशकी अर्थव्यवस्थामें वृद्धि हो रही है, समस्त संसाधनोंका स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही नागरिकोंकी आय बढ़नेपर, वे जलवायु प्रभावके परिणामोंसे बचनेको निजी तौरपर अधिक खर्च कर पायंगे, मसलन सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य देखभालपर अधिक खर्च, जल-संचयन और अतिशयी आपदाओंके सन्दर्भमें बीमा करवाना इत्यादि। कुल मिलाकर जैसे-जैसे देशकी अर्थव्यवस्थामें वृद्धि होगी वैसे-वैसे जलवायु परिवर्तनके प्रभावसे नागरिकोंका जोखिम कम होता जायगा। इस असरसे मुक्ति पानेमें विकास एक चाबी है। कदाचित सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेका मुख्य आशय जलवायु संबंधी जोखिमोंसे बचाव करनेपर खर्चमें कटौतीकी भावी संभावनाको खत्म करना है।

सर्वोच्च न्यायालयका फैसला उस याचिकाके संदर्भमें आया है जिसमें राजस्थान और गुजरातमें संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (तिलोर) पक्षीके अभयारण्य स्थलसे होकर गुजरनेवाली अक्षय ऊर्जाकी बिजली तारोंको जमीनके नीचे डालनेका फैसला देनेके खिलाफ अपील लगायी गयी थी। ऊंचे खम्भोंके माध्यमसे लगी बिजली आपूर्ति तारोंसे टकरा कर बड़ी संख्यामें पक्षी मारे जाते हैं। बिजली कम्पनियोंकी दलील है कि इसमें बहुत खर्च आयगा और अक्षय ऊर्जाकी दरें प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहेंगी। जलवायु सतत्ताका अधिकार और ग्रीन हाऊस गैसोंका उत्सर्जन घटानेमें भारतकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारीका निर्वहन इस मामलेमें परस्पर विरोधाभासी है। यदि इस योजनाको जारी रखें तो संकटग्रस्त पक्षीकी प्रजाति को बचाना कठिन हो जायगा। अदालतका सुझाव है कि व्यावहारिक हल निकालनेके लिए विशेषज्ञ अध्ययन करवाया जाय। यदि रास्ता निकलता है तो बहुत बढ़िया वर्ना शायद नीति अनुसंधान संस्थान इस मुश्किल दुविधाका हल निकालनेमें मददगार हो पाये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 73

संतुलनकारी कदम

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पांच वर्षों में जब पहली बार यूरोप की यात्रा की तो व्यापार और यूक्रेन के मुद्दे एजेंडे में शीर्ष पर जरूर रहे लेकिन इन दोनों ही मसलों पर किसी तरह की सहमति बनती नहीं नजर आई। अमेरिका और चीन के बीच बीते डेढ़ साल की थका देने वाली कूटनीति की तरह ही शी की छह दिवसीय यात्रा से भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने अपने-अपने एजेंडे पर जोर देने के साथ संबद्धता बढ़ाने की बात कही। बहरहाल उनकी तीन देशों की यात्रा जिसमें सर्बिया और हंगरी भी शामिल थे, यूरोप की एकजुटता की पड़ताल करती प्रतीत हुई। गत माह जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की चीन यात्रा के तत्काल बाद हुई इस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तथा यूरोपीय संघ की चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक में एजेंडे में सबसे अहम था यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चीन का रूस को समर्थन। लेयेन के अनुसार यूरोपीय संघ ने चीन से कहा कि वह रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध को समाप्त करे। हालांकि इस प्रकरण पर अपनी टिप्पणी को लेकर यूरोपीय संघ काफी हद तक सतर्क रहा। उसने अपने साझेदार अमेरिका का अनुसरण नहीं किया। अमेरिका ने चुनिंदा चीनी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया है। उसे आशंका है कि वे रूस को समर्थन मुहैया करा रहे हैं।

शी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वह पुनर्विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कूटनीतिक अंदाज में मैक्रों के इस आह्वान में स्वर मिलाया कि पेरिस में आयोजित होने जा रहे ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों के दौरान वैश्विक शांति कायम हो। बहरहाल उन्होंने जून में यूक्रेन को लेकर आयोजित हो रहे शांति सम्मेलन में भाग लेने की प्रतिबद्धता नहीं जताई और कहा कि इस संकट का अंत बातचीत के जरिये होना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि युद्ध उन्होंने नहीं शुरू किया और न ही वह इसका हिस्सा थे और न ही उनकी इसमें शामिल होने की इच्छा है। व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ के नेताओं की अधिक संतुलित व्यापार और बेहतर बाजार पहुंच की दलील पर प्रगति नहीं हुई। चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों की यूरोपीय संघ द्वारा जांच में फ्रांस की भूमिका का प्रतिरोध करते हुए उसने यूरोपीय ब्रांडी खासकर फ्रांसीसी कौगनैक को लेकर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी। कौगनैक चीन में लोकप्रिय है। परंतु जर्मन बीफ और सेब पर से प्रतिबंध हटाने के अलावा शी ने यूरोपीय संघ के व्यापक बाजार पहुंच के प्रश्न का निराकरण नहीं किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को चीन की सरकारी सब्सिडी को लेकर यूरोपीय संघ की चिंता के मामले में शी चिनफिंग ने अपना पुराना रुख बरकरार रखा कि इस उद्योग ने जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है।

बहरहाल सर्बिया और हंगरी की उनकी यात्रा ने संभवतः यूरोप को असहज करने वाले संदेश दिए हों। हंगरी यूरोपीय संघ का सदस्य है जहां बढ़ता अधिनायकवाद यूरोपीय संघ की सदस्यता की परीक्षा ले रहा है। सर्बिया 2012 से सदस्यता का उम्मीदवार है। दोनों देशों का झुकाव रूस की ओर है और वे चीन की बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) पर हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक देश हैं। बेलग्रेड-बुडापेस्ट हाई स्पीड रेलवे इस पहल की प्रमुख योजना है। यह चीन की '16 प्लस वन' पहल का हिस्सा है जिसके जरिये चीन मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ कारोबारी और निवेश संबंधी रिश्ते बढ़ाना चाहता है। माना जा रहा है इस दौरान ग्रीस तक संपर्क कायम करके जमीन से समुद्र के माध्यम से एक असाधारण मार्ग तैयार किया जाएगा जो पूर्वी यूरोप से भूमध्यसागर के बंदरगाहों तक जाएगी। इससे चीन को यूरोपीय संघ के बाजारों की करीबी हासिल होगी। कुल मिलाकर शी को शायद यूरोप की इस यात्रा से अपेक्षाकृत ज्यादा हासिल हुआ और मेजबान यूरोपीय संघ की तुलना में उन्होंने अपने देश के हितों का अधिक ध्यान रखा।

जटिलताओं से उबरने की उम्मीद में लघु वित्त बैंक

ज्यादातर लघु वित्त बैंकों का लघु होना उनके सफर का केवल एक पड़ाव है, उनकी मंजिल नहीं है। इन बैंकों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

लगभग एक दशक पहले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के करीब एक दर्जन संस्थापक और प्रवर्तकों ने इस तरह के बैंक स्थापित करने के वास्ते लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास आवेदन दिया था। ऐसे दो बैंकों को छोड़कर (एक का विलय सबसे बड़े लघु वित्त बैंक के साथ और दूसरे का वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी (फिनटेक) के साथ किया जा रहा है) बाकी सभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गए हैं। शायद अधिकांश का यही कहना होगा कि वे लघु बैंक वाली पहचान से मुक्ति और सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंक बनना चाहते हैं। आरबीआई द्वारा लघु वित्त बैंकों को बड़े सार्वभौमिक बैंकों में तब्दील करने पर विचार करने से जुड़े फैसले पर इस उद्योग के सभी लोगों को राहत मिली है।

बैंक सेवाओं से वंचित उधारकर्ताओं तक पहुंचने के लिए आरबीआई ने एसएफबी मॉडल का प्रयोग करने का फैसला किया था। ज्यादातर एसएफबी सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनैंस) संस्थान थे और उन्होंने इन वंचित उधारकर्ताओं को सेवाएं देने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन जहां तक जमा राशि संग्रह करने की बात की जाए तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है क्योंकि उन्हें जमा के लिए सार्वभौमिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती रही है।

एसएफबी के सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

- न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक के संतोषजनक प्रदर्शन के रिकॉर्ड वाली स्थिति।
- बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए।
- न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये की हैसियत।
- 15 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात।
- पिछले दो वित्त वर्षों में शुद्ध लाभ।
- पिछले दो वित्त वर्षों में अधिकतम 3 प्रतिशत सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) और प्रावधान के बाद, 1 प्रतिशत शुद्ध एनपीए।
- विविध ऋण पोर्टफोलियो।
- पिछले दो वित्त वर्षों में शुद्ध लाभ।
- अधिकतम 3 फीसदी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और प्रावधान के बाद पिछले दो वित्त वर्ष में 1 प्रतिशत का शुद्ध एनपीए
- एक विविधता वाला ऋण पोर्टफोलियो

सभी एसएफबी में से केवल एक एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ही इन सभी शर्तों को पूरा करता है जो सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है। बाकी में उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड को छोड़कर कोई भी एनपीए मानदंड को पूरा नहीं करता है। लेकिन उज्जीवन एसएफबी के पास विविधता वाला ऋण पोर्टफोलियो नहीं है जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड और शायद एक और लघु वित्त बैंक के पास है। आरबीआई ने उन एसएफबी की शेयरधारिता को लेकर अपने कदम को स्पष्ट किया है जो सार्वभौमिक बैंक का दर्जा पाना चाहते हैं।

- किसी पात्र एसएफबी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उन्हें किसी प्रवर्तक की पहचान करनी हो। हालांकि, पात्र एसएफबी के मौजूदा प्रवर्तक, यदि हैं तब वे सार्वभौमिक बैंक में बदलाव के दौरान प्रवर्तक के रूप में बने रहेंगे।
- सार्वभौमिक बैंक बनने के दौरान किसी पात्र एसएफबी को नए प्रवर्तकों को जोड़ने या प्रवर्तकों में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- लघु वित्त बैंक से सार्वभौमिक बैंक बनने के बाद मौजूदा प्रवर्तकों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता की कोई नई अनिवार्य लॉक-इन आवश्यकता नहीं होगी।
- आरबीआई द्वारा पहले से स्वीकृत प्रवर्तकों की शेयरधारिता कम करने की योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।

पात्र लघु वित्त बैंक को इस तरह के बदलाव के लिए बाकायदा विस्तृत तर्क देने होंगे। आरबीआई सार्वभौमिक बैंकों के लिए लाइसेंसिंग मानदंडों के माध्यम से इसके आवेदन की जांच करेगा।

इस बदलाव के लिए तर्क स्पष्ट है: सभी एसएफबी एक ही संस्थान के भीतर दो बैंक की तरह काम कर रहे हैं जिसमें परिसंपत्ति के लिए एक एसएफबी और देनदारियों के लिए एक सार्वभौमिक बैंक है। वे लोगों और उद्यमों को ऋण दे रहे हैं जो आमतौर पर सार्वभौमिक बैंकों की सेवाएं नहीं लेते हैं। लेकिन जहां तक जमा का सवाल है, उसके लिए उन्हें महानगरों वाले बाजार में सार्वभौमिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जमा के लिए उनके पास एकमात्र तरीका यह है कि वे ग्राहकों को जमा पर उच्च दरों की पेशकश करें।

इनके नाम में 'लघु' जुड़ने का बड़ा नुकसान होता है। कई भावी जमाकर्ता इस तरह के बैंकों में अपना पैसा रखने से पहले दो बार सोचते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात को लेकर हैरानी होती रहती है कि आखिर इन्हें लघु बैंक क्यों कहा जाता है। भले ही इन सभी को अनुसूचित बैंक का दर्जा हासिल है लेकिन इसके बावजूद अनेक जमाकर्ताओं को ऐसा लगता है कि लघु बैंक पैसे रखने के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो एसएफबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमा हासिल करने की है। दरअसल इन लघु वित्त बैंकों को ऊंची दरों पर भुगतान करना पड़ता है, इसलिए सार्वभौमिक बैंकों की तुलना में इनकी पूंजी लागत अधिक होती है। वे अब भी प्रबंधन करने की स्थिति में हैं और मुनाफे के साथ अपना कारोबार कर सकते हैं क्योंकि वे आमतौर पर छोटे उधारकर्ताओं से उच्च दर वसूलते हैं।

जिस वक्त इनके नाम से 'लघु' हट जाएगा इनकी पूंजी की लागत घट जाएगी। इन्वेस्टेक बैंक पीएलसी ने हाल में कहा है कि लघु वित्त बैंकों के सार्वभौमिक बैंक में बदलने के बाद, फंड की लागत 20 आधार अंकों तक कम हो सकती है, जिससे इक्विटी पर रिटर्न में 60 आधार अंकों की वृद्धि होगी।

इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं। एक एसएफबी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सेवाएं देनी होती है और यह कुल ऋण में से करीब 75 प्रतिशत तक होना चाहिए। वहीं सार्वभौमिक बैंक के लिए प्राथमिकता वाले ऋण की आवश्यकता बेहद कम करीब 40 प्रतिशत तक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कम ऋण के चलते एसएफबी से सार्वभौमिक बैंक बने संस्थान को लाभदायक तरीके से ऋण परिसंपत्ति का प्रबंधन बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी।

एक एसएफबी के लिए 15 फीसदी पूंजी पर्याप्तता अनुपात की आवश्यकता होगी। यानी प्रत्येक 100 रुपये के ऋण पर 15 रुपये की पूंजी चाहिए होगी। (यह मानते हुए कि शत-प्रतिशत पूंजी की आवश्यकता है। व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋणों के लिए, पूंजी की आवश्यकता करीब 125 प्रतिशत तक है।) सार्वभौमिक बैंक के लिए इस तरह की आवश्यकता बहुत कम है और यह केवल 11.5 प्रतिशत (9 प्रतिशत के साथ 2.5 प्रतिशत पूंजी संरक्षण भंडार के रूप में) तक है। कम पूंजी आवश्यकता के ज्यादा लाभ हैं। पहले उन्हें 100 रुपये का ऋण देने के लिए 15 रुपये की आवश्यकता थी। एक बार जब वे एक सार्वभौमिक बैंक बन जाएंगे तब उन्हें 100 रुपये के ऋण पर केवल 11.5 रुपये देने होंगे। कुल मिलाकर, वे इक्विटी पर उच्च रिटर्न के साथ अधिक लाभदायक हो जाएंगे। भारतीय बैंकिंग तंत्र में सार्वभौमिक बैंक का दबदबा है और यहां एसएफबी के अलावा कई तरह के बैंक हैं जैसे कि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और पेमेंट बैंक। एसएफबी और पेमेंट बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत नए बैंक हैं और पिछले दशक की दूसरी छमाही में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है।

अब यह सर्वविदित है कि पेमेंट बैंक एक श्रेणी के तौर पर विफल है। आखिरकार एक पेमेंट बैंक ऐसा क्या कर सकते हैं जो एक सार्वभौमिक बैंक नहीं कर सकते हैं? केवल भुगतान के क्षेत्र में काम करने वाले किसी बैंक का कारोबारी मॉडल क्या है?

इसके उलट एसएफबी एक अलग ही कहानी है। आमतौर पर इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। नोटबंदी और कोविड महामारी जैसी घटनाओं ने उन्हें यह सबक दिया है कि वे अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाएं क्योंकि लघु असुरक्षित ऋण पर बाहरी घटनाक्रम का हमेशा तेजी से प्रभाव पड़ता है।

जमा हासिल करने की चुनौती के अलावा एसएफबी को अनुपालन लागत से जुड़ी दिक्कतें भी महसूस हुई हैं। निजी बातचीत में कुछ प्रवर्तक यह स्वीकार करते हैं कि अगर उन्हें पहले जानकारी होती तब वे किसी बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं करते और उनके मुताबिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के दौर वाले दिन बेहतर थे। अगर वे सार्वभौमिक बैंक बन जाते हैं तब भी हालात में बहुत बदलाव नहीं दिखेगा क्योंकि आरबीआई ने अपनी निगरानी के तरीके में बदलाव किया है।

ज्यादातर एसएफबी का एक लघु बैंक होना उनके सफर का हिस्सा है और यह गंतव्य नहीं है। हालांकि इनमें से कई की दिलचस्पी मुख्यधारा का बैंक बनने की होगी और जब वे पात्र होंगे तब मुझे इस बात को लेकर संदेह है कि आरबीआई नई इकाई का स्वागत एसएफबी की तरह करेगा जैसा कि सब तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के काम पर अमल करने के लिए एसएफबी का किया गया था।

सिक्किम: राजनीतिक-सामाजिक समस्याएं

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

सिक्किम में भले ही विधान सभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है (निर्वाचन आयोग के हालिया फैसले के मुताबिक यहां मतदान 19 अप्रैल को हुआ था और मतगणना 2 जून को होगी जबकि देश भर में 4 जून को मत गिने जाएंगे) लेकिन वर्ष 2023 के चार घटनाक्रम ही राज्य के भविष्य की राह तय करेंगे। पहला घटनाक्रम, फरवरी 2023 का है जब मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया ने अपनी हमरो सिक्किम पार्टी का विलय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के साथ कर दिया। ठीक उसी दौरान एसडीएफ के प्रमुख और पांच बार सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन चामलिंग ने यह घोषणा कर दी कि 2024 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने भूटिया को एसडीएफ का उपाध्यक्ष बना दिया और उनके लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन की पेशकश भी कर दी।

हालांकि भूटिया की राजनेता बनने की कोशिश को अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली है। वह सिलीगुड़ी के मेयर के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी थे और वह यह चुनाव हार गए। उन्हें 2014 में दार्जिलिंग लोकसभा सीट भी भाजपा के उम्मीदवार के हाथों गंवानी पड़ी। वर्ष 2018 में उन्होंने अपने गृह राज्य लौटने के साथ ही हमरो सिक्किम पार्टी की शुरुआत की। भूटिया के चुनावी रिकॉर्ड को लेकर सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाग गोले ने मजाक उड़ाया। उन्होंने उन्हें राजनीति में पांव जमाने की कोशिश करने के बजाय फुटबॉल के क्षेत्र में ही बने रहने की सलाह दी।

दूसरा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सिक्किम में हाल में सबसे भयावह स्तर पर अचानक आई बाढ़ से जुड़ा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में एक हिमनद झील के चलते तीस्ता नदी और तीस्ता 3 की जलविद्युत परियोजना बांध में बाढ़ की स्थिति बन गई। सिक्किम जैसे छोटे राज्य में इससे बड़ी तबाही जैसी स्थिति बन गई। सेना के 20 से अधिक जवान और बड़ी मात्रा में हथियार आदि बाढ़ में बह गए। इस आपदा में 100 से अधिक शव बरामद किए गए थे और इस बाढ़ से 60,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे में जाहिर है कि मुआवजे में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया। यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उठा।

तीसरी महत्त्वपूर्ण घटना पिछले साल दिसंबर महीने में दलाई लामा की सिक्किम की तीन दिवसीय यात्रा से जुड़ी थी जो 13 वर्षों में पहली बार थी। पालजोर स्टेडियम में उन्होंने अपने अनुयायियों को संबोधित किया जो नाथू ला में भारत-चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। उनके दौरे के बाद ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तीन भारतीय वुशु खिलाड़ियों को 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए देश में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर सैनिकों के बीच आखिरी हिंसात्मक झड़प 2021 में हुई थी।

सरकारी सूत्रों के आधार पर मिली इस रिपोर्ट का भारत ने खंडन नहीं किया है कि उत्तरी सिक्किम के नाकू ला इलाके में चीन की तरफ कंक्रीट के बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि सैनिकों की तैनाती में आसानी हो।

चौथी अहम घटना यह रही कि सिक्किम के उत्साही युवा इस घोषणा को लेकर बेहद अभिभूत थे कि सिक्किम मूल के हार्ड रॉक/हेवी मेटल बैंड जिसे गिरीश ऐंड दि क्रॉनिकल्स कहा जाता है, उसने जून, 2023 में अबू धाबी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर रॉक ग्रुप, गंस ऐंड रोजेज के साथ पहली बार मंच साझा किया।

समूह ने ट्विटर पर ट्वीट किया, 'हम अभी जो महसूस कर रहे हैं, उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि हमें आज सिक्किम और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है।' गिरीश प्रधान और उनके भाई योगेश, गिटारवादक सुराज सुन और ड्रम वादक नागेन मॉनग्रांती सभी सिक्किम से हैं। रोलिंग स्टोन पत्रिका का कहना है कि प्रधान आज हार्ड रॉक और हेवी मेटल सर्कल में सबसे चर्चित गायकों में से एक हैं और उनकी काफी मांग है। इन सभी घटनाओं का 32 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के नतीजे पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

वर्ष 1994 से 2019 तक 25 वर्षों तक सिक्किम में सत्ता में रही एसडीएफ को पिछले विधानसभा चुनावों में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाले एसकेएम से हार का सामना करना पड़ा था। अब 2 जून को ही तय होगा कि भूटिया की उपस्थिति से एसडीएफ की किस्मत चमकेगी या नहीं। मौजूदा सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करेगी। इस फैसले को लागू कराने और इसकी वित्तीय जिम्मेदारी नई सरकार पर होगी।

लिम्बू और तमांग समुदायों के लिए आरक्षण का मुद्दा भी गर्म है जिसको लेकर मौजूदा सरकार ने वादा किया है लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सिक्किम खेती के जैविक तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ऐसे में जो भी सत्ता में आएगा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे के इस दौर में आजीविका का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। सिक्किम के विकास का मॉडल, अन्य राज्यों से अलग है। सिक्किम ने 13 पनबिजली परियोजनाओं के लिए 'ना' कहा है क्योंकि इससे राज्य के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। विकास का वैकल्पिक मॉडल दरअसल 'प्रकृति की ओर वापस' लौटने से जुड़ा है।

राज्य में रोजगार की भी जरूरत है। इस चुनाव से पहले भाजपा और एसकेएम के बीच गठबंधन टूट गया था। एक कारण यह डर है कि अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 एफ की तरह बदला जा सकता है। इस संवैधानिक संरक्षण के कारण सिक्किम के लोगों को जमीन खरीदने और राज्य सरकार की नौकरी पाने का अधिकार है। इसके अलावा उन्हें आयकर भुगतान से भी छूट दी गई है। आप नए दोस्त बना सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते हैं। सिक्किम इस बात को लेकर बेहद सजग है कि इसे कभी भी भारत-चीन की शत्रुता का गवाह बनना पड़ सकता है। लेकिन इन सबमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात सिक्किम के युवाओं की आकांक्षा और महत्त्वाकांक्षा है।

राज्य में भारत में आत्महत्या की दर सबसे अधिक (100,000 लोगों पर 37.5 लोग) है और यह भारतीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। सिक्किम में 10 में से सात किशोर दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। हर परिवार का एक व्यक्ति किसी न किसी तरह के अवैध मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है। ये सभी मुद्दे चुनाव में छाए रहे हैं। अब इन सबका नतीजा आना है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

अगली बार 'एक देश एक चुनाव'

हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगले 5 साल में 'एक देश एक चुनाव' के बारे में बयान मायने रखता है। अब यह लगने लगा है कि 2029 में लोक सभा और विधान सभाओं का चुनाव एक साथ ही होगा। चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से यह निर्णय बहुत महत्त्वपूर्ण है। जितने ईवीएम चुनाव आयोग के पास हैं, कम से कम उससे दोगुनी ईवीएम की जरूरत होंगी। प्रचार में लोक सभा और विधान सभाओं के प्रत्याशियों की संख्या मिलाकर भी कम से कम दो गुना प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। चुनाव पर्यवेक्षकों की संख्या भी कम से कम पांच गुना होगी। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किए जाएं जिससे नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक सब कुछ नियंत्रण में रहे। विस्थापित मतदाताओं को अपने चुनाव क्षेत्र के मतदान में दूरस्थ स्थान से भी मतदान का अधिकार और सुविधा मिले। नए संसद भवन में सांसदों के लिए पहले से अधिक सीटें हैं। इसलिए लोक सभा और विधान सभाओं के लिए फिर से परिसीमन की आवश्यकता है। पांच वर्ष में भी जनप्रतिनिधि अपना चुनाव क्षेत्र कवर नहीं कर पाते, क्षेत्र की समस्याएं समझना और सुलझाना तो दूर की बात है। एक देश एक चुनाव से राजनीतिक स्थिरता मिलेगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को गुरुग्राम में ईवीएम का मॉडल लगाया

देश में प्रशिक्षित साइबर सेना की जरूरत

भारत में अभी तक साइबर सुरक्षा संबंधित कड़े कानून नहीं है। साइबर हमलों के मामले में फिलहाल आईटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है। नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इसके लिए काम करती है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं लेकिन उनके बीच अपेक्षित तालमेल का अभाव दिखता है। यूरोपोल (यूरोपियन पुलिस एजेंसी) सहित कई देशों की एजेंसियां इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ट्रैक करने के लिए एफबीआई के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब भारत को भी सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। सरकार को डिजिटल इंडिया की तर्ज पर साइबर सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जब सब कुछ इंटरनेट के भरोसे हो जाएगा तो उसकी सुरक्षा भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत लोगों को सलाह दी जाती है कि वह अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, सीवीवी और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताएं। हालांकि सेना भी कोशिश करती रहती है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर कोई साइबर हमला न हो और हमला होने पर मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन भारतीय सेना का यह काम ज्यादातर अनऑफिशयल है और ऑफिशियल स्तर पर कोई साइबर सेना नहीं है। इसलिए आप साइबर चुनौतियों का उस तरह सामना नहीं कर सकते हैं जबकि चीन के पास डेडिकेटेड साइबर सेना है। इसलिए भारत को ऐसी साइबर सेना की जरूरत है, जो प्रशिक्षित हो ताकि वह भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट छह माह बंद रहने के बाद शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ इस वर्ष की चारधाम यात्रा आरंभ हो गई। दोनों धामों के कपाट सुबह सात बजे खुले और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 11 मई 2024

नहीं मिले सारे जवाब

दाभोलकर केस में 11 साल बाद फैसला

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के करीब 11 साल बाद आया विशेष अदालत का फैसला कम से कम यह संतोष देता है कि इस मामले में न्याय प्रक्रिया का एक चक्र पूरा हुआ। हालांकि कई अहम सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण अपनी तार्किक परिणति तक पहुंच गया।

हत्या का सिलसिला | 20 अगस्त 2013 की सुबह हुई डॉ. दाभोलकर की हत्या ने अगर पूरे देश को सकते में डाल दिया था, तो वह बेवजह नहीं था। माना गया कि उनकी हत्या उनके विचारों को दबाने के मकसद से की गई है। उसके बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसारे, अगस्त 2015 में एम एम कलबुर्गी और सितंबर 2017 में हुई गौरी लंकेश की हत्या को इसी श्रेणी में रखकर देखा जा रहा था।

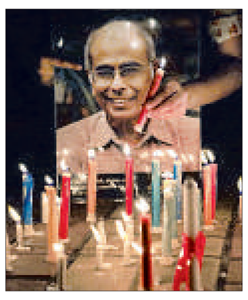

साजिश का नहीं हुआ खुलासा

टिकी थीं निगाहें | शुरुआती जांच में कुछ ऐसे बिंदु मिले भी थे जिनसे लगता था कि कहीं न कहीं इन हत्या की साजिशों के तार एक-दूसरे से जुड़े हैं। इस लिहाज से भी नरेंद्र दाभोलकर हत्या से जुड़े इस मामले पर सबकी नजरें टिकी थीं। लग रहा था कि अदालत में अगर इन साजिशों की परतें खुलें और कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचे तो देश में अपनी तरह के इन हत्याकांडों के पीछे की सचाई सामने आएगी।

साजिश नहीं खुली | अदालत में उन दो लोगों के खिलाफ दोष साबित हो गया, जिन्होंने 20 अगस्त 2013 की सुबह डॉ. दाभोलकर पर गोलियां चलाई थीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने यह हत्या की क्यों? क्या इनकी डॉ. दाभोलकर से कोई निजी दुश्मनी थी? सीबीआई के मुताबिक हत्या का कारण वैचारिक टकराव था। अभियोजन पक्ष ने हत्या की साजिश के मामले में तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन जांच एजेंसियां इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकीं।

कमजोर जांच-पड़ताल | जाहिर है, कमजोर जांच-पड़ताल की वजह से हत्या के पीछे की साजिश उजागर नहीं हो सकी। हत्या के पीछे कोई दूसरा ठोस, तर्कसंगत कारण भी स्थापित नहीं हो पाया। नतीजा यह कि हत्या करने वालों को सजा सुना दिए जाने के बाद भी, देश इस बात को लेकर अंधेरे में है कि आखिर इस हत्या के पीछे किन लोगों की और कैसी साजिश थी।

कोई निष्कर्ष नहीं | इसी वजह से यह सवाल भी अनुत्तरित ही है कि उसके बाद हुई तीन हत्याओं – गोविंद पानसारे, एम एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की – को एक साथ जोड़कर देखने का कोई ठोस आधार है या नहीं। क्या इन चारों हत्याओं की साजिश के पीछे एक ही संगठन से जुड़े समान सोच वाले लोगों का हाथ था? जाहिर है, ठोस जवाब के अभाव में ऐसी हत्याओं तक ले जाने वाले कारकों से निपटने के तरीके ढूंढना भी आसान नहीं होगा।

अंतर्दृष्टि

जो नहीं हुआ, वह भी ब्रह्मांड ने ही किया

सुंदर चंद ठाकुर

जीवन जीना बहुत सरल है, लेकिन हम सोच-सोचकर उसे मुश्किल बना देते हैं। आनंद में रहना बहुत सरल है, लेकिन हम अपने ईगो को पकड़े रहकर उसे मुश्किल बना देते हैं। कभी किसी को अगर किसी मृतक को विदा देने श्मशान जाना होता है, तो वह चिता पर शव को देखकर सहज ही सोचने लगता है – क्या लेकर आए इस दुनिया में, क्या जो लेकर जाएंगे। फिर इतनी लड़ाई, इतना गुस्सा, इतना तेरा-मेरा किसलिए। हालांकि श्मशान में जाकर यूं मन में वैराग्य पैदा होना बड़ी बात नहीं। सभी के साथ ऐसा होता है। इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। श्मशान के गेट से बाहर निकलते ही हम पर फिर से संसार हावी हो जाता है। हमें अपने हिसाब-किताब में उलझने में देर नहीं लगती।

क्या आपने कभी गौर किया कि कई बार मनचाही चीज हासिल न होने पर आपका मन गहरे अवसाद में डूबा जाता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह परिणाम जिसे पाने के लिए आप पिछले कुछ महीनों या सालभर से तैयारी कर रहे थे, जब समय आया तो वह आपको नहीं मिला। इस नहीं मिलने से आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आपको भूख लगना तक बंद हो जाता है। आपको उस वक्त उन चीजों का जरा भी खयाल नहीं आता, जो कि आपके पास होती हैं। आपके जेहन में बस एक ही बात रहती है कि आपने जिस चीज की इच्छा की और पूरे मन से इच्छा की, वह आपको नहीं मिली।

मनुष्य को प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वह बहुत लंबे समय तक उदास और हताश नहीं रह सकता। वह अपने लिए कोई न कोई उम्मीद खोज ही लेता है और फिर उस उम्मीद का दामन थामकर जिंदगी जीता है। मनचाही चीज न मिलने के बाद कुछ दिन इस 'न मिलने का मातम' मना लेने के उपरांत हम धीरे-धीरे उदासी और निराशा के घेरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद ही हमें 'मनचाही चीज' से भी कोई बड़ी चीज हासिल हो जाती है। आपको दुख हो रहा था कि आप बैंक के पीओ का एग्जाम नहीं पास कर पाए और एक साल बात आप सिविल सर्विसेज पास कर लेते हो। कहां तो आप बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर न बन पाने का दुख मना रहे थे और कहां आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। यानी आपने तो पीओ बनने का सोच रखा था, लेकिन ब्रह्मांड आपको आईएएस अधिकारी बनाना चाहता था। अब क्योंकि आप खुद तो आईएएस बनना नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए उसने आपको पीओ में फेल किया। यानी जो हुआ वह तो ब्रह्मांड ने किया ही, जो नहीं हुआ वह भी ब्रह्मांड ने ही किया।

असल में अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंद के परम भाव में जीना चाहते हैं, तो आपको पाने और खोने से तो ऊपर उठना ही होगा। क्योंकि सच यही है कि आप कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। चूंकि आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आपमें यह सामर्थ्य और संभावना है कि आप बिना वजह के ही अतीव आनंद में जीवन जी सकते हो। जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, जो परम शक्ति आपको इस संसार में लाई है, उसने इसकी बखूब व्यवस्था की हुई है कि आप अकारण भी आनंद में बने रहो। स्वयं प्रकृति हमेशा आनंद में बनी रहती है। ब्रह्मांड की डिफॉल्ट स्थिति आनंद की स्थिति है। ब्रह्मांड हमेशा ही जीवन के पक्ष में, सकारात्मकता के पक्ष में झुका हुआ रहता है। इसलिए अगर आप ब्रह्मांड से खुद को जोड़े रह सको, तो आप भी हमेशा आनंद की स्थिति में बने रह सकते हो। ब्रह्मांड से आशय परम शक्ति से है। जैसे ही आप स्वयं को परम शक्ति से जोड़ते हैं, अपनी छोटी इंसानी सीमाओं से मुक्त होकर उसकी असीमित शक्तियों से जुड़ जाते हैं। ऐसा होते ही आप मनचाही चीज के न होने पर भी उदास या निराश होना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपमें पाने की चाह पैदा करने वाली कोई चीज ही नहीं रह जाती।

ऑफ दि ट्रैक

डेडबॉट्स का जोखिम

दिलीप लाल

क्या आप अपने खोए हुए प्रियजनों से बात कर पाएंगे? या आपके बाद आपकी बातें आपके परिजन सुन पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की नई तकनीक ऐसा दावा करती है। उदाहरण के लिए, इस तकनीक की मदद से पोते-पोतियां अपनी मृत दादी से कहानियां सुन सकती हैं। यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन कैंब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस 'डिजिटल आफ्टरलाइफ इंडस्ट्री (DAI)' के प्रति चिंता व्यक्त की है जिससे छोटे स्टार्ट-अप और बड़ी डेटा कंपनियां जुड़ी हैं। 'डेडबॉट्स', 'ग्रीफबॉट्स' नाम के चैटबॉट्स, कम्युनिकेशन प्लैटफॉर्म्स या अवतारों के माध्यम से संवाद कराते हैं। ये मृत या जीवित व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे ऑनलाइन गतिविधि और मेसेज का इस्तेमाल करके उनकी तरह बात करने और व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। डेडबॉट्स से बात करने से एक भुतहा माहौल बन सकता है। दुखी व्यक्ति को किसी काल्पनिक दुनिया में ले जाकर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वह व्यक्ति इससे मानसिक अवसाद में आ सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल डेडबॉट बनाने के लिए करने से नैतिक अधिकार के भी हनन का खतरा है। यूजर्स को भी डेडबॉट्स के जोखिमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जब भी इस तकनीक का उपयोग किया जाए, सावधानी बरतना और संभावित खतरों के प्रति जागरूक होना जरूरी है।

शिशु लिंग परीक्षण की इजाज़त समाज को उलटी दिशा में ले जा सकती है

कानून नहीं, सोच पर हो फोकस

नासिरा शर्मा

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) अध्यक्ष डॉ आरवी अशोकन ने गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण को लेकर एक बहस शुरू की है कि कुछ शर्तों के साथ गर्भ में शिशु का लिंग परीक्षण होना चाहिए और इसके लिए PNDT (Pre-conception & pre-Natal Diagnostic Techniques) एक्ट में कुछ ढील भी दी जानी चाहिए। उनकी दलील है कि मौजूदा कानून के तहत जो डॉक्टर फॉर्म F ठीक से नहीं भर रहे हैं, उन्हें अपनी इस लापरवाही के लिए वही सजा दी जा रही है जो भ्रूण की जांच करने पर दी जाती है।

कड़ी सजा | गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण की भारत में 3 वर्ष की कड़ी सजा है। जाहिर है इसमें एक बार पकड़े जाने पर डॉक्टर का पूरा करियर जाता रहता है। बाद में उसे काम नहीं मिलता। अगर किसी तरह काम मिल भी जाए तो उसके व्यक्तित्व का ह्रास हो चुका होता है। डॉ आरवी अशोकन ने इस बात को नजर में रखते हुए कहा है कि परीक्षण की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कि शिशु कन्या है और फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि उसे किसी तरह की हानि न पहुंचे।

व्यावहारिक नहीं | यह एक अच्छी सोच हो सकती है परंतु व्यावहारिक नहीं है। कुछ डॉक्टर कसम खाने के बावजूद ये काम करते हैं। यदि कानून हटा दिया गया तो क्या गारंटी है कि बच्ची मारी नहीं जाएगी? हमारे देश में भ्रूण हत्या तक ही मामला नहीं रहता है बल्कि लड़की की पूरी जिंदगी खतरे में रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि कानून बदलने की जगह समाज की सोच बदलने पर ध्यान दिया जाए। यह काम डॉक्टर अच्छी तरह कर सकते हैं।

कहानी पर मिली प्रतिक्रिया | काफी पहले मैंने एक कहानी लिखी थी 'अपनी कोख।' इसकी कथावस्तु यह थी कि साधना दो बेटियों के बाद जब तीसरी बार मां बनने को होती है तो परिवार के दबाव में टेस्ट कराती है जिसमें लड़का निकलता है। इस पर वह अपना अबॉर्शन करा लेती है और सास से झूठ बोलती है कि इस बार भी लड़की थी।

फैसले के पीछे | फैसले के पीछे उस पात्र की सोच यह थी कि कि भाई आएगा तो दोनों बहनों की पूरी जिंदगी एक साये में आ जाएगी। फिर वे उतना पनप नहीं पाएंगी।

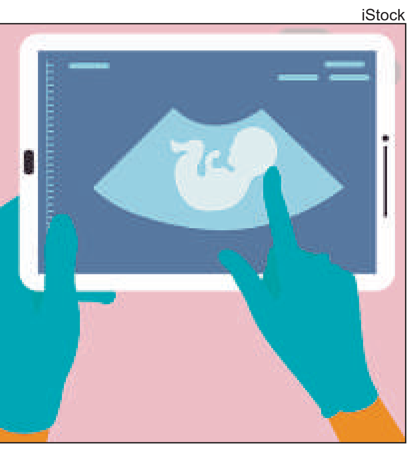

iStock

उनकी पढ़ाई में कमी रह जाएगी और उनकी शादियां हो जाएंगी, जैसा कि खुद उसके साथ हुआ था। इस कहानी पर मिली प्रतिक्रियाएं भी काफी कुछ कहती हैं।

टीचर्स का सवाल | इस कहानी को मैंने करनाल के B.Ed गणेशदास कॉलेज में पढ़ा था। वहां श्रोता लड़कियों से जब सवाल-जवाब हुआ तो सब चुप रहीं मगर टीचरों ने उग्र प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि जब लड़का था तो उसकी हत्या क्यों करवाई गई। इसके बाद मैंने यही कहानी बाल भवन टीचर्स ट्रेनिंग टीचरों के सामने पढ़ी। सभी का ख्याल था कि लड़के की भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए थी।

वक्त लगेगा हालात बदलने में
- कानून के खौफ का है असर
- यह खौफ हटाना ठीक नहीं
- भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे

प्ले किया गया | इसके बाद कल्चरल एक्टिविस्ट राजीव रंजन और उनकी पत्नी रीता ने एक वर्कशॉप करके 'साधना' नाम से ड्रामा बनाया, जिसके हरियाणा में 300 शो हुए। खास बात यह कि इसके हर शो के बाद शपथ लेनी पड़ती थी कि कोई गर्भ की जांच नहीं करवाएगा, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की। दोनों को खुदा की नेमत समझना चाहिए।

जन्म के बाद के हालात | मैं कोई out of the way जाकर बात नहीं कर रही, IMA अध्यक्ष की ही बात का जवाब दे रही हूं। जन्म के बाद भी अगर लड़की है तो उसे कुछ पिला न दिया जाए या उसका गला न घोट दिया जाए, यह पक्का करने में डॉक्टर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर इस मानसिकता को बदलने के लिए समाज में अपना योगदान कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार का असर | आज के जमाने में लड़कियां मां-बाप का ख्याल रख रही हैं। बहुत सी चीजों को वे बदल भी रही हैं और देश के निर्माण में भी उनका योगदान हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण शुरू हो गया तो हमारे समाज में जो परत-दर-परत भ्रष्टाचार है, वह इस मामले में भी रंग नहीं दिखाने लगेगा? जो लोग चुपचाप ऐसे परीक्षण करते हैं, क्या वे उसका रेकॉर्ड रखने में हेरफेर नहीं करेंगे? इस सुझाव पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है।

कानून का खौफ | अभी PNDT कानून के खौफ के चलते लोग टेस्ट नहीं कराते। अगर कराते भी हैं तो बहुत छुप-छुपाकर कराते हैं। लेकिन जब यह खुलेआम होने लगेगा, कानून की रोक हट जाएगी तो उसका नतीजा ऐसे देश में क्या निकलेगा, जहां हर कदम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है? डॉ अशोकन की इस बात के लिए जरूर तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने डॉक्टरों की तकलीफ को उजागर किया लेकिन उनकी चिंता एकतरफा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सजा इतनी कड़ी है तो डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं?

डॉक्टरों की वर्किंग कंडिशन | छोटे अस्पतालों में पहले ही बहुत तकलीफदेह हालात में डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैंने सरकारी अस्पतालों में उनकी बुरी दशा देखी है, वे मरीजों की बड़ी तादाद को हैंडल करते हैं, और उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। इस हालात में सिर्फ फॉर्म F भरने या ना भरने की ही नहीं, और भी तरह की गलतियां या लापरवाहियां उनसे हो सकती हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

रोज़गार का रास्ता

दुनियाभर की आईटी इंडस्ट्री में भारतीयों की मांग है। यहां के डॉक्टर-इंजीनियर छाए हुए हैं। लेकिन, इसके अलावा भी रोजगार के मौके हैं, जहां भारतीयों की मांग बढ़ रही। कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, जानते हैं...

AI image

5 पॉइंट

मालामाल करता Emigration
विदेश से पैसे भेजने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। विदेश कमाने गए लोगों ने साल 2023 में भारत में 125 बिलियन डॉलर भेजे। इन पैसों से न सिर्फ इन लोगों का घर चलता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा सोर्स है रोजगार का।

विदेश की मजबूरी
विकसित देशों में जन्मदर कम होने के कारण काम करने वाली आबादी बूढ़ी हो रही है। सबसे अधिक युवा आबादी से लैस भारत दूसरे देशों में वर्कफोर्स की कमी को पूरा कर सकता है। भारत में औसत आयु 29.5 साल है।

AI का असर
AI के बढ़ते दखल के साथ emigration की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। IMF Blog की रिपोर्ट के मुताबिक, 40% वैश्विक रोजगार पर AI का असर पड़ रहा। विकसित देशों में 60% नौकरियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। सबसे ज्यादा असर होगा high-skilled jobs पर। Low-skilled jobs में वर्कफोर्स की डिमांड बनी रहेगी, शायद बढ़े भी।

किन कामों में मांग
Blue collar जॉब में, यानी लेबर और स्किल्ड ट्रेड, मसलन – इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, दर्जी, राजमिस्त्री वगैरह। खाड़ी देशों, यूरोप, US, कनाडा, जापान में ब्लू कॉलर जॉब करने वाले भारतीय अधिक हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन केरल से हुआ है। केरल के 40 लाख लोग 182 देशों में काम कर रहे हैं।

क्या करना चाहिए
कई राज्य अपने नागरिकों को विदेश में रोजगार तलाशने में मदद कर रहे हैं। ऐसी पहल सभी करें। इमिग्रेशन के लिए युवाओं को गाइड किया जाए। उन स्किल को बढ़ाया जाए, जिनकी दुनियाभर में मांग है। इससे बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

फाल्के अवॉर्ड की लालसा नहीं रह गई है

वैजयंती माला दिग्गज अभिनेत्री और भरतनाट्यम की शानदार नृत्यांगना हैं। वह 15 वर्ष तक पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की सांसद भी रहीं। उन्हें अपने करियर में पद्मश्री, फिल्मफेयर और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो पहले ही मिल चुके हैं, पिछले दिनों पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उनसे बात की ***प्रदीप सरदाना*** *ने। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू

वैजयंती माला

■ पद्म विभूषण मिलने पर क्या कहना चाहेंगी?

मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। जब मुझे यह बताया गया तो अच्छा तो लगा, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। मैं भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी हूं, और बहुत खुश भी हूं। मैं मानती हूं, यह भगवान की देन है। साथ ही कला में मेरी जो भागीदारी रही है, यह उसकी वजह से है। मैं इसके लिए भगवान को कितना भी धन्यवाद करूं, कम ही है।

■ पिछले दिनों आशा पारेख, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के सम्मान मिला, तो लगा कि अब आपको फाल्के मिलेगा

सच कहूं तो फाल्के पुरस्कार की अब मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं पद्म विभूषण से ही बहुत खुश हूं, 90 की उम्र में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।

■ आपने फिल्मों में काम करना तो कब का छोड़ दिया, लेकिन नृत्य के प्रति आपका लगाव आज भी कायम है। कुछ साल पहले दिल्ली में आपने अपने नृत्य से सभी को दंग कर दिया था। बीती 29 फरवरी को राम मंदिर, अयोध्या में भी आपने इस उम्र में नृत्य किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। नृत्य के प्रति अभी भी इतना प्रेम, इतना समर्पण कैसे?

नृत्य मेरी जिंदगी में बेहद अहम रहा है। फिल्मों की मेरी सफलता में भी नृत्य का योगदान रहा। नृत्य से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वह मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था। कभी सोचा नहीं था कि मंदिर बनने का सपना मेरे जीवन में पूरा होगा। मैंने उस दिन टीवी पर समारोह को पूरा देखा। सोचा, रामलला के दर्शन के लिए मुझे कब बुलावा आएगा। जब अयोध्या से मुझे नृत्य के लिए बुलावा आया तो मैं धन्य हो गई। मुझे नृत्य के साथ वहां परिवार सहित रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं बढ़ती उम्र के कारण घूम-घूम कर तो नहीं नाची, लेकिन मैंने 'सीताराम श्लोकम' पर अभिनय, भाव और मुद्रा से नृत्य प्रस्तुति की। मुझे तो उस दिन परम सुख मिला।

■ अभी मार्च में पीएम मोदी चेन्नै आए तो उन्होंने आपसे भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात का क्या प्रयोजन था?

बस यह एक शिष्टाचार भेंट थी। असल में पद्म पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद मैंने पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र लिखकर एक आग्रह भी किया था कि जब हम पुरस्कार लेने दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलने का समय चाहेंगे। पर वह तभी चेन्नै आ रहे थे, तो उन्होंने हमें चेन्नै में मिलने का समय दे दिया।

■ पीएम मोदी ने क्या आपकी फिल्मों को लेकर भी बात की ?

फिल्मों पर नहीं, लेकिन नृत्य और मेरे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बात हुई। हम उनके व्यक्तित्व और आभामंडल से कुछ असहज थे। मेरा बेटा और बहू तो उन्हें देखते ही रह गए। लेकिन मिलने पर उन्होंने बहुत ही सहज महसूस कराया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी अयोध्या नृत्य करके आई हूं, तो उन्होंने कहा- हां, मुझे मालूम है। तो मैं यह जानकर बहुत खुश हुई। वह मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी।

■ आपने 20 वर्ष के करियर में कई अविस्मरणीय फिल्में देने के साथ उस दौर के सभी बड़े नायकों के साथ काम किया। लेकिन आपको अपनी जोड़ी किस नायक के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगी?

ज्यादातर अच्छे रहे। लेकिन मैं समझती हूं कि दिलीप कुमार के साथ मेरी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। मैंने सबसे ज्यादा और हिट फिल्में दिलीप साहब के साथ कीं, जैसे- देवदास, मधुमती, गंगा-जमुना, पैगाम, लीडर, नया दौर, संघर्ष। सायरा जी भी कहती हैं कि दिलीप साहब की मेरे साथ जोड़ी सबसे अच्छी रही।

> कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर का सपना मेरे जीवन में पूरा होगा। जब अयोध्या से मुझे बुलावा आया तो मैं धन्य हो गई। नृत्य के साथ वहां परिवार सहित रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। बढ़ती उम्र के कारण घूम-घूम कर तो नहीं नाची, लेकिन मैंने 'सीताराम श्लोकम' पर अभिनय, भाव और मुद्रा से नृत्य प्रस्तुति जरूर की

■ आपको अपने करियर में क्या कभी किसी फिल्म को छोड़ने का अफसोस रहा?

एक नहीं, ऐसी दो फिल्में हैं जिन्हें ना करने का अफसोस रहा। एक बिमल रॉय की 'बंदिनी' और दूसरी गुलजार की 'आंधी'।

■ 1970 में ही फिल्मों से संन्यास लेने के कारण आप 54 बरसों से फिल्मों से दूर हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे बाद भी लोग आपको प्रेम करते हैं, सम्मान से याद करते हैं..

यह देख अच्छा लगता है कि बरसों बाद भी लोगों के दिल में मेरे लिए वही प्रेम है। भगवान ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, मैं उसके लिए भगवान को सदा धन्यवाद करती हूं।

■ आप इन दिनों चेन्नै में रह रही हैं। लेकिन क्या आप मुंबई में फिल्म दुनिया के किन्हीं पुराने लोगों के संपर्क में हैं?

कोविड के बाद मुंबई जाना नहीं हो पाया। लेकिन दिलीप कुमार, सायरा बानो, हेमा मालिनी से हमेशा अच्छे संबंध रहे। मुंबई जाती तो इनसे मिलना होता ही था। साथ ही श्रीदेवी से भी मेरे काफी घनिष्ठ संबंध रहे। दिलीप साहब और श्रीदेवी तो अब रहे नहीं। लेकिन सायरा बानो और हेमा मालिनी से आज भी अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी कुछ समय पहले भी हमारे घर आई थीं। वैसे फोन पर भी इन दोनों से बातचीत होती रहती है।

■ इन दिनों आपकी दिनचर्या क्या है ?

आजकल मैं अपना अधिकतर समय भरतनाट्यम नृत्य के शोध में लगाती हूं। साथ ही अपने परिवार और खासकर अपनी दोनों पोतियों के साथ समय बिताना पसंद करती हूं। फिर नृत्य का रियाज तो करती ही हूं।

यारी की मिठाई हमने भी खाई

खुद अपनी आंख से

अलका 'सोनी'

मेरे किचन की खिड़की से लगा नीम का एक घना पेड़ है। वैसे आसपास भी पेड़ ही पेड़ हैं, जिनकी सूखी पत्तियां उड़कर अक्सर हमारे घर के अंदर और बालकनी में भर जाया करती हैं। कभी आंधी-तूफान आ जाए, फिर तो कहना ही क्या! पूरे घर में पत्तियां ही पत्तियां, और उनके साथ टूटकर आई सूखी हुई टहनियां। लेकिन आंधी-तूफान के दिनों को छोड़ दें तो सामान्य दिनों में नीम का यह पेड़ और भी बहुत कुछ देता है। ठंडी हवा के झोंके और आंख भर हरियाली के अलावा भी बहुत कुछ। गर्मियों में इसकी पकी, पीली निंबोली बचपन की यादों में ले जाती है। और जब पानी बरसता है तो नीम सहित निंबोलियों की भी महक आती है। दिन भर नीम का वह पेड़ पक्षियों के कलरव से भी गुंजायमान रहता है। मेरी रसोई की खिड़की के पास तक भी इसकी एक डाल पहुंचती है। उस डाल पर तोतों का जमघट लगा रहता है। हर दिन डाल पर बैठने वाले तोतों के झुंड में दो तोते मुझे विशेष प्रिय हो गए। रोज उन्हें देखते-देखते उनसे मित्रता करने की इच्छा होने लगी। मगर उनसे दोस्ती करना आसान नहीं रहा। जाने कितने जतन करने पड़े।

मैं रोज खिड़की के पास आकर 'मिठू-मिठू' बोलती, थोड़ा पुचकार कर हट जाती। पहले दो-चार दिन तो वे उड़ गए मेरी आवाज से। लेकिन मैं भी कहां कम थी। हार मुझे मंजूर नहीं थी। कभी भिगोए चने चुपके से रख देती खिड़की के बाहर। कभी कटे मीठे फलों के टुकड़े और उसी तरह आवाज लगाकर हट जाती। फिर छिपकर देखती कि कैसे वे प्यार से उसे खाते हैं। समय के साथ उन्होंने मुझे देखकर भागना भी बंद कर दिया। धीरे-धीरे उनको मुझ पर भरोसा होने लगा। अब न तो वे पहले की तरह उड़ते और न अचकचाते। ढीठ की तरह बैठे रहते। मैं भी उनके साथ खूब बहस करती। हारकर कभी वे चुप हो जाते तो कभी मैं।

हमारी इस मजेदार दोस्ती पर घरवाले भी हंसते। आखिर इतना सब्र जो किया था मैंने उनकी दोस्ती के लिए। लेकिन कहते हैं न कि खुशियों को भी नजर लग जाती है। जाने कैसे अचानक मैं बहुत बीमार पड़ गई। इतनी कि एडमिट होना पड़ गया मुझे अस्पताल में। वहां घरवालों के साथ मैं अपने उन दोनों दोस्तों को भी मिस करती रहती। पता नहीं, परेशानी की इस घड़ी में उन तोतों को कौन देख पाता होगा!

करीब हफ्ते बाद जब घर आई, तो सबसे पहले उन्हीं दोनों को ढूंढती किचन की खिड़की तक पहुंच गई। वहां कुछ भीगे चने पड़े थे। पता चला काम वाली दीदी रख दिया करती थीं। थोड़ी तसल्ली मिली दिल को। लेकिन इतने दिनों तक कोई मनुहार नहीं कर पा रहा था उनसे, सो वे भी उदास हो गए थे। देखा, डाल पर एक तोता तो है लेकिन दूसरा नहीं। मेरी खड़बड़ाहट सुनकर वह चौंक गया। फिर जब मैंने 'मिठू' कहकर पुचकारा, तो वह गर्दन हिला-हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगा। इतने में दूसरा तोता भी आ गया। बस फिर क्या था! अपनी बकझक दोबारा शुरू हो गई। इतने दिनों बाद तीन दोस्त मिल जो रहे थे। मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि अब हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लगे।

चलते-चलते...

जैतून का तेल (olive oil) सेहत के लिए उपयोगी है। हृदय रोग और हड्डियों के लिए तो यह फायदेमंद है ही, मनोभ्रंश रोग (dementia) से होने वाली मृत्यु के खतरे भी इससे कम हो रहे हैं। बोस्टन में Harvard T.H. Chan School of Public Health की स्टडी में बताया गया है कि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट मस्तिष्क सुरक्षा में कारगर भूमिका निभाते हैं।

रीडर्स मेल

■ मतदान से वंचित होना होगा

मतदान सभी का अधिकार है। लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका चुनाव के लिए भारी-भरकम रकम खर्च किया जाता है। चुनाव आयोग कैंपेन भी चलाता है। इसके बावजूद मेरे जैसे कई लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हो पाया। दो साल पहले हम लोगों ने फॉर्म नंबर 6 भरा था, संबंधित डॉक्यूमेंट भी जमा कराए थे। लेकिन, इलेक्शन ऑफिस की लापरवाही के कारण हम लोगों का नाम दर्ज नहीं हो पाया। यह बहुत ही अफसोस की बात है। विभाग को सिस्टम की इस खामी को दूर करना चाहिए, ताकि कोई अपने अधिकार से वंचित न रह जाए।

-आर. डी. अग्रवाल (मुंबई), ईमेल से

■ हैप्पी मदर्स डे

मां वो अलौकिक शब्द है, जिसके स्मरण मात्र से ही रोम-रोम पुलकित हो उठता है, हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता है। मां की ममता और उसके आंचल को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मां, दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता होता है। स्नेह, त्याग, उदारता और सहनशीलता के कितने प्रतिमान गढ़ती है मां? कौन देखता है? कौन गिनता है भला? और कैसे गिने? ऋण, आभार, कृतज्ञता जैसे शब्दों से परायों को नवाजा जाता है। मां तो अपनी होती है, बहुत अपनी सी। हम उसका ऋण भला कैसे चुका पाएंगे, इसलिए हैप्पी मदर्स डे।

-नितेश मंडवारिया, ईमेल से

■ स्वस्थ रहने की चुनौती

फ़ास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है। रेस्टोरेंट या ढाबे के खाने में पौष्टिक तत्वों का समावेश कम ही होता है। अधिक धन कमाने की होड़ में लोगों ने स्वास्थ्य पर ध्यान देना कम कर दिया है। लोग व्यायाम और योग से भी दूर हो रहे हैं। इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इस तरह की जीवनशैली को त्यागना ही श्रेष्ठ होगा। कहते हैं 'सुबह की हवा लाख रुपये की दवा' का काम करती है। इसलिए सुबह जल्द उठना चाहिए, धूम्रपान-नशा करने से दूर रहना चाहिए। इन अच्छी आदतों से हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

-अंकित सोनी, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों से बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 11 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

editpagesahara@gmail.com

अनमोल वचन

अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है

-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

आबादी पर सवाल

देश में हिंदुओं की आबादी में कमी आ रही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारीः राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (1950-2015) दस्तावेज में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने खुलासा किया है। इसमें हिन्दू आबादी के 7.82 फीसद कम होने के साथ मुसलमानों की 43.15 फीसद बढ़ने की बात की गई है। सिखों की आबादी 1.24 फीसद से बढकर 1.85 फीसद तथा इसाइयों की 2.24 फीसद से बढ कर 2.36 फीसद हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बौद्ध भी बढ़े हैं, जबकि जैन व पारसियों की संख्या घटी है। यूं तो जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के माध्यम से आते हैं। जो 2011 के बाद से नहीं हो सकी है। जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, जो करोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस अध्ययन में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक

आबादी में आए उतार-चढाव के अंतरराष्ट्रीय रुझान का पता लगाने के लिए 167 देश शामिल थे, जिसके मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आबादी की बढ़ोत्तरी सबसे ज्यादा हुई। जबकि बांग्लादेश में 10 फीसद व पाकिस्तान में 10 फीसद मुसलमानों की आबादी में बढ़त देखी गई। देश में मौजूदा वक्त में लोक सभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें सत्ताधारी दल पहले ही धार्मिक आधार पर बयानबाजियां करने और समाज में दरारें पैदा करने में हिचक नहीं रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट का प्रचार खास समुदाय को निशाना बनाने में सहायक साबित हो सकता है। विपक्ष भी इसे चुनावी चाल कह आरएसएस का एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहा है। वास्तव में हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाना और उनके साथ सहिष्णुता बरतना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुसलमानों की आबादी बढ़ने के कारणों में यूं तो उनकी चार शादियां, धर्मांतरण व घुसपैठ को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि इसके पीछे अशिक्षा व जागरूकता की कमी अधिक है। विशेष समुदाय पर देश की जनसांख्यिकी बदलने के प्रयासों का आरोप मढ़ना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। बीते सौ वर्षों में वे 12.5 फीसद से बढकर 22.5 फीसद हो चुके हैं। इसलिए केवल भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के लिए भ्रामक प्रचार से बाज आना चाहिए। साथ ही उन्हें जागरूक करने और सेहत संबंधी फायदों के विषय में आगाह करने के प्रयास करने चाहिए।

सतर्क रहें निवेशक

शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,062.22 अंक यानी 1.45 फीसद गिरकर 72,404.17 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस भारी गिरावट से निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि डूब गई। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि लोक सभा चुनाव के परिणामों की अनिश्चितताओं से शेयर बाजार भयभीत है। जाहिराना तौर पर देश की घरेलू (चुनाव परिणाम संबंधी) परिस्थितियां और विदेशी परिदृश्य दोनों शेयर बाजार की दृष्टि से प्रतिकूल हैं। इस कारण जहां एक ओर चौतरफा बिकवाली और दूसरी ओर विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी भी गिरावट की बड़ी वजह बताई जा रही हैं। लोक सभा चुनाव का तीसरा चरण हो चुका है और करीब आधी सीटों पर मतदान के बावजूद तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सरकार

किसकी बनेगी। चुनाव के दौरान संपत्ति के पुनर्वितरण का मामला बहस के केंद्र में है। कांग्रेस के टेक्नोक्रेट नेता सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद विरासत कर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनाव सभाओं में कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं। ज्यादातर अमीर और समृद्धशाली लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं। जाहिर है कि यह अमीर तबका भयभीत है कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आ जाती है तो उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देगी। विदेशी मोर्चे पर भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इस्राइल-फिलिस्तीन और रूस-यूक्रेन युद्ध किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। गाजा के दक्षिण शहर राफा में इस्राइली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। इस्राइल ने अपने गॉड फादर अमेरिका की सलाह को अनसुना कर दिया है। इस्राइल पर हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के हमले तेज हो सकते हैं। इधर, रूस ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो यूक्रेन में अपने सैनिक भेजता है तो परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। इन परिस्थितियों में शेयर बाजार की अनिश्चितता आगे भी बने रहने की आशंका है। ऐसे में शेयर बाजार के निवेशकों को बहुत ही चतुराई से अप ना पूंजी निवेश करना चाहिए। यह बाजार जोखिमों से भरा है और ऐसे में कमजोर दिल वालों को शेयर बाजार से दूर ही रहना चाहिए।

कटाक्ष/ कबीरदास

दोस्त-दोस्त ना रहा!

इन विरोधियों को मोदी जी कभी माफ नहीं करेंगे। दिल से माफ करना छोड़ो, कहने को भी माफ नहीं करेंगे। बताइए, पीछे पड़ पड़ के, पीछे पड़ पड़ के, बेचारे से पाप करा दिया। वही रात-दिन एक ही रट--तुम्हारा दोस्त अडानी, तुम्हारा दोस्त अंबानी। वही रात दिन एक ही शिकायत, तुम्हारे यार अडानी ये कर दिया, तुम्हारे यार अंबानी ने वो क्यों कर दिया? वही हर वक्त की तानाकशी--तुम दो, तुम्हारे दो; जो दो, अपने यारों को दो! और भी न जाने क्या-क्या! इंसान तो इंसान, भगवान के बर्दाश्त की भी एक हद्द होती है। गुस्से में साहेब के भी मुंह से निकल गया--अडानी, अंबानी यार होंगे तेरे! कमबख्तों ने डलवा दी ना पक्की दोस्ती में दरार। अब देते रहें सफाइयां; प्यार का धागा तो टूट गया! बेचारे शेयर बाजार को खामखां में तगड़ी पटकनी लग गई सो ऊपर से।

अब प्लीज कोई विरोधियों के इस पाप पर यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करे कि टैंपो का तो इस चुनावी सीजन में विरोधियों ने एक बार जिक्र तक नहीं किया था, फिर नोटों से लदे टैंपुओं की तो बात ही कहां उठती है, लेकिन नोटों से लदे टैंपुओं की बात से ही क्या होता है? बेशक, नोटों से भरे टैंपुओं की बात मोदी जी की ऑरीजिनल थी। बोरों में भरे नोटों की बात भी उनकी ऑरीजिनल थी। काले धन के बोरों की बात भी। आखिर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, क्या दूसरों की कही बातें दोहराएगा? मोदी जी को नकलची समझ रखा है क्या? मोदी जी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, तो ऑरीजिनल विचार अपने आप झरने लगते हैं, उनके टेलीप्राम्टर से। बोलने लगते हैं तो कल्पना के प्रवाह में दूर तक बहते चले जाते हैं। इस बार प्रवाह में बहते-बहते जरा ज्यादा दूर तक निकल गए। इतनी दूर तक कि राहुल ने पूछना शुरू कर दिया कि नोटों से लदे टैंपो रिसीव करने का आप का अनुभव है क्या? टैंपो का नंबर क्या था? और न भी जाने क्या अल्लम-गल्लम। पर ये सब करा-धरा तो विरोधियों का ही है। न पब्लिक के बीच हर टैम अडानी-अंबानी करते, न साहेब को गुस्सा आता और न साहेब दोस्तों को सारे आम गाली देते। विरोधी अब कुछ भी सफाई दें, तीन दोस्तों की सालों पुरानी दोस्ती में दरार डलवाने का पाप तो उनके ही सिर पर है।

ईयू में चीन की घुसपैठ

सामयिक

प्रो. ब्रह्मदीप अलूने

मध्य और दक्षिणपूर्व यूरोप के चौराहे पर स्थित सर्बिया में हजारों लोगों ने चीन और सर्बिया के झंडे हाथों में लिए शी जिनिपंग का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है उसने यह संदेश दिया है कि चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है और यह नई विश्व व्यवस्था में चीन के मजबूती से उभरने के संकेत है। दरअसल, नई विश्व व्यवस्था में शक्तियां क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में केंद्रित है इसलिए कूटनीति का संचालन इसी व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। शी जिनिपंग आर्थिक महाशक्ति बनने की चीनी प्रतिबद्धता को यूरोपीय यूनियन, आसियान और कुछेक क्षेत्रीय सहयोग मंच के जरिए बखूबी पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चीन का ख्वाब पूरा होने की उम्मीदें भी बढ़ गई है।

बेल्ट एंड रोड चीन की विदेश नीति का केंद्र बिंदु रहा है, इसके तहत चीन ने नई सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और आधारभूत संरचना के निर्माण में अरबों डॉलर दांव पर लगाकर अपने व्यापारिक संबंधों को दुनिया भर में विकसित किया है। चीन की ये रणनीति एशिया, इंडो पैसिफिक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक गहरा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही है।

सर्बिया, मध्य बाल्कन के सुदूर दक्षिणी किनारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है और यह देश बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। सर्बिया में तेल, गैस, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, मैग्नीशियम तथा संगमरमर के भंडार हैं। चीन ने सर्बिया में आधारभूत ढांचे को मजबूत करके यहां के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। चीन और सर्बिया ने बेल्ट एंड रोड पहल के ढांचे के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे न केवल सर्बिया में लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है, बल्कि दोनों देशों में विकास की गति भी बढ़ी है। सर्बिया और आसपास के बाल्कन देशों में पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अरबों यूरो का निवेश किया है। मध्य यूरोप के एक और देश हंगरी और चीन का सहयोग भी नई उंचाइयों पर है। बीजिंग में हंगेरियन सांस्कृतिक केंद्र वर्षों से सफलता के साथ काम कर रहा है। बुडापेस्ट में चीन सांस्कृतिक केंद्र का जल्द ही आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा। हंगेरियन भाषा पाठ्यक्रम कई चीनी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हैं। कन्फ्यूशियस संस्थान और कन्फ्यूशियस क्लासरूम हंगरी में लोकप्रियता और भागीदारी प्राप्त कर रहे हैं। शी जिनिपंग ने कहा है कि हम बेल्ट एंड रोड पहल और हंगरी की पूर्वी उद्घाटन रणनीति के बीच अधिक

तालमेल बनाने के लिए हंगरी के साथ काम करेंगे और बुडापेस्ट बेलग्रेड रेलवे लिंक और अन्य महत्त्वपूर्ण सहयोग परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित विकास और अन्य उभरते क्षेत्रों में हंगरी के साथ चीन का सहयोग निरंतर मजबूत हुआ है।

यूरोप के इन दो देशों की यात्रा के पहले शी जिनिपंग फ्रांस पहुंचे थे। फ्रांस यूरोपीय संघ का अहम सदस्य होने के बाद भी कूटनीतिक स्वायत्ता को लेकर अमेरिका के खिलाफ मुखर रहा है। पिछले वर्ष मेक्रों ने चीन की यात्रा के बाद वन चाइना नीति का समर्थन किया था। यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक मजबूत संगठन है जो व्यापार, सुरक्षा, कृषि मत्स्य पालन, पर्यावरण और जलवायु सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। वैश्विक कूटनीति में इसका अहम स्थान है। यूरोपीय संघ स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि, लोकतंत्र, आधारभूत स्वतंत्रता एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधि के नियमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अमेरिका के साथ इसके गहरे आर्थिक और सामरिक सरोकार है और नाटो इसका संवर्धन करता है। इंडो पैसिफिक में चीन सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन फ्रांसिसी राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर देनी चाहिए। जाहिर है चीन को लेकर यूरोपीय देशों और अमेरिका में मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। यूरोपीय संघ में शामिल हंगरी और फ्रांस चीन के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे है। इससे अमेरिका की उस मुहिम को धक्का लगा है, जिसके अनुसार वह यूरोपीय देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देता रहा है।

अमेरिका यूरोप में साझा विदेशी एवं सुरक्षा नीति के लिए भी प्रतिबद्धता दिखाता रहा है, लेकिन चीन के विरोध को लेकर एकरूपता दिखाई नहीं पड़ती। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में तथा चीन के यूरोप पर बढ़ते प्रभाव का असर एशिया, अफ्रीका, यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक पर भी पड़ सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचार के सुरक्षित समुद्री मार्ग को लेकर यूरोपीय संघ की स्पष्ट नीति रही है और चीन इसके मार्ग में बड़ी चुनौती नजर आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने चीन के वैश्विक प्रभावों को स्वीकार कर लिया है। चीन ने 2012 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के इरादे से एक फोरम शुरू किया था। दक्षिण पूर्वी, मध्य और पूर्वी यूरोप में चीन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की यह कोशिश रही है की वह यूरोपीय संघ के साथ एक ऐसी वैश्विक निवेश योजना पर आगे बढ़े जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के तौर पर सामने रखा जा सके, लेकिन जमीन पर ऐसा कोई भी प्रयास सफल नजर नहीं आता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही अब ग्लोबल गेटवे के रूप में प्रभाव छोड़ रही है और इससे यूरोप के कई देश इनकार भी नहीं कर रहे हैं। कोविड काल में चीन ने दुनिया को चमत्कृत करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का इतिहास रचा था।

चीन चाहता है कि यह कारोबार और बढ़े इसके लिए चीनी राष्ट्रपति यूरोप की यात्रा पर गए थे। यह भी दिलचस्प है कि चीन की उपस्थिति से जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी और रोमानिया में विकास तो हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर भी हुए हैं। चीन ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों की मदद कर प्रतिबंध रहित समांतर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा है। इन सबके बाद भी यूरोपीय संघ के कई देश आर्थिक प्रगति के लिए चीन को स्वीकार कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों पर गहरी चोट होने की आशंका बढ़ गई है।

चीन चाहता है कि यह कारोबार और बढ़े इसके लिए चीनी राष्ट्रपति यूरोप की यात्रा पर गए थे। यह भी दिलचस्प है कि चीन की उपस्थिति से जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी और रोमानिया में विकास तो हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर भी हुए हैं। चीन ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों की मदद कर प्रतिबंध रहित समांतर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा है। इन सबके बाद भी यूरोपीय संघ के कई देश आर्थिक प्रगति के लिए चीन को स्वीकार कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों पर गहरी चोट होने की आशंका बढ़ गई है

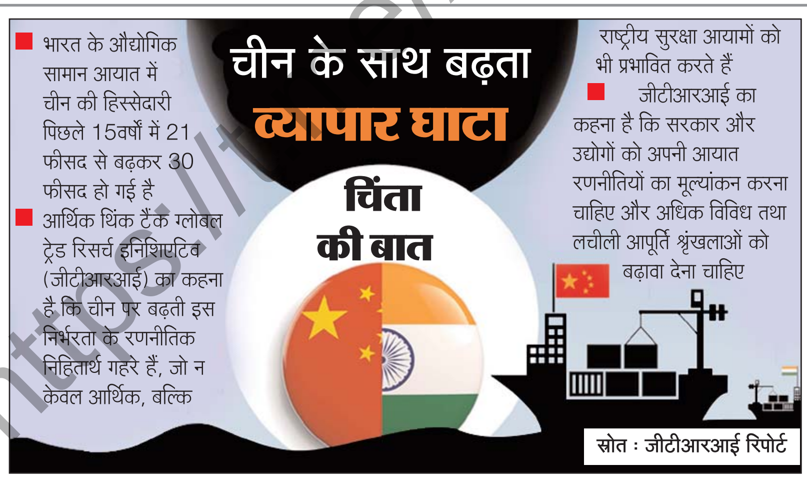

क्या भारतीय चुनाव करवट ले रहा है? शेयर बाजार जैसे संकेतकों से तो लगता है कि हां! क्या इंडिया ब्लॉक, जो गठबंधन से ज्यादा राजनीतिक जोड़-तोड़ है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है! द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश जनरल को चर्चिल की कही बात याद आ रही है- 'सबसे खराब बात है कि आप सहयोगियों से लड़ पड़ें और उससे भी खराब उनको साथ लिये बिना दूसरों से लड़े।'

एन. राम, पत्रकार
@nramind

अब वो बात नहीं रही

सीएनजी | पंकज चतुर्वेदी

राजधानी दिल्ली की हवा में इन दिनों अजब किस्म का जहर घुल रहा है। अजब इसलिए कि जिस ईंधन से वाहनों को चलाना सुरक्षित घोषित किया गया था, अब वही ईंधन दम घोंट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) के ताजे एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 224 है और इस बार हवा का मिजाज बिगड़ने का अकारण नाइट्रोजन डाई आक्साईड (एनओ 2) का आधिक्य है। एनओ-2 की हवा में मौजूदगी कार्बन डाईआक्साइड से भी अधिक घातक होती है। सीपीसीबी का आकलन है कि एनओ 2 की मात्रा बढ़ने का कारण सीएनजी वाहनों से निकलने वाली रासायनिक गैस हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के तंत्र ने महज पीएम 2.5 और 10 को नियंत्रित करने की कोशिशें की और इसके लिए सीएनजी वाहनों की संख्या इतनी हो गई कि अब काला धुएं की जगह अदृश्य धुआं इंसानों के जीवन का दुश्मन बना है। जुलाई-21 में जारी की गई रिपोर्ट 'बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन : सैटेलाइट डाटा रिवील एयर पॉल्यूशन इन्क्रीज इन इंडियाज एट मोस्ट पॉपुलस स्टेट कैपिटल्स' में चेतावनी दे गई थी कि साल दर साल दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हो रहा है। सेटेलाइट डाटा विश्लेषण के आधार पर ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 125 फीसद तक ज्यादा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के बढ़ने के कारण खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद का इस्तेमाल, मवेशी पालन आदि होता है, लेकिन बड़े शहरों में इसका मूल कारण निरापद या ग्रीन फ्यूल कहे जाने वाले सीएनजी वाहनों का उत्सर्जन है। जान लें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ मिल कर बनीं गैसें-जिन्हें 'आक्साईड आफ नाइट्रोजन' कहते हैं, मानव जीवन और पर्यावरण के लिए उतनी ही नुकसानदेह हैं जितना कार्बन आक्साईड या मोनो आक्साइड। यूरोप में हुए शोध बताते हैं कि सीएनजी वाहनों से निकलने वाले नेनो मीटर (एनएम) आकार के बेहद बारीक कण कैंसर, अल्जाइमर, फेफड़ों के रोग का खुला न्योता हैं। पूरे यूरोप में इस समय

सुरक्षित ईंधन के रूप में वाहनों में सीएनजी के इस्तेमाल पर शोध चल रहे हैं। विदित हो यूरो-6 स्तर के सीएनजी वाहनों के लिए भी कण उत्सर्जन की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है और इसी लिए इससे उपज रहे वायु प्रदुषण और उसके इंसान के जीवन पर कुप्रभाव और वैश्विक पर्यावरण को हो रहे नुक्सान को नजरअंदाज किया जा रहा है। जान लें पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले इस ईंधन से बेहद सूक्ष्म लेकिन घातक 2. 5 एनएम (नेनो मीटर) का उत्सर्जन पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में 100 से 500 गुना अधिक है। खासकर शहरी यातायात में जहां वाहन बहुत धीरे चलते हैं, भारत जैसे चरम गर्मी वाले परिवेश में सीएनजी वाहन उतनी ही मौत बांट रहे हैं जितनी डीजल कार-बसें नुकसान कर रही थी बस कार्बन के बड़े पार्टिकल कम हो गए हैं। यह सच है कि सीएनजी वाहनों से अन्य ईंधन की तुलना में पार्टिकुलेट मेटर 80 फीसद और हाइड्रो कार्बन 35 प्रतिशत कम उत्सर्जित होता है, लेकिन इससे कार्बन मोनो आक्साइड उत्सर्जन पांच गुना अधिक है। शहरों में स्मोग और वातावरण में ओजोन परत के लिए यह गैस अधिक घातक है। परिवेश में 'आक्साईड आफ नाइट्रोजन 'गैस अधिक होने का सीधा असर इंसान के स्वशन तंत्र पर पड़ता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2011 के एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सीएनजी पर्यावरणीय कमियों के बिना नहीं है, यह कहते हुए कि सीएनजी जलाने से संभावित खतरनाक कार्बोनिल उत्सर्जन की उच्चतम दर पैदा होती है।

अध्ययन से पता चला था कि रेट्रोफिटेड सीएनजी कार इंजन 30 प्रतिशत अधिक मीथेन उत्सर्जित करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कॉनर रेनॉल्ड्स और उनके सहयोगी मिलिंद कांडलीकर ने वाहनों में सीएनजी इस्तेमाल के कारण ग्रीनहाउस गैसों कार्बन डाईआक्साइड और मीथेन के प्रभावों पर शोध किया तो पाया कि इस तरह के उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की वृद्धि है। यह जान लें कि सीएनजी भी पेट्रोल-डीजल की तरह जीवाश्म ईंधन ही है। यह भी स्वीकार करना होगा कि ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में एरोसोल (पीएम) अल्पकालिक होते हैं, उनका प्रभाव अधिक क्षेत्रीय होता है और उनके शीतलन और ताप प्रभाव की सीमा अभी भी काफी अनिश्चित है। सीएनजी से निकली नाइट्रोजन आक्साईड अब मानव जीवन के लिए खतरा बन कर उभर रही है। दुर्भाग्य है कि हम आधुनिकता के जंजाल में उन खतरों को पहले नजरअंदाज करते हैं जो आगे चल कर भयानक हो जाते हैं। जान लें प्रकृति के विपरीत ऊर्जा, हवा, पानी किसी का भी कोई विकल्प नहीं हैं। नैसर्गिकता से अधिक पाने का कोई भी उपाय इंसान को दुख ही देगा ।

पात्रता | संत राजिन्दर

इं पात्र बनना एक खाली प्याला होने की भांति है। यह जीवन जीने की एक कला है। पात्रता का अर्थ है जो प्रभु हमें दे उसे पाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें।

यह प्रार्थना की सर्वोत्तम अवस्था है, जिसमें हम किसी वस्तु की मांग नहीं करते बल्कि केवल प्रेम और भक्ति-भाव से जो कुछ प्रभु हमें देना चाहते हैं उसे खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ हमारे लिए बेहतर होगा परमात्मा हमें वही देंगे। हम ऐसी प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब प्रभु में हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो। प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का पनपना बहुत जरूरी है, यह अनुभव से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर हम प्रभु के आशीर्वाद को उसी रूप में पाना चाहते है, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होती हों। जब प्रभु का आशीश हमें उस रूप में प्राप्त नहीं होता तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। कभी-कभी हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारे लिए भली नहीं होती या इतनी अच्छी नहीं होती जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना किसी वस्तु को पाने के लिए करते हैं, तब हो सकता है कि हमारी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाए या फिर अगली बार बिल्कुल स्वीकार न हो। इससे हमारे उदास हो जाने का खतरा बना रहता है। हम प्रभु में आस्था खो देते हैं, लेकिन जब हम ऐसी वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करते जो प्रभु हमें देना नहीं चाहते, फिर हमारे निराश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पात्र बनकर प्रार्थना कर पाने के लिए आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है। हमें आध्यात्मिक विकास पाने के लिए किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाना होगा। उनके संपर्क में रहते हुए, उनकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार चलकर एवं आत्मिक अनुभव पाकर हमारा श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। तब हमें यह भरोसा हो जाता है कि प्रभु हमारे मित्र, शुभचिंतक व रक्षा करने वाले हैं और तब हम स्वयं को प्रभु के हवाले छोड़ देते हैं। 'तेरा भाणा मीठा लागे।' पात्रता की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत होता है और हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। प्रभु द्वारा दी गई देनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें खाली प्याले की तरह विनम्रता अपनानी चाहिए। यदि हम धैर्य और इंतजार करेंगे, तब हम उनसे और भी अधिक प्राप्त करेंगे जितनी कि हमारी कल्पना भी न थी।

रीडर्स मेल

बयान से मुसीबत में कांग्रेस

विदेश में रहने वाले सैम पित्रोदा के वक्तव्य से भारत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्षेत्रवाद की नई परिभाषा देते हुए पूर्व में रहने वाले को चीनी, दक्षिण में रहने वाले को अफ्रीकी ,उत्तर में रहने वालों को श्वेत और पश्चिम में रहने वालों को अरब की संज्ञा से नवाजा है, जिसने भारत में जारी राजनीतिक उठापटक और घमासान में आग में घी डालने का काम किया है। इससे पहले पित्रोदा ने विरासत टैक्स की भारत में वकालत की थी। हालांकि उस संदर्भ में भी कांग्रेस बचाव करते दिखाई दी थी। इस प्रकरण से कांग्रेस को ही नहीं बल्कि इण्डिया 'गठबंधन को भी लोक सभा चुनाव में भारी नुकसान होने का संकट बना रहेगा। कांग्रेसी नेतायों को बयानबाजी से हर हाल में बचाना होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

जल्द निकले समाधान

एअर इंडिया की उड़ाने रद्द होने से यात्रियों की परेशानी जायज है। भारत में हजारों लाखों लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का रास्ता केवल इसलिए चुनते है ताकि वो जल्दी अपनी यात्रा तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, परंतु उड़ाने रद्द होने अथवा इनमें अकारण देरी होने से सभी यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने से ना केवल उनके समय बल्कि धन का भी नुकसान होता है। एयर इंडिया सहित भारत की सभी एअरलाइंस को इस विषय पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। एअर इंडिया को अपने प्रबंधन में सुधार करके यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की ओर ध्यान देना चाहिए। एअर इंडिया केवल अपनी अंदरूनी समस्याओं को आधार बनाकर यात्रियों को परेशान नहीं कर सकती। इस मामले में विमानन महानिदेशालय ने एअर इंडिया प्रबंधन से जवाब-तलब किया है। परंतु यात्रियों को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। एयर इंडिया और नागरिक विमानन निदेशालय को जल्द-से-जल्द इस समस्या के निवारण के प्रयास करने चाहिए ताकि भविष्य में यात्रियों को इस तरह की परेशानियों से बचाया जा सके।

हितेंद्र डेढा, चिल्ला गांव, दिल्ली

खाड़ी देशों में पानी अनमोल

खाड़ी के शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्य में, जहां तेल लंबे समय से क्षेत्र का आर्थिक आधार रहा है, एक नई कहानी सामने आ रही है। खाड़ी में पानी नया तेल कहा जाने लगा है। चूंकि पानी वहां एक महत्त्वपूर्ण और सीमित संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए उसकी उपलब्धता पर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। एक उपाय और है कि नमकीन पानी की पर्यावरणीय लागत को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाए। नमकीन पानी को कम करने और पुनः उपयोग करने के तरीकों की खोज करना इसके प्रमुख भाग हैं। अगले दशक में अनुमानित 30 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के साथ, खाड़ी को अपने जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। जीसीसी देशों द्वारा अपने जल संसाधनों पर डीकार्बोनाइजेशन, विविधता लाने और मांग को कम करने के नेतृत्व से न केवल क्षेत्र को बढ़ते जल सुरक्षा जोखिमों के अनुकूल होने में मदद मिलेगी, बल्कि इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य शुष्क देशों को भी मदद मिलेगी।

मनीष कुमार चौधरी, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 267
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
।समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

संदेशखाली : कौन सच्चा, कौन झूठा

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली मामले पर उठा राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। संदेशखाली का पूरा घटनाक्रम एक हॉरर शो की तरह सामने आया। इसी वर्ष 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर छापामारी करने गई ईडी की टीम पर पार्टी समर्थकों ने हमला कर दिया था। उसके बाद एक के बाद एक खौफनाक कहानियां सामने आती गईं। शाहजहां शेख और उसके दो ताकतवर सहयोगियों के कथित अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के खिलाफ गांव की महिलाओं के विरोध के चलते कालिंदी नदी के किनारे बसा यह गांव देशभर में कुख्यात हो गया। संदेशखाली कांड लोकसभा चुनावों के दौरान कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक मुद्दा बन गया। बलात्कार या महिलाओं को जबरन उठाने संबंधी कहानियां सामने आने के बाद ऐसा आभास कराया गया जैसे आजादी से पूर्व जागीरदार लोगों के साथ अत्याचार ढाते थे वैसा ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है। दो तरह के मामले सामने आए। पहला गांव की जमीनों पर जबरन कब्जे का और दूसरा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का। न्यायपालिका ने भी इन घटनाओं को शर्मनाक बताया और पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा।

पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 55 दिनों की भागदौड़ के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। अब इस मामले ने यूटर्न ले लिया है। शाहजहां शेख पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली तीन महिलाओं में से दो ने अपनी शिकायत वापिस ले ली है। इन महिलाओं का कहना है कि भाजपा के एक स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए, बाद में इसे तृणमूल नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों के रूप में पेश किया गया है। इन दो महिलाओं ने दावा किया है कि उनका यौन उत्पीड़न नहीं हुआ और न ही उन्हें किसी ने रात के अंधेरे में शाहजहां शेख और उनके साथियों के घर जाने के लिए दबाव बनाया। हाल ही में एक स्टिंग आपरेशन ने सारे मामले में नाटकीय मोड़ ला दिया है। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें संदेशखाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने उनसे और अन्य भाजपा नेताओं से कहा था कि क्षेत्र की तीन-चार स्थानीय महिलाओं को शाहजहां शेख सहित तीन टीएमसी नेताओं के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाने के लिए उकसाएं। यानि सारी साजिश शुभेन्दु अधिकारी ने ही रची थी। शुभेन्दु अधिकारी और भाजपा दोनों ने वीडियो को फर्जी करार दिया है और भाजपा का कहना है कि यह स्टिंग आपरेशन फर्जी है और संदेह है कि इसे एआई का उपयोग करके बनाया गया है।

> **अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा। क्या संदेशखाली मामला एक बड़ी साजिश है और बंगाल की सरकार को अस्थिर करने का कोई खेल है? तृणमूल ने भाजपा के आरोपों को बंगाल की महिला अस्मिता पर प्रहार करार दिया है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए महिलाओं को धन भी दिया गया। चुनावों के दौरान हर पार्टी अपने-अपने हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी हुई है। आज की राजनीति में मूल्यों और नैतिकता तथा सिद्धांतों की कोई जगह नहीं बची है। हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए कर रहा है।**

दूसरी तरफ तृणमूल इस पूरे प्रकरण के लिए भाजपा पर ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। तृणमूल इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच चुकी है और निर्वाचन आयोग ने शुभेन्दु अधिकारी और अन्य पर शिकायत भी दर्ज करा दी है। तृणमूल ने भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल और बशीरहाट सीट से भाजपा प्रत्याशी रेखा पात्रा के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया है। अब सवाल यह है कि महिलाओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतें झूठी हैं या वायरल वीडियो सच्चा है या झूठा। संदेशखाली की पांच महिलाओं समेत हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और अपना दुख-दर्द बयान किया था।

अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा। क्या संदेशखाली मामला एक बड़ी साजिश है और बंगाल की सरकार को अस्थिर करने का कोई खेल है? तृणमूल ने भाजपा के आरोपों को बंगाल की महिला अस्मिता पर प्रहार करार दिया है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए महिलाओं को धन भी दिया गया। चुनावों के दौरान हर पार्टी अपने-अपने हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी हुई है। आज की राजनीति में मूल्यों और नैतिकता तथा सिद्धांतों की कोई जगह नहीं बची है। हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए कर रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया खातों से फर्जी कंटेंट को संज्ञान में आने के तीन घंटे के भीतर हटा दें।

निर्वाचन आयोग ने सूचनाओं को विकृत करने या गलत सूचना का प्रचार करने वाले 'डीपफेक' बनाने के लिए आर्टिफियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर राजनीतिक दलों को चेतावनी दी और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा आचार संहिता के कुछ उल्लंघन और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने आज सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग को अब इस मामले में वायरल वीडियो को परखना होगा कि क्या यह सही है या फर्जी। अगर सही है तो भाजपा नेताओं की जवाबदेही तय करनी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश करनी होगी। अगर यह फर्जी है तो इसे बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

कैसे नेता जी का दिव्यास्त्र उन्हीं को...

समस्त देश लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है,
तो वहीं एक राज्य में निर्दलीय विधायकों पर चढ़ा सरकार गिराने का बुखार है,
इस सत्ता के बनते बिगड़ते गणित में आलाकमान दिख रहा लाचार है,
कैसे नेता जी का दिव्यास्त्र उन्हीं को घायल करने को बेकरार है..!

गीता पाढा

क्या भाजपा की बी टीम बन गई है बसपा?

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

भाजपा पर लगातार तीखे हमले कर रहे अपने भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। हालांकि इस सारी कवायद से पहले ही यूपी में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया था कि वह गुप्त रूप से राज्य में भाजपा की मदद कर रही हैं। यह अटकलें तब शुरू हुईं जब उन्होंने अचानक राज्यभर में कम से कम आठ लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवारों के समान जाति वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा ताकि इन दोनों दलों को नुक्सान पहुंचाया जा सके। आखिरी मिनट में हुए बदलावों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों की मदद करने के प्रयास के रूप में देखा गया। उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिये जो समाजवादी पार्टी के वोट काट सकें।

इस राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला बदलाव जौनपुर में हुआ, जहां बसपा ने जेल में बंद बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें एक विजयी उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन बाद में उनकी जगह एक यादव को उम्मीदवार बनाया गया, जिससे सपा के यादव वोटों में कटौती हो सके। जौनपुर में यादव समुदाय का दबदबा है। सीतापुर में एक रैली में भाजपा पर हमला करने के बाद आनंद को पार्टी से बाहर करने का उनका निर्णय पुष्टि करता है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भाजपा की बी-टीम में बदल दिया है।

आखिर पित्रोदा से कांग्रेस ने पीछा छुड़ाया

गांधी परिवार के विवादास्पद मित्र सैम पित्रोदा का अपनी पार्टी को मुश्किल में डालने का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में यह कहकर तूफान खड़ा कर दिया था कि गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी के लिए मध्यम वर्ग को अधिक कर देना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया था कि 'स्वार्थी' नहीं होना चाहिए। लगभग उसी समय एक अन्य साक्षात्कार में, उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों को कम महत्व दिया। पित्रोदा ने तब कहा था कि जो हुआ सो हुआ। पित्रोदा ने उस समय कहा था कि भाजपा ने पांच साल में क्या काम किया। 2019 में वह विवादों में घिरने से बच गये थे, क्योंकि बालाकोट हमला पुलवामा आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में हुआ था। और यह चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया जिससे भाजपा को बहुमत मिल गया। इस बार पित्रोदा उतने भाग्यशाली नहीं रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 2024 के अभियान में कांग्रेस पर तीखे हमले बोले और पित्रोदा की टिप्पणियों को चर्चा के मुख्य केंद्र में ला दिया। पित्रोदा ने सबसे पहले विरासत कर के बारे में बात की और फिर उन्होंने जातीय विशेषताओं और त्वचा के रंग के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों के बीच तुलना करके कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का काम किया। इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें 'नस्लवादी' कहा और उनके साथ जुड़ने के लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। यहां तक कि गांधी परिवार को भी एहसास हुआ कि पित्रोदा अत्याधिक व्यस्त चुनाव में पार्टी को नुक्सान पहुंचा रहे हैं और इसके बाद उनसे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगा गया। हालांकि कांग्रेस हलकों में ऐसी अटकलें हैं कि पित्रोदा का इस्तीफा चुनाव की अवधि के लिए एक रणनीतिक कदम है और चुनाव के बाद पित्रोदा फिर से आईओसी के प्रमुख बन सकते हैं।

डेनमार्क के राजदूत स्वेन के पोस्ट के मायने क्या हैं?

भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने एक्स पर एक हालिया पोस्ट से हलचल मचा दी है जिसमें उन्होंने संभ्रांत चाणक्यपुरी क्षेत्र में अपने दूतावास के पीछे बढ़ते कूड़े के ढेर के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दूतावास की दीवार के पास कूड़े के ढेर दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बड़ी हरी-भरी और गंदगी भरी नई दिल्ली में आपका स्वागत है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसे हटाने की अपील भी की। उनका यह तरीका कई भारतीयों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की। कई भारतीयों ने पश्चिम देशों पर भारत की छवि खराब करने पर तुले होने का आरोप लगाया। एक अन्य उपयोगकर्ता ने जानना चाहा कि क्या उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाया गया था और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए डांटा गया था। अब सवाल यह है कि क्या वह वहां सफाई होने के बाद धन्यवाद का फॉलोअप वीडियो पोस्ट करेंगे।

विडंबना यह है कि स्वेन को भारत में तैनात मोदी के पसंदीदा राजनयिकों में से एक माना जाता है। बेशक उस क्षेत्र में सफाई का दायित्व एनडीएमसी के पास है और उसने त्वरित कार्रवाई की। इसका कोई राजनीति महत्व भी है या स्वेन की टिप्पणी को केवल सफाई के महत्व के तौर पर ही देखा जाए।

मंदिर की धुलाई : नफा या नुकसान

राहिल नोरा चोपड़ा

समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव 6 मई को पूजा-अर्चना करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर महादेव मंदिर गए थे। इसके बाद, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मंदिर को पवित्र गंगा जल से धोया। जबकि मंदिर के पुजारी मथुरा प्रसाद ने कहा कि मंदिर परिसर की धुलाई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी और इस घटना से मंदिर समिति का कोई लेना-देना नहीं है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा, "पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) इस बार उन्हें (बीजेपी को) धोने जा रही है। उन्होंने कहा, चुनाव में आसन्न हार को देखकर बीजेपी के लोग ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं।

मयावती के कैंडिडेट बदलने का किसको फायदा

बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर और बस्ती लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। पार्टी ने जौनपुर में गैंगस्टर-राजनेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के स्थान पर अपने मौजूदा पार्टी सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। इस बदलाव को जमानत पर जेल से बाहर आए धनंजय सिंह के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि अब बसपा के टिकट पर श्याम सिंह यादव मैदान में हैं, ऐसे में वह सपा के यादव वोट में सेंध लगाएंगे और इससे भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब जबकि धनंजय सिंह की पत्नी मैदान में नहीं हैं तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इससे न केवल जौनपुर में भाजपा की संभावनाएं उज्ज्वल हो गई हैं, बल्कि बगल के मछलीशहर कांस्टीट्वेंसी पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वहीं, बस्ती में बसपा ने दयानशंकर मिश्र की जगह लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट नहीं मिलने पर मिश्रा ने पिछले महीने भाजपा छोड़ दी थी और बाद में वह बसपा में शामिल हो गए थे।

टीडीपी-जनसेना के वादों की झड़ी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 13 मई को 175 सदस्यीय विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ होने वाले चुनाव केवल विधायकों या सांसदों को चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव मौजूदा योजनाओं को मजबूत करके राज्य के भविष्य को आकार देने का भी है। दूसरी ओर, टीडीपी और जन सेना ने तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी की तर्ज पर सुपर सिक्स लॉन्च किया है।

'सुपर सिक्स' में जनता से जो वादे किए गए हैं, उनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, हर साल गरीबों को मुफ्त में तीन एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक गरीब परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक लड़की के लिए 1500 रुपए की दर से 18,000 रुपए प्रति वर्ष की बालिका निधि, 3000 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त जल कनेक्शन और प्रत्येक बच्चे को 15,000 रुपए की वार्षिक शैक्षिक सहायता शामिल है। उनके घोषणापत्र में मुसलमानों के लिए हज भत्ते के रूप में 1 लाख रुपए, मौलवियों को मासिक मानदेय और ईसाइयों को यरूशलम जाने के लिए भत्ता भी दिया गया है। यह सब तब है जब, उनकी सहयोगी भाजपा ने प्रतिद्वंद्वी सरकारों द्वारा मुफ्त योजनाओं के रूप में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मजाक उड़ाया है।

कांग्रेस के गढ़ में प्रियंका का डेरा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित भुएमऊ गेस्ट हाउस में डेरा डालने का फैसला किया है। वह 6 मई को यहां पहुंची थीं और 20 मई को 5वें चरण के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी 18 मई तक यहां रहेंगी और रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के संबंधों की दुहाई देते हुए रायबरेली से अपने भाई राहुल और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को जिताने के पार्टी के प्रयासों का नेतृत्व करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 8 मई को रायबरेली में 25 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और मोदी सरकार पर ऐसे समय में अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का आरोप लगाया, जब उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेताओं के भी दोनों सीटों पर प्रचार करने की उम्मीद है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी में वरिष्ठ पर्यवेक्षक होंगे, जहां से परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा ताल ठोंक रहे हैं।

अब लवली के लिए नया उपनाम

दिल्ली में शहर की सबसे चर्चित खबर यह है कि अरविंदर सिंह लवली, जो अब 'पलटू राम' के उपनाम से मशहूर हो गए हैं, 4 मई को आप के साथ गठबंधन का हवाला देते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी वह अप्रैल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि, कुछ ही महीनों के बाद 2018 में वह वापस कांग्रेस में लौट आए थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को पार्टी का अंतरिम दिल्ली प्रमुख नियुक्त किया है।

यादव ने पार्टी छोड़ने पर लवली की आलोचना की "मैं अरविंदर सिंह लवली को अवसरवादी व्यक्ति की श्रेणी में रखता हूं। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।'' जबकि लवली ने दावा किया कि दिल्ली में चार सीटों पर प्रचार कर रही आप कांग्रेस और उसके नेताओं के नाम का भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, फिर भी वह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के वोट पाने की उम्मीद कर रही है। भाजपा में शामिल होने के लिए लवली की प्रमुखता स्पष्ट है, क्योंकि वह दिल्ली में चुनावों के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में से एक हैं।

देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगाह किया है कि संघर्षों, सत्ता केंद्रों में बदलाव और तेज होती प्रतिस्पर्धा के कारण इस दशक में दुनिया में 'बहुत अधिक उथल-पुथल' होगी और ऐसे में बहुत जरूरी है कि देश की कमान मजबूत हाथों में हो। जयशंकर ने गुरुवार शाम को दिए विशेष साक्षात्कार में 2020 के दशक के अंत तक एक ऐसी दुनिया की तस्वीर चित्रित की जो हमारे आज के संसार से बिल्कुल अलग होगी। वैश्विक शक्ति संतुलन के इस आकलन में उन्होंने कूटनीति और राजनीति में अपने लगभग 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर कुछ चिंतित करने वाले तथ्य पेश किए।

चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2019 में राजनीति में लेकर आए थे। जयशंकर ने कहा, ''कई सारे संघर्ष, तनाव, विभाजन! इन सभी पहलुओं के साथ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं,... मैं वास्तव में, इस दशक की शेष अवधि में बहुत अधिक उथल-पुथल वाले अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की तस्वीर पेश कर रहा हूं।'' विदेश मंत्री ने इस 'उथल-पुथल' की भविष्यवाणी के लिए विशेष रूप से अमेरिका के घटते दबदबे, यूक्रेन में युद्ध, गाजा में संघर्ष, लाल सागर में हमले, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती और नई प्रौद्योगिकियों के आविर्भाव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा-मेरा मानना है कि आज ये सभी घटनाक्रम मिलकर एक जबदरस्त उथल-पुथल की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और इन सबसे ऊपर प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा-ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में मतदाता विवेकपूर्ण तरीके से चुनाव करें ताकि भारत में एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व नेतृत्व कायम रहे।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को बनाए रखने की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा-मेरे हिसाब से, आज के हालात में भारतीय मतदाताओं को जो सबसे बड़ा चुनाव करना है- वह ये है कि आप भारत सरकार की कमान सौंपने के लिए किस पर भरोसा करेंगे? अपने राजनयिक अनुभव से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और मोदी सरकार की साख बढ़ाने के लिए देश में लोकप्रिय जयशंकर ने संकेत दिया कि दुनिया में यह उथल-पुथल पहले से ही शुरू हो चुकी है।

वरुण और चित्रा संग विज के वायरल वीडियो पर अटकलें

अम्बाला, (पंजाब केसरी) : अम्बाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण चौधरी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा संग हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अम्बाला छावनी के विधायक अनिल विज का वायरल वीडियो बीती शाम से ना केवल चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि राजनीतिक पंडितों ने इस पर अटकलें भी लगानी शुरू कर दी हैं। यह वायरल वीडियो अम्बाला छावनी में निकलसन रोड स्थित भाजपा कार्यालय के निकट का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में चित्रा सरवारा यह कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि उनके अभी तीन प्रोग्राम हैं तो इसके जवाब में अनिल विज यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यह भी प्रोग्राम है। इसके बाद जलपान का सिलसिला शुरू होकर इन दिनों पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण स्कूलों की होने वाली छुट्टियों का जिक्र करते हुए इस बात पर भी चर्चा होती सुनाई दे रही है कि भीषण गर्मी के चलते चुनाव भी दो महीने बाद होने चाहिए थे। इसी बीच वहां मौजूद एक समर्थक यह कहते हुए भी सुनाई दे रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपका जिक्र हो रहा था और आप आ भी गए। इन तीनो नेताओं के बीच हंसी खुशी के माहौल में बातचीत होते हुए दिखाई और सुनाई दे रही है हालांकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के समर्थक इसे एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित इसे आपदा में अवसर मानकर तरह तरह से अटकलें लगा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वरुण चौधरी अम्बाला छावनी में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा के साथ प्रोग्राम में जा रहे थे कि इसी बीच निकलसन रोड से जब उनकी कारों का काफिला गुजरा तो भाजपा कार्यालय के निकट उनकी मुलाकात वहां मौजूद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से हो गई।

हमीरपुर के लोग मेरी ताक़त, हर पल दिया साथ : सुक्खू

शिमला/हमीरपुर, विक्रान्त सूद (पंजाब केसरी) : हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायज़ादा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थित में अपना नामांकन दाखिल किया।

● कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायज़ादा ने हमीरपुर लोकसभा सीट से किया नामांकन

इसके बाद हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के लोग मेरी ताक़त हैं और यहां के लोगों ने मेरा हर पल साथ दिया है। आज मैं जिस मुक़ाम पर पहुँचा हूँ, उसके लिए हमीरपुर और नादौन की जनता का जीवन भर आभारी रहूँगा। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी के आशीर्वाद से आज एक साधारण परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। उन्होंने कहा कि अपने नेता पर विश्वास करने के लिए आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमीरपुर जिला की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हमीरपुर जिला से जानबूझकर कर एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। जिस जिला को मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्री पद मिलता था, उस जिला को पिछली सरकार में कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने पूछा कि जयराम ठाकुर ने पांच साल में हमीरपुर जिला के लिए क्या किया। पंद्रह साल पहले मुख्यमंत्री रहते प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में बस अड्डे का शिलान्यास किया था और जयराम ठाकुर ने बस अड्डा बनाने के लिए एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री का पद सँभालते ही युद्ध स्तर पर बस अड्डा बनाने का काम शुरू हो गया है जो आने वाले नौ महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही गांधी चौक की तारों को अंडरग्राउंड करने का काम भी शुरू हो गया है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

केजरीवाल को राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देकर प्रथम दृष्टया चुनाव और लोकतंत्र का महत्व बढ़ाया है। शीर्ष अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद उन्हें 1 जून तक रिहाई दी है। देश में मतदान का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न होगा और 2 जून को उन्हें समर्पण करना होगा, वह फिर जेल जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि चुनाव के बचे हुए कम से कम तीन चरणों में केजरीवाल ठीक से चुनाव प्रचार कर पाएंगे। बेशक, आम आदमी पार्टी में एक नए जोश का संचार होगा और विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, यह अंतरिम जमानत सशर्त है। रिहाई के इन 21 दिनों में वह मुख्यमंत्री का कोई कर्तव्य नहीं निभाएंगे। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जाएंगे। अपने इस मुकदमे के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद अनेक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के पास मुद्दों का अभाव नहीं है।

अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के दो मुख्य आधार हैं। पहला आधार तो यही है कि मुकदमा नया नहीं है, पर गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल लाजिमी है। किसी भी पार्टी के प्रमुख या मुख्यमंत्री के लिए चुनाव प्रचार का विशेष महत्व होता है। किसी पुराने मामले में अगर ठीक चुनाव से पहले कार्रवाई शुरू होती है, तो संदेह की गुंजाइश बन जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को माना है और ईडी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर ईडी गिरफ्तारी के समय और जरूरत को न्यायोचित ठहरा पाती, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिन की रिहाई नसीब नहीं होती। दूसरी बात, मुकदमा होने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, वह मुकदमे से जुड़े तथ्यों के साथ तब भी खिलवाड़ कर सकते थे, पर अदालत की नजरों में उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका लाभ उन्हें रिहाई के रूप में मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ इशारा किया है कि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। इन तथ्यों की रोशनी में ईडी केजरीवाल की रिहाई का ठीक से विरोध नहीं कर सकी है। खैर, ईडी के पास अभी भी मौका है, उसे आगामी दिनों में पूरी तैयारी और अकाट्य साक्ष्यों के साथ अदालत में आना होगा, वरना एक मुख्यमंत्री को ज्यादा समय तक जेल में रखना गरिमामय नहीं है।

ईडी के पास अभी भी मौका है, उसे अकाट्य साक्ष्यों के साथ अदालत में आना होगा, वरना एक मुख्यमंत्री को ज्यादा समय तक जेल में रखना गरिमामय नहीं है।

खैर, अदालत में 2 जून को चाहे जो हो, आगामी 21 दिन केजरीवाल के लिए उतने ही अहम होंगे, जितने उनके विरोधियों के लिए। विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता या प्रासंगिकता से भला कौन इनकार कर सकता है? अगर इन दोनों राज्यों में आम आदमी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी अपनी बात मजबूती से रखने का आधार मिलेगा। लोकतंत्र में बहुत हद तक जनता ही फैसला करती है, किसी दागी को किनारे लगाने की बात हो या सत्ता सौंपने की बात, जनादेश के बाद ही व्यवस्था को आगे बढ़ने या ठिठक जाने का इशारा मिलता है। बेशक, यह एक विरल मामला है, जब जेल में बंद एक मुख्यमंत्री या नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया है, पर यह समग्र भारतीय राज्य की उदारता का नवीनतम प्रमाण है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
11 मई, 1949

मजदूर संगठन

मजदूर समाज का महत्वपूर्ण वर्ग है। समाज में सुख और शांति जितनी इस वर्ग पर निर्भर करती है, उतनी और किसी पर नहीं। मजदूर ही संपत्ति का असली उत्पादनकर्ता है। मजदूर पूंजी पैदा करने वाला है। यह समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था है कि पूंजी को पैदा करने वाला नंगा-भूखा रहे और पूंजी का अधिकतर हिस्सा चन्द व्यक्तियों की तिजोरियों और बैंक खातों में जमा हो जाये। गरीब और अमीर के बीच जब अन्तर बेहद बढ़ जाता है तो समाज के अस्तित्व के लिये गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। मजदूर वर्ग में ऐसी असंतोष की आग भड़क उठती है जो समाज की शांति को खतरे में डाल देती है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वितीय इन्दौर अधिवेशन का उद्घाटन करते समय सरदार पटेल ने यह यथार्थ ही कहा कि मजदूरों की शांति और समृद्धि पर समस्त दुनिया की शांति निर्भर करती है।

महात्मा गांधी मजदूरों के महत्व को खूब समझते थे। उन्होंने श्रम को अनोखी प्रतिष्ठा प्रदान की। कांग्रेस और कांग्रेसजनों के सामने उन्होंने जो रचनात्मक कार्यक्रम पेश किया था, मजदूरों का संगठन और उनकी सेवा उसका एक अनिवार्य अंग था। इस देश में अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही उन्होंने मजदूरों के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। उनकी देखरेख और पथ-प्रदर्शन में अहमदाबाद के मजदूरों का संगठन बना और चला। अहमदाबाद का यह मजदूर संगठन एक आदर्श संगठन माना जाता है। उसकी कार्य पद्धति से मजदूरों का अधिक से अधिक हित-साधन हुआ है।

मजदूरों में संगठित होकर अपनी बात मनवाने की जबर्दस्त ताकत होती है। किन्तु इस ताकत का विवेकपूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के मजदूरों ने हड़ताल की खातिर कभी हड़ताल नहीं की। वहां के मालिकों और मजदूरों दोनों ने पंच फैसले का सिद्धांत मंजूर किया। इसका नतीजा यह हुआ कि मालिक और मजदूरों के आपसी झगड़े शांतिपूर्वक निपट गये और अन्य स्थानों में मालिकों और मजदूरों में जो कटुता देखने में आती है, उससे अहमदाबाद मुक्त है।

लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप मतदान न बढ़ने से देश में चर्चा तेज है। लोगों को ज्यादा मतदान के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? साल 2004 में लोकसभा में अनिवार्य मतदान के पक्ष में एक विधेयक पारित करने का प्रयास हुआ था, तब हुई रोचक चर्चा आज भी प्रासंगिक है।

आमने-सामने

मतदान न करने वालों को सजा होनी चाहिए

यहां स्कैन करें

बची सिंह रावत 'बचदा' | वरिष्ठ नेता व सांसद

- अनिवार्य मतदान नहीं होगा, तो निगेटिव वोटिंग का औचित्य नहीं।
- अनिवार्य मतदान की व्यवस्था दुनिया के करीब 32 देशों में है।
- अनिवार्य मतदान को पहले लागू करना मुश्किल था, पर अब आसान।

उपाध्यक्ष जी, 17 दिसंबर, 2004 को इस पर चर्चा शुरू हुई थी कि देश की लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो मतदान हो, वह अनिवार्य होना चाहिए। इस संबंध में गैर-सरकारी विधेयक मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 17 दिसंबर, 2004 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल, द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर माननीय न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस देकर जवाब मांगा था, वह जनहित याचिका निगेटिव वोटिंग के बारे में थी।

देश के मतदाता अधिकतर उदासीन रहते हैं और किसी को भी मतदान करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में निगेटिव वोटिंग करने के लिए उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और वोटिंग मशीन पर एक बटन या चिह्न नकारात्मक वोटिंग का भी अंकित होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जब सूचना दी गई, तो उसने इस मामले का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी कि हमने सरकार को 10 दिसंबर, 2001 और 5 जुलाई, 2004 को दो बार ऐसा संशोधन जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत करने के लिए निवेदन किया है।...

आम मतदाता किसी को भी वोटिंग करना नहीं चाहता है, तो इसका नतीजा यह होता है कि कहीं 15 प्रतिशत और कहीं 20 प्रतिशत या दिल्ली जैसे शहर में 30 प्रतिशत मतदान होता है। सीधे-सीधे जो जनादेश आना चाहिए या स्वस्थ परंपरा आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती है। इसलिए हमारा कहना यह है कि जब तक अनिवार्य मतदान नहीं होगा, तब तक निगेटिव वोटिंग का प्रावधान करने का भी कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए ये दोनों बिंदू एक-दूसरे से संबंधित हैं। ...

अनेक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है और यह विचार नया नहीं है। सबसे पहले 1892 में बेल्जियम में इसे स्वीकार किया गया। उसके बाद 1914 में अर्जेंटीना में और 1924 में ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गई। आज ऐसी व्यवस्था करीब 32 देशों में है। उनका सीधा तर्क है कि जिस आजादी या मताधिकार को हजारों बलिदानों के बाद प्राप्त किया जाता है, उस मताधिकार के प्रति जब जागरूकता न हो, तो शासन या राज्य को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो मतदान में लगातार हिस्सा लें, उनको बढ़ावा दिया जाए और जो जान-बूझकर मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होते, उनके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यही मेरे विधेयक में व्यवस्था है। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मतदान है, जिसके कारण शासन या सत्ता सामने आती है और उसके द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों से, न केवल वे लोग, जिन्होंने मतदान किया है, बल्कि जिन्होंने मतदान नहीं किया है, वे भी प्रभावित होते हैं।...

यह चर्चा आज की नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 16 अक्तूबर, 1999 को एक सेमिनार में कहा था कि 'राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी को शामिल करने के लिए, मैंने 1951 में अंतरिम संसद में जन-प्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव रखा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'डॉक्टर आंबेडकर ने इस विचार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था। 1952 में जब पहली बार वयस्क मताधिकार लागू किया गया, तब अनिवार्य मतदान लागू करना मुश्किल हो सकता था। पचास साल बाद कोई भी हितैषी सुधार के विरुद्ध व्यावहारिक कठिनाई का बहाना नहीं बना सकता, मैं इस अवसर पर सुझाव दोहराऊंगा।'

...आज जब हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छी दिशा देने के लिए और सही परिणाम देश के सामने लाने के लिए अनिवार्य मतदान का कानून बनना चाहिए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

अगर सजा देने लगें, तो जेलें भर जाएंगी

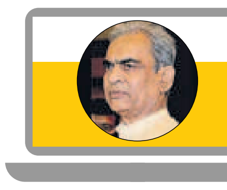

यहां स्कैन करें

मोहन सिंह | वरिष्ठ नेता और सांसद

- इस निजी विधेयक की भावना ठीक है, पर प्रावधान पूरी तरह से गलत।
- अनिवार्य मतदान की व्यवस्था छोटे देशों में हो सकती है, बड़े देशों में नहीं।
- इस विचार पर भारत सरकार एक समिति बनाए और विचार करे।

सभापति महोदय, मैं बची सिंह रावत को धन्यवाद देता हूं कि एक निजी विधेयक पेश कर उन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद और जो लोकतंत्र का मूल मतदाता है, उसके साथ लोकतंत्र का रिश्ता क्या हो, इसकी ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। उनकी भावना ठीक है, पर इस विधेयक में उन्होंने जो प्रावधान किया है, उसमें कहा गया है- कोई भी व्यक्ति जो अपना वोट डालने में विफल रहता है, उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या एक दिन की कैद होगी, और जान-बूझकर मतदान न करने पर दोनों सजा होंगी, मतदान न करने वाले का राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और छह साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।...

इसमें जो दंडात्मक प्रावधान हैं, यदि उनको लागू कर दिया जाए, तो इस देश की जेलों में कहीं इतनी जगह नहीं है और न ही उन्हें पकड़ने वाले इतने रक्षा बल और पुलिसकर्मी है कि इतनी तादाद में लोगों को जेल में डालने का काम हो। दूसरी बात है, उन्होंने अपने भाषण के दौरान उदाहरण दिया है कि इस तरह का प्रावधान बेल्जियम और अर्जेंटीना में है। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हम लोग हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। बेल्जियम की आबादी तो ऑस्ट्रेलिया से भी कम है। हमारे जो छोटे-छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तरांचल (अब उत्तराखंड), जहां के बची सिंह रावत प्रतिनिधि हैं, इस राज्य की जितनी आबादी है, पूरे बेल्जियम की आबादी उसके बराबर है। अर्जेंटीना उससे कुछ छोटा होगा। 60-65 लाख से लेकर एक करोड़ आबादी के देश को इस तरह के कठोर नियम बनाकर उस पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था कर देना आसान काम है। भारत में इससे अधिक घुमंतू आबादी है, जो घूमती रहती है...। यदि रावत जी का यह विधेयक मान लिया जाए और कानून पास कर दिया जाए, तो उस पूरी जाति को रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन के किनारे से पकड़कर जेलों के भीतर एक हफ्ते के लिए रख दें कि आपने वोट नहीं डाला। उनका स्थान जेल में सुरक्षित करना पड़ेगा।...

पुराने लोग जानते हैं कि 1962 का जो चुनाव हुआ, उसमें बक्से में परची डालने के नियम थे। सभी पार्टी के अलग-अलग बक्से और अलग-अलग चुनाव चिह्न थे। ...उस समय जनता जयप्रकाश नारायण को सुनने के लिए एकत्र होती थी, पर मतदान के बाद जब बक्सा खोला जाता था, तो सारे वोट कांग्रेस को मिलते थे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन से निकले थे और सरकारी मशीनरी पर उनका अधिकार था। कांग्रेस के सारे लोग इकट्ठा परची काटकर दो बैलों की जोड़ी वाले बक्से में डाल देते थे और ऐसे सारी सीटें कांग्रेस जीत जाती थी। जिसे हमारे लालू भाई बाद में कहते थे कि वोट कहीं डालो, बक्से से जिन्न निकलेगा और इन्हीं की ही पार्टी जीतेगी। वस्तुतः जिन्न 1952 में जब निकला था, तब इसी तरह से वोट डाले गए थे। महोदय, अब हमने काफी पद्धति विकसित कर ली है। फर्जी और बोगस वोटिंग के सिस्टम को हमने धीरे-धीरे अपने देश में बदला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से बिहार के रिजल्ट पर भी असर पड़ा है।

...पर वोट का प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे बुनियादी कारण हैं, ...इस देश का आम आदमी यह महसूस करना धीरे-धीरे बंद कर रहा है कि मतदान की पद्धति के जरिये हमारे भाग्य का निर्धारण होने वाला है और इस धारणा के चलते धीरे-धीरे वोट का प्रतिशत कम हो रहा है। ...इस विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं। भारत सरकार की ओर से एक समिति बनाई जानी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हम इस देश में किस तरह की चुनाव पद्धति अपनाएं, ताकि जनता के सही अभिमत का प्रतिनिधित्व हो सके। इस भावना के साथ इस विधेयक के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करता हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

कर्तव्य से अधिकार तक दो पीढ़ियों की माओं का सफर

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

'मदर्स डे' यानी मां का दिन। मां को याद करना। उनको शुभकामनाएं देना। आज की माताओं के बारे में कहा जाता है कि वे एक तरह से चौबीस घंटे, सातों दिन काम करती हैं। दफ्तर और घर, दोनों मोर्चे संभालती हैं। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। 'मदर्स डे' को मनाने का उद्देश्य ही यही है कि मां ने हमारे लिए जो किया, इसके लिए उनको सराहा जाए!

बात सच भी है। आज की युवा स्त्री हो या पुरुष, दोनों हरदम दौड़ते-भागते ही दिखते हैं। एक तरफ तकनीक ने जहां उनके जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसी तकनीक ने दफ्तर को घर के अंदर पहुंचा दिया है और इस तरह वे हर वक्त दफ्तर की निगाह में भी हैं। आज की माओं को देखती हूं और अपनी पीढ़ी की मां, चाची, नानी, दादी, ताई, बुआ आदि के बारे में सोचती हूं, तो महसूस होता है कि उनको शायद ही वह सम्मान कभी मिला, जिसकी वे हकदार थीं। किसी ने शायद ही कभी उन्हें 'हैप्पी मदर्स डे' कहा। उनका सारा परिश्रम कर्तव्य की वेदी पर होम हो गया। मां का मतलब था, चौबीस घंटे काम करने वाली स्त्री। सवेरे सबसे पहले उठने वाली और रात में सबके सो जाने के बाद सोने वाली।

मां के कामों की सूची लंबी थी- सुबह उठकर बच्चों के स्कूल जाने से पहले गाय-भैंसों की देखभाल, सानी-पानी और उनकी कोठरियों की साफ-सफाई। फिर स्नान के बाद बच्चों का नाश्ता बनाना, उनको दोपहर का भोजन देना। संयुक्त परिवार के बीस-तीस लोगों के लिए चूल्हे पर भोजन ही नहीं पकाना, सबको गरम-गरम भी खिलाना। सवेरे मुंह अंधेरे चक्की में आटा पीसना या बेसन अथवा मसाले कूटना, गेहूं को धोना, सुखाना, साफ करना, पीसना। गेहूं के मौसम में साल भर की खपत लायक गेहूं इकट्ठा करना, उन्हें कीड़ा न लगे, इसकी व्यवस्था करना, साल भर की दालों को मौसम में ही सुखाना, तेल लगाकर कीड़ों से बचाना। सुबह-सवेरे दही बिलोना, मक्खन निकालना, दूध उबालना। दोपहर में पापड़-बड़ियां, चिप्स, सेवइयां और तरह-तरह के अचार बनाना। पुराने कपड़ों को ठीक करना, या उनसे कुछ और उपयोगी बना लेना, कपड़ों की सिलाई, सर्दियों में स्वेटर बुनना और रजाई में रुई भरवाकर उनमें डोरे डालना। किसी त्योहार से पहले पकवानों की तैयारी। आए-गए की खातिरदारी। पड़ोस की किसी शादी, मुंडन, कथा-कीर्तन आदि की दुनियादारी निभाना। वहां से लौटकर फिर से घर के कामों में जुट जाना। उस दौर की हर मां या कहें कि हर स्त्री की यही कहानी है। इन कामों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि हो सकता है कि कुछ काम बताने से रह ही गए हों।

आज की मां और उस दौर की मां के परिश्रम में एक बड़ा फर्क यह है कि आज की स्त्री को उसके परिश्रम का मूल्य मिलता है, उसकी मेहनत सबको दिखाई देती है। उस दौर की मां इनसे वंचित थी।

उस दौर की स्त्रियां जो भी काम करती थीं, आज वे सारे काम बाजार के हवाले हैं। आज की महिलाओं के पास इतना समय नहीं कि वे किसी त्योहार पर पकवान बना सकें, मसाले पीस सकें, घर में गेहूं साफ करके आटा पिसवा सकें। इसके अलावा आज की स्त्री को तमाम किस्म की तकनीकी सुविधाएं प्राप्त हैं। पुरानी स्त्री जिस चूल्हे पर रात-दिन लगी रहती थी, उसकी जगह आज गैस चूल्हे हैं। कुकर है, मिक्सी है, माइक्रोवेव है, खाना खराब न हो, इसके लिए फ्रिज है, कपड़े धोने की मशीन है। इनके अलावा घरेलू सहायिकाएं हैं। खाना पकाने वाले या वालियां हैं। कहीं आने-जाने के लिए तरह-तरह की सुविधाएं हैं। काश! हमारी नानी-दादी के जीवन काल में ये सुविधाएं होतीं। वे भी कुछ चैन पा सकतीं।

आज की मां और उस दौर की मां के परिश्रम में एक बड़ा फर्क यह है कि आज की स्त्री को उसके परिश्रम का मूल्य मिलता है, इसलिए उसकी मेहनत सबको दिखाई देती है। उस दौर की मां चाहे जितनी मेहनत करती थी, वह सब घर-परिवार की देखभाल के खाते में चला जाता था, इसलिए उसके श्रम की कोई कीमत नहीं थी। उस दौर की स्त्री को हमने सिर्फ मां के कर्तव्यों की सीमा-रेखा में कैद कर दिया। शायद उनके साथ बहुत अन्याय किया!

अपनी परिचित जितनी भी स्त्रियों के बारे में सोचती हूं, वे सब पचासी-नब्बे के पार होकर इस दुनिया से विदा हुईं। जीवन में शायद ही कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी अन्य रोग का कोई टेस्ट हुआ। उनके अथक परिश्रम ने उन्हें कम से कम अच्छे स्वास्थ्य की सौगात सौंपी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि पुराने जमाने की मां से कुछ मेहनत करना सीखें, कुछ श्रम का बंटवारा करें और खुद को उनकी तरह स्वस्थ भी रखें।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संतुलन बहुत जरूरी

जीवन अत्यंत सरल है, साथ ही जटिल भी और जीवन के इन दोनों ही पहलुओं को तुम्हें साथ-साथ संभालना है। जब कभी भी जीवन बहुत जटिल लगे, तो सरलता की ओर मुड़ जाओ। याद रखो, सरलता शांति लाती है। जब मन में शांति हो, तब जीवन की जटिलताओं पर ध्यान दो। यह संतुलन तुम्हें अधिक कुशल बनाता है।

केवल सरलता में रहने से तुम आलसी और निष्क्रिय हो सकते हो। इसी तरह, केवल जटिलताओं में उलझे रहने से तुम क्रोधित और हताश हो सकते हो। ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं और इसीलिए दोनों का ही आनंद लेते हैं। यदि तुम सिर्फ सरलता को देखते हो, तब विकास नहीं होता और केवल जटिलताओं को देखने से कोई जीवन ही नहीं दिखेगा। तुम्हें केवल इन दोनों में कुशल संतुलन की जरूरत है। यदि तुम जीवन की सरलता और जटिलता, दोनों को पहचान लो, तब कुशलतापूर्वक सुखी रह सकते हो। जटिलताएं जीवन का रंग हैं, तो उज्ज्वलता है सरलता। जब तुम्हारा हृदय पवित्र रहता है, तब जीवन रंगीन बन जाता है।

मैं यह हमेशा कहता हूं कि जीवन एक उपहार है और तुम इस उपहार के आवरण को खोलने के लिए आए हो। अनावरण करते समय ध्यान रखो कि आवरण के कागजों को भी बचाकर रखना है। तुम्हारे वातावरण, तुम्हारी परिस्थितियां, घटनाएं व शरीर इस आवरण के कागज हैं। प्रायः अनावरण करते समय हम कागजों को फाड़ देते हैं। कभी-कभी तो इतनी जल्दी में होते हैं कि उपहार को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए धैर्य व सहनशीलता के साथ उपहारों को खोलो और आवरण को बचाकर रखो!

श्री श्री रविशंकर

बेंजामिन नेतन्याहू | इजरायली प्रधानमंत्री

आज हम बहुत मजबूत हैं, एकजुट हैं और हमने यह ठान रखा है कि अपने दुश्मनों व हमारी तबाही चाहने वालों को हराकर रहेंगे। इसके लिए अगर हमें अकेले भी खड़े होने की जरूरत पड़ी, तो खड़े होंगे!

अनुलोम-विलोम
मदर्स डे

मां अपने बच्चों के लिए आज भी पूजनीय

रविवार (12 मई) को 'मदर्स डे' है। यह दिवस पूरी तरह से मां को समर्पित होता है। ऐसे किसी भी दिवस की प्रासंगिकता काफी अधिक है, क्योंकि मां के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर मां न होती, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए मां के नाम सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि साल के हर दिन को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कहा भी जाता है कि ईश्वर ने मां को इसलिए बनाया कि यह उसकी तरह ही सृजन करती है। यह एक ऐसा नाम है, जिसमें खुद भगवान वास करते हैं। जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चे की मां को ही होती है। अपने बच्चे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती है। यही कारण है कि पिता अगर संतान के लिए बट वृक्ष माने जाते हैं, तो मां उसकी घनी-शीतल छाया।

एक बच्चे के जीवन में मां-बाप की अहमियत शायद ही किसी से छिपी है। वे बच्चों की जिंदगी में एक सांचे की तरह काम करते हैं और उनके भविष्य को सही आकार देते हैं। माता-पिता अपने बच्चों में अच्छा संस्कार भरते हैं और उनको जीवन की मुश्किलों से निर्भीक होकर लड़ने के लिए तैयार करते हैं। चूंकि बच्चे को सही दिशा उसके मां-बाप ही दिखाते हैं, इसलिए बच्चे भी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। विशेषकर मां के प्रति बच्चों का सम्मान हमेशा दिखता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आज की पीढ़ी अपने मां-बाप का ख्याल रखने के मामले में कमजोर है। यह सरलीकरण है। इसमें कोई दोराय नहीं कि कुछ बच्चे माता-पिता की उपेक्षा करते हैं और चकाचौंध से भरी इस दुनिया में अपनी जननी से भी दूरी बना लेते हैं। मगर इनको अपवाद ही मानना चाहिए। आमतौर पर आज भी मां का ख्याल पहले जैसा रखा जाता था। भारत के ज्यादातर घरों में मां के प्रति बच्चों में विशेष अनुराग दिखेगा।

आज का समाज काफी हद तक भौतिकवादी हो गया है, फिर भी अपने बीजक को शायद ही भूल सका है। हम अपने आसपास ही ऐसे अनगिनत नौजवानों को देख सकते हैं, जो सिर्फ इसलिए अपने घर से दूर हाड़-तोड़ मेहनत या मजदूरी कर रहे हैं, ताकि उनके घर की रोजी-रोटी आराम से चलती रहे और उनकी मां को मेहनत-मजदूरी न करनी पड़े। ऐसे में, मां का ख्याल न रखने जैसा आरोप लगाने या नई पीढ़ी को कोसने से बचा जाना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी परंपरा बच्चों को अपने मां-बाप के आशीष की छांव में चलना सिखाती है, उनसे दूर होना नहीं।

स्वाति चौहान, टिप्पणीकार

अब उनका पहले जैसा सम्मान नहीं होता

दुनिया के तमाम देश मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस, यानी 'मदर्स डे' मनाते हैं। यह दिन 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से अलग है, क्योंकि यह माना गया कि कोई भी मां सिर्फ एक महिला नहीं होती, बल्कि एक सर्जक होती है। इसीलिए उसे अपने बच्चे से असीम लगाव होता है और उसकी जरा सी तकलीफ से व्याकुल हो उठती है। मां का दुलार बच्चे के लिए दवा जैसा काम करता है, इसलिए ममता और स्नेह के इस रिश्ते को संसार का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा गया है। इस मामले में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग थी। यहां के लोगों के लिए मां से प्रेम सदैव अद्भुत और अकल्पनीय माना जाता रहा है। मगर अब तस्वीर बदलती दिख रही है, जो दुखद व निराशाजनक है।

हम पश्चिमी देशों की नकल करके आज जरूर मदर्स डे मनाते हैं, पर क्या वास्तव में अपनी मां से उतना प्यार करते हैं, जितना करना चाहिए या उनको वाजिब सम्मान देते हैं? विशेषकर नई पीढ़ी व्यस्त दिनचर्या, बाहरी भागदौड़, नौकरी के तनाव या छोटे परिवार की वजह से मां को भूलती जा रही है। स्थिति यह है कि कई परिवारों में बुजुर्ग महिलाएं बोझ समझी जाने लगी हैं। उनकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं। वे एकांत में चुपचाप बैठी या लेटी रहती हैं और टुकुर-टुकुर सबको निहारती रहती हैं। कोई उनके पास बैठने को तैयार नहीं होता। हां, कभी-कभी घर के बच्चे जरूर उनके साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन यह भी किसी न किसी दबाव में किया जाता है, स्वेच्छा से नहीं। यही कारण है कि आज देश के वृद्धाश्रमों में भी जगह नहीं मिलती। मानो सभी बच्चे अपने मां-बाप को वृद्धाश्रम में रखकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहते हैं।

संभवतः इन्हीं सबके कारण केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया कि जो बच्चे अपने मां-बाप के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं या जो उनको अपने साथ नहीं रखते, उनको पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। बुरे बर्ताव के लिए उनको जेल भी भेजा जा सकता है। जाहिर है, यह कानून इसलिए बनाया गया, ताकि आज की पीढ़ी को सही रास्ते पर लाया जा सके। हम सिर्फ एक दिन मदर्स डे या फादर्स डे मनाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते। हमें वास्तविक अर्थों में अपने माता-पिता का ख्याल रखना चाहिए और उनको पर्याप्त सम्मान देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें उनकी संतान कहलाने और पैतृक संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ऐसा कोई कानूनी संशोधन करना चाहिए।

सुमन सिंह, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण

पुरुषार्थी व्यक्ति सदैव किसी उद्यम में संलग्न रहता है

विपक्ष की रणनीतिक दुर्बलता

डा. एके वर्मा

विपक्ष यह नहीं बता सका कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है और राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा?

लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसे अपने-अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। अकादमिक जगत में कम मतदान संबंधी कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं, जो बता सके कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के 'चार सौ पार' के आह्वान से भाजपा समर्थक निश्चिंत और भाजपा विरोधी उदासीन हो गए हैं, जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है। मतदाता मोदी को तो चाहता है, लेकिन भाजपा के स्थानीय सांसदों से वह कुछ कुपित है। इसलिए विजयी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर संभवतः कम होगा। इस बार चुनावी स्पर्धा में विपक्ष गंभीर राष्ट्रीय विमर्श नहीं गढ़ सका। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण एवं तथ्यात्मक सवाल उठाए तथा उसे जवाब देने के लिए विवश करे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। आइएनडीआइए न तो अपना राष्ट्रीय वजूद रख सका और न ही सरकार की नीतियों पर समन्वित आक्रमण कर सका। वह अपनी वैकल्पिक नीतियां भी मतदाता के समक्ष नहीं रख पाया। उसके घटक दल अपने-अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन बांटने को तैयार नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर उनमें सीटों, मुद्दों और रणनीतियों पर भी कोई आम सहमति नहीं बनी। परिणामस्वरूप वे भाजपा पर वहां प्रहार कर रहे हैं, जहां वह सबसे मजबूत है। वे 'मोदी हटाओ' पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की स्वीकार्यता 65 से 70 प्रतिशत तक है।

विपक्ष की दूसरी रणनीतिक दुर्बलता है कि वह भाजपा के किले के कमजोर दरवाजों को चिह्नित नहीं कर पाया। प्रहार करना तो दूर विपक्षी दल अब आरोप लगाने तक सिमट गए हैं। कह रहे हैं कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। वह संविधान बदल देंगे। आरक्षण समाप्त कर देंगे। क्या यह सब जनता के गले उतरेगा? जनता भूली नहीं है कि 1975 में आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष को 'मीसा' और 'डीआइआर' जैसे काले-कानूनों में जेल भिजवा कर तथा प्रेस पर 'सेंसरशिप' लगाकर कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। देश में लोकतंत्र नहीं होता तो विपक्ष को पीएम मोदी के विरुद्ध आरोप, अशिष्टता और अभद्र भाषा के प्रयोग का अवसर मिलता क्या?

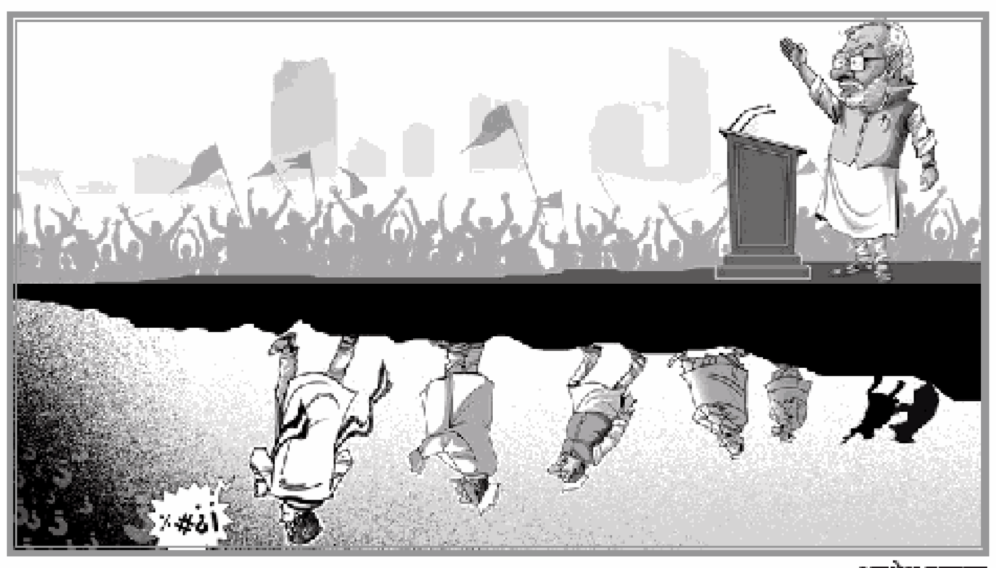

अवधेश राजपूत

विपक्ष की तीसरी रणनीतिक दुर्बलता है कि वह यह नहीं बता सका कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है और उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा? आइएनडीआइए के अंतर्विरोध सार्वजनिक हैं। भले ही कांग्रेस और मीडिया राहुल को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करते रहते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में, जिसकी संभावना बहुत कमजोर है, आइएनडीआइए के घटक दल राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व को स्वीकार करें? विपक्ष के पास विदेश-नीति, प्रतिरक्षा-नीति, शिक्षा-नीति, कृषि-नीति, आर्थिक-नीति आदि पर कोई भी रोडमैप नहीं। ऐसे में, क्या जनता उनके 'न्याय की अमूर्त परिकल्पनाओं' और कुछ अव्यावहारिक आश्वासनों के आधार पर सत्ता सौंपेगी? इस कारण विपक्ष मोदी को केवल कमजोर व्यक्तिगत चुनौती दे पा रहा है, नीतिगत चुनौती नहीं। परिणामस्वरूप मोदी को अवसर मिल गया कि वह स्वयं राष्ट्रीय विमर्श स्थापित करें। उन्होंने 'अबकी-बार, चार सौ पार' का ऐसा विमर्श उछाल दिया, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं। अभी भी अपने सहयोगियों सहित उनके पास 350 के आसपास का बहुमत है। यदि वह 400 पार हो भी जाए तो सत्तारूढ़ दल के शक्ति और प्रभाव संरचना में क्या मौलिक परिवर्तन आएगा, लेकिन इससे मोदी ने विपक्ष को प्रतिरक्षात्मक बना दिया? विपक्ष ने मोदी को अवसर दे दिया कि वह जनता के सामने अपनी सरकार के पिछले दस वर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखें। स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण होने पर देश की उन्नत स्थिति की अपनी कल्पना का चित्रांकन करें और अपनी समावेशी राजनीति की स्वीकार्यता को तीसरी बार भी सतत राजनीतिक वैधता प्रदान करें। यह आसान नहीं।

अपने कार्यकाल में मोदी ने करीब 18 राज्यों में भाजपा को सत्ता दिलाई। जातीय रूप से विखंडित हिंदू समाज को एकीकृत किया। मुस्लिम समाज से भाजपा की दूरी घटाई। भाजपा को 'ब्राह्मण-बनिया-मध्यवर्गीय-शहरी' पार्टी की छवि से मुक्त कर उसे सर्वसमाज का बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने जातीय राजनीति का मिथक तोड़कर उसे चार वर्गीय (महिला, युवा, किसान एवं गरीब) राजनीति से जोड़ दिया। इसमें मोदी ने टेक्नोलाजी और तटस्थता, समावेशन और समानता तथा कर्मठता एवं कौशल का ऐसा प्रयोग किया जो भावी नेताओं के लिए प्रतिमान होगा।

इस चुनाव में विपक्ष न केवल राष्ट्रीय विमर्श गढ़ने में असफल रहा, बल्कि सटीक मुद्दे भी नहीं उठा पाया। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के जो मुद्दे उठा रहा है, वे स्वतंत्रता के समय से बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। जिस देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष बेल्जियम, क्यूबा या सूडान की जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती हो, वहां कोई भी सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती और न महंगाई को स्थायी रूप से रोक सकती है। यह एक राष्ट्रीय चुनौती है। इसलिए जो भी दल महंगाई कम करने और रोजगार देने के आश्वासन पर सत्ता में आएगा, वह संभवतः उसका आत्मघाती कदम होगा।

सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दलों को बाबासाहब आंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना समानता के स्वतंत्रता तथा बिना बंधुत्व के समानता और स्वतंत्रता दोनों अर्थहीन हैं। अतः एकता, अखंडता और बंधुत्व के 'फ्रेमवर्क' में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सभी दलों विशेषकर विपक्ष को अर्थपूर्ण राजनीतिक स्पर्धा के लिए सार्थक राजनीतिक विमर्श, प्रभावी मुद्दे, जनोन्मुखी चुनाव प्रचार, मजबूत संगठन और कुशल नेतृत्व पर ध्यान देना होगा।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

चुनाव प्रचार की सुविधा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जो अंतरिम जमानत दी, उस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। उन्हें जेल से बाहर आने की विशेष सुविधा केवल इसलिए दी गई, ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जिस मामले में जेल में हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार खत्म होते ही फिर से जेल में लौटना होगा। इसका अर्थ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर लगे आरोपों को गंभीर मान रहा है या फिर फिलहाल उन्हें निर्दोष मानकर नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जिस आधार पर यह पाया हो कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किसी नेता की ओर से चुनाव प्रचार करना मौलिक या संवैधानिक अधिकार है? यदि है तो क्या वह अन्य नेताओं और खासकर ऐसे नेताओं को भी मिलेगा, जो अपने दल या संगठन के प्रमुख या वरिष्ठ नेता हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई छोटे-छोटे दलों के नेता दागी किस्म के हैं। क्या अब उन्हें वैसी ही सुविधा मिला करेगी, जैसी केजरीवाल को मिली?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की यह दलील ठुकरा दी कि केजरीवाल को जमानत से एक खराब नजीर कायम होगी, क्योंकि देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और कल को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी इसी आधार पर जमानत मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की नजर में अमृतपाल का मामला केजरीवाल के मामले से अलग है, लेकिन क्या इससे अमृतपाल जैसे लोग अदालत का दरवाजा खटखटाना बंद कर देंगे? प्रश्न यह भी है कि जिस आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली, क्या उसी आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिलेगी? हाई कोर्ट की ओर से अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उनसे अगले सप्ताह आने को कहा गया। हो सकता है कि उन्हें भी राहत मिल जाए, लेकिन तब तक तो झारखंड की कुछ सीटों पर मतदान हो जाएगा। क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले त्यागपत्र दे दिया और जेल से सरकार चलाने की जिद नहीं पकड़ी? न्याय समानता के सिद्धांत की मांग करता है। केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए भी सवाल खड़ा करने वाली है कि अतीत में कई प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केजरीवाल को चुनाव के मौके पर इसलिए जेल जाना पड़ा और शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई इस कारण नहीं हो सकी, क्योंकि वह कई महीनों तक प्रवर्तन निदेशालय के समन की अनदेखी करते रहे।

आस्था की चारधाम यात्रा

उत्तराखंड हिमालय की चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया पर्व पर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो गई है। 12 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार देशभर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। इसका प्रमाण है चारधाम के लिए अब तक हो चुके 23 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। मौसम ने साथ दिया तो तय मानिए कि इस बार यात्रा पिछले सारे रिकार्ड तोड़ देगी। यात्रा का बढ़ना निश्चित रूप से सुखद है, लेकिन इसके आलोक में यह ध्यान रखा जाना भी जरूरी है कि प्रकृति के नियमों की अवहेलना न हो।

वस्तुतः उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण चारों धाम बेहद संवेदनशील हैं। सो, वहां पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप आचरण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तीर्थयात्री हों या स्थानीय लोग अथवा धामों में ड्यूटी पर तैनात कार्मिक व व्यापारी, सभी को चाहिए कि धामों की स्वच्छता का खास ख्याल रखें। साथ ही धामों की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह न भूलें कि धाम आस्था का केंद्र हैं, न कि पिकनिक स्पाट और आस्था के केंद्रों में उच्छृंखलता कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके लिए सरकार की ओर से भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सरकार का यह भी प्रयास है कि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, लेकिन यह तीर्थ यात्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार और यात्रा से जुड़े विभागों का सहयोग करें। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चारों धाम, खासकर यमुनोत्री व केदारनाथ का भूगोल बेहद जटिल है। यहां आक्सीजन की कमी से तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए वह यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए धामों की ओर बढ़ें। इससे उन्हें उच्च हिमालयी क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में मदद मिलेगी।

अस्तित्व के संकट से जूझते वामपंथी दल

हरेंद्र प्रताप

साम्यवाद अपनी विश्वसनीयता इसलिए खो बैठा, क्योंकि जनता ने इस विचार को नकार दिया है

निरंतर सिकुड़ता वामपंथ का दायरा। प्रतीकात्मक

इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी वामपंथी दल प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। उस बंगाल में भी नहीं, जहां उन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक शासन किया। वहां अब वे कांग्रेस के भरोसे हैं। यही हाल तमिलनाडु और उन अन्य राज्यों में भी हैं, जहां वे कभी थोड़ा-बहुत असर रखते थे। ध्यान रहे कि सोशलिस्ट पार्टी के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा को तमिलनाडु से केवल दो सीटें मिली थीं। चुनावों में निर्धारित मत प्रतिशत तथा सीटें नहीं मिलने के कारण पिछले साल उससे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। ऐसा तब हुआ है जब सोवियत क्रांति के बाद मार्क्स और लेनिन एवं साम्यवादी विचार को मानवमुक्ति का महामंत्र घोषित कर दिया गया था। भारत के नेता और संगठन भी अपने को कम्युनिस्ट/सोशलिस्ट विचार का वाहक मानकर इतराते थे। भारत में जिस नेहरूवियन माडल की चर्चा होती है, उसमें समाजवाद भी शामिल था। साम्यवाद और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। समाजवाद का भूत इस प्रकार सवार था कि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया।

प्रथम लोकसभा के गठन के लिए देश में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश मिलाकर 26 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने 24 में जीत दर्ज की थी। जिन दो जगहों पर उसे सफलता नहीं मिली, उनमें से एक राज्य त्रिपुरा था, जहां दोनों सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। तब त्रिपुरा के अलावा मद्रास, बंगाल तथा ओडिशा में उसे चुनावी सफलता मिली थी तथा वह कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में भी वह नौ राज्यों से 27 सीटें जीतकर देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी रही। 1962 के चुनाव में भी उसे सात राज्यों से 29 सीटें प्राप्त हुई थीं। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का भाकपा और माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के रूप में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी दोनों वामपंथी दल नौ राज्यों से 42 सीटें जीते थे। 1967 के चुनाव में भाकपा माकपा से आगे थी, पर उसके बाद माकपा बड़ा भाई हो गई। माकपा को चीन समर्थक तथा भाकपा को सोवियत संघ समर्थक पार्टी कहा जाता है। चीन समर्थक कम्युनिस्टों ने 1962 के चीनी आक्रमण का समर्थन किया था। भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाले देश हैं। इसे जानते हुए भी माकपा के इस बार के घोषणा पत्र में भारत को परमाणु शक्तिहीन बनाने की घोषणा उसके चीनपरस्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। चूंकि वैश्विक स्तर पर ही साम्यवाद का पतन हो गया, अतः आज भारत के साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट भी अपनी पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भाकपा के बाद अब माकपा के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में उसे 22.96 प्रतिशत मत मिले, जो 2019 में घटकर 6.34 प्रतिशत रह गए। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 4.71 प्रतिशत मत मिले। विगत लोकसभा चुनाव में उसे तमिलनाडु से दो तथा केरल से सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली थी। त्रिपुरा और बंगाल में दशकों सत्ता में काबिज रहने वाली यह पार्टी विगत चुनाव में किसी सीट पर दूसरा स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकी। राष्ट्रीय दल की मान्यता बचाए रखने के लिए त्रिपुरा और बंगाल में इसे कांग्रेस के साथ समझौता करने को बाध्य होना पड़ा।

केरल को नजरअंदाज कर दें तो कांग्रेस-कम्युनिस्ट दलों के गठबंधन का इतिहास पुराना है। 1980 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी पर जब सभी गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया तो उस समय उन्होंने बंगाल और त्रिपुरा की कम्युनिस्ट सरकारों को छोड़ दिया था। देश के प्रथम आम चुनाव में सोशलिस्ट कुछ राज्यों से 12 सीटें जीते थे। 1957 में उन्होंने अपना नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कर लिया, फिर भी वे आठ राज्यों से 19 सीटें जीते। कम्युनिस्टों से पहले सोशलिस्टों का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी 1962 में वे नौ राज्यों से 18 सीटों पर जीते। बाद में सोशलिस्ट कहे जाने वाले दल टुकड़ों में बंटते गए और अपनी राष्ट्रीय पहचान खोते चले गए। अंतिम बार 2009 के चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन 2014 में वह इसका दर्जा खो बैठी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाकपा, तृणमूल और राकांपा राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बनाए रखने मे सफल नहीं रहीं। अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए टीआरएस ने अपना नाम बदल कर बीआरएस किया, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया।

विभिन्न क्षेत्रीय या परिवारवादी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जिन तौर-तरीकों का उपयोग किया उनमें वे सफल नहीं हो पाए। राजद, तृणमूल, राकांपा के बाद अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसका कारण साम्यवादी और समाजवादी नेताओं का सोच और रवैया है। उनका विलासितापूर्ण जीवन अक्सर चर्चा का केंद्र बनता रहा है। रोमानिया के कम्युनिस्ट तानाशाह के घर में सोने के नल लगे थे। भारत में भी सोशलिस्ट नेताओं के बेटे-बेटी नाम के समाजवादी रह गए हैं। उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई है और विलासितापूर्ण तरीके से रहते हैं। सरकारी आवास में ऐशोआराम की चीजें जुटाने में ताजा नाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आया है। इसी वजह से जनता का साम्यवाद से मोहभंग हो रहा है। जनता के नकारने के चलते साम्यवादी और उनके साथ समाजवादी भी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

सार्थक संवाद

संवाद की प्रक्रिया में दो पक्षों के बीच सार्थक रूप से विचारों का विनिमय होता है। जब संवाद तल्ख रूप धारण कर ले तो वह विवाद बन जाता है। विवाद में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो संबंधों में तनाव बढ़ा देती है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि हम व्यर्थ के विवाद में पड़ने के बजाय स्वस्थ संवाद की राह पर चलते हुए विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आत्मिक शांति तो प्राप्त होगी ही, आपके मूल्यवान समय एवं ऊर्जा का भी अपव्यय नहीं होगा।

हम प्रायः किसी न किसी से बहस करते हैं, क्योंकि अपनी मान्यताओं के आधार पर हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं। जब हम दूसरों की धारणाओं को अपनी धारणा के प्रति खतरे के रूप में देखने लगते हैं तो विवाद भड़कने की आशंका बढ़ जाती है। इतिहास साक्षी है कि विश्व में छिड़े बड़े-बड़े युद्धों के पीछे विचारों में मतभेद और मान्यताओं का संघर्ष एक प्रमुख कारण रहा। इसलिए अपना दृष्टिकोण रखते हुए दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु बने रहना ही उचित है। इसके लिए साहस एवं धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि बहस करके तो हर कोई अपना स्तर दिखा देता है, किंतु सबके विचारों को स्वीकार करके आवश्यकता पड़ने पर अपनी भूमिका में अपेक्षित बदलाव एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा करने से हम दूसरों को यह प्रतीत कराते हैं कि हमारे भीतर परिवर्तन एवं समायोजन की क्षमता है।

हालांकि इतना धैर्यवान और उदार बनने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साक्षात्कार करना होता है, क्योंकि केवल एक प्रबुद्ध आत्मा ही सरलता से तर्क की स्थिति से निकल चर्चा में और फिर संवाद में आ सकती है। तब फिर, हम सभी अविलंब खुद को आध्यात्मिक शक्तियों से सुसज्जित कर वाद-विवाद से भरी इस दुनिया को सार्थक संवाद के माध्यम से परिवर्तित कर शांतिपूर्ण परिवेश बनाने का सद्प्रयास करें।

राजयोगी ब्रह्मकुमार निकुंज जी

मानव तस्करी के जाल में मासूम

देवेंद्रराज सुथार

देश में मानव तस्करी का नेटवर्क अब तक समाप्त नहीं हुआ है जो चिंता का विषय है

बिहार के जोगबनी से चलकर राजधानी दिल्ली के आनंद विहार तक आने वाली सीमांचल एक्सप्रेस से हाल ही में 93 बच्चों को मानव तस्करी के लिए राजस्थान और उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। शुक्र है कि सभी बच्चों को प्रयागराज जंक्शन पर मानव तस्करों के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया। इस मामले में नौ एजेंटों ने सीमांचल एक्सप्रेस के विभिन्न डिब्बों में छह समूहों में बाल तस्करी को अंजाम दिया, जो अपराध की संगठित प्रकृति को रेखांकित करता है। यह स्पष्ट है कि मानव तस्कर किस प्रकार बेखौफ होकर काम करते हैं, खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं और हाशिए पर मौजूद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं।

ऐसे अनगिनत उदाहरणों के बारे में सोचना चिंताजनक है, जब ऐसे मामलों का पता ही नहीं चल पाता और निर्दोष जिंदगियां शोषण के चक्र में फंस जाती हैं। हालांकि मानव तस्करी अंतरराष्ट्रीय अपराध के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में से एक है। भारत में वर्ष 2021 तक मानव तस्करी के करीब सात हजार मामले सामने आ चुके हैं। मौजूदा मामले में बच्चों की उम्र सीमा नौ से 16 साल के बीच है। जीवन के जिस प्रारंभिक चरण में बच्चों का पालन-पोषण किया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। इसके बजाय वे तस्करी की अंधेरी खाई में अपने अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं। मानव तस्करी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह व्यक्तियों से उनकी स्वायत्तता, गरिमा और स्वतंत्रता छीन लेता है।

मानव तस्करी से निपटने के प्रयास बहुआयामी और सहयोगात्मक होने चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों एवं समुदायों को तस्करी नेटवर्क को खत्म करने, अपराधियों पर मुकदमा चलाने और बचे लोगों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस जटिल मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए रोकथाम, सुरक्षा और अभियोजन साथ-साथ चलना चाहिए। निवारक उपायों को गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसे असुरक्षा के मूल कारणों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समुदायों के भीतर जागरूकता बढ़ाने और सतर्कता को बढ़ावा देने से व्यक्तियों को तस्करी के मामलों को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। लिहाजा हम सभी को इस आधुनिक गुलामी को खत्म करने के अपने संकल्प में एकजुट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को उनकी परिस्थितियों के बावजूद सम्मान और स्वतंत्रता का जीवन जीने का अवसर मिले।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चिंतित करता मतदान का रुझान

'चुनाव का अर्थ सिर्फ प्रतिनिधि चुनना नहीं' शीर्षक से लिखे आलेख में राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने उचित ही लिखा है कि नागरिकों का मतदान न करना सरकार में गलत लोगों की एंट्री करा सकता है। लेखक के अनुसार मतदान में लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि देश में सशक्त सरकार बन सके। देश को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। मजबूत विपक्ष भी तभी अस्तित्व में आ पाएगा जब हम मतदान करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा चुनावों में मतदान का घटता रुझान चिंताजनक है। अब तो चुनाव में नोटा का बटन भी उपलब्ध है। हालांकि यह सकारात्मक तो नहीं, लेकिन इससे अपनी पसंद को लेकर तो अवश्य ही अवगत कराया जा सकता है। समय आ गया है कि सभी जिम्मेदार पक्ष आम जन को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करें ताकि जहां चुनाव शेष हैं, वहां मतदान बढ़ सके। मतदान नागरिकों का एक प्रमुख कर्तव्य है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

घातक है कांग्रेस का सोच

कांग्रेस के नेता लंबे अरसे से, यहां तक कि चुनाव के दौरान भी एक के बाद एक राजनीतिक कारणों से देश के लिए घातक बयान दे रहे हैं। लगभग पूरा देश अभी देशप्रेम से ओतप्रोत है। लेकिन मोदी विरोध के चलते आइएनडीआइए के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, जो देशप्रेमियों को आहत करते हैं, तो वहीं भारत के दुश्मनों पाकिस्तान और चीन को गदगद करते हैं। अभी एक पखवाड़े में ही सैम पित्रोदा दो बार अप्रासंगिक बयान दे चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने फिर से पाक प्रेम दर्शाया है। वह कह रहे हैं कि पाक परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए भारत को उसका सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता उस कसाब को क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी हुई थी। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की भी बात कही थी। ये तो केवल कुछ ही उदाहरण हैं। जब भाजपा व इंटरनेट मीडिया ज्यादा हमलावर हो जाता है तो कांग्रेस इसे नेता का निजी बयान बता कर किनारा कर लेती है। कांग्रेस नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि किनारा करने के बाद भी ऐसी क्षति पहुंच जाती है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। भाजपा के अतिरिक्त कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बची है। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र और स्वयं के हित में कांग्रेस के बड़े-छोटे नेताओं को परिपक्व एवं देश हित में बयान देने चाहिए। कांग्रेस जनमानस रूपी धारा के विपरीत राजनीति कर रही है।

सीपी बंसल, दिल्ली

जनसंख्या नियंत्रण जरूरी

वर्ष 1950 से 2015 यानी पिछले 65 वर्षों में देश में हिंदू आबादी का 7.82 प्रतिशत घट जाना और मुस्लिम आबादी का 43.15 प्रतिशत बढ़ जाना निश्चित ही जनसंख्या नियंत्रण की ओर इशारा करती है। यही नहीं, पाकिस्तान में हिंदू 24 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत के स्तर पर आ चुके हैं। वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1992 से 2019 के बीच प्रजनन दर 3.4 प्रतिशत से घटकर लगभग दो प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में हिंदुओं में यह 3.3 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गया, जबकि मुसलमानों में यह 4.4 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत हो गया है। मुस्लिम समुदाय में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण प्रजनन क्षमता, धर्म परिवर्तन और बाहरी घुसपैठ शामिल हो सकते हैं। आज देश को यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) की सख्त आवश्यकता है। यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

पुरुषार्थी व्यक्ति सदैव किसी उद्यम में संलग्न रहता है

चुनाव प्रचार की सुविधा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 23 दिनों की जो अंतरिम जमानत दी, उस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। उन्हें जेल से बाहर आने की विशेष सुविधा केवल इसलिए दी गई, ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जिस मामले में जेल में हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार खत्म होते ही फिर से जेल में लौटना होगा। इसका अर्थ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर लगे आरोपों को गंभीर मान रहा है या फिर फिलहाल उन्हें निर्दोष मानकर नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जिस आधार पर यह पाया हो कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किसी नेता की ओर से चुनाव प्रचार करना मौलिक या संवैधानिक अधिकार है? यदि है तो क्या वह अन्य नेताओं और खासकर ऐसे नेताओं को भी मिलेगा, जो अपने दल या संगठन के प्रमुख या वरिष्ठ नेता हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई छोटे-छोटे दलों के नेता दागी किस्म के हैं। क्या अब उन्हें वैसी ही सुविधा मिला करेगी, जैसी केजरीवाल को मिली? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की यह दलील ठुकरा दी कि केजरीवाल को जमानत से एक खराब नजीर कायम होगी, क्योंकि देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और कल को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी इसी आधार पर जमानत मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की नजर में अमृतपाल का मामला केजरीवाल के मामले से अलग है, लेकिन क्या इससे अमृतपाल जैसे लोग अदालत का दरवाजा खटखटाना बंद कर देंगे? प्रश्न यह भी है कि जिस आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली, क्या उसी आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिलेगी? हाई कोर्ट की ओर से अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उनसे अगले सप्ताह आने को कहा गया। हो सकता है कि उन्हें भी राहत मिल जाए, लेकिन तब तक तो झारखंड की कुछ सीटों पर मतदान हो जाएगा। क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले त्यागपत्र दे दिया और जेल से सरकार चलाने की जिद नहीं पकड़ी? न्याय समानता के सिद्धांत की मांग करता है। केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए भी सवाल खड़ा करने वाली है कि अतीत में कई प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केजरीवाल को चुनाव के मौके पर इसलिए जेल जाना पड़ा और शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई इस कारण नहीं हो सकी, क्योंकि वह कई महीनों तक प्रवर्तन निदेशालय के समन की अनदेखी करते रहे।

अस्पताल की नाजुक दीवार

सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए कि हाल के वर्षों में निर्माण से जुड़ी गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। भवन, सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण में तो हर साल रिकार्ड ही बन रहा है। लेकिन, कभी-कभी निर्माण की गुणवत्ता हमें चिंतित भी करती है। राजधानी से सटे फुलवारीशरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला सामने आया है। बताया गया कि हवा का तेज झोंका आया और इस स्वास्थ्य केंद्र की दीवार भहराकर गिर गई। हवा की गति 30-40 किमी प्रति घंटे थी, जिसे यह दीवार झेल नहीं पाई। 2018 में इस स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण हुआ था। उसी समय फाल्स सीलिंग गिरने की घटना हुई थी। आंधी, तूफान और तेज वर्षा में बड़े बड़े घर गिर जाते हैं तो दीवार की क्या हैसियत है। लेकिन, यह मामला थोड़ा अलग किस्म का है। हवा की जिस गति से इस दीवार की दुर्गति हुई, उसपर ध्यान देने की जरूरत है। झोपड़ियां सलामत रहीं और ईंट की दीवार गिर गई। असल में दीवार बनाने वालों का भी दोष नहीं है। अब तो यह सुनने में किसी को बुरा नहीं लगता है कि ठेका या निर्माण का पूरा कारोबार कमीशन से शुरू होता है। कुछ मामलों में पद के अनुसार कमीशन निर्धारित है। उस पद का धारक भले ही ईमानदार हो, मगर उस पद के लिए निर्धारित कमीशन का भुगतान करना ही पड़ता है। जाहिर है, कमीशन की वह राशि कोई ठेकेदार अपने मुनाफे में से अदा नहीं करता है। वह निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में से ही इसका भुगतान करता है। ऐसे में निर्माण सामग्रियां एक के बदले दो-तीन नंबर की लग जाती हैं तो दीवार या किसी अन्य निर्माण की मजबूती की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हां, जांच होती है। जांच रिपोर्ट भी आती है। उसमें किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। जवाबदेही तय करने की नौबत भी आती है तो यह किसी अदृश्य के खाते में दर्ज कर दिया जाता है।

अब तो यह सुनने में किसी को बुरा नहीं लगता कि ठेका या निर्माण का पूरा कारोबार कमीशन से शुरू होता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से कांग्रेस राजनीतिक नुकसान से बच सकेगी?

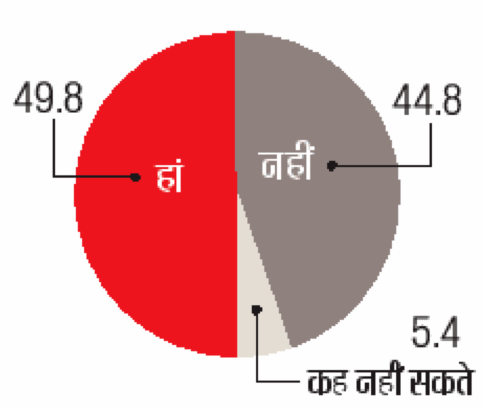

आज का सवाल
क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से उनकी पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विपक्ष की रणनीतिक दुर्बलता

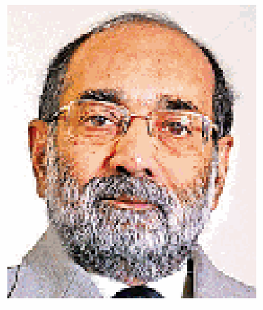

डा. एके वर्मा

विपक्ष यह नहीं बता सका कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है और राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा?

लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसे अपने-अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। अकादमिक जगत में कम मतदान संबंधी कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं, जो बता सके कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के 'चार सौ पार' के आह्वान से भाजपा समर्थक निश्चिंत और भाजपा विरोधी उदासीन हो गए हैं, जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है। मतदाता मोदी को तो चाहता है, लेकिन भाजपा के स्थानीय सांसदों से वह कुछ कुपित है। इसलिए विजयी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर संभवतः कम होगा। इस बार चुनावी स्पर्धा में विपक्ष गंभीर राष्ट्रीय विमर्श नहीं गढ़ सका। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण एवं तथ्यात्मक सवाल उठाए तथा उसे जवाब देने के लिए विवश करे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। आइएनडीआइए न तो अपना राष्ट्रीय वजूद रख सका और न ही सरकार की नीतियों पर समन्वित आक्रमण कर सका। वह अपनी वैकल्पिक नीतियां भी मतदाता के समक्ष नहीं रख पाया। उसके घटक दल अपने-अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन बांटने को तैयार नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर उनमें सीटों, मुद्दों और रणनीतियों पर भी कोई आम सहमति नहीं बनी। परिणामस्वरूप वे भाजपा पर वहां प्रहार कर रहे हैं, जहां वह सबसे मजबूत है। वे 'मोदी हटाओ' पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की स्वीकार्यता 65 से 70 प्रतिशत तक है।

विपक्ष की दूसरी रणनीतिक दुर्बलता है कि वह भाजपा के किले के कमजोर दरवाजों को चिह्नित नहीं कर पाया। प्रहार करना तो दूर विपक्षी दल अब आरोप लगाने तक सिमट गए हैं। कह रहे हैं कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। वह संविधान बदल देंगे। आरक्षण समाप्त कर देंगे। क्या यह सब जनता के गले उतरेगा? जनता भूली नहीं है कि 1975 में आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष को 'मीसा' और 'डीआइआर' जैसे काले-कानूनों में जेल भिजवा कर तथा प्रेस पर 'सेंसरशिप' लगाकर कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। आज देश में लोकतंत्र नहीं होता तो विपक्ष को पीएम मोदी के विरुद्ध आरोप, अशिष्टता और अभद्र भाषा के प्रयोग का अवसर मिलता क्या?

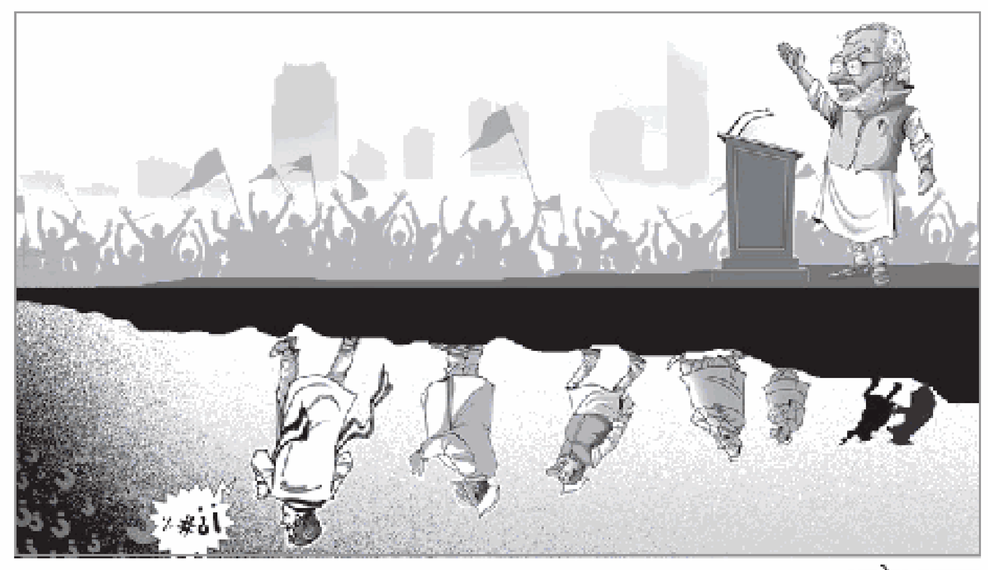

अवधेश राजपूत

विपक्ष की तीसरी रणनीतिक दुर्बलता है कि वह यह नहीं बता सका कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है और उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा? आइएनडीआइए के अंतर्विरोध सार्वजनिक हैं और घटक दलों में समन्वय हेतु कोई राष्ट्रीय इकाई भी नहीं। यह राष्ट्रीय सरकार के गठन का सवाल है। भले ही कांग्रेस और मीडिया राहुल को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करते रहते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में, जिसकी संभावना बहुत कमजोर है, आइएनडीआइए के घटक दल राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व को स्वीकार करें? विपक्ष के पास विदेश-नीति, प्रतिरक्षा-नीति, शिक्षा-नीति, कृषि-नीति, आर्थिक-नीति आदि पर कोई भी रोडमैप नहीं। ऐसे में, क्या जनता उनके 'न्याय की अमूर्त परिकल्पनाओं' और कुछ अव्यावहारिक आश्वासनों के आधार पर सत्ता सौंपेगी? इस कारण विपक्ष मोदी को केवल कमजोर व्यक्तिगत चुनौती दे पा रहा है, नीतिगत चुनौती नहीं। परिणामस्वरूप मोदी को अवसर मिल गया कि वह स्वयं राष्ट्रीय विमर्श स्थापित करें। उन्होंने 'अबकी-बार, चार सौ पार' का ऐसा विमर्श उछाल दिया, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं। अभी भी अपने सहयोगियों सहित उनके पास 350 के आसपास का बहुमत है। यदि वह 400 पार हो भी जाए तो सत्तारूढ़ दल के शक्ति और प्रभाव संरचना में क्या मौलिक परिवर्तन आएगा, लेकिन इससे मोदी ने विपक्ष को प्रतिरक्षात्मक बना दिया? राजनीतिक विमर्श इस पर केंद्रित हो गया कि 'चार सौ पार' होगा या नहीं? विपक्ष ने मोदी को अवसर दे दिया कि वह जनता के सामने अपनी सरकार के पिछले दस वर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखें। स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण होने पर देश की उन्नत स्थिति की अपनी कल्पना का चित्रांकन करें और अपनी समावेशी राजनीति की स्वीकार्यता को तीसरी बार भी सतत राजनीतिक वैधता प्रदान करें। यह आसान नहीं।

अपने कार्यकाल में मोदी ने करीब 18 राज्यों में भाजपा को सत्ता दिलाई। जातीय रूप से विखंडित हिंदू समाज को एकीकृत किया। मुस्लिम समाज से भाजपा की दूरी घटाई। भाजपा को 'ब्राह्मण-बनिया-मध्यवर्गीय-शहरी' पार्टी की छवि से मुक्त कर उसे सर्वसमाज का बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने जातीय राजनीति का मिथक तोड़कर उसे चार वर्गीय (महिला, युवा, किसान एवं गरीब) राजनीति से जोड़ दिया। इसमें मोदी ने टेक्नोलाजी और तटस्थता, समावेशन और समानता तथा कर्मठता एवं कौशल का ऐसा प्रयोग किया जो भावी नेताओं के लिए प्रतिमान होगा।

इस चुनाव में विपक्ष न केवल राष्ट्रीय विमर्श गढ़ने में असफल रहा, बल्कि सटीक मुद्दे भी नहीं उठा पाया। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के जो मुद्दे उठा रहा है, वे स्वतंत्रता के समय से बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। जिस देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष बेल्जियम, क्यूबा या सूडान की जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती हो, वहां कोई भी सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती और न महंगाई को स्थायी रूप से रोक सकती है। यह एक राष्ट्रीय चुनौती है। इसलिए जो भी दल महंगाई कम करने और रोजगार देने के आश्वासन पर सत्ता में आएगा, वह संभवतः उसका आत्मघाती कदम होगा। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दलों को बाबासाहब आंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना समानता के स्वतंत्रता तथा बिना बंधुत्व के समानता और स्वतंत्रता दोनों अर्थहीन हैं। अतः एकता, अखंडता और बंधुत्व के 'फ्रेमवर्क' में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सभी दलों विशेषकर विपक्ष को अर्थपूर्ण राजनीतिक स्पर्धा के लिए सार्थक राजनीतिक विमर्श, प्रभावी मुद्दे, जनोन्मुखी चुनाव प्रचार, मजबूत संगठन और कुशल नेतृत्व पर ध्यान देना होगा।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अस्तित्व के संकट से जूझते वामपंथी दल

हरेंद्र प्रताप

साम्यवाद अपनी विश्वसनीयता इसलिए खो बैठा, क्योंकि जनता ने इस विचार को नकार दिया है

इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी वामपंथी दल प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। उस बंगाल में भी नहीं, जहां उन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक शासन किया। वहां अब वे कांग्रेस के भरोसे हैं। यही हाल तमिलनाडु और उन अन्य राज्यों में भी हैं, जहां वे कभी थोड़ा-बहुत असर रखते थे। ध्यान रहे कि सोशलिस्ट पार्टी के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा को तमिलनाडु से केवल दो सीटें मिली थीं। चुनावों में निर्धारित मत प्रतिशत तथा सीटें नहीं मिलने के कारण पिछले साल उससे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। ऐसा तब हुआ है जब सोवियत क्रांति के बाद मार्क्स और लेनिन एवं साम्यवादी विचार को मानवमुक्ति का महामंत्र घोषित कर दिया गया था। भारत के नेता और संगठन भी अपने को कम्युनिस्ट/सोशलिस्ट विचार का वाहक मानकर इतराते थे। भारत में जिस नेहरूवियन माडल की चर्चा होती है, उसमें समाजवाद भी शामिल था। साम्यवाद और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। समाजवाद का भूत इस प्रकार सवार था कि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया।

प्रथम लोकसभा के गठन के लिए देश में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश मिलाकर 26 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने 24 में जीत दर्ज की थी। जिन दो जगहों पर उसे सफलता नहीं मिली, उनमें से एक राज्य त्रिपुरा था, जहां दोनों सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। तब त्रिपुरा के अलावा मद्रास, बंगाल तथा ओडिशा में उसे चुनावी सफलता मिली थी तथा वह कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में भी वह नौ राज्यों से 27 सीटें जीतकर देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी रही। 1962 के चुनाव में भी उसे सात राज्यों से 29 सीटें प्राप्त हुई थीं। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का भाकपा और माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के रूप में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी दोनों वामपंथी दल नौ राज्यों से 42 सीटें जीते थे। 1967 के चुनाव में भाकपा माकपा से आगे थी, पर उसके बाद माकपा बड़ा भाई हो गई। माकपा को चीन समर्थक तथा भाकपा को सोवियत संघ समर्थक पार्टी कहा जाता है। चीन समर्थक कम्युनिस्टों ने 1962 के चीनी आक्रमण का समर्थन किया था। भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाले देश हैं। इसे जानते हुए भी माकपा के इस बार के घोषणा पत्र में भारत को परमाणु शक्तिहीन बनाने की घोषणा उसके चीनपरस्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। चूंकि वैश्विक स्तर पर ही साम्यवाद का पतन हो गया, अतः आज भारत के साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट भी अपनी पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भाकपा के बाद अब माकपा के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में उसे 22.96 प्रतिशत मत मिले, जो 2019 में घटकर 6.34 प्रतिशत रह गए। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 4.71 प्रतिशत मत मिले। विगत लोकसभा चुनाव में उसे तमिलनाडु से दो तथा केरल से सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली थी। त्रिपुरा और बंगाल में दशकों सत्ता में काबिज रहने वाली यह पार्टी विगत चुनाव में किसी सीट पर दूसरा स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकी। राष्ट्रीय दल की मान्यता बचाए रखने के लिए त्रिपुरा और बंगाल में इसे कांग्रेस के साथ समझौता करने को बाध्य होना पड़ा।

निरंतर सिकुड़ता वामपंथ का दायरा • प्रतीकात्मक

केरल को नजरअंदाज कर दें तो कांग्रेस-कम्युनिस्ट दलों के गठबंधन का इतिहास पुराना है। 1980 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी पर जब सभी गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया तो उस समय उन्होंने बंगाल और त्रिपुरा की कम्युनिस्ट सरकारों को छोड़ दिया था। देश के प्रथम आम चुनाव में सोशलिस्ट कुछ राज्यों से 12 सीटें जीते थे। 1957 में उन्होंने अपना नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कर लिया, फिर भी वे आठ राज्यों से 19 सीटें जीते। कम्युनिस्टों से पहले सोशलिस्टों का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी 1962 में वे नौ राज्यों से 18 सीटों पर जीते। बाद में सोशलिस्ट कहे जाने वाले दल टुकड़ों में बंटते गए और अपनी राष्ट्रीय पहचान खोते चले गए। अंतिम बार 2009 के चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन 2014 में वह इसका दर्जा खो बैठी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाकपा, तृणमूल और राकांपा राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बनाए रखने मे सफल नहीं रहीं। अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए टीआरएस ने अपना नाम बदल कर बीआरएस किया, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया। भ्रष्टाचार के आरोप में बीआरएस नेता की पुत्री के. कविता सलाखों के पीछे हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय या परिवारवादी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जिन तौर-तरीकों का उपयोग किया उनमें वे सफल नहीं हो पाए। राजद, तृणमूल, राकांपा के बाद अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसका कारण साम्यवादी और समाजवादी नेताओं का सोच और रवैया है। उनका विलासितापूर्ण जीवन अक्सर चर्चा का केंद्र बनता रहा है। रोमानिया के कम्युनिस्ट तानाशाह के घर में सोने के नल लगे थे। भारत में भी सोशलिस्ट नेताओं के बेटे-बेटी नाम के समाजवादी रह गए हैं। उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई है और विलासितापूर्ण तरीके से रहते हैं। सरकारी आवास में ऐशोआराम की चीजें जुटाने में ताजा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आया है। इसी वजह से जनता का साम्यवाद से मोहभंग हो रहा है। जनता के नकारने के चलते साम्यवादी और उनके साथ-साथ समाजवादी भी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

सार्थक संवाद

संवाद की प्रक्रिया में दो पक्षों के बीच सार्थक रूप से विचारों का विनिमय होता है। जब संवाद तल्ख रूप धारण कर ले तो वह विवाद बन जाता है। विवाद में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो संबंधों में तनाव बढ़ा देती है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि हम व्यर्थ के विवाद में पड़ने के बजाय स्वस्थ संवाद की राह पर चलते हुए विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आत्मिक शांति तो प्राप्त होगी ही, आपके मूल्यवान समय एवं ऊर्जा का भी अपव्यय नहीं होगा।

हम प्रायः किसी न किसी से बहस करते हैं, क्योंकि अपनी मान्यताओं के आधार पर हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं। जब हम दूसरों की धारणाओं को अपनी धारणा के प्रति खतरे के रूप में देखने लगते हैं तो विवाद भड़कने की आशंका बढ़ जाती है। इतिहास साक्षी है कि विश्व में छिड़े बड़े-बड़े युद्धों के पीछे विचारो में मतभेद और मान्यताओं का संघर्ष एक प्रमुख कारण रहा। इसलिए अपना दृष्टिकोण रखते हुए दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु बने रहना ही उचित है। इसके लिए साहस एवं धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि बहस करके तो हर कोई अपना स्तर दिखा देता है, किंतु सबके विचारों को स्वीकार करके आवश्यकता पड़ने पर अपनी भूमिका में अपेक्षित बदलाव एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा करने से हम दूसरों को यह प्रतीत कराते हैं कि हमारे भीतर परिवर्तन एवं समायोजन की क्षमता है और हम सभी के विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ने में सक्षम हैं।

हालांकि इतना धैर्यवान और उदार बनने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साक्षात्कार करना होता है, क्योंकि केवल एक प्रबुद्ध आत्मा ही सरलता से तर्क की स्थिति से निकल चर्चा में और फिर संवाद में आ सकती है। तब फिर, हम सभी अविलंब खुद को आध्यात्मिक शक्तियों से सुसज्जित कर वाद-विवाद से भरी इस दुनिया को सार्थक संवाद के माध्यम से परिवर्तित कर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण परिवेश बनाने का सद्प्रयास करें।

राजयोगी ब्रह्मकुमार निकुंज जी

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

चिंतित करता मतदान का रुझान

'चुनाव का अर्थ सिर्फ प्रतिनिधि चुनना नहीं' शीर्षक से लिखे आलेख में राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने उचित ही लिखा है कि नागरिकों का मतदान न करना सरकार में गलत लोगों की एंट्री करा सकता है। लेखक के अनुसार मतदान में लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि देश में सशक्त सरकार बन सके। देश को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। मजबूत विपक्ष भी तभी अस्तित्व में आ पाएगा जब हम मतदान करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा चुनावों में मतदान का घटता रुझान चिंताजनक है। अब तो चुनाव में नोटा का बटन भी उपलब्ध है। हालांकि यह सकारात्मक तो नहीं, लेकिन इससे अपनी पसंद को लेकर तो अवश्य ही अवगत कराया जा सकता है। समय आ गया है कि सभी जिम्मेदार पक्ष आम जन को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करें ताकि जहां चुनाव शेष हैं, वहां मतदान बढ़ सके। मतदान नागरिकों का एक प्रमुख कर्तव्य है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बड़े निर्णय नहीं लेतीं गठबंधन सरकारें

आर. विक्रम सिंह द्वारा लिखित आलेख 'संसदीय प्रणाली की समस्याएं' पढ़ा। लोकतंत्र शासन प्रणाली की सर्वोत्तम व्यवस्था है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश लोकतंत्र के महापर्व के दौर से गुजर रहा है। सभी राजनीतिक दलों की असली परीक्षा चुनावी मैदान में होती है। समय के साथ लोकतंत्र की समस्याएं भी उजागर हुई हैं। आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में मजबूत सरकारें रहीं, उसके बाद देश में गठबंधन का दौर चला। देश ने कमजोर प्रधानमंत्री का दौर भी देखा। गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थीं। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। गठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता सत्ता को बचाए रखना होता है, इस कारण सरकार कोई साहसिक निर्णय नहीं ले पाती है। अभी देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युग है। मोदी के रूप में देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। कुछ देशों में राष्ट्रपति प्रणाली है, लेकिन उस प्रणाली में भी कुछ खामियां हैं। भारत जैसे देश के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव के लिए केवल राष्ट्रीय दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्षेत्रीय दलों को केवल विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए, तभी देश में मजबूत लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। क्षेत्रवाद और जाति-धर्म की राजनीति से लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए आम जन को केंद्र व राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। आज अधिकांश वोटर देश व राज्य के व्यापक हित की बात नहीं सोच पाते। जाति व धर्म के चक्कर में फंस कर मतदान कर देते हैं। प्रत्याशी की योग्यता मायने खो देती है। राजनीतिक दलों को भी प्रत्याशी चयन का तौर-तरीका बदलना चाहिए। इसके लिए छात्र राजनीति को जीवंत करना होगा। पढ़े लिखे युवाओं को चुनावी राजनीति में आगे आना होगा।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

कई पाबंदियों के साथ मिली जमानत

आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद विपक्ष की ओर से यह संदेश प्रसारित किया जाने लगा कि भारत का संविधान अब खतरे में नहीं है। संविधान सुरक्षित है। लोकतंत्र जीवंत है। ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कई बिंदुओं की ओर उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया था। कोर्ट ने एक जून तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वे दो जून को समर्पण करेंगे। 21 दिनों के लिए मिली जमानत अवधि में केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे और न ही किसी संचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। इस केस से संबंधित किसी फाइल का वे अवलोकन नहीं करेंगे। जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए आवश्यक ना हो, तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही किसी गवाह से बातचीत करेंगे। सनद रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में 21 मार्च से बंद थे। उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैध बताया था। वे जेल में भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाकर भी अपने संवैधानिक पद का त्याग नहीं किया।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

आइपीएल ने ऐसे दिन भी दिखा दिए कि किताबी क्रिकेट खेलने वाले कम रन बना पाएंगे और अयोग्य एवं आड़ा-तिरछा खेलने वाले '360 डिग्री प्लेयर' की उपाधि पाएंगे।
मंजीत ठाकुर@manjit2007

जेल में बंद हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आदि भी सोच रहे होंगे कि नेता तो हम भी हैं और चुनाव हमारे लिए भी पांच साल में एक बार ही आते हैं।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

हेमंत सोरेन जब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि हाई कोर्ट जाइए। वह हाई कोर्ट गए तो वहां के जज ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया। अदालत वह फैसला कब सुनाएगी, उसकी मर्जी। इस बीच उसी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है।
अरविंद कुमार@arvind_kumar__

एक देश के रूप में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का कोई सवाल ही नहीं। जो देश आपको हजार घाव देना चाहता हो, वह कभी दोस्त नहीं हो सकता। बिच्छू के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसका वह हकदार है। हालांकि वहां के लोगों के साथ मित्रता सदैव स्वागतयोग्य होनी चाहिए।
राहुल पंडिता@rahulpandita

जनपथ

हज करके वो आ रहे पूजो उनके पांव,
अब तो सीना तान कर घूमेंगे वह गांव।
घूमेंगे वह गांव लगेगा बिल्कुल ऐसे,
आजादी की जंग जीतकर लौटे जैसे।
अब तो लोग शरीफ रह रहे हैं डर डरके,
पर जो काटें जेल लगें आए हज करके!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 29

****

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

अब जरूरी हो गया है शोर के खिलाफ शोर

दुनिया लगातार प्रदूषण के जाल में फंसती जा रही है। दिन-ब-दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इसमें आम जन का जीना मुहाल हुए जा रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है, जिससे हर खास-ओ-आम का पाला लगातार पड़ता रहता है। आमजन और प्रकृति को अपनी बपौती समझने वाले आकाओं को सजग और आगाह करने का काम वैज्ञानिक कर रहे हैं। दुनिया भर में वायु प्रदूषण और इसे दूर करने के उपायों पर भी चर्चा होती है, पर सामान्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर सभी का रवैया अनदेखी करने वाला है। इसे लेकर समाज के स्तर पर भी खास जागरूकता नहीं है।

डेनेवर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया और कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को अनदेखा करना बहुत जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने झींगुरों पर किए गए तीन साल के अध्ययन का उदाहरण भी दिया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि 70 डेसिबल तक के शोर में रहने वाले झींगुरों के वयस्क होने तक जीवित रहने की संभावना 35 प्रतिशत कम हो जाती है। यह चिंताजनक खुलासा है। इसे सिर्फ इसलिए अनदेखा नहीं किया जा सकता कि झींगुर ही प्रभावित हो रहे हैं। प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं है। वह समस्त प्राणियों की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि अन्य प्राणियों पर भी इसका असर आना ही है। असर आ भी रहा होगा। यह अलग बात है कि इंसान जानते-बूझते हुए इस समस्या की अनदेखी कर रहा है। इंसान की बात इसलिए कि प्रकृति में कहीं भी किसी भी तरह की असमानता, अव्यवस्था और अंधेर पैदा हुआ है, तो उसके लिए केवल और केवल इंसान ही जिम्मेदार है। यह उजागर तथ्य है कि मानवजनित विभिन्न तरह के प्रदूषणों के कारण ही दुनिया के कई इलाकों में कीटों की संख्या तीस प्रतिशत तक घट गई है। ऐसा ही चलता रहा तो यह जल्दी ही चालीस और पचास प्रतिशत के स्तर को भी पार कर जाएगी। झींगुरों का खुद का शोर तो कानों में मिश्री घोलने वाले संगीत के मानिंद होता है, जो आनंद के अहसास से अभिभूत करने वाला होता है। आदमी ही कल पुर्जों और तेज आवाज के उपकरणों के जरिए ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहा है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के ये निष्कर्ष तो पहले से हमारे सामने हैं कि ध्वनि प्रदूषण श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। नींद, एकाग्रता और फिर पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। नसों की कई बीमारियों व माइग्रेन के कारणों में ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है।

भारत के संदर्भ में बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम की प्राथमिकताओं में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था सिर्फ रात दस बजे के बाद शोर को वर्जित करती हैं। इन निर्देशों की भी पालना नहीं हो पा रही है। दिन भर में शोर कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर भी सभी अंगों को ध्यान देना होगा। और इस नुकसान को कम से कमतर करने के उपाय भी क्रमशः करने ही पड़ेंगे। हमारी खुद की सुरक्षा और प्रकृति की बेहतरी के लिए यह जरूरी है।

शरीर में अग्नि पुरुष रूप-अव्यय, अक्षर, क्षर रूप कार्य करता है। प्रकृति माया-शक्ति-क्रिया रूप में कार्य करती है। माया के परिग्रहों (आवरणों) के कारण अव्यय ही अक्षर और क्षर रूप में परिणत हो जाता है। परिग्रहों के कारण एक ही आत्मा छह भागों में विभक्त हो जाता है।

ईश्वर पुरुष - प्रकृति शरीर

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

ईश्वर ही पुरुष है- प्राण है। प्रकृति शरीर है, क्रियाओं का साधन है। ईश्वर की इच्छा से ही प्राण प्रेरित होकर कर्म करते हैं। अर्थात् ब्रह्म ही स्वेच्छा से कर्म बनते हैं। ब्रह्म ही कर्म के सहारे पुन: लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत ब्रह्म-कर्ममय है। प्रकृति-पुरुषमय है।

सृष्टि का संचालन प्रकृति और पुरुष करते हैं। प्रकृति सोम है, कर्ता है। पुरुष अग्नि है, भोक्ता है। अग्नि के तीन स्वरूप हैं-अग्नि-यम-आदित्य। सोम के तीन स्वरूप है-आप्-वायु-सोम। ये ही क्रमशः घन-तरल-विरल रूप में रहते हैं। इन्हीं को स्थूल-सूक्ष्म-कारण कहा जाता है। ये ही अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म हैं। जब भी सोम अग्नि में आहूत होता है तब दोनों के घन-तरल-विरल स्वरूप यज्ञ रूप में कार्य करते हैं। यहां भावनाओं की घनता-तरलता-विरलता भी प्रेरक वायु का कार्य करती हैं। पंच महाभूत क्रमशः आकाश-वायु-अग्नि-जल-पृथ्वी रूप लेते जाते हैं। तीनों हृद्-प्राण-ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र- क्षर ब्रह्म के प्राणों के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं। मन-प्राण मिलकर वाक् का निर्माण करते हैं। वाक् को असुर कहा है।

शरीर में अग्नि पुरुष रूप-अव्यय, अक्षर, क्षर रूप कार्य करता है। प्रकृति माया-शक्ति-क्रिया रूप में कार्य करती है। माया के परिग्रहों (आवरणों) के कारण अव्यय ही अक्षर और क्षर रूप में परिणत हो जाता है। परिग्रहों के कारण एक ही आत्मा छह भागों में विभक्त हो जाता है- माया-कला, गुण-विकार तथा अंजन-आवरण। इन तीन युगलों का एक-एक परिग्रह बनता है। माया-कला परिग्रह से अव्यय बनता है। वास्तव में माया निष्कल परात्पर को आवरित कर अव्यय पुरुष का निर्माण करती हैं। अनेक खण्डों में विभक्त करने वाली योगमाया ही कला है, इसके कारण निष्कल परात्पर षोडशकल बन जाता है।

गुण व विकार का संबंध अक्षर या परा प्रकृति से है। गुणभाव के कारण पुरुष ही सत्त्व-रज-तम युक्त सत्य प्रजापति बनता है। विकार संबंध अर्थात् पंचीकरण प्रक्रिया से वही सत्य प्रजापति यज्ञ प्रजापति बनता है–

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्।। (गीता 13.20)

अंजन और आवरण परिग्रह दो प्रकार के हैं–स्वच्छ और मलिन। स्वच्छ आवरण 'अंजन' और मलिन आवरण 'आवरण' कहलाता है। जड़ भाव का कारक आवरण है। अंजन परिग्रह से यज्ञ प्रजापति ही विराट् बनता है। यही ईश्वर और जीव दो भावों में विभक्त हो जाता है। स्वच्छ अंजन ईश्वर तथा मलिन अंजन जीव है।

मूल में तीनों एक हैं। अव्यय- अमृत परिग्रह, अक्षर- ब्रह्म परिग्रह तथा क्षर ही शुक्र-परिग्रह बनता है। ये ही मन-प्राण-वाक् अथवा ज्ञान-क्रिया-अर्थ रूप में विश्व में प्रतिष्ठित हैं। परिग्रह हटने पर तीनों एक ही आत्मा बन जाते हैं–**तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।** (कठ. 6.1) यही षोडशी पुरुष अश्वत्थ वृक्ष है। यही भौतिक विश्व रूप है।

यहां एक सिद्धान्त ध्यान देने योग्य है-अग्नि पानी में प्रवेश कर सकता है, पानी अग्नि में प्रवेश नही कर सकता। अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए स्वयंभू के अग्नि प्राण परमेष्ठी के अप् में प्रवेश करके भृगु-अंगिरा-अत्रि को उत्पन्न करते हैं। सूर्याग्नि चान्द्र सोम में, देवाग्नि दिक् सोम में तथा पृथ्वी की अग्नि अन्तरिक्ष सोम में प्रवेश करती है। विद्युत पर्जन्य में प्रवेश करता है। सभी पिण्डात्मक अग्नि अपने चारों ओर वेष्टित सोम से ही योग करके यज्ञात्म भाव पैदा करती है। हृदय में विष्णु सोम लाकर ब्रह्म के स्वरूप की पूर्ति करता है। जिस अग्नि को इन्द्र बाहर ले जाता है, वही बाहर जाकर सोम बन जाता है। यह अग्नि 33 स्तोम तक जाता है।

स्त्री-पुरुष के समागम में स्त्री-सोम पुरुषाग्नि में आहूत होता है। भीतर स्त्री भी अग्नि रूप है। सोम एवं पुरुषाग्नि योषाग्नि में मिलते हैं। पुरुषाग्नि भी स्त्री-सोम से युक्त होकर भीतर अपने सोम स्वरूप से मिल जाती है। स्त्री के भीतर आग्नेय तत्त्व बढ़ता है-शोणित में। पुरुष का शुक्र-सोम एकत्र होने लगता है। अरणी मन्थन में अग्नि प्रज्वलित हो उठता है। वायु के प्रहार से सोम अग्नि में आहूत होता है। सोम शुक्र में पुरुष शुक्राणु है- उसका रेत भी सोम है। यही (शुक्राणु) रेत डिम्ब तक पहुंचता है।

यहां स्त्री-पुरुष के मन-प्राण तथा शुक्राणु-डिम्ब के मन-प्राण भी गतिमान रहते हैं। इनका भी आदान-प्रदान रहता है। कामना का स्वरूप दोनों के मन में एक ही हो यह आवश्यक नहीं है। पुरुष के मन में भोग हो तो स्त्री के मन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वहां सन्तान की कामना भी हो सकती है। दोनों के मन की कामनाएं एक जैसी भी हो सकती हैं। उस समय दोनों किस गुण (सत्व, रज, तम) में बहते हैं, प्रसन्नता से आनन्द की ओर अग्रसर हैं या नहीं अथवा उदासीनता-थकान का भाव बना है। शरीर की व्याधि भी प्रभावित करती हैं। मन तो तीनों शरीरों के भिन्न-भिन्न होते हैं। सर्वेन्द्रिय और इन्द्रिय मन स्थूल देह को जोड़ते हैं। रस्म अदायगी या मनोरंजन से आगे उद्देश्य नहीं रहता है। महन्मन जीवात्मा का आश्रय है। आकृति-प्रकृति-अहंकृति तीनों की भूमिका रहती है। स्थूल शरीर का सुख क्षणिक होता है। यहां सूक्ष्म स्तर पर मन और प्राण दोनों ही अक्षर धरातल पर रहते हैं।

जीवात्मा के साथ पहले महन्मन ही पैदा होता है। यही अव्यय मन का प्रथम प्रतिनिधि है। साधक-भीतर जीने वाला ही इसका अनुभव कर सकता है। यदि दोनों के मन सात्विक-श्रद्धायुक्त हैं तो परिणाम भी आनन्द की ओर ही प्रेरित करते हैं। दोनों ही अन्तस् को समर्पित हो जाते हैं। कर्मपूजा बन जाता है। प्राण उपस्थ में आनन्द का भाव पैदा करते हैं।

शरीर स्वयं जड़ है। प्राणों के कारण गतिशील दिखाई पड़ता है। शरीर के साथ इन्द्रियां, इन्द्रियों के प्राण, इन्द्रियों के विषय, स्थूल प्राण आदि अनेक अंग कार्य करते हैं। मन का आवेग इतना तीव्र होता है कि इन क्रियाओं का आभास तक नहीं होता। यह तल्लीनता यदि पूर्णरूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाए तो कर्म भी ईश्वरीय हो जाता है। फल भी शून्य हो जाता है।

मन की कामना से ही प्राण गतिमान होकर वाक् का निर्माण करते हैं। मूल में तो ऋषि प्राण है-अव्यय मन के। पितर प्राणों के साथ सात पीढ़ियों के अंश आते हैं। देव प्राणों के द्वारा सभी 33 प्राण शरीर का निर्माण करते हैं- जैसे जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आठवें स्तर पर निर्माण पूर्ण होता है। शरीर के प्राण स्थूल होते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इनमें मुख्य है। इनमें भी जो प्राण है, वही प्रमुख है। यही सूक्ष्म शरीर से जोड़ता है। क्षर पुरुष की पांच कलाओं में पहला प्राण ही है। इसी का मूल अक्षर पुरुष का प्रथम प्राण ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही हृदय प्रतिष्ठ है। स्वयंभू प्राण है।

रेत में (शुक्राणु के) जो पुंभ्रूण होता है उसमें एक ईश्वर प्रजापति का तथा दूसरा जीव प्रजापति को रेत होता है। आते दोनों पंचाग्नि के सिद्धान्त से हैं। समागम में यदि महन्मन नहीं जुड़ा तो ईश्वर आत्मा का पदार्पण नहीं होता। संतति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ईश्वर आत्मा को चन्द्रमा पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह सीधा हृद्-प्रतिष्ठ हो जाता है। जीवात्मा कर्मों के भोग-स्वर्ग/नरक तक जाने-आने के लिए चन्द्रमा से होकर जाता है। वापिस भी चन्द्रमा से ही पर्जन्य में प्रवेश करता है और अन्न के माध्यम से रेत में प्रवेश करता है। शरीरी होने से यह शरीर में व्याप्त हो जाता है। इसी से अगले शरीर में सारे अंग बन जाते हैं। ईश्वर आत्मा अशरीरी है। शरीर धारण नहीं करता-द्रष्टा मात्र है, निर्लिप्त भाव में रहता है।

ईश्वर ही पुरुष है- प्राण है। प्रकृति शरीर है, क्रियाओं का साधन है। ईश्वर की इच्छा से ही प्राण प्रेरित होकर कर्म करते हैं। अर्थात् ब्रह्म ही स्वेच्छा से कर्म बनते हैं। ब्रह्म ही कर्म के सहारे पुनः लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत ब्रह्म-कर्ममय है। प्रकृति-पुरुषमय है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

आर्ट एंड कल्चर

मतदान के प्रति उत्साह जगा सकता है सिनेमा

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

कुछ फिल्में होतीं तो बहुत साधारण हैं, लेकिन उनके कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि वर्षों बाद भी स्मृतियों में बने रह जाते हैं। 1996 में डेविड धवन के निर्देशन में 'लोफर' का एक ऐसा ही दृश्य है जो हर आम चुनाव के समय जेहन में तैर जाता है। यह फिल्म मूल तमिल में बनी थी, बाद में यह तेलुगू में 'एसेम्बली राउडी' और कन्नड़ में 'राउडी एंड एम एल ए' टाइटल से बनी। टाइटल से ही फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कोई विधानसभा क्षेत्र है,जिसके विधायक का मुख्य काम ही अपराध और वसूली है। उसके आतंक के डर से कोई भी विरोध नहीं करता। रवि विरोध में खड़ा होता है, लेकिन विधायक एक झूठे केस में फंसा कर उसे जेल भिजवा देता है। पूरा शहर रवि के साथ है, लेकिन विधायक के डर से कोई सामने नहीं आता। शहर में चुनाव होना है, रवि के पिता उसे जेल से चुनाव लड़ने को तैयार करते हैं ताकि विधायक का साम्राज्य खत्म हो सके। मतदान का दिन है, विधायक के गुंडों ने मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के बाहर घेरा डाल रखा है। पूरा शहर डर से घर में बंद है, तभी एक बूढ़ा लाठी टेकते घर से निकलता है। गुंडे रोकते हैं, वह कहता है कि अब इस उम्र में उसे जान का क्या डर। गुंडे उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाकर जाने देते हैं कि एक वोट से क्या बिगड़ जाएगा। बूढ़े का हौसला देख सारा शहर वोट देने उमड़ पडता है । जाहिर है चुनाव परिणाम रवि के पक्ष में आता है और विधायक के साम्राज्य का अंत होता है। मतदान के महत्त्व को रेखांकित करती गिनती की फिल्में ही हिंदी में बनी हैं। ऐसे में 'लोफर' का यह दृश्य सुकून देता है। यह दृश्य एक वोट की ताकत भी दिखाता है और वोट के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की सबसे मजबूत आदमी पर जीत भी। वास्तव में मतदान जैसे मुद्दे पर सिनेमा जैसे जनसंचार माध्यम को सक्रिय होने की आवश्यकता है।

बतंगड़

...इक तेरे भरोसे पर बैठे हैं सब भूल के

हरीश पाराशर

चुनाव परवान पर चढ़ते देख नेताजी वोटर्स को 'भरोसा' दिलाने में पीछे नहीं हैं। वे कह रहे हैं- हमें वोट देकर देखो, फिर तुम्हें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहने देंगे। देख नहीं रहे- हम भी तो रातों-रात पाला बदलकर दूसरों पर 'भरोसा' कर रहे हैं। जो कभी 'हाथ' के साथ थे उन्होंने अब जनता का भरोसा जीता तो 'कमलासन' पर विराजे नजर आएंगे। भरोसे का भी क्या कहें- लोग कहते हैं कि कल का ही भरोसा नहीं, फिर भी वे भरोसे पर भरोसा दिलाए जा रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने से लेकर महंगाई कम करने तक का भरोसा। हाथ वालों को 'भाई-बहन' पर भरोसा है तो फूल वाले 'गारंटीदार' के भरोसे हैं। लेकिन ये सब इतने भरोसे में क्यों हैं जी? देख नहीं रहे बयानवीर किस-किस तरह के बातें भरोसे के साथ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दक्षिण वाले अफ्रीकन और पूर्व वाले चीनी लगते हैं। अपने मणि भाई को सुना- उनको भी भरोसा होने लगा है कि इज्जत नहीं दी तो पड़ोस से कोई परमाणु बम फोड़ देगा। फिर भी उनका भरोसा पक्का है कि इस बार 'हाथ' को साथ मिलने वाला है। पन्द्रह मिनट व पन्द्रह सैकण्ड की बातों पर भी भरोसा करने वाले कम नहीं। कुछ को चुनावों में हिन्दू-मुसलमान करने पर भरोसा है। 'दूसरा युद्ध लड़ने वाले' भाई पर बहिन को भरोसा है। और तो और, कलमकारों को भी पूरा भरोसा है कि इस बार उनकी कलम 'नई इबारत' लिखने वालों के साथ रहेगी। नई इबारत के लिए दोनों पक्ष आतुर हैं। एक ...आर-पार के नारे के साथ तो दूसरा ...इस बार की उम्मीद के साथ। लेकिन जो भरोसेमंद हैं यानी इस देश का मतदाता। वह सब पर भरोसा कर रहा है, यही उसकी मासूमियत है। असल बात तो यह है कि जमाने पर भरोसा करने वालों का जमाना भी अब जाता जा रहा है। फिर सवाल यह है कि किसका भरोसा करें और किसका नहीं। 'देवतुल्यों ' का तो अब भरोसे पर से ही भरोसा उठता दिख रहा है। 'रामभरोसे' जो रहना है।

देश का मतदाता जो सब पर भरोसा कर रहा है, यही उसकी मासूमियत है। असल बात तो यह है कि जमाने पर भरोसा करने वालों का जमाना भी जाता जा रहा है।

harish.parashar@epatrika.com

सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र : प्रवासियों के वोट हो सकते हैं निर्णायक

चुनावी जंग में रंग बदल टकराए दिग्गज, त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे किशन रेड्डी

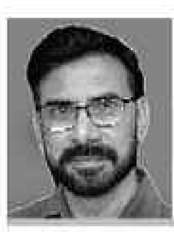

सिकंदराबाद से
राजीव मिश्रा

त्रिकोणीय भिड़ंत ने सिकंदराबाद लोकसभा सीट को रोचक बना दिया है। केसीआर की पार्टी बीआरएस से विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र राव कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें सिकंदराबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो, बीआरएस ने सिकंदराबाद के विधायक टी.पद्माराव गौड़ को उतार दिया। यहां तीसरे दिग्गज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। रेड्डी दूसरी बार और भाजपा हैट्रिक के लिए जोर लगा रही है।

जी. किशन रेड्डी

टी.पद्माराव गौड़

नागेंद्र राव

कहने को सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वां शहर है, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर ही माहौल बदल जाता है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र रानीगंज को मिनी भारत भी कह सकते हैं। यहां कई पीढ़ियों से प्रवासी राजस्थानी, गुजराती और उत्तर भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं। चुनाव में ये निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। भले ही दक्षिण के अन्य राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा चर्चा में नहीं रहा पर यहां इसकी चर्चा है।

उज्जैनी महाकाली मंदिर से निकल पास ही पूजा सामग्री की दुकान पर बैठे संजयसिंह से चुनावी माहौल के बारे में पूछा तो आंख बंद कर और सिर हिलाते हुए सिर्फ दो शब्द बोले- 'मोदी...मोदी।' यहां की गलियों और तंग गलियों से गुजरते हुए महसूस हुआ कि भगवा रंग का बोलबाला है। आगे बढ़ा तो, बीआरएस का गुलाबी रंग भी चटख दिखा। पूछा तो मालूम हुआ कि यह मोंडा मार्केट है। यहां बैग का कारोबार करने वाले वसंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर राव बीआरएस से आए हैं। वे बार-बार पार्टी बदलते हैं। उन पर विश्वास नहीं है। समर्थन इस बार बीआरएस उम्मीदवार टी.पद्मा राव को मिलेगा। मोंडा मार्केट के अलावा सिकंदराबाद और मुशीराबाद में भी बीआरएस के पक्ष में आवाजें सुनाई दीं। सिकंदराबाद से मुशीराबाद, आरटीसी और नारायणगुड़ा तक मेट्रो के खंभों पर पीएम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पोस्टर लगे हुए हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे दिखाई देते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक दुकान पर बैठे राजेश्वर राव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी से लोग नाराज हैं। हालांकि किशन रेड्डी दावा करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की हैं। सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन के पुनर्निर्माण की यहां खूब चर्चा है। पवन, संदीप और हरिकिशन वर्मा इससे काफी उत्साहित नजर आए। रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है, लेकिन गति धीमी है। हैदराबाद बम धमाके की घटना याद करते हुए देवकरण सोनी कहते हैं कि देश अब सुरक्षित हुआ है। आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। बजरंग लाल हीरालाल और घनश्याम सोनी कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण का मुद्दा प्रवासियों को खूब प्रभावित कर रहा है। यहां लगभग 2 लाख प्रवासी मतदाता हैं। किशन रेड्डी को इन मतदाताओं पर काफी भरोसा है। सिकन्दरबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नामपल्ली और अम्बरपेट इलाके मुस्लिम बहुल हैं। बावजूद इसके किशन रेड्डी अम्बरपेट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भी उन्हें व्यापक समर्थन मिलता रहा है। अकबर अली कहते हैं कि यहां दोनों धर्म के लोग मोहब्बत से रहते हैं। गले पर निशान दिखाते हुए अली कहते हैं कि दो साल पहले पतंग के माझे से उनकी गर्दन कट गई थी। तब एक हिंदू साथी ही उन्हें अस्पताल लेकर गया। कई दिनों तक आइसीयू में रहा, लेकिन जान बच गई। अली कहते हैं कि नफरत और दूरियां बढ़ाने की बातें नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। दरअसल, रेड्डी की पहचान सॉफ्ट बोलने वाले एक नेता के तौर पर है जो हार्ड हिंदुत्व की राह नहीं अपनाते। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र इस बार रेड्डी की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

सिकन्दरबाद में भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के पक्ष में बराबर आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि, हैदराबाद शहर में बीआरएस, मजलिस और भाजपा के ही विधायक हैं। कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं हैं। लेकिन, राजेश्वर कहते हैं कि, यहां जो भी पार्टी सत्ता में आती है,उसके उम्मीदवार स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं। दानम नागेंद्र को कम नहीं आंक सकते। मुकाबला त्रिकोणीय है और टक्कर कांटे की।

गठबंधन दलों की नजदीकियां और दूरियां चर्चा में

प्रियरंजन भारती

गठबंधन दलों की दूरियां और नजदीकियां भी मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय हैं। इंडिया गठबंधन यानी बिहार के महागठबंधन में विभिन्न दल शामिल तो हो गए, मगर इनके बीच दूरियां भी दिख रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक दो उदाहरण छोड़कर गठबंधन के दलों ने एक मंच से साझा चुनाव प्रचार तक नहीं किया। चौथे दौर का मतदान होने वाला है और यह चर्चा गरम हो गई कि दल मिले, दिल नहीं। महागठबंधन के घटक दल अपने ही स्तरों पर हिस्से में मिली सीटों पर चुनाव प्रचार करते देखे जा रहे हैं। अकेले आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जोर लगाते हुए प्रचार अभियान चला रखा है। वह वीआइपी के मुकेश सहनी के साथ आरजेडी को आवंटित सीटों पर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं।

महागठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस को नौ, वीआइपी को तीन, सीपीआइ को एक, सीपीएम को एक तथा सीपीआइ-एमएल को तीन और शेष तेईस सीटें आरजेडी को मिली हैं। इनमें चुनाव प्रचार महागठबंधन की साझा रैलियों के साथ नहीं हो रहा है। सभी घटक दल अपनी सीटों पर अपने ही स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीपीआइ एमएल काराकाट, आरा और नालंदा संसदीय सीटों पर चुनाव मैदान में अपने दम पर प्रचार कर रहा है। सीपीएम खगड़िया और सीपीआइ बेगूसराय लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही वामपंथी पार्टियों के नेता अपने ही क्षेत्र में अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की ओर से भागलपुर में राहुल गांधी की अब तक एकमात्र हुई चुनावी सभा में तेजस्वी यादव जरूर मंच पर मौजूद थे। दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों के बीच चुनाव अभियान और प्रचार में सामंजस्य साफ दिख रहा है। चुनावी रैलियों में घटक दलों के नेता मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों में जदयू, लोजपा और रालोमो नेता भागीदार होते हैं। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारकों के चुनावी सभाओं और रोड-शो में गठबंधन के घटक दलों के नेता मौजूद होते हैं।

आपकी बात

गलत संगति का दुष्परिणाम

पारिवारिक उपेक्षा, गलत संगति, सामाजिक-आर्थिक दबाव, शिक्षा की कमी और मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण भी किशोर राह भटक जाते हैं। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए समाज और सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। किशोरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।

-अतुल सर्राफ, रीवा, मध्यप्रदेश

संस्कारों की कमी है कारण

दिशाहीनता और संस्कारों की कमी की वजह से किशोरों में स्वच्छंदता पनप रही है। परिणामस्वरूप अपराध की दुनिया मे किशोरों के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। मोबाइल पर अश्लीलता और अपराध से भरे अनेक वीडियो सुलभ हैं। अच्छा साहित्य, परिवार और समाज ही उन्हें इस भटकाव से रोक सकता है।

- पवन कुमार जैन, जयपुर

आज का सवाल

राजनीति में सुधार कैसे हो सकता है?

कल का सवाल था, किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

आर्थिक तंगी से हताशा

किशोरों में अपराध का बढ़ना चिंताजनक है। अशिक्षा, आर्थिक तंगी और बढ़ती बेरोजगारी से उपजी हताशा भी बढ़ते अपराधों की वजह है। इंटरनेट पर फैली अश्लीलता भी अपराधों का कारण है। किशोरों पर हिंसक और अश्लील दृश्यों का बहुत गलत असर पड़ता है। वे अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं और अपराध की राह पकड़ लेते हैं।

-राजन गेदर, सूरतगढ़ ,गंगानगर

परिवार में संवाद की कमी

परिवारों में किशोरों से निरंतर संवाद की कमी होती जा रही है। किशोरों की दिनचर्या पर अभिभावक उदासीन रहते हैं। किशोरों की खराब संगत, हार्मोनिक बदलाव के कारण उनके आचार-व्यवहार में बदलाव पर परिवार के सदस्यों को संज्ञान न लेने के कारण वे पथ भ्रमित होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण भी वे राह से भटक रहे हैं।

-सतीश उपाध्याय, मनेंद्रगढ़ एमसीबी, छत्तीसगढ़

कल्पमेधा

कट्टरपन और असहिष्णुता सत्यान्वेषण में बाधक तो होते ही हैं, परंतु वे जिस पक्ष का समर्थन करते हैं उसे भी हानि पहुंचाते हैं।

– गांधी

सियासी खींचतान

चलते चुनाव में हरियाणा की राज्य सरकार अल्पमत में आ गई। उसकी सबसे बड़ी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जजपा तो करीब ढाई महीने पहले ही साथ छोड़ गई थी, इस हफ्ते तीन निर्दलीय विधायक भी हाथ छुड़ा कर अलग खड़े हो गए। इस तरह सरकार अल्पमत में आ गई। स्वाभाविक ही विपक्षी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मगर मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। संवैधानिक प्रावधान है कि अगर किसी सरकार ने सदन में बहुमत हासिल किया है, तो वह छह महीने तक काम कर सकती है। मार्च में जब मनोहरलाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जजपा ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। तब बहुमत साबित करना पड़ा था। अब जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर नैतिक दबाव बनाना शुरू किया है, तो जजपा भी उसके साथ खड़ी हो गई है। दोनों दलों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख कर मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि इससे उन्हें कोई उल्लेखनीय कामयाबी मिलने की संभावना कम है। इन दोनों दलों की हड़बड़ी और भाजपा की निश्चिंतता की वजहें भी स्पष्ट हैं। दरअसल, सैनी सरकार को बहुमत के लिए केवल एक विधायक की जरूरत है, जो इस महीने होने वाले करनाल विधानसभा उपचुनाव के बाद, संभव है उसे मिल जाए।

हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने, जजपा के अलग होने और अब निर्दलीय विधायकों के छिटक जाने के पीछे का गणित किसी से छिपा नहीं है। यह सब आम चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले हुआ। किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा में लोग सरकार के विरोध में हैं। दूसरी बार जब किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे थे, तब जिस तरह उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लगातार उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए और पुलिसिया दमन का सहारा लिया गया, उससे खट्टर सरकार के प्रति नाराजगी और बढ़ गई। जजपा चूंकि सरकार का हिस्सा थी, इसलिए उसके प्रति भी बराबर की नाराजगी देखी गई। भाजपा ने मुख्यमंत्री बदल कर उस नाराजगी को हल्का करने का प्रयास किया, तो जजपा ने भाजपा से अलग होकर। सरकार का साथ दे रहे निर्दलीय विधायक भी उस नाराजगी से बचे नहीं थे। फिर, इसी साल अक्तूबर-नवंबर में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों और निर्दलीय विधायकों ने आम चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव का समीकरण भी साधने का प्रयास किया। मगर वास्तव में उन्हें इसका कितना लाभ मिल पाएगा, कहना मुश्किल है।

अब जब निर्दलीय विधायकों के छिटकने से सरकार कमजोर पड़ गई है, कांग्रेस को वहां अपना जनाधार बढ़ाने का अवसर हाथ लग गया है। चलते आम चुनाव की सरगर्मी में वह इसे भुना लेना चाहती है। अगर तत्काल किसी तरह राज्य में तख्ता पलट संभव हो पाता है, तो न केवल लोकसभा चुनाव, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का हाथ मजबूत हो सकता है। लगे हाथ जजपा भी अपने ऊपर लगे कुछ दाग धो लेने के फेर में है। हालांकि वास्तव में बहुमत साबित करने की बात आएगी, तो खुद उसके कितने विधायक साथ खड़े होंगे, वह दावा नहीं कर सकती। मगर यह सारा सियासी खेल जिस ढंग से चल रहा है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ में लोकतंत्र को एक तरह से मजाक बना दिया है।

बीमारी का आहार

पिछले कुछ दशक में जीवन-शैली संबंधी बीमारियां सरकार के लिए चिंता का विषय बनती गई हैं। स्वास्थ्य और आहार विशेष निरंतर लोगों से अपनी जीवन-शैली में बदलाव लाने, आहार संबंधी सतर्कता बरतने का आह्वान करते रहे हैं, मगर उसका अपेक्षित असर नहीं देखा जाता। खासकर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह लोगों की खानपान संबंधी आदतें बदली हैं, उससे कई नई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी इन नई समस्याओं की गिरफ्त में बच्चों और युवाओं को अधिक देखा जा रहा है। मोटापा और मधुमेह अब युवाओं के बीच आम समस्या की तरह उभरे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आइसीएमआर ने अपनी एक रपट में खुलासा किया है कि 56.4 फीसद बीमारियां अस्वास्थ्यकर खानपान की वजह से होती हैं। आइसीएमआर की तहत काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी एनआइएन ने आहार संबंधी विवरण पेश करते हुए सत्रह ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है, जिनसे परहेज करके बीमारियों से दूर रहा और स्वास्थ्यकर जीवन बिताया जा सकता है। निश्चय ही इससे लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता बढ़ेगी।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खासकर शहरी और कस्बाई जीवन में खानपान की आदतें बहुत तेजी से बदली हैं। जबसे डिब्बाबंद और बने-बनाए भोज्य पदार्थों का बाजार बढ़ा है, तबसे खानेपीने के पारंपरिक नियम-कायदे छिन्न-भिन्न होने लगे हैं। बच्चों और युवाओं की जीभ पर बाजार का स्वाद अपना राज करने लगा है। इसमें लोग भूल ही गए हैं कि क्या खाना सेहत की दृष्टि से उचित है और क्या अनुचित। खानेपीने का कोई तय समय भी नहीं रह गया है। इस तरह युवाओं के चयापचय पर बुरा असर पड़ा है, जिसका नतीजा उनमें बढ़ता मोटापा और उनके हृदय पर बढ़ता बोझ है। बहुत सारे कसरत करने वाले युवा, बिना सोचे-समझे प्रोटीन की खुराक लेते हैं, यह उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। इसे लेकर आइसीएमआर ने आगाह किया है। यह निश्चय ही चिंता का विषय है कि आधे से अधिक लोगों में बीमारियां केवल गलत खानपान की आदतों की वजह से पैदा हो रही हैं। इसके लिए जनजागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

सहजीवन में सांसत भरा जीवन

अपनी इच्छा से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में हो रही भयावह घटनाएं अनगिनत प्रश्न उठाती हैं। जीवन की हर उलझन से दूर, आपसी सहमति से चुने सहजीवन संबंध क्यों असुरक्षा, अपमान और अवसाद की ओर धकेलने वाले साबित हो रहे हैं?

मोनिका शर्मा

यह अत्यंत चिंता का विषय है कि मन के जुड़ाव की बुनियाद पर चुने गए सहजीवन संबंधों में भी आए दिन शारीरिक-मानसिक शोषण, हत्या, आत्महत्या, धोखाधड़ी और 'ब्लैकमेलिंग' के मामले सामने आते हैं। बावजूद इसके, दायित्वबोध से दूर यों साथ रहने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कभी महानगरों में देखे-सुने जाने वाले सहजीवन रिश्तों के वाकये अब छोटे शहरों और कस्बों तक में आम हो चले हैं। माता-पिता बन चुके महिला-पुरुष भी सहजीवन रिश्तों को चुनने लगे हैं। कभी दबे-छुपे रहने वाले आधुनिक जीवनशैली के इन रिश्तों को लेकर अब खुलकर संवाद होने लगा है। शोषण और जीवन से हार जाने की ऐसी दर्दनाक घटनाएं इन्हें चर्चा का विषय बनाती हैं। ऐसे में सवाल है कि केवल अपनी सहूलियत और आपसी समझ के आधार पर चुने गए जीवन के साझेपन में भी संघर्ष की स्थितियां क्यों बन जाती हैं? आमतौर पर सहजीवन संबंधों में न तो समाज का दबाव होता है और न ही परिजनों का दखल। एक-दूजे संग जीने के अलावा कोई जिम्मेदारी भी ऐसे युवक-युवतियों या उम्रदराज महिला-पुरुषों पर नहीं होती। फिर भी कभी जीवन से हारने की स्थितियां बन जाती हैं, तो कभी एक-दूजे की जान ले लेने की।

इसमें दो राय नहीं कि साझा संबंधों में दायित्वबोध का भाव ही सुरक्षा और संबल देता है। साझेपन के इन पहलुओं को सहजीवन संबंधों के मामले में भी न्यायिक रूप से परिभाषित किया जा चुका है। ऐसे रिश्तों को काफी समय पहले कानूनी मान्यता मिल चुकी है। सहजीवन में रहने के लिए अठारह वर्ष से अधिक आयु वाला जोड़ा किसी भी लिंग का हो सकता है। साथ ही, बिना किसी दबाव के दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। सहजीवन में रहने वाले जोड़े के जीवन में उनके माता-पिता सहित कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सहजीवन वाले जोड़ों को जीवन का अधिकार है। स्पष्ट है कि ऐसे रिश्तों में नाते-रिश्तेदारी के किसी दूसरे संबंध या परिजनों के कारण उपजे मानसिक दबाव के चलते उलझनें पैदा नहीं हो सकतीं।

एक ओर बगैर शादी के लंबे समय तक एक ही घर में साझा जीवन जीने वाले जोड़ों के संबंधों से जुड़ी पेचीदगियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर अपराध के आंकड़े। गौरतलब है कि किसी सहजीवन संबंध में माता-पिता बने जोड़े के बच्चों के अधिकार की बात हो या पहले से शादीशुदा लोगों का सहजीवन में रहने का रास्ता चुन लेना। बिखराव-उलझाव के कई पक्षों पर न्यायालय की टिप्पणियां आ चुकी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पति को तलाक दिए बिना सहजीवन में रहने वाली एक विवाहित महिला की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ सहजीवन में नहीं रह सकती। इस मामले में न्यायालय ने महिला की सुरक्षा की मांग को खारिज करते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा था कि अगर ऐसे रिश्तों को मान्यता दी जाती है, तो इससे अराजकता बढ़ेगी और समाज का

ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।

दरअसल, परंपरागत बंधनों से परे और सामाजिक-पारिवारिक जीवन की रीति-नीति से हट कर अपनी इच्छा से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में हो रही भयावह घटनाएं अनगिनत प्रश्न उठाती हैं। जीवन की

> **चिंताजनक है कि प्रेम और परवाह के भाव से शुरू होने वाले सहजीवन में साथी और उसके परिजनों का जीवन छीनने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जबकि कई सहजीवन रिश्तों की शुरुआत तो इस सोच के साथ होती है कि आगे चलकर परंपरागत ढंग से शादी कर साझा जीवन जीएंगे। सहजीवन रिश्तों को अपनाने वाले बहुत से लोग इस संबंध को शादी से पहले एक-दूसरे को पूरी अंतरंगता से जान लेने के लिए जरूरी बताते हैं। दुखद है कि जानने-समझने की इस यात्रा में ही शोषण और हिंसा के हालात बन जाते हैं। बिना पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दबाव के, मनमर्जी से चुने संबंधों में भी समाज को दहलाने वाली पीड़ादायी घटनाएं होने की परिस्थितियां बन जाती हैं।**

हर उलझन से दूर, आपसी सहमति से चुने सहजीवन संबंध क्यों असुरक्षा, अपमान और अवसाद की ओर धकेलने वाले साबित हो रहे हैं? रहने-सहने के मोर्चे पर क्या मनमर्जी से चुने रिश्ते निभाना भी अब कठिन हो गया है? देखने में आ रहा है कि प्रेम, सहजता और आपसी समझ के आधार पर साथ रहने का मार्ग चुनने वाले संबंधों में भी हत्या और आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामलों का भावनात्मक भटकाव और व्यावहारिक पहलुओं की समझ नदारद होती है। समाज से टूटकर और खुलकर जीने के नाम पर किए गए अनगिनत वादों-इरादों में वास्तविक जीवन से जूझने की समझ और साहस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। साथ ही, दायित्वबोध की कमी कभी नकारात्मक और बर्बर सोच ले आती है, तो कभी भावनात्मक टूटन। बिखरी मानसिकता के दौर में पहली वजह अपने साथी का जीवन छीन लेने का कारण बनती है, तो दूसरी अपनी जान देने की। स्नेह-साथ के जुड़ाव में मौखिक दुर्व्यवहार और हिंसा के मामले भी आए दिन सामने आते हैं। यही वजह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सहजीवन में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून से संरक्षण दिया है। ऐसे में सहजीवन में रहने वाली महिला के साथ किसी भी तरह का हिंसात्मक बर्ताव होता है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। पुलिस में रपट दर्ज करा सकती है।

चिंताजनक है कि प्रेम और परवाह के भाव से शुरू होने वाले सहजीवन में साथी और उसके परिजनों का जीवन छीनने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जबकि कई सहजीवन रिश्तों की शुरुआत तो इस सोच के साथ होती है कि आगे चलकर परंपरागत ढंग से शादी कर साझा जीवन जीएंगे। सहजीवन रिश्तों को अपनाने वाले बहुत से लोग इस संबंध को शादी से पहले एक-दूसरे को पूरी अंतरंगता से जान लेने के लिए जरूरी बताते हैं। दुखद है कि जानने-समझने की इस यात्रा में ही शोषण और हिंसा के हालात बन जाते हैं। बिना पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दबाव के, मनमर्जी से चुने संबंधों में भी समाज को दहलाने वाली पीड़ादायी घटनाएं होने की परिस्थितियां बन जाती हैं। यही वजह है कि 2022 में इंदौर उच्च न्यायालय ने पिछले कुछ बरसों में सहजीवन संबंधों में बढ़ते अपराधों का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की थी कि यह अभिशाप नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का सह-उत्पाद है।

सहजीवन संबंधों में हो रहे अपराधों को देखते हुए अदालत यह टिप्पणी करने पर मजबूर है कि यह भारतीय समाज के लोकाचार को निगल रहा है। सहजीवन संबंध तीव्र कामुक व्यवहार के साथ ही व्यभिचार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे यौन अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि इंदौर हाईकोर्ट यह टिप्पणी सहजीवन में रह रही एक महिला से बार-बार बलात्कार, उसकी सहमति के बिना उसका जबरन गर्भपात कराने, और आपराधिक धमकी देने वाले पच्चीस वर्षीय युवक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की थी। निस्संदेह, मनचाहे रिश्तों में बन रही अनचाही स्थितियां आज के दौर में समग्र समाज को चेताने वाली हैं। साथ ही व्यक्तिगत मोर्चे पर भी ऐसे आपराधिक वाकये हर इंसान को आगाह करते हैं कि जिम्मेदारियों को छोड़ कर मन-मुताबिक जीवन जीने की जद्दोजहद भी कम नहीं। दायित्वबोध का भाव और सम्मानजनक मानवीय जुड़ाव हर संबंध में आवश्यक है।

अनुभव और व्यक्तित्व

राजेंद्र प्रसाद

हमारा जीवन अनेक पड़ावों से गुजरता है। उसको सार्थकता से पार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के निखार और निर्माण के लिए बहुत-से कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं भी व्यक्तित्व की नींव ढीली हुई तो हम जीवन के संघर्षों का मुकाबला उतनी मजबूती से नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। अपने गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तित्व नवनिर्माण के लिए अन्य बातों के अलावा अनुभव, धीरज, व्यवहार और विवेक मुख्य रूप से महत्त्ववपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का मिलाजुला संयोजन व्यक्तित्व कहलाता है। एक व्यक्ति बनकर जीना महत्त्वपूर्ण नहीं, बल्कि एक वजनदार व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवंत रहता है।

हमारे व्यक्तित्व की चमक के लिए धीरज, जब हमारे पास कुछ न हो और दूसरा, हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। सबसे पहले जो दूसरे के संपर्क में आएगा, वह है व्यक्तित्व। भीतरी गुण तो बाद की वस्तु है। जाहिर है कि जिंदगी में शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जिया जाए, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाएगा, मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं, जो फलों से लदा होता है। किसी को सूखे पेड़ पर शायद ही कोई पत्थर फेंकते देखा गया हो। विचार और व्यवहार बगीचे के वे फूल हैं, जो व्यक्तित्व को महकाते हैं। हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा, वैसा ही दुनिया का नक्शा बनाएंगे। महान आदमी वे होते हैं, जो पहले कभी न सोचे गए और न किए गए काम को अंजाम देने के काम में निरंतर जुटे रहते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **सुख-दुख अतिथि हैं, बारी-बारी आएंगे, चले जाएंगे। अगर वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। कटु सत्य है कि सलाह के सौ शब्दों से ज्यादा अनुभव की ठोकर इंसान को मजबूती देती है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा भी गलत फैसलों से ही आता है।**

कहा जाता है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, जबकि अधिक बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से सीखता है। कष्ट सहने से अनुभव भी मिलते हैं। जीवन में कोशिशें आखिरी सांस तक करनी चाहिए, जिससे लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। मनुष्य के अनुभव को रास्ते का प्रकाश माना जाता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में पीछे देखा जाए तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखा जाए तो आशा मिलेगी। दाएं-बाएं देखेंगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखेंगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में सही रास्ते दिखाने वाला दोस्त है अनुभव। अगला कदम एक सवाल है, लेकिन उठाए गए पिछले कदम के अनुभव उसके जवाब की ताकत है।

वैसे पूरा जीवन एक अनुभव है। समस्याएं सदा नहीं रहतीं, लेकिन वे हमारे अनुभव की किताब पर हस्ताक्षर करके चली जाती हैं।

सुख-दुख अतिथि हैं, बारी-बारी आएंगे, चले जाएंगे। अगर वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। कटु सत्य है कि सलाह के सौ शब्दों से ज्यादा अनुभव की ठोकर इंसान को मजबूती देती है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा भी गलत फैसलों से ही आता है। तजुर्बा अच्छा है, अगर उसका अधिक मूल्य न चुकाना पड़े। अच्छे फैसले अनुभव से आते हैं, लेकिन बुरे फैसलों से अनुभव आता है। इसलिए पछताना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अनुभव कहता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अनुभव के लिए मूल्य चुकाना पड़ सकता है, पर जो शिक्षा मिलती है, वह और कहीं नहीं मिलती। अनुभव सच में एक बेहतरीन स्कूल है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है।

अनुभव बताता है कि मुसीबत के समय में दृढ़ निश्चय पूरी सहायता करता है। अनुभव तर्क से परे है। बहुत से लोग राह में पत्थर ही फेंकेंगे, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन पत्थरों से क्या बनाते हैं- मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है, जो वह कर नहीं सकता था। साहस व्यक्ति से वह करवाता है, जो वह कर सकता है, मगर अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है, जो वास्तव में उसे करना चाहिए। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा, खुद का दिमाग और खुद की कोशिश, कभी जिंदगी में हारने नहीं देती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बड़े बुजुर्गों के पास बैठना है, क्योंकि चंद लम्हों के बदले वह बरसों का तजुर्बा दे सकते हैं।

अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं, वे पुस्तकों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। दूसरों के अनुभव से जान लेना भी मनुष्य के लिए एक अनुभव है। अच्छा निर्णय अनुभव से प्राप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अनुभव का जन्म अक्सर खराब निर्णयों से होता है। किसी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से ज्यादा नहीं हो सकता।

जो लोग पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वे केवल सुख में साथ खड़े रहेंगे और जो लोग वाणी, विचार और व्यवहार से जुड़े हैं, वे संकट में भी खड़े रहेंगे। अनुभव व्यक्तित्व की वाणी है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छूती है। चरित्र मनुष्य की इमारत का भीतरी द्वार है, तो व्यक्तित्व बाहरी। हम जैसा दिखना चाहते हैं, वैसे ही बन जाएं। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची नहीं करें, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा और मजबूत बनाएं कि हमको सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करें। भाषा एक ऐसा वस्त्र है, जिसे शालीनता से पहनने की जरूरत है। सही व्यक्तित्व न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

प्रोत्साहन के शब्द

हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशियों में खुशियां नहीं, मन ही मन में हिंसा पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी परीक्षा में फेल होने पर कोई भी साहस नहीं बंधाता, बल्कि भावनात्मक रूप से तोड़ा जाता है। इसकी जड़ से उपजी मनोदशा की वजह से भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की दुखद घटनाएं हो जाती हैं। वहीं अच्छे काम को प्रोत्साहित करना तो दूर, उन्हें बधाई देने वाले लोगों की भी इस समाज में कमी है। दरअसल, पहले के जमाने में हमारे समाज में लोग एक-दूसरे का सुख-दुख बांटकर समाज में एक नया संदेश फैलाते थे, लेकिन अब वे दिन कहीं न कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवाज देना पर्याप्त है। लोगों की मीठी आवाज कभी-कभी बहुत साहस और प्रोत्साहन देती है। जब बच्चा कोई भी परीक्षा के लिए शहर से बाहर जाता है, तो हर माता-पिता प्यार से बच्चे से कहते हैं कि जाओ तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे लिए है। वास्तव में, इस तरह शब्द कभी-कभी साहस के हथियार के रूप में दिमाग में खड़े होते हैं।

– चंदन कुमार नाथ, गुवाहाटी, असम

बेलगाम बोल

अक्सर देखा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी एक दूसरे के लिए अमर्यादित बात कह देते हैं। भड़काऊ भाषण अक्सर जातीय और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। किसी भी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता को कुछ भी बोलने से पहले आत्मचिंतन करना आवश्यक है। भड़काऊ भाषण दे कर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाता है। जनता को इस प्रकार के नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे भाषण देकर एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष तथा क्षेत्र विशेष का समर्थन हासिल करना इन लोगों का लक्ष्य होता है। इस तरह के भाषणों के कारण जनता के मन में घृणा पैदा होता है, इसलिए भाषण में सिर्फ विकास की उपलब्धियां होनी चाहिए। भड़काऊ भाषणों पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष एवं सशक्त होनी चाहिए।

– संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

लोकतंत्र के लिए

लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो चुका है। प्रथम दो चरणों की तुलना में मतदान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन पूर्व की तुलना में यह अभी भी कम है। बंगाल में छिटपुट हिंसा के बावजूद 66 फीसद से अधिक मतदान संपन्न हुआ है। तृतीय चरण के दौरान असम में सर्वाधिक 79.06 फीसद मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34 फीसद मतदान हुआ। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रशासन द्वारा मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद मतदान में गिरावट चिंताजनक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में बढ़ोतरी अनिवार्य है, लेकिन उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं की उदासीनता झलक रही है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मिलकर मतदान फीसद बढ़ाने पर गंभीरता से उपाय करने चाहिए। मतदान में हिस्सेदारी अगर इसी तरह गिरती गई तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

संबंधों की गरिमा

'रिश्तों की डोर' (दुनिया मेरे आगे, 8 मई) पढ़ा। इसमें रिश्तों की आज के दौर में महत्ता को बखूबी उजागर किया गया है। आज भागती-दौड़ती जिंदगी में किसी के पास रिश्तों के लिए वक्त नहीं है। लोग परिवार में साथ बैठना, बातचीत करना, समय बिताना सब भूल चुके हैं। इसके चलते बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है। पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ सामाजिक रिश्तों की भी अपनी भूमिका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते रहते लोगों से मेलजोल, बातचीत, सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी जरूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया की आड़ में लोग असल जिंदगी में रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। दुख-सुख, जिंदगी के अच्छे-बुरे दौर में यही रिश्ते हमें कंधा देते हैं। प्यार, समझदारी, आदर सम्मान के साथ रिश्तों की डोर थामे रहना बहुत जरूरी है।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

https://t.me/AllNewsPaperPaid
www.readwhere.com

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ शनिवार, 11 मई 2024

अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचें और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। -नेल्सन मंडेला

सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन लोगों की निगाहें अब इसके राजनीतिक असर पर रहेंगी।

राहत और रिहाई

शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए एक अभूतपूर्व फैसले में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत भले मिल गई हो, पर यह उन पर लगे कथित आरोपों से रिहाई नहीं, बल्कि तात्कालिक राहत ही है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय में असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम राहत दी है, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी दो जून को उन्हें हर हाल में समर्पण करना होगा। यही नहीं, इस दौरान मुख्य मामले में सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी, जिसके निर्माण और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र आने पर उपराज्यपाल ने जहां सीबीआई जांच की सिफारिश की, वहीं ईडी ने अगस्त, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी द्वारा एक के बाद एक नौ समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए। अंततः 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इन्कार करने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अदालत ने पहले 28 मार्च, फिर एक अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर और फिर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। इस बीच केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई, फिर उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से फौरी जमानत मिलने के बावजूद इस मामले से जुड़ी पेचीदगियों से सवाल पैदा होते हैं। केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अंतरिम जमानत के दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते।

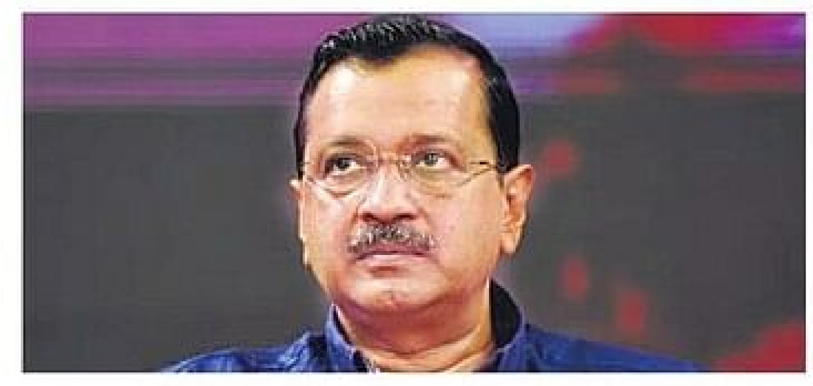

दूसरी बात, यह फैसला क्या दूसरे मामलों के लिए नजीर बनेगा और जेल में बंद अन्य राजनेता क्या इसी आधार पर जमानत नहीं मांगेंगे? चुनाव के बीच केजरीवाल की अंतरिम रिहाई के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। शीर्ष अदालत द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार, केजरीवाल विचाराधीन मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते और न ही मामले से जुड़े गवाहों से बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को भी इससे दिल्ली और बाहर एक चेहरा मिलेगा, हालांकि निर्वाचन आयोग की भी उन पर नजर रहेगी। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाकी चार चरणों में इसका क्या असर होता है।

तलाक का चलन बढ़ रहा है

बढ़ते तलाक की समस्या का समाधान पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों में तलाशा जा सकता है। हमने परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया है। एक साथ भोजन करने और दिल से दिल की बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं है, जहां परेशानियों व खुशियों का आदान-प्रदान होता है।

दंत चिकित्सक की कुर्सी बातचीत करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, आपका मुंह खुला हुआ होता है और आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। सौभाग्य से मेरे पास एक बातूनी दंत चिकित्सक है। यह युवा महिला विवाह बाजार में तब से है, जबसे मैं उसे जानती हूं। वह लगभग 35 वर्ष की है और विवाह बाजार पर उसकी बातचीत आमतौर पर प्रफुल्लित करने वाली होती है। लेकिन पिछली कुछ मुलाकातों (हां, मैं अक्सर दंत चिकित्सक के पास जाती हूं) में वह तलाकशुदा लोगों की बढ़ती संख्या के बारे में बताती रही है।

अद्वैता काला
पत्रकार, फिल्म कथा लेखक एवं चर्चित उपन्यासकार

डेढ़ दशक पहले एक योग्य और शिक्षित युवा महिला, जिसने कभी शादी नहीं की हो, कभी तलाकशुदा लोगों की ओर देखती तक नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे, पर बहुत कम थे। तलाकशुदा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए फिर से जीवनसाथी तलाशना मुश्किल था, महिलाओं के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। मगर अब विवाह बाजार बदल चुका है, सभी इच्छुक विवाह बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अब तलाक को कलंक समझे जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है।

शहरी इलाकों में तलाक अब सामान्य बात हो गई है, हालांकि लोग अब भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह अच्छी बात है या बुरी। उदारीकरण के बाद के युग में भारतीय समाज में नाटकीय बदलाव आए हैं, क्योंकि पारिवारिक इकाई में रिश्ते और लैंगिक भूमिकाएं भी विकसित हुई हैं। जिस भारतीय समाज में कभी तलाक के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, वहां आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशकों में तलाक के मामलों में 350 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षित रूप से बड़े शहरों में तलाक के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 से 2017 के बीच तलाक के मामलों में मुंबई में 40 फीसदी की और दिल्ली में 1990 से 2012 के बीच 36 फीसदी की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक

हैं, क्योंकि देश में अब भी तलाक के मामले एक फीसदी के निचले स्तर पर हैं। हालांकि धीरे-धीरे इनमें वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय विवाह की स्थिरता की अवधारणा खतरे में है। वर्ष 2019 में दिल्ली में 60 फीसदी से अधिक तलाक की पहल महिलाओं ने की। इसके कई कारण हैं-उच्च साक्षरता दर, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने महिलाओं को अपने जीवन और निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित किया है।

शोध के मुताबिक, दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक विवाहों की तुलना में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों में वैवाहिक विफलता की दर उच्च है। लेकिन इसकी सफलता एवं विफलता का अनुमान केवल आंकड़ों से नहीं लगा सकते। ऐसे कई कारक हैं, जो तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं और महिला सशक्तीकरण के कदमों को तलाक दर के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह इस देश की महिलाओं एवं बेटियों से अन्याय के साथ-साथ एक गलत धारणा होगी।

आइए, देखते हैं कि वे कौन से कारण हैं, जो तलाक दर को प्रभावित करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 53 फीसदी तलाक की पहल 24 से 35 वर्ष के लोगों द्वारा होती है। जाहिर है कि पीढ़ीगत नजरिये में बदलाव हो रहा है। जैसे-जैसे दुनिया ऑनलाइन एक-दूसरे से जुड़ रही है, मानवीय रिश्ते और अधिक नाजुक हो गए हैं। 'समझौता' एक बुरा शब्द बन गया है, जबकि एक समय यह वैवाहिक जोड़ों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गुण था। अब समझौते को विफलता माना जाता है। इसके अलावा, हनीमून स्थलों के साथ इंस्टाग्राम के लिए तैयार और फिल्टर की गई छवियां, गंतव्य शादियां, दुल्हन के पहनावे एक तरह की वैवाहिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, जिससे वैवाहिक रिश्ते संबंधों के जुड़ाव की तुलना में उत्सव ज्यादा बन जाते हैं। ये सब चीजें युवा जोड़ों के समक्ष एक नई वास्तविकता प्रस्तुत करते हैं, जो स्थायी रिश्ते के लिए अस्थिर नींव प्रदान करता है।

पारिवारिक संरचना भी नाटकीय रूप से बदली है और नौकरी की जरूरतों के कारण घर से दूर जाने की मजबूरी ने परिवार में बुजुर्गों की भागीदारी लगभग समाप्त कर दी है। अब युवा अपने दम पर रिश्ते तय करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15 भारतीय जोड़ों में से एक बांझपन से जूझ रहा है। हालांकि प्रजनन संबंधी उपचार में नाटकीय प्रगति हुई है, मगर यह बहुत महंगा विकल्प है। ज्यादातर जोड़े वित्तीय स्थिरता सहित कई कारणों से माता-पिता बनने में देरी कर रहे हैं। बच्चे जोड़ों के लिए दांपत्य संभालने और रिश्तों में स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा होते हैं। पारिवारिक मूल्य और जुड़ाव अब भी भारतीय समाज को दूसरों से अलग करते हैं और तलाक के आंकड़े कम रखते हैं।

हालांकि तलाक का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इसका समाधान पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों और उनसे मिलने वाली स्थिरता और सहयोग में तलाशा जा सकता है। हमने परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया है। एक साथ भोजन करने और दिल से दिल की बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं है, जहां परस्पर सहयोग और परेशानियों व खुशियों का आदान-प्रदान होता है। रोजगार के लिए युवाओं का घर-परिवार से दूर जाना एक अन्य पहलू है, जिससे निपटने की जरूरत है। पिछले दशकों में छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है और कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है। अब लोग अपने घर के नजदीक रोजगार के अवसर पा सकते हैं, जिससे उन्हें काम और पारिवारिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।

हमें अपनी विचार प्रक्रिया को नया स्वरूप देना होगा और पश्चिमी जीवन-शैली के अंधानुकरण से दूर जाना होगा। हमें व्यक्तिगत सशक्तीकरण और पारिवारिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाना होगा। एक समय पश्चिम ने व्यक्तिगत उत्कृष्टता का जश्न मनाया था और दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत किया था, पर अब वह अपनी विफलता दर्शा रहा है, जिसमें किशोर उम्र में गर्भधारण, एकल अभिभावक वाले घर, स्कूलों में हिंसा, नशीले पदार्थों की लत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सब कई कारणों से होता है, जिसमें परिवार का टूटना भी शामिल है। एक समाज के रूप में आगे बढ़ने के लिए रुककर एक कदम पीछे हटने का वक्त आ गया है।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

विनोबा भावे

फल की उम्मीद मत करो। *गीता* यह भी बताती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता के साथ करना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए।

फल की इच्छा का त्याग भी जीवन की कला है

जो कर्म करते हैं, उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे। यह हमारा अधिकार है। और इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखने को न मिले तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी ही भावना या वृत्ति बताती है। वह कहती है-'कर्म तो अवश्य करो, पर फल पर अपना अधिकार मत मानो'। जो कर्म करता है, उसे फल का अधिकार अवश्य है। परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है-लूंगा तो फल के सहित ही। जबकि तमोगुण कहता है-छोड़ूंगा तो कर्म के सहित ही। यों दोनों एक-दूसरे के भाई ही हैं। इसलिए तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सतगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो, पर फल को छोड़ दो। यानी फल को छोड़कर कर्म करो। फल की उम्मीद मत करो।

गीता यह भी बताती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता के साथ करना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न-चिंतन में उसका थोड़ा-बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी। परंतु फलेच्छा-रहित पुरुष की तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। जैसे नदी को छुट्टी नहीं, हवा को विश्राम नहीं और सूर्य सदैव जलते ही रहना जानता है, उसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा-कर्म को ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट नहीं होगा तो किसका होगा! इसके अलावा सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म-दृष्टि में जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ की दृष्टि से देखता है-'मेरा ही कर्म और मुझे ही फल'। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका थोड़ा भी ध्यान हटा, तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं दिखता। ज्यादा हुआ तो व्यावहारिक दोष दिखेगा। परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। इसलिए वह इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी-सी भी कमी न रह जाए। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। कैसे भी देखिए, फल-त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है। इसलिए फल-त्याग को योग या जीवन की कला ही कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें, तो भी खुद कर्म में जो आनंद है, वह उसके फल में नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है, वह आनंद का एक स्रोत ही है। जैसे- चित्रकार से कहो कि तुम चित्र मत बनाओ और ऐसा करने के लिए तुम जो मांगोगे, देंगे। लेकिन उसका मन चित्र बनाए बिना कहां मानने वाला है! वह तो चित्रकारी किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही कर्म उसका आनंद है। इसी तरह बच्चा खेल के मजे के लिए खेलता है और इसमें उसे व्यायाम का फल अपने आप मिल जाता है।

जैसी भावना, वैसा फल

सूत्र

सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़े-से कर्म से अनंतगुना फल प्राप्त कर लेता है। यह फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है। हालांकि सांसारिक मनुष्य की तपस्या कम कठिन नहीं होती, लेकिन बस फर्क इतना है कि वह तपस्या क्षुद्र फलों की खातिर ही होती है

दूसरा पहलू

दो शोधार्थियों ने दावा किया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सजगता कार्यक्रम से बच्चों और किशोरों में अवसाद बढ़ रहा है।

स्वस्थ बच्चों को बीमार न बनाएं

हाल के वर्षों में बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। विकसित देशों के किशोर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपने अवसाद और उसके इलाज के बारे में बताते रहते हैं। छोटी उम्र के बच्चों में उदासी और खुद को नुकसान पहुंचाने की बढ़ती प्रवृत्ति से परेशान स्कूल भी पाठ्यक्रम में इनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ शोधार्थी यह चेतावनी दे रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देकर हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस संबंध में सजगता के कार्यक्रम निश्चित तौर पर कुछ बच्चों का भला करते हैं, लेकिन इससे समाज में यह सोच बनती है कि ज्यादातर बच्चे व किशोर अवसादग्रस्त हैं, जिसका इलाज जरूरी है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।

एलेन बैरी

मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देकर हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। इससे यह सोच बनती है कि ज्यादातर बच्चे व किशोर अवसादग्रस्त हैं, जबकि ऐसा नहीं है।

शोधार्थियों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में अवसाद से बचने के कार्यक्रमों का हवाला दिया, जिनमें शामिल होने वाले बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उन बच्चों की तुलना में बेहतर नहीं पाया गया, जिन्होंने इन कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था।

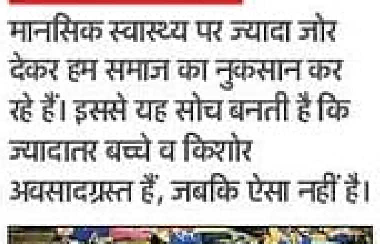

मेंटल हेल्थ अमेरिका का ताजा आंकड़ा बताता है कि 60 फीसदी से अधिक अवसादग्रस्त अमेरिकियों को इलाज नहीं नहीं मिलता। मानसिक स्वास्थ्य एक समस्या है, जिसके निदान से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अमेरिका में हुआ एक नया शोध बताता है कि जो बच्चे और किशोर स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, उन्हें अवसादग्रस्त और मानसिक समस्या से ग्रस्त बता दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो शोधार्थियों ने तो दावा किया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सजगता कार्यक्रम से बच्चों और किशोरों में अवसाद बढ़ रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में यह संदेश जा रहा है कि किशोर मानसिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं, जिनका निदान कोई पेशेवर ही कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों की राय यह है कि स्कूलों को छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने से बचना चाहिए।

अजीब विडंबना है कि एक तरफ तो मानसिक रूप से मजबूत स्कूली बच्चों को भी अवसाद मिटाने के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करनी पड़ती है, दूसरी ओर, मेंटल हेल्थ अमेरिका का ताजा आंकड़ा बताता है कि 60 फीसदी से अधिक अवसादग्रस्त अमेरिकियों को इलाज नहीं नहीं मिलता। हालांकि ऐसे शोध के अपने खतरे भी हैं। कई स्कूलों ने ऐसे शोधों को खारिज किया है। जाहिर है, जब पूरी दुनिया के बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य एक समस्या है, तब इसके निदान से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि इस पर इतना भी जोर नहीं देना चाहिए, जिससे स्वस्थ बच्चे भी बीमार हो जाएं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

सौर ऊर्जा उत्पादक

वर्ष 2023 में हमारा देश जापान एवं जर्मनी को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है।

आंकड़े किलोमीटर में, वर्ष 2023-24 के नवंबर तक के | स्रोत : Ember

परमहंस ने अपने भांजे से कहा-मुझे आज तक ईश्वर के अतिरिक्त कोई मिला नहीं। हरेक प्राणी में ईश्वर को खोजोगे, तो तुम्हें सब में ईश्वर ही मिलेंगे।

ईश्वर सब में हैं

अंतर्यात्रा
संकलित

स्वामी परमहंस साधना और ध्यान करने के लिए रात में पंचवटी के जंगल में जाया करते थे। पंचवटी के जंगल को बहुत भयानक माना जाता था। इसलिए रात तो छोड़िए, दिन में भी वहां कोई जाना नहीं चाहता था।

रामकृष्ण परमहंस के भांजे हृदयराम रोज उन्हें जंगल में जाते देखते, तो चिंतित हो उठते थे। हृदयराम उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह दिन भर उनके साथ रहते और उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, मामा, आप हर रात इतने खतरनाक जंगल में जाकर साधना क्यों करते हैं? स्वामी जी ने कहा, नहीं हृदयराम, वह जंगल खतरनाक नहीं है। वहां मुझे ईश्वर की निकटता का आभास होता है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, जो खतरनाक हो। वह स्थान निर्जन होने के कारण शांत है। और ईश्वर का चिंतन शांति में ही हो पाता है।

हृदयराम ने अपने मन का भय व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन वहां जंगली जीव भी तो हैं, जिनसे आपको खतरा हो सकता है।

स्वामी जी ने प्यार से कहा, सभी में तो ईश्वर हैं। मुझे तो आज तक ईश्वर के अतिरिक्त कोई मिला नहीं। असल में हरेक प्राणी में ईश्वर को खोजोगे, तो तुम्हें सबमें ईश्वर ही मिलेंगे। हृदयराम निरुत्तर हो गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 28 फरवरी, 1991

दस वैज्ञानिकों को शांतिस्वरूप पुरस्कार

दस वैज्ञानिकों को शांतिस्वरूप पुरस्कार

छह विषयों के दस वैज्ञानिकों को शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनमें डॉ. समीर, डॉ. चौधरी, प्रो. महार्ति, प्रो. शंकर, डॉ. गगन, डॉ. मान, प्रो. सुब्रमण्यम आदि शामिल हैं।

कृषि व खाद्य के लिए समग्र नीति बने

किसानी के पारंपरिक ज्ञान के बेहतर उपयोग के साथ ही किसानों के खर्च और कर्ज में कमी बेहद जरूरी है।

भारत डोगरा
कृषि

राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कृषि व खाद्य नीति की बहुत चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ऐसी समग्र नीति नहीं बन पाई है, जिसमें सभी जरूरतों का संतुलित समावेश हो सके। ऐसी समग्र नीति में आठ उद्देश्यों का संतुलित निर्वाह होना चाहिए, जो परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

पहला उद्देश्य तो यह है कि किसानों को, विशेषकर छोटे व मध्यम किसानों को संतोषजनक, टिकाऊ व रचनात्मक आजीविका उपलब्ध हो। संतोषजनक का मतलब उन्हें उपज की उचित कीमत मिले, जिससे जीवन-निर्वाह के अनुकूल आय प्राप्त हो। टिकाऊ का अर्थ आजीविका व इसका आधार भावी पीढ़ी के लिए भी टिका रहे। पानी-मिट्टी जैसी खेती की बुनियादी जरूरतें अच्छी स्थिति में बनी रहें। रचनात्मक का अर्थ खेती-किसानी के ज्ञान का किसान बेहतर उपयोग कर सकें, जिसमें परंपरागत ज्ञान व महिला किसानों की समझ की बड़ी भूमिका है। खर्च और कर्ज में कमी जरूरी है।

दूसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य पदार्थ उचित कीमत पर मिलें, जो उन्हें स्वस्थ व नीरोग रखें। तीसरा उद्देश्य यह है कि कृषि व गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। भू-जल स्तर ठीक बना रहे, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहे, जल-स्रोत उपलब्ध हों, किसान के मित्र, जो कीट-पतंगे, मधुमक्खियां, पक्षी आदि हैं, उनकी भी रक्षा हो तथा परागण की क्रिया ठीक से हो। सभी गांवों में भरपूर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष रहें। परंपरागत बीजों की रक्षा भी बहुत जरूरी है।

चौथा उद्देश्य यह है कि जलवायु बदलाव के मौजूदा दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम रखा जाए और इस कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी स्थितियों व आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो। बुरे मौसम व आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से बेहतर तैयारी करनी होगी। यदि ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने का कार्य ठीक से हो, तो इसके लिए विश्व स्तर पर स्थापित कोष से धनराशि प्राप्त की जा सकती है और किसानों को दी जा सकती है।

पांचवां उद्देश्य है कि भूमिहीन खेत मजदूरों को बेहतर मजदूरी और जहां संभव हो, कुछ भूमि देकर उनकी सहायता की जाए। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की भलाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। विशेषकर डेयरी व पशुपालन, किचन गार्डन आदि के माध्यम से भी इनकी मदद हो सकती है।

छठा उद्देश्य है कि खेती के उत्पादों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि केवल खेती से गांव व गांव के लोगों की समृद्धि का मजबूत आधार नहीं बनता है। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

सातवां उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न भागों की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार कृषि विकास की अलग-अलग जरूरतों के अनुकूल नियोजन होने चाहिए। यानी विकेंद्रित स्थानीय जरूरतों के अनुकूल कृषि नीति पर अधिक जोर देना चाहिए।

आठवां और अंतिम उद्देश्य यह है कि खेती व ग्रामीण विकास के लिए सरकारों को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। एक बार किसानों के कर्ज को माफ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि सस्ती तकनीक अपना कर वे आगे कर्ज से बच सकें।

बेशक इन सब उद्देश्यों का एक साथ एक समग्र संतुलित नीति में समावेश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस राह पर चलते हुए हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों में कोई आपसी टकराव नहीं है। इन सभी उद्देश्यों को हम एक साथ एक समय में समावेशी नीति से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक इन नीतियों के साथ कुछ समाज-सुधार के कार्य नहीं जुड़ेंगे, तब तक बेहतर से बेहतर आर्थिक नीतियां भी सफल नहीं होंगी। नशे के विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध सशक्त आवाज उठानी होगी। तरह-तरह की उपभोक्तावाद आधारित फिजूलखर्ची को भी कम करना ही होगा।

आज की दुनिया में शॉर्ट-कट बहुत पसंद किए जाते हैं। ऐसे में, आश्चर्य नहीं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर प्रायः सतही तौर पर एक-दो उद्देश्यों या फार्मूलों पर चर्चा होती रही है। लेकिन सही व टिकाऊ समाधान तभी मिलेंगे, जब इनके लिए समग्र नीतियां बनेंगी, जब अल्पकालीन हितों के साथ दीर्घकालीन हितों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

चिंतन

कनाडा को अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं

खालिस्तानी अलगावादी तत्वों को लेकर कनाडा का रुख चिंतनीय है। भारत के आतंकवाद के खतरे के बारे में बार बार आगाह करने के बाद भी कनाडा का खालिस्तानी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति वाले रुख से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर पड़ेगा। कनाडा को इस बात का भान है कि नहीं, लेकिन समूची दुनिया खतरनाक आतंकवाद का सामना कर रही है, और सभी प्रमुख ताकतें इसके खिलाफ लड़ रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके आदि देश आतंकवाद के दंश को झेल चुके हैं। खालिस्तानी अलगाववादियों के प्रति कनाडा का सिलेक्टव होना खतरनाक प्रवृत्ति है। भारत ने दो टूक कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं है। कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानी अलगाववादियों के कृत्यों का समर्थन करना रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद विश्व के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका विश्व के सामने कुछेक बड़े उदाहरण हैं। अमेरिका ने 9/11 भुगता, भारत ने मुंबई ब्लास्ट व 26/11 का सामना किया, भारत तो करीब चार दशक से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकी गुट तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन है, इस्लामिक स्टेट की वजह से इराक व सीरिया लहूलुहान हुए। आज आतंकी गुट हमास के हमले के चलते इजराइल को जंग लड़ना पड़ रहा है, इसमें खास बात है कि आतंकी गुट हूती समेत ईरान व कतर जैसे राष्ट्र आतंकी गुट हमास के पक्ष में इजराइल को धमका रहे हैं और हमास का साथ दे रहे हैं। इसलिए वैश्विक आतंकवाद के सभी रूपों को पहचानना जरूरी है, इसके खतरे के प्रति सचेत रहना आवश्यक है और इसके खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ना भी जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना उचित है कि खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक प्रश्रय देकर कनाडा सरकार यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से 'अधिक शक्तिशाली' है। भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान और पालन करता है, लेकिन इसका मतलब विदेशी राजनयिकों को धमकाने, अलगाववाद को समर्थन देने या हिंसा की वकालत करने वाले तत्वों को राजनीतिक प्रश्रय देने की स्वतंत्रता नहीं है। हैरानी है कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश करने और रहने की अनुमति कैसे दी जा रही है? किसी भी नियम-आधारित समाज में आप लोगों की पृष्ठभूमि, वे कैसे आए, उनके पास कौन सा पासपोर्ट था, आदि चीजों की जांच करेंगे। अगर कनाडा में ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर वहां मौजूद हैं, तो कनाडा सरकार का दायित्व है कि वह इसकी जांच करे। पिछले साल सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोप लगाए जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तल्खी आ गई थी। नई दिल्ली ने ट्रूडो के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया था। भारत कहता रहा है कि मुख्य मुद्दा कनाडा द्वारा कनाडाई धरती से सक्रिय खालिस्तानी समर्थक तत्वों को प्रश्रय देने का है। निज्जर मुद्दे में अमेरिका भी कूदा हुआ है, हालांकि भारत की प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका संभला है। भारत की चिंताओं पर कनाडा की प्रतिक्रिया यही रही है कि उसके यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में, कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर भारत चिंता व्यक्त करता रहा है। कनाडा अड़ियल रुख छोड़े, खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह देना बंद करे, आतंकवाद को पालने का क्या हश्र होता है, यह कनाडा पाकिस्तान से सीखे।

सारा संसार

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर नगरकोट में स्थित है, भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जलती हुई देवी सती का बायां स्तन उस भूमि पर गिरा जहां आज खूबसूरत बृजेश्वरी मंदिर है, जिसे भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से माना जाता है।

सवाल

बालमुकुन्द ओझा

राहुल को गुस्सा क्यों आता है

राहुल गांधी को लोग गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं, यह प्रश्न सियासी क्षेत्रों में तेजी से चर्चित हो रहा है। राहुल गांधी को बहुत गुस्सा आता है, जब लोग उन्हें तरह-तरह की उपमाओं से नवाजते हैं। राहुल कई बार यात्राएं निकालकर लोगों के बीच गए। हर तबके के लोगों से मिले। उनका प्यार भी उन्हें मिला, मगर राजनीति में जो सफलताएं उन्हें मिलनी चाहिए उससे वंचित रहे। राहुल की दादी इंदिरा गांधी की आवाज में जादू था। राहुल यह जादू अपने भाषणों में जाहिर नहीं कर पाए। लोगों ने तमाम तरह की उपमाओं से उन्हें विभूषित किया। किसी ने पप्पू कहा तो किसी ने शहजादा। आलू से सोना बनाने की किंवदंती भी उनसे जोड़ दी गई। राहुल की बहन प्रियंका ने इस पर भाजपा को कई बार घेरा और कहा मेरा भाई हजारों किलोमीटर पैदल चला है। इस बीच उनके विवादित भाषण भी काफी चर्चा में रहे विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी टिप्पणियां लोगों को हजम नहीं हुई। राहुल ने अपने विवादित बयानों से कई बार मोदी को पटकने की चेष्टा की, मगर हर बार उनका दांव खाली गया। चौकीदार चोर से लेकर आरक्षण ख़त्म करने के उनके बयान हवा हवाई साबित हुए। अमेठी में हार से भी उनका जनाधार घटा। भाजपा का कहना है कि जब उनकी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों ले। सोनिया, प्रियंका और कांग्रेस के नेता इस सोच में डूबे हैं कि आखिर राहुल में क्या कमी रह गई की जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। राहुल गांधी खूब पसीना बहाने के बावजूद सियासत में वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयासरत है। गांधी-नेहरू परिवार में दो ही ऐसे नेता हुए जिन्होंने हार का स्वाद चखा। एक हार इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी है। 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली से समाजवादी नेता राज नारायण से हार गई थी। इस सियासी परिवार के नाम दूसरी हार राहुल गांधी के नाम है, जिन्हें 2019 में स्मृति ईरानी ने हराकर धमाका कर दिया था। हालांकि राहुल वायनाड से जीत कर संसद पहुंच गए थे। राहुल पिछले दो दशकों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर लगातार एक सफल राजनेता की भूमिका में सक्रियता से जुड़े हैं, मगर लाख प्रयासों के बावजूद वे अपनी पार्टी को हार के गर्त में जाने से नहीं रोक पाए। राहुल की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा भी जनता में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। जब दुनियाभर के दिग्गज नेता दिल्ली में आयोजित जी-20 में शामिल होकर जहां भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में खुलकर सराहना कर रहे थे तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर देश और मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है। गौरतलब है राहुल ने संवैधानिक संस्थाओं पर भी हमला बोला है। कांग्रेस में यह क्या हो रहा है, अपनी पार्टी को संगठित करने के बजाय देश को तोड़ने वाली बातें कर क्या हासिल करेंगे यह समझ से बाहर है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्लेषण
प्रभात कुमार राय

यूक्रेन युद्ध एक नए दौर में

यूक्रेन 2 वर्ष से भी अधिक वक्त से जारी युद्ध की ज्वालाओं में जलकर खाक होता रहा है और समस्त दुनिया यूक्रेन की तबाही का महज तमाशा देखती रही है। रूस की सेना द्वारा यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन विमानों के हमले तेज कर दिए गए हैं। एक ही दिन में 500 से 1000 मिसाइलों को यूक्रेन के शहरों पर दागा जा रहा है। विगत वर्ष पूर्वी यूक्रेन के जिन शहरों पर यूक्रेन सेना द्वारा फिर से अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इस वर्ष उन शहरों को रूसी सेना द्वारा फिर से जीत लिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन युद्ध तकरीबन अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, जबकि रूस सैन्य फतेह के अत्यधिक निकट आ चुका है।

पूर्वी यूक्रेन में चारों तरफ विध्वंस और भयानक तबाही का दर्दनाक मंजर दिखाई देता है। यूक्रेन वस्तुत 2 वर्ष से भी अधिक वक्त से जारी युद्ध की भीषण ज्वालाओं में जलकर खाक होता रहा है और समस्त दुनिया यूक्रेन की तबाही का महज तमाशा देखती रही है। वर्ष 2024 प्रारंभ होते ही रूस की सेना द्वारा यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन विमानों के हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। एक ही दिन में 500 से 1000 मिसाइलों को यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर लगातार दागा जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन इन के शहरों में राजधानी कीव, वलेरी, खार और जापोरोजिया के नगर मुख्य तौर पर शामिल है। विगत वर्ष पूर्वी यूक्रेन के जिन शहरों पर यूक्रेन सेना द्वारा फिर से अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इस वर्ष उन शहरों को रूसी सेना द्वारा फिर से जीत लिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन युद्ध तकरीबन अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, जबकि रूस सैन्य फतेह के अत्यधिक निकट आ चुका है।

यूक्रेन के नागरिकों को और यूक्रेन की हुकूमत को यह प्रबल उम्मीद थी कि इन नाटो सैन्य संगठन में शामिल पश्चिम के यूरोपीय देश और अमेरिका यकीनन यूक्रेन को रूस के विरुद्ध जारी युद्ध में भरपूर सैन्य सहायता करेंगे। पश्चिम के नाटो सैन्य संगठन के दमखम पर ही यूक्रेन ने नाटो का सदस्य देश बनने की दरखास्त पेश की थी, जिसकी प्रतिक्रिया के कारण रूस द्वारा इस युद्ध का आगाज किया गया। क्योंकि रूसी हुकूमत को पक्का अंदेशा था कि नाटो सैन्य संगठन में यूक्रेन के शामिल हो जाने के पश्चात नाटो सेनाएं उसकी सरहद पर तैनात हो जाएंगी, इसीलिए रूस द्वारा 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर सैन्य धावा बोल दिया गया। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों में रूसी सेना का लाल झंडा यूक्रेन की राजधानी कीव पर लहरा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन की इस उम्मीद पर विकट वज्रपात करने के लिए वस्तुतः यूक्रेन की पराक्रम और शौर्य से परिपूर्ण आम जनता जिम्मेदार है। यूक्रेन के बेहद बहादुर जनमानस ने 2 वर्ष से अधिक वक्त तक रूस की सेना के छक्के छुड़ाए रखें है, किंतु इस वक्त यूक्रेन की जनसेना के पास आधुनिकतम हथियारों की बेहद कमी हो गई है, क्योंकि अमेरिका की संसद में यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने पर कुछ नए अवरोध उत्पन्न कर दिए गए हैं। यूक्रेनी जनसेना के कमांडर इन चीफ जनरल वेलेरिली ने फरमाया है कि इस युद्ध को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के बल पर ही जीता जा सकता है। यूरोप के नाटो देशों में यूक्रेन युद्ध के प्रश्न पर गंभीर फूट पड़ गई है। पूर्वी यूरोप के देश स्लोवाकिया में तो रूस समर्थक सरकार सत्तासीन हो गई है। यूक्रेन युद्ध के दौर में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तो तकरीबन बर्बाद हो चुकी है, किंतु तीव्र गति से रूस की अर्थव्यवस्था निरंतर शक्तिशाली होती जा रही है और रूस की जीडीपी में पांच प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है। यूक्रेन युद्ध के दौर में रूस की अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होते जाने की पृष्ठभूमि में निहित है, उसका आर्थिक स्रोत प्राकृतिक गैस और तेल का निर्यात। एक तरफ अमेरिका और यूरोप द्वारा रूस पर कड़े आर्थिक

प्रतिबंध आयद किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस और तेल की सप्लाई यूरोप में बेहद कम हो गई है, किंतु रूस को चीन में और भारत में प्राकृतिक गैस और तेल निर्यात का नए बाजार उपलब्ध हो गए हैं। रूस के लिए प्राकृतिक गैस और तेल और सैन्य हथियारों का निर्यात ऐसा प्रबल आर्थिक स्रोत हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के लंबे दौर में भी डगमगाई नहीं है, वरन और अधिक शक्तिशाली होकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि रूस विश्व पटल पर प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देशों की श्रेणी में एक रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस और तेल की आर्थिक ताकत को प्रेसिडेंट येल्तसिन के दौर में रूस का प्रधानमंत्री बनते ही पहचान लिया था और रूस का प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले उन्हें उन्होंने तेल उत्पादन के औलीगार्क बन गए खोदरकोवस्की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादन करने वाली कंपनी गैसप्राम को पूरी तरह से हुकूमत के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया।

नेपोलियन का कहना था की फ़ौज पेट के बल मार्च करती है। अतः कोई भी देश प्रबल आर्थिक शक्ति के बलबूते पर ही कोई दीर्घकालीन युद्ध लड़ सकता है। युद्ध के दौर में तकरीबन नष्ट हो चुकी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यूक्रेन के नागरिक बड़े पैमाने पर पूर्वी यूरोप के देशों में पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन के पास आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों का जबरदस्त अभाव उत्पन्न हो चुका है और नाटो राष्ट्रों की ओर से उसको भरपूर सैन्य सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों के संचालन में सैनिकों को दीक्षित होने में काफी वक्त लग जाता है और युद्ध के दौर में किसी सेना के पास सैन्य प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त वक्त भी नहीं होता है। केवल सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर यदि युद्ध जीता जा सकता तो फिर यूक्रेन को भी वियतनाम की तरह कोई पराजित नहीं कर सकता है। वियतनाम को अमेरिकी सेना से युद्ध करने के लिए सोवियत रूस और चीन के आधुनिकतम हथियार प्राप्त होते रहे थे, किंतु जमीनी हकीकत है कि किसी सेना को युद्ध में निर्णायक तौर पर फतेहयाब होने के लिए आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी उतनी ही रहती है, जितनी कि सैन्य पराक्रम और शौर्य। यूरोपीय यूनियन ने अब यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने के बारे में विचार करना प्रारंभ किया है। यदि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश बन जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी जा सकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका यूक्रेन युद्ध में सीधे कूदने को तैयार नहीं है। अमेरिका की कयादत के बिना कोई भी नाटो देश यूक्रेन युद्ध में रूस के विरुद्ध अपने सैनिक नहीं भेजेगा, अतः रूस को अब कौन पराजित कर सकेगा। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, मनोबल बचा है। हां अगर आधुनिकतम हथियार भरपूर मात्रा में यूक्रेन को प्रदान कर दिए जाएं तो फिर इस युद्ध को आगे भी यूक्रेन की जनसेना दीर्घकाल तक लड़ा सकती है।

यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण निदान निकालने के लिए समस्त यूरोप ने बड़ी उम्मीद के साथ भारत की तरफ देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत अपने इस कथन से आगे नहीं बढ़ सका कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भारत ने यूक्रेन युद्ध का समुचित निदान निकालने के लिए कोई सार्थक पहल अंजाम नहीं दी। चीन तो कदाचित कोई निदान निकल नहीं सकता था क्योंकि वह तो खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है और उसको आधुनिक लड़ाकू विमान और अन्य अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करा रहा है। तकरीबन दो सैन्य खेमों में विभाजित हो चुके विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है, जिसके कूटनीतिक ताल्लुकात रूस और अमेरिका के साथ अत्यंत मैत्रीपूर्ण हैं। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और विश्व शांति की खातिर शानदार पहल करने में भारत कूटनीतिक रूप से चूक गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है

संकलित
दर्शन

भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की पूजा होती है, ऐसे स्थानों में उनकी सत्ता अधिक अनुभूति होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्माचार्यों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि ये आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते, उसके प्रति कभी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के लिए वह भटकता फिरता है और बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह। विरह प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। यह दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग वस्तु को न जान सकने के कारण तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और अत्यंत व्याकुल हो पागल-सा हो जाता है, उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है, यहां तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक कहना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है।

दूसरों की जरूरतें पूरी करना ही दान है

संकलित
प्रेरणा

महाभारत का एक प्रसंग है। एक दिन युधिष्ठिर ने वेद व्यास से पूछा कि दान बड़ा है या पूजा-पाठ और तपस्या? व्यास जी ने युधिष्ठिर को अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के महर्षि थे, वे भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। भिक्षा में उन्हें आटा, खाने-पीने की चीजें, हवन सामग्री मिल जाती थीं। दान में मिली चीजों से ही वे खाना बनाते और पूजा-पाठ करते थे। कभी-कभी ऐसे दिन भी आते थे, जब उन्हें भिक्षा नहीं मिल पाती थी। अधिकतर अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसा हुआ करता था। इन दोनों तिथियों पर ऋषि मुद्गल से मिलने दुर्वासा ऋषि आया करते थे। दुर्वासा मुनि को खाना खिलाने के बाद उनके लिए कुछ बचता नहीं था तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ तो दुर्वासा मुनि ने मुद्गल ऋषि से पूछा कि आप मुझे खाना देकर खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भूख के लक्षण नहीं देखे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगती है? मुद्गलजी ने कहा कि मेरे लिए दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अन्न दान तो सर्वश्रेष्ठ होता है, जब आपकी भूख शांति होती है, तब मैं भी तृप्त हो जाता हूं। मैं दान पुण्य कमाने के लिए नहीं करता हैं, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता हूं। व्यास जी ने युधिष्ठिर को आगे समझाया कि तपस्या स्वयं के लिए की जाती है, लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। इसलिए दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना ही दान है। इसलिए दान तप से भी श्रेष्ठ है। जब हम दान करते हैं तो प्रकृति भी हमें इसका शुभ फल किसी न किसी रूप में जरूर लौटाती है।

अंतर्मन

आज की पाती

कई राज्यो में चिलचिलाती गर्मी से जनजीवन प्रभावित

कई राज्यो में मई के पहले सप्ताह में गर्मी के तेवर तीखे हो गए है। पारा उबाल पर है और लू के थपेड़ों से जीवन प्रभावित हुआ है। कई राज्यो में पारा ने लोगों को खूब तपाया। बढ़ती गर्मी के कारण लोग दोपहर को घर से निकलना पसंद नही करते हैं। मौसम विभाग ने भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 से शाम को 4 बजे तक बच्चों को बाहर नही निकलना चाहिए। मौसम विभाग ने पारा और अधिक बढ़ने की संभावना जताई है। लोग घरों में कुलर और वातानुकूलित व्यवस्था में लगे है। देश में गर्मी बढ़ने से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। – **कान्तिलाल मांडोत**, सूरत

करंट अफेयर

पोप का आग्रह, इतालवी ज्यादा बच्चों को जन्म दे

पोप फ्रांसिस ने इटली के लोगों से ज्यादा बच्चों को जन्म देने का आग्रह किया और आगाह किया कि देश का जनसांख्यिकीय संकट भविष्य के लिए खतरा है। पोप ने परिवारों की मदद के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाने की भी मांग की। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'जन्म की संख्या लोगों की उम्मीदों को दर्शाती है। बच्चों और युवाओं के बिना एक देश की भविष्य के प्रति कोई आकांक्षा नहीं रह जाती।' इटली में जन्म दर पहले ही काफी कम है और यह 15 वर्षों से लगातार गिर रही है। यह पिछले साल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। देश में पिछले वर्ष 3,79,000 शिशुओं का जन्म हुआ। वैटिकन के मजबूत समर्थन से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने 2033 तक सालाना कम से कम 5,00,000 शिशुओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह दर इटली की बढ़ती आबादी के बोझ तले अर्थव्यवस्था को ढहने से रोकने के लिए जरूरी है। पोप ने दंपतियों को और अधिक बच्चे जन्म देने के प्रति प्रोत्साहित करने के वास्ते दीर्घकालिक नीतियां बनाने की भी मांग की।

ऑफ बीट

नींद में पड़ी झुर्रियां होती हैं अस्थायी

जब आप सुबह नींद से जागते हैं और शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो पता चलता है कि रातों रात चेहरे पर कुछ झुर्रियां उभर आयी हैं। नींद में पड़ने वाली ये झुर्रियां अस्थायी होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र के साथ त्वचा का लचीलापन खत्म होता है, ये झुर्रियां सही हो सकती हैं। झुर्रियां बनने से रोकने की संभावना कम से कम करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। करवट लेकर सोने से आपके चेहरे पर क्या असर होता है : आपकी त्वचा पर कई कारणों से झुर्रियां पड़ती हैं, जिनमें उम्र बढ़ना, धूप से होने वाला नुकसान, धूम्रपान, पानी कम पीना, आदतन चेहरे के भाव (जैसे मुस्कुराना, थपथपाना, भौंहें चढ़ाना) और सोने की स्थिति शामिल हैं। जब आप करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं तो आपके चेहरे की त्वचा में कसावट आ जाती है और पीठ के सहारे सोने पर यह और अधिक कस जाती है। जब आप करवट लेकर या पेट के सहारे सोते हैं तो तकिए के विरुद्ध आपके चेहरे पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव होता है। तो जब आप नींद में हिलते हैं तो आपके चेहरे की त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, यह दबती है और सभी दिशाओं में खिंचती है। आप पीठ के सहारे या बार-बार सोने की मुद्रा बदलकर चेहरे पर इन बाहरी कारकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। डॉक्टर आपके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि आपको किस करवट सोना चाहिए।

ट्रेंड

इंडी का सूरज अस्त होगा

विकसित भारत के निर्माण के महायज्ञ में आहुति देने के लिए जनता-जनार्दन इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। नंदुरबार में लोगों का उत्साह साफ बता रहा है कि 4 जून को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी का सूरज अस्त होने जा रहा है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं

यदि आप इच्छाओं को पूरा करने के बजाय अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो आप इस जीवन को सहजता से, शालीनता से, बहुत अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंसान होने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में सचेत रहने में सक्षम होना
-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

गिनती का विरोध क्यों

बजाय जातिगत जनगणना कराने के मोदी अकर्मण्य आर्थिक सलाहकार समिति की मनगढ़ंत रिपोर्ट के पीछे ना छुपें। हम डंके की चोट पर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं जिससे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीब सामान्य वर्ग से न्याय हो। मोदी गिनती का विरोध क्यों करते हैं?
-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

500 मिलियन डॉलर खर्च करेगा

टेस्ला इस साल हजारों नए चार्जर बनाने के लिए हमारे सुपरचार्जर नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 500 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च करेगा। यह केवल नई साइटों पर है, संचालन लागतों की गणना नहीं की जा रही है, जो बहुत अधिक हैं।
-एलोन मस्क, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid